Sixth Series, Vol. XIV—No.45

Thursday, April 27, 1978
Vaisakha 7, 1990 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Fourth Session)

(Vol XIV contains Nos. 41—50)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

Price: Rs. 4.00

CONTENTS

COLUMNS

No. 45, Thursday, April, 27, 1978/Vaisakha 7, 1900 (Saka)

Oral Answers to Questions:

*Starred Questions Nos. 884 to 886, 889, 891 and 893 to 895 . 1—28

Written Answes to Questions:

Starred Questions Nos. 887, 888, 890, 892 and 896 to 903 . 28—43

Unstarred Questions Nos. 8320 to 8380, 8382 to 8428, 8430 to 8457, 8459 and 8461 to 8464 . . 43—175

Matters under Rule 377—

(i) Reported Robbry in Passenger Train on 21-4-1978 . . 175

Shri Yuvraj 175

(ii) Reported cases of Food Poisoning in B.I.T., Mesra (Ranchi) . 176

Dr. Ramji Singh 176

(iii) Reported Attacks by hooligans on foreign residents of Auroville, Pondicherry . . 176—78

Shri Bijoy Singh Nahar . . . . . 176—78

(iv) Present Status of Banking Service Commission . . . 178—82

Shri Saugata Roy . . . . 178—80

(v) Demand for running Express Train from Durg to Banaras . 182—85

Shri Mohan Bhaiya . . . . 182—84

Papers laid on the Table 185

Public Accounts Committee—

Seventy-eighth & Eighty-first Reports presented . . . 185—86

Committee on Public Undertkings—

Tenth Report and Minutes presented 186

Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes—

Twenty-first and Twenty-third Reports presented . . . 186

Petition *Re.* Grievances of Employees of Coal India Ltd . . . 187

---

*The sign + marked above the name of a *Member* indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

Statement *Re.* Reported AIR Broadcasts alleging ticketless travel by some Congress(I) Workers on 6th April, 1978 187

Shri Jagbir Singh 187

Business Advisory Committee—

Sixteenth Report adopted 188

Appropriation (No. 3) Bill, 1978—

Motion to consider . . . . 188—209

Shri H. M. Patel . . . . . . 188, 208—209
Shri Jyotirmoy Bosu . . . . 189—95
Shri Keshavrao Dhondge . . . . 195—98
Shrimati Parvathi Krishnan . . . . . . 198—200
Shri A. K. Roy . . . . 200—201
Shri Annasaheb Gotkhinde . . . . . 201—202
Shri P. Ankineedu Prasada Rao . . . . . . 202—203
Shri Vasant Sahte . . . . 203—204
Shri Vayalar Ravi . . . . 204—205
Shri Saugata Roy . . . . 205—206
Shri K. T. Kosalram . . . . 206—208

Clauses 2 to 4 and Schedule and Clause 1 . . . . . . 209—10

Motion to pass—

Shri H. M. Patel 210

Finance Bill, 1978 . . . . 210—

Motion to consider . . . . 210—308
Shri H. M. Patel . . . . 210—15
Shri R. Venkataraman . . . . 216—26
Shri Harikesh Bahadur . . . . 226—35
Shri T. A. Pai . . . . 235—43
Shri M. P. Sinha . . . . 243—48
Shri R. D. Ram . . . . 248—54
Shri G. M. Banatwalla . . . . 254—57
Shri Chandra Pal Singh . . . . 257—61
Shri Kunwar Mahmud Ali Khan . . . . . 260—69
Shri D. G. Gawai . . . . 269—75
Shri Dhirendranath Basu . . . . 275—79
Shri Bharat Bhushan . . . . 279—91
Shri M. Satyanarayan Rao . . . . . . 291—96
Shri Pabitra Mohan Pradhan . . . . . . 297—301
Shri Ram Naresh Kushwaha . . . . . . 301—308

LOK SABHA

Thursday, Ap il 27, 1978 Vaisakha 7 1900 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

National Policy on Medical Education

*884. SHRI DHARMA VIR VASISHT Will the Minister of HELATH AND FAMILY WELFARE be pleased to state ·

(a) whether it is a fact that the Estimates Committee in its Sixth Action Taken Report (1977-78) on the Ministry of Health and Family Welfare reiterated its earlier stand and urged Government to bring before Parliament the national policy on medical education ;

(b) if so, the action taken thereon,

(c) whether Government has taken up the matter with the Medical Council of India, and

(d) if so with what results and if not why not ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). 'चिकित्सा शिक्षा और सहायक कार्मिकों सम्बन्धी ग्रुप की रिपोर्ट पर बनाई गई कार्य-योजना के अनुसार भारत सरकार सभी मेडिकल कालेजों में चिकित्सा शिक्षा परिस्थिति अनुकूलन' की योजना को जोरदार ढंग से क्रियान्वित कर रही है। अन्य बातों के साथ-साथ इसका लक्ष्य यह भी है कि बड़े अस्पतालों में की जाने वाली चिकित्सा सेवाओं की एक सुव्यवस्थित प्रणाली के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाए सीधे प्रदान करने के काम में मेडिकल कालेजों को लगाया जाये। उक्त योजना की मुख्य मुख्य बातें स्नातकपूर्व चिकित्सा पाठ्यचर्या के विषय में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के विनियमों में दी गई है। इनके अनुसार मेडिकल कालेजो के लिए कानूनी अपेक्षा के रूप मे यह अनिवार्य हो जाता है कि वे चिकित्सा शिक्षा का अधिकाधिक लोगों की जरूरतों को पूरा करने के निमित्त बड़े पैमाने पर अपना योगदान दें। सक्षेप मे, इस उपाय का दीर्घकालिक और अल्पकालिक उद्देश्य सरकार के उस दृढ़ संकल्प का परिचायक है जिस के माध्यम से वह देश की चिकित्सा शिक्षा को चिकित्सा व्यवसायियों के दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं मे अपेक्षित प्रवृत्तिपरक परिवर्तन लाने और लोगो के प्रति निष्ठा की भावना उत्पन्न करने का एक साधन बनाना चाहती है। अत सरकार का यह मत है कि वर्तमान स्नातकपूर्व चिकित्सा पाठ्यचर्या मे हड़बड़ी मे कोई अधिक महत्वपूर्ण और प्रमुख परिवर्तन करने से पहले जो 'चिकित्सा शिक्षा परिस्थिति अनुकूलन' वाली योजना पहले से ही क्रियान्वित कर दी गई है उसे समुचित रूप से प्रयोग मे लाया जाना चाहिए ताकि इस योजना के अन्तर्गत निकले परिणाम और उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जा सके। इसलिए जैसा कि अनुमान समिति ने सिफारिश की है, इस अवस्था मे चिकित्सा शिक्षा के विषय में कोई राष्ट्रीय नीति तय करना मुनासिब नही है।

SHRI L. K. DOLEY : Sir, I want a clarification on the question (a) 884(a). It is stated like this :

"(a) whether it is a fact that the Estimates Committee in its Sixth

Action Taken Report 1977-78 on the Ministry of Health and Family Welfare reiterated its earlier stand and urged Government bring before Parliament the National *police* on medical education ;.."

Here, in the last line of the above question, the word 'policy' has been misprint as 'poce'

श्री धर्मवीर वशिष्ठ : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि रिम्रोरिएण्टेशन म्राफ़ मेडिकल एजूकेशन, जिस के बारे मे म्राप ने कहा है कि बल दिया जा रहा है म्रौर डि'मेंके जो मोटे मेलिएण्ट फीचर्स हैं उन को इस कल कउन्सिल म्राफ़ इण्डिया रेगुलेशन्ज मे म्रण्डर-ग्रेजुएट्स का जो करिकुलम है, उसमें शामिल कर दिया गया है—क्या म्राप बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन सेलिएण्ट फीचर्स को मैडिकल काउन्सिल म्राफ़ इण्डिया के रेगुलेशन्ज में शामिल किया गया है, वे क्या हैं म्रौर उन के प्रति मेडिकल एसोसियेशन म्राफ़ इण्डिया की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : म्रध्यक्ष महोदय, हमने समिति को सूचित किया था कि चिकित्सा शिक्षा म्रौर सहायक कार्मिक सम्बन्धी ग्रुप की सिफारिशों पर कार्य-योजना की, जिस का उद्देश्य देश की चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में जबरदस्त परिवर्तन करना था, भारत सरकार ने उपर्युक्त ग्रुप की सिफारिशों के म्राधार पर बड़े ध्यानपूर्वक बनाई थी। म्रप्रैल, 1976 में हुई स्वास्थ्य म्रौर परिवार कल्याण की केन्द्रीय परिषदों की बैठक में इस कार्य योजना पर विचार-विमर्श कर के इसे म्रनुमोदित कर दिया गया। इस बैठक में विभिन्न राज्य सरकारों/संघ-राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने भाग लिया था म्रौर इस लिए यह इस समय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी एक प्रकार की राष्ट्रीय नीति का ही काम दे रही है।

इस में सामुदायिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याम्रों पर मेडिकल कालेजों का सहयोग लेने म्रौर चिकित्सा शिक्षा को पुन: परिस्थितियों के म्रनुकूल बनाने के प्रश्न पर भी विचार किया गया है। इस की मुख्य बातें यह हैं कि सभी मेडिकल कालेजों के प्रत्येक जिले के तीन-तीन ब्लाकों, जहां पर वे स्थित हैं म्रथवा म्रासपास के जिलों जहां पर चार म्रौर पांच वर्षों में पूरे जिले में चरणबद्ध विस्तार सम्बन्धी सुविधाम्रों की व्यवस्था की गई है, वहां तर बीमारियों की रोक-थाम, स्वास्थ्य सुधार .....

MR. SPEAKER : You have not answered to his question. He wants to know what are the salient points and what is the reaction of the Medical Council

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन्, मैं सेलिएण्ट फीचर्स के बारे मे ही बतला रहा हूं। ग्रुप ने जो प्रस्तावित किया है जो-जो सुझाव दिये है, जिन को हम कार्यान्वित कर रहे हैं—मैं वही बतला रहा हूं।

श्री धर्मवीर वशिष्ठ : मैं कार्यान्विति के बारे में नही पूछ रहा हूं—म्राप ने म्रपने उत्तर में कहा है कि "चिकित्सा शिक्षा परिस्थिति म्रनुकूलन" की योजना को जोरदार ढंग से क्रियान्वित कर रहे हैं। इस को मेडिकल कौन्सिल म्राफ़ इण्डिया रेगुलेशन्ज में भी शामिल कर दिया गया है, मेरा मतलब है उस के सेलिएण्ट फीचर्स का शामिल कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि चिकित्सा शिक्षा परिस्थिति म्रनुकूलन में कौन-कौन से सेलिएण्ट फीचर्स को मैडिकल कौन्सिल म्राफ़ इण्डिया रेगुलेशन्ज में शामिल किया गया है म्रौर उन के प्रति मेडिकल कौन्सिल म्राफ़ इण्डिया का क्या रिएक्शन है ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन्, जो हम ने स्वीकार किया है, उसी के सेलिएण्ट फीचर्स बतला रहा हूं—प्रत्येक कालिज के साथ तीन-तीन ब्लाकों को एटेच किया गया है म्रौर उस में जो सुविधायें दी गई हैं—उनको भी मैंने बतलाया है। वहां पर बीमारियों की रोक-थाम, स्वास्थ्य सुधार के

कार्यों तथा उपचार विषयक स्वास्थ्य देखरेख करने की पूरी जिम्मेदारी दे दी जानी चाहिए । कार्य-योजना मे बताये गये विचारों को कार्यरूप देने के लिए, कार्य-योजना के अनुसार मार्गदर्शी सिद्धान्त भी बना लिये गये है । यह कार्य योजना आयोग तथा वित्त मत्रालय की सहमति मे किया गया है, ।

जो सेलिएण्ट फीचर्स मैंने यहा बताये है, इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन ने उन का कोई विरोध नही किया है ।

श्री धर्मवीर वशिष्ठ : मैने मंत्री महोदय से पिछले सवाल मे यह पूछा था कि उन की प्रतिक्रिया (रिएक्शन) क्या है ? मैंने यह नही पूछा था कि उन्होंने विरोध किया है या नही ।

साथ ही मैं यह भी पूछना चाहता हू वर्तमान अण्डर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम को हर दफा बदलने से पहले, परिवर्तन करने से पहले, नेशनल पालिसी मे चेञ्ज लाने से पहले, क्या सरकार रि-ओरिएण्टेशन पर गौर करना चाहती है ? मैं यह भी पूछना चाहता हू---रिओरिएण्टेशन आफ मेडिकल एजूकेशन पालिसी पर गौर करने मे आप कितना समय लगायेंगे, जिस के बाद आप यह तय करेंगे कि नेशनल मैडिकल एजूकेशन की पालिसी क्या हो ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन्, यह जो रिआरिएण्टेशन कार्यक्रम है---यह अभी-अभी प्रारम्भ किया गया है, इसका प्रतिफल एक-दो वर्षों मे सामने आयेगा । प्रतिफल को देखने के बाद तय करेंगे कि चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रीय नीति क्या हो । इस समय स्थिति यह है कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इस लिए चिकित्सा शिक्षा नीति तय करने से पहले हमे राज्यों तथा इन के साथ ही जो स्टेचूटरी और आटोनामस बाडीज है उन को भी इस मे इन्वाल्व करना पडेगा, उनके साथ भी चर्चा करनी पडेगी । इसलिए रिओरिएण्टेशन का जो तत्काल कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है, हम समझते है कि उस के प्रतिफल अवश्य देखने मे आयेंगे, उन को देखने के बाद यह तय करेंगे कि किस प्रकार की नीति हो ।

MR. SPEAKER : You have not mentioned what is the reaction of the Medical Council.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन्, हम ने पहले कहा है कि इस नीति का, इस कार्यक्रम को उन्होंने अपनाया नही किया है । इस के मायने है कि उन्होंने इस नीति का समर्थन किया है और उसके समर्थन के कारण ही हर कालिज के साथ तीन-तीन ब्लाक्स को एटेच करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

डा० बल्देव प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, देश की परिस्थिति को देखते हुए---डाक्टर्स देहाती इलाकों में नही जाते है और जो आजकल मेडिकल ग्रेजुएट्स का कोर्स है एफ० एस० सी० करने के बाद, इण्टरमीडिएट के बाद, पाच साल का कोर्स है । क्या कोई ऐसा कोर्स सरकार के विचाराधीन है जैसा कि पहले था कि 10वीं के बाद तीन साल मैं अण्डर-ग्रेजुट्स को डिग्री मिलती थी और अधिक से अधिक लोग ट्रेण्ड हो कर देहातों में जा सकते है ---क्या ऐसा कोई कोर्स सरकार के विचाराधीन है ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन, यह सर्व विदित है कि जो चिकित्सा शिक्षा वर्तमान में है, विशेष कर एलापैथी में जो चल रही है, वह अपने देश और विशेष कर ग्रामीण जनता के अनुकूल नही है । इस लिए हम ने यह सोचा है .

MR SPEAKER : The question is different. Are you accepting what he suggested ? It is a short question.

डा० बलदेव प्रकाश : उस में 2 साल ज्यादा लगते हैं, लेकिन जो पहले था उसमें 6 साल कम हो जायेंगे ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैंने इन प्रश्नों को साफ करने के लिए ही थोड़ा विस्तार में बताया है । मेरा उद्देश्य यही था कि जो विचार हमारे माननीय सदस्यों के आय है उन पर हम आगे विचार कर सकें कि इस पद्धति में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है ।

SHRI L. K. DOLEY : This question raises another specific question. Here the Minister has said : "I am hopeful that the Medical or Health Department will do the needful as far as is possible for the Medical Department." But so far as the welfare of the families is concerned, what is the attitude of the Government ? What is the attitude of the Government specifically with regard to the growth of population.

MR SPEAKER : That does not arise from the question. The question is about certain proposals.

SHRI EDUARDO FALEIRO : Is the Government aware that the concerned bo Medical Education have suggested the constitution of a Medical Education Commission for disbursing funds on the lines of UGC to supervise the Medical, Dentral and Nursing profession ?

MR SPEAKER : It does not arise from the question.

बोकारो इस्पात संयंत्र में धमन भट्टियां

*885. श्री राम विलास पासवान : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो महीने में बोकारो इस्पात संयत्र की दो धमन भट्टियां एक दूसरे के बाद बन्द कर दी गई हैं और वहां के अधिकारियों द्वारा तीसरी धमन भट्टी पर कार्य किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) : (a) Blast Furnaces No 1 and 2 of the Bokaro Steel Plant were banked during the following periods only and not for two months :—

Blast Furnace No 1—from March 8 to March 17, 1978.

Blast Furnace No 2—from March 9 to March 28, 1978.

However, the third Blast Furnace continued to be operated by the workers.

(b) The operators of electrically operated travelling cranes and mobile equipment as well as high pressure welders of the Plant Struck work from February 27, 1978 to March 27, 1978.

श्री राम विलास पासवान : मंत्री महोदय ने इतनी बात तो कबूल की है कि बोकारो इस्पात कारखाने की धमन भट्टी बन्द की गई थी, पीरियड में थोड़ा अन्तर है । इस तरह ये इस्पात संयत्र और जगह भी बन्द हो रहे है और हम ने एक प्रश्न पहले भी किया था जिस का उत्तर इस्पात और खान राज्य मंत्री श्री करिया मुण्डा ने दिया था और बताया था कि भिलाई इस्पात संयंत्र में 482 तप्त धातु का औसतन दैनिक उत्पादन पिछले आठ महीने से कम होता जा रहा है, जिस का मूल्य 3 लाख 12 हजार रुपया प्रति दिन होता है और अब तक संयंत्र को 8 करोड़ रुपये से ज्यादा का घाटा हुआ है । यह घाटा पिछली सरकार के नुमायन्दे अफ़सर जो वहां पर बैठे हुए है, उन के कारण हुआ है ।

MR SPEAKER : We are on a short question. You are not to raise a debate here.

श्री राम विलास पासवान : मैं बोकारो के क्वेश्चन पर ही आ रहा हूं । मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी अवधि तक जो यह संयंत्र बन्द रहा, तो उस के कारण कितने का घाटा हुआ है और हड़ताल के कारण क्या थे और क्या वह हड़ताल लीगल थी या इल्लीगल थी और सरकार ने उस बारे में क्या कार्यवाही की है ।

SHRI BIJU PATNAIK: The hon. Member has raised two questions. What is the loss on account of strike? The loss of production to the plant during the strike period is valued at Rs. 4.18 crores and the loss of wages to the workers during the strike period was Rs. 8.42 lakhs approximately. The strike was an illegal strike and it was, in my opinion, not called for because it was mainly on a demand to give the operators a certain pay scale which is contrary to the pay scales available in other steel plants. So, at the moment, I have requested the Chief Minister of Bihar to look into the whole problem and settle this case and fix the pay scales, etc. on the basis of those in other steel plants like Rourkela or Bhilai.

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि आपने मेरे प्रश्न की गंभीरता को समझा होगा कि इसमें पांच-पांच करोड़ रुपये का घाटा चला आ रहा है। आपकी आज्ञा से अब मैं दूसरा प्रश्न मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार यह उपयुक्त समझती है कि जिस तरह से इण्डस्ट्रीज वैगरह में जो लाएंड आर्डर का मामला चलता है और उसको राज्य सरकार देखती है उसी तरह इस्पात कारखानों में जो ला एण्ड आर्डर का मामला पैदा होता है उसको भी राज्य सरकार को देखना चाहिए? क्या इस दिशा में आप कुछ करने जा रहे हैं? क्या सरकार यह भी समझती है कि एक इंडस्ट्री में एक ही यूनियन होनी चाहिए?

SHRI BIJU PATNAIK: Does that question arise out of this? There is nothing special that he has asked. Law and order is a general question of the State. But I deliberately did not wish to take a harsh attitude towards the erring workers, because they have gone on an illegal strike. They have been made to understand that this kind of thing will not be allowed to continue. Their loss of wages should have been sufficient punishment for them for carrying on an illegal strike, declared illegal by the Bihar Deputy Labour Commissioner.

SHRI A. K. ROY: The crane operators' strike took place not because of any new demand. It was only to get implemented the arbitration award given by the Labour Minister of Bihar during the Congress regime. The management also is a signatory to the condition that whatever the Labour Minister will say, the management will implement. The crane operator went on strike because the Labour Minister's arbitration award was not implemented by the management. I wonder how a strike on account of the non-implementation of a legal award could be illegal. Actually the mangement's action is illegal on this point. The Steel Minister should clarify it. It is a very important matter. Secondly, what would have been the expenditure if the management would have conceded the demand of the workers?

SHRI BIJU PATNAIK: The strike was declared illegal by a communication from the Deputy Labour Commissioner-cum-Conciliation Officer of the Government of Bihar on 27th February, 1978.

SHRI A. K. ROY: On a point of order, Sir.

MR. SPEAKER: During Question Hour, no point of order.

SHRI A. K. ROY: As per the present law the Deputy Labour Commissioner has no power to declare a strike as illegal, only a tribunal can declare it illegal.

SHRI BIJU PATNAIK: He is also the Conciliation Officer. No authorised notice was given for the strike. Therefore it was declared illegal.

SHRI A. K. ROY: It is not a question of notice.

SHRI BIJU PATNAIK: When it is without notice it is not a legal strike.

MR. SPEAKER: He asked what would have been the expenditure if the demand had been conceded.

SHRI BIJU PATNAIK: It is not only a question of cost but a question of principle. In the entire steel industry there are certain grades for different operators. Here I think the management of Bokaro Steel Plant were unduly generous to the local people to train them over the years before they were upgraded.

And that is why this threat has come about. They should have in my opinion, got trained operators from other plants to fill up their higher posts. Then this would not have come. They trained these people, the new entrants, who were given opportunity to be trained and upgraded. Suddenly, these people started saying that because they were doing the other work while under training, they must get the same grade, which is wrong. Therefore, all the union leaders agreed to go round Rourkela and Bhilai and find out what is

happending there and what sort of grade there is etc. and I have no doubt that will be settled.

SHRI A. K. ROY : My question was precisely whether the strike was for implementation of an arbitration award given by the Labour Minister of Bihar. You just understand the implication. The matter was referred to arbitration and the Labour Minister of Bihar gave an award and these people went on strike for implementation of the award. I want to know whether it is a fact.

SHRI BIJU PATNAIK : This is not the question. It was an award, I believe, but the management protested against that 'award and therefore, that award .. (*interruptions*). There is no use in howling about these things. You listen to me. The management again brought it up to the person concerned who gave the award.

(*Interruptions*) r

SHRI B. P. MANDAL : He said "howling". The hon. Minister should withdraw that word. We are Members of Parliament....

MR. SPEAKER : Yes, it is a wrong word.

(*Interruptions*)

SHRI BIJU PATNAIK : It is not 'howling', it is 'shouting'. The position is this The previous Minister of Labour gave an award after discussing the whole thing and then these people prosteted that this award was given on wrong premises and the Minister herself agreed that this should be reviewed. After that, the Government fell. That is the correct position. Therefore, it is not correct for Mr. A. K. Roy, who knows the whole 'position, to distort this. Dont smile, Mr. A. K. Roy. It is not right to do this.

Training of Medical Practitioners Specialists, Nurses, and Auxiliaries

*886. SHRI D. G. GAWAI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government have formulated a balanced policy for training medical practitioners, specialists, nurses and auxiliaries so that all of them could function together as a team; and

(b) the steps taken or proposed to be taken by the Ministry in this respect ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख). गांवों के लोगों को स्वास्थ्य की मिली-जुली सेवायें प्रदान करने के अभिप्राय से भारत में 1958 से स्वास्थ्य दल को प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। यह प्रशिक्षण प्राइमरी हेल्थ सेण्टरों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों अर्थात् चिकित्सा अधिकारियों, स्वास्थ्य परिचारिकाओं, सहायक नर्स मिडवाइफों, मिडवाइफ़ों और सफाई निरीक्षकों को ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्रों में सामूहिक रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। उनके विशिष्ट दायित्व निर्धारित किये जाते हैं और वे किस-किस क्षेत्र में काम करेंगे उसे भी समचित ढंग से अंकित कर दिया गया है ताकि उन्हें एक सुसंगठित दल का रूप दिया जा सके। बहुधन्धी कार्यकर्ता योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों के मुख्य प्रशिक्षकों अर्थात् प्रिंसिपल, स्वास्थ्य शिक्षक, समाज विज्ञान शिक्षक, जन स्वास्थ्य नर्सों के शिक्षक को केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाता है। वे आगे प्राइमरी हेल्थ सेण्टरों के चिकित्सा अधिकारियों और खण्ड विस्तार शिक्षकों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का मिला-जुला प्रशिक्षण देते हैं तथा ये कार्मिक प्राइमरी हेल्थ सेण्टरों के स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (पुरुष और महिला) तथा स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों (पुरुष और महिला) को प्रशिक्षण देते हैं और उनमें से प्रत्येक को यह भी समझाते हैं कि लोगों को मिली-जुली चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने में उनका क्या-क्या योगदान होना चाहिए। जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के अन्तर्गत भी प्राइमरी हेल्थ सेण्टरों के स्टाफ को, जिसमें स्वास्थ्य परिचारिका, सहायक नर्स मिडवाइफ, सफाई निरीक्षक, खण्ड विस्तार शिक्षक आदि भी शामिल हैं, सामूहिक

रूप से शिक्षण दिया जाता है ताकि वे जन स्वास्थ्य रक्षकों को कारगर ढग से प्रशिक्षित कर सकें ।

प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों के कर्तव्यों और उनके दायित्वों को निर्धारित करने के लिए सरकार ने कदम उठायें है तथा प्रत्येक वर्ग के लिए वर्क-मेनुअल तैयार किये जा रहे है। प्रशिक्षण सम्बन्धी पाठ्यचर्या भी तैयार कर ली गई है और उसे सभी केन्द्रीय प्रशिक्षण सस्थानो स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों और प्राइमरी हैल्थ सेन्टरो आदि में भेज दिया गया है ।

AN HON MEMBER Sir he is reading a long statement

(*Interruptions*)

MR SPEAKER Mr Minister, long statements are expected to be laid on the Table of the House It is only very small statements that are read This is a long one You should have laid it on the Table of the House

SHRI KANWARLAL GUPTA Sir you allow 30 minutes to answer for Mr Raj Narain Will you not give three minutes to this Minister ?

MR SPEAKER No, no I am not calculating on the basis of the Minister The rule is same for every body What is said is that large statement should be laid on the Table of the House This applies to Mr Raj Narain and this applies to everybody

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : चार लाइने और है ।

प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों के कर्त्तव्यो और उनके दायित्वो को निर्धारित करने के लिए सरकार ने कदम उठाए है तथा प्रत्येक वर्ग के लिए वर्क-मैनुअल तैयार किए जा रहे हैं । प्रशिक्षण सबंधी पाठ्यचर्या भी तैयार कर ली गई है और उसे सभी केन्द्रीय प्रशिक्षण सस्थानो, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रो और प्राइमरी हैल्थ सन्टरो आदि मे भेज दिया गया है ।

SHRI K GOPAL Sir, you should give a ruling

MR SPEAKER I thought everybody knew the distinction between long and short statements

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव मैं निवेदन करना चाहता हू कि लोग स्टेटमेट की भी कुछ परिभाषा होगी । लेकिन यह तो एक पृष्ठ और चार पक्ति का ही है । अगर यह लोग स्टेटमेट है तो फिर शोर्ट क्या होगा ? आधे पेज का तो सवाल ही है । अगर उतने का भी जवाब नही दिया जायगा तो क्या होगा?

श्री डी० जी० गवई अध्यक्ष महोदय, सरकार का कहना है कि इन चिकित्सा सेवाओं म लगे कर्मचारियो को व्यापक ट्रेनिंग दे रहे है । लेकिन 25 फरवरी को पटना मे मेडिकल कालेज का जब जयन्ती उत्सव आरम्भ हुआ उस समय हमारे राष्ट्रपति जी ने इस बात पर बल दिया था कि चिकित्सा सेवाओ मे लगे लोगो को प्रशिक्षण देने के लिये एक सतुलित नीति बनायी जाय । मैं जानना चाहता हू कि क्या स्वास्थ्य मन्त्रालय ने राष्ट्रपति जी को कभी यह नही बताया कि ऐसी कोई नीति चल रही है? सरकार और राष्ट्रपति जी के बीच यह समन्वय न होने का क्या कारण है ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव । अध्यक्ष महोदय इस प्रश्न से तो यह नही उठता है ।

श्री डी० जी० गवई · वर्क्स-मनुअल जो बनाने जा रहे है वह कब तक तैयार हो जायगी ताकि हर व्यक्ति को अपना काम करने की जिम्मेदारी मालूम हो सके ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : कुछ वर्क-मैनुअल बन चुकी है और बहुत थोड़ी बची हैं । सीमित समय मे उसको भी तैयार कर दिया जायगा ।

चौधरी बलबीर सिंह : मंत्री जी बतायेंगे कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टीशनर्स हैं उनके लिये कोई रिफ्रेशर्स कोर्स, 1, 2 महीने का दिलायेंगे, कोई सेमीनार वगैरह बुलाया जाय ताकि उनको म.प कुछ और ट्रेनिंग दे सकें ताकि देहातों में जो काम कर रहे है उनको कुछ और ज्यादा वाकफियत हो सके और वह ठीक ढंग से लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल कर सकें ?

MR. SPEAKER : They will be useful in reducing the population.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : वर्ष 1976-77 के दौरान सामान्य चिकित्सकों के विषय परिचायक पाठ्यक्रमों का आयोजन करने के लिये राज्य सरकारों आदि को केन्द्रीय सहायता हेतु एक योजना शामिल करने का विचार था। यह मेडिकल कालेजों के डीनों और प्रिंसिपलों के अप्रैल 1976 में हुए सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुसार था। लेकिन इसका राज्य सरकारों ने स्वागत नहीं किया। फिर भी विचार कर रहे है कि किस प्रकार उनको अधिकतम ज्ञान इस चिकित्सा स्वास्थ्य में दिया जा सके।

श्री कचरूलाल हेमराज जैन : अध्यक्ष जी, यह सवाल इतना साफ है और मंत्री जी ने भी जितना वक्तव्य दिया है जरा देख लीजिये। इसमें साफ लिखा है कि क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने डाक्टरों, विशेषज्ञों, नर्सों और सहायक कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिये एक संतुलित नीति बनाई है जिससे वे सब मिल कर एक टीम के रूप में कार्य कर सकें, और इस संबंध में मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? तो सीधी बात है कि संतुलित नीति तैयार की है कि नहीं ? और यदि नहीं, तो कब तक तैयार कर लेंगे जिससे तीनों बातें साथ जोड़ी जायें ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैंने जो अभी मूल प्रश्न के उत्तर में पढ़ा वह भी एक संतुलित नीति ही थी जिसका विशद् विचार हमने रखा है, और माननीय सदस्य ने सुना भी है। मैं समझता हूं कि वह काफी है, और अगर श्रीमन्, चाहें तो और लम्बा जवाब दे सकता हूं।

E.S.I. Scheme for Rural Workers

*889. SHRI K. RAMAMURTHY: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether Government have completed the examination of the possibility of extending the Emplyees' State Insurance Scheme to rural workers as mentioned in replies to Starred question No. 520 on the 22nd December, 1977 and Unstarred question No. 4945 on the 30th March, 1978 ; and

(b) if so, the action proposed to be taken in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (Dr. RAM KIRPAL SINHA) : (a) and (b). The matter is still under consideration.

SHRI K. RAMAMURTHY : This question relates to the coverage of rural people under the Employees State Insurance scheme. This year the agricultural workers contributed to the nation a record production of 125 million tonnes of foodgrains. They also form the bulk of the rural community. In view of all that, will the Government consider giving them some incentive like social security schemes by extending the ESI scheme to the rural masses ?

DR. RAM KIRPAL SINHA : We are very much thankful to the rural workers that because of their labour this much of production has been achieved. So far the social security scheme prevailing in the country has been urban-oriented and oriented in the interest of the organised labour. We are now seriously thinking of devising some plan for the rural workers also, but no clear-cut programme has yet taken shape.

SHRI K. RAMAMURTHY : This Government talk all the time of rural development and 40 per cent of their allo-

cations have been given for the development of agriculture and rural areas. The Government say that the matter is still under consideration, which is nothing but showing lip sympathy towards the rural people. I would like to know whether the Government will categorically assure this House that they will constitute a committee to go into the matter and will have a time-bound programme to implement the recommendations of that Committee.

MR. SPEAKER : He said he is evolving a scheme.

DR. RAM KIRPAL SINHA : The hon. Member says that we are paying only lip service. That is not a fact. We are feeling it from the very core of our heart that something tangible should be done for the rural workers. As far as the question of constituting a committee is concerned, at the Ministry level we are thinking of devising some plans. Only then some action can be taken.

SHRI PURNANARAYAN SINHA: May I know whether the ESI scheme will be extended to plantation workers who are in the rural areas ? Where the quantum of medical assistance given by the ESI is more than the medical assistance given by the plantation owners, will extension be considered ?

MR. SPEAKER : I think that is outside this question

SHRI VAYALAR RAVI : I am sure the Minister is aware of the fact that the rural workers are very much in need of ESI scheme, but it is not provided to them. On the other hand, it is imposed on organised labour, which is already enjoying the medical benefits under bilateral agreements. This is the malady. In this background, will you review the whole enactment and bring a comprehensive scheme before this House as early as possible ?

DR. RAM KIRPAL SINHA : So far as the allegation of its imposition is concerned, I deny it.

SHRI VAYALAR RAVI : How can you deny it ? It is a fact. I objected to its imposition on the workers and I sent a letter to the Minister. Let Shri Varma say whether it is not a fact.

DR. RAM KIRPAL SINHA : As far as medical benefits are concerned, it is only after the recommendation of the State Government that we take it to a particular area. So, imposition by the Central Government does not come into the picture.

The hon. Member mentioned about improving the working of the ESI. Yes, we are considering reviewing the functioning of the ESI scheme.

श्री रामदेनी राम : माननीय मन्त्री जी ने नेशन के लिये मजदूरो ने जो उपलब्धियां हासिल कराई है—उसके लिये धन्यवाद दिया है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हू—एग्रीकल्चर लेबर के लिये आप क्या करने जा रहे है, उनके लिये आपके पास क्या योजनाये है—ताकि वे भी आपको अपना धन्यवाद दे सके ?

डा० राम कृपाल सिंह : एग्रीकल्चर लेबर के लिये भी हमारे पास बहुत सी योजनाये है। यदि, अध्यक्ष महोदय, हुक्म दे तो मै डिटेल्स मे बतला सकता हू कि हम क्या-क्या करने जा रहे है।

SHRI DINEN BHATTACHARYYA : ESI is a contributory scheme, and those who are covered have to make a contribution to it, and even after payment of the contribution they are not getting the facilities in any respect, medical or any other benefit. They are abusing it. So, while extending it to the rural people, are you going to make it non-contributory for the rural population ?

DR. RAM KIRPAL SINHA : Only when the scheme takes concrete shape can it be said whether it willl be contributory or not.

About the present condition, that they do not get medical benefits and they are abusing etc. I believe that the workers do not abuse it, and it is only an allegation that they abuse the medical benefits.

As far as paucity of medicines and other things hinted at by him are concerned, I can assure him that we are revising the pharmacopoeia also, and we are trying to bring better benefits to them.

Survey by G.S.I. in H. P. for Minerals

*891. SHRI BALAK RAM : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to refer to the reply given to the Unstarred question No. 743 on the 17th November, 1977 and state :

(a) whether the Geological Survey of India carried out surveys for various minerals like limestone, gypsum,

rock salt, antimony ore and quartzite etc. etc. in various Districts of Himachal Pradesh during the field season 1977-78;

(b) if so, the details thereof and the estimate of mineral wealth in the State; and

(c) the steps taken or proposed to be taken to explore and exploit such places having rich mineral wealth?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c). Geological Survey is a continuous process. The programme of Geological Survey of India for the current field season (starting from October, 77) include investigations for cement grade lime stone in Simla district; clay in Mandi district; slate in Kulu, Kangra and Mandi districts and antimony-lead-zinc around Bara-Shigri glacier in Lahaul-Spiti district.

As a result of investigations carried out so far, reserves of important minerals estimated in different parts of Himachal Pradesh include about 900 million tonnes of limestone; 1·3 million tonnes of gypsum; 12000 tonnes of barytes and about 3000 tonnes of antimony ore.

The Cement Corporation of India are setting up a cement plant at Rajban in Sirmur district with a capacity of 2 lakh tonnes. The Government of Himachal Pradesh is also considering possibilities of setting up more cement plants; a letter of intent has also been granted to Messrs. Associated Cement Company.

The gypsum deposits in certain areas are to be used for cement production (at Rajban), and the rock salt deposits in Mandi district are being exploited by M/s. Hindustan Salt Limited. Mining leases have been granted by the State Government for limestone, barytes, gypsum and Magnesite'..

श्री बालक राम : माननीय मंत्री जी ने मेरे सवाल के (ए) तथा (बी) के जवाब में बताया है कि इन धातुओं की खोज की जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि यह खोज कब की जाएगी और कब तक हकीकत में यह काम शुरू किया जाएगा? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इसके लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने इस साल और अगले साल के लिये कितना बजट रखा है?

SHRI BIJU PATNAIK: Answering the second part of the question, we do not keep separate budgets for the different parts of the country. It is a general budget, and wherever it is required to undertake a certain work, the necessary orders are given

As the hon. Member must have noticed from the statement, already 900 million tonnes of limestone have been located It is no use going on searching for more material when it will take 100 to 200 years to consume this. This is more than enough to start any industry

The Cement Corporation of India, as we have said in the statement, are setting up a cement plant at Rajbah in Sirmur District with a capacity of two lakh tonnes. The Himachal Pradesh Government is also considering possibilities of setting up certain factories. It is now for the State Government and other departments to make use of this for the setting up of factories

श्री बालक राम : अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा सवाल यह है कि सीमेंट कार्पोरेशन आफ इण्डिया राजबन, जो सिरमोर डिस्ट्रिक्ट मे है, मे कब तक सीमेंट का कारखाना खुलेगा और इसमे कितने लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा सेन्ट्रल गवर्नमेंट और किन किन धातुओं की खोज के लिए कोशिश कर रही है और हिमाचल प्रदेश की सरकार को इस के बारे में किस किस रूप में कितनी कितनी मदद देने की प्रोपोजल है?

SHRI BIJU PATNAIK: Certain informations that I have got I have already given to him like the Hindustan Salt Limited are exploiting rock salt; the Cement Corporation of India is building a cement factory and the State Governments are considering building up some factories. But if the hon. Member wants to know whether the Cement Corporation of India is going to expand the factory or what other things the State Governments are doing, the question may kindly be referred to the appropriate Ministry.

श्री भारत भूषण : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि कुमायूं में मेगनासाइट का खनन हो रहा है और इसके अलावा वहां पर लोहे के भंडार और चूने के भंडार हैं ....

MR SPEAKER : Kumaon is not in Himachal Pradesh. So, this question does not arise.

श्री भारत भूषण : सारे का सारा पहाड़ी क्षेत्र एक दूसरे से मिला हुआ है। इस सदन में केवल हिमाचल के लोग ही नहीं है बल्कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोग है। इसके अलावा हिमाचल और कुमायू मे दूरी कितनी है।

MR SPEAKER : This question does not arise. Next question.

श्री भारत भूषण : मै हिमाचल की बात पूछ रहा हूं।

MR SPEAKER : I have already, gone to the next question.

Companies Producing Aluminium Ingots

*893 SHRI SARAT KAR : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) the total number and names of companies producing aluminium ingots in the country together with their respective production ;

(b) the general procedure under which these companies supply aluminium to the consumers and whether Government are aware that a large number of persons and firms to whom supply has been allotted by Government are not getting the product from these companies; and

(c) if so, the reasons therefor and the steps taken thereon ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) :

(in tonnes)

(a) Name of the company	Production in 1977-78
1. Bharat Aluminium Company Ltd.	31,681
2. Indian Aluminium Company Ltd.	65,927
3. Hindustan Aluminium Corporation Ltd.	62,199
4. Madras Aluminium Company Ltd.	18,731
	178,538

(b) There is no control over distribution of aluminium, except that 50 per cent of total monthly production of an aluminium producer is to be supplied as 'levy metal' (electrical conductor grade) to cable and conductor manufacturing units only. Government does not make unitwise allocations for supply of aluminium by the producers.

(c) Does not arise.

SHRI SARAT KAR : May I know whether the production of these companies is upto the maximum target? If it is not surplus or maximum and is below the target, should not the Government consider to control distribution so that the small units are not deprived of the raw material ?

SHRI BIJU PATNAIK : The plants are not producing upto the full capacity due to shortage of electric power. That is why, Government has permitted import of nearly 30,000 tonnes of aluminium during the last year. As far as small units are concerned imported metal is allocated under the recommendation of the DGTD and the Small Scale Development Commissioner, Government has yet not seen sufficient reason to bring the metal under distribution control.

SHRI SARAT KAR : The small units were representing for the last one year about this inadequate supply for preparing utensils, but they were always deprived of such things. So, I would request for the personal intervention of the Minister. In view of this, whether there is any proposal to create new aluminium industries in our country so that there is no difficulty in future.

SHRI BIJU PATNAIK : Whereve: it comes to our notice that small units dealing with aluminium metal are suffering from lack of material, the Government intervenes and tries to see that it is supplied to them during the period of shortage. When the import comes and more import will be coming in the coming months, I do not think that the shortage will be felt. The Government is also considering putting up new aluminium plants, as I have already answered in this House during the last week. I am sure, the hon. Member will take note of that.

SHRI S. R. DAMANI : May I know from the hon. Minister whether it is a fact that the production during 1977-78 was much lower than the production achieved during 1976-77 and, if so, what

was the main reason for the fall in production and, secondly, whether production will be increased during the course of the year and, if so, what is the capacity that has been newly licensed and when production is likely to be commenced.

SHRI BIJU PATNAIK : I have already answered these questions last week. The total installed capacity towards the end of this year will be 3,16,000 tonnes. At the moment, it is less, that is, 2,66,000 tonnes. As regards production, during the last year, it was 1,78,000 tonnes, roughly about 70 per cent of the installed capacity. That is because of the shortage of power. Karnataka has cut power by 50 per cent They have raised the power rates; they have doubled the rates. The tariff is raised by hundred per cent almost. Not only the aluminium plants but also the mini-steel plants will close down. The Kudremukh steel plant will suffer a loss of about Rs. 1 crore. There is no question of putting up new steel plants at the moment.

श्री भानु कुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर मे बताया है कि शार्टेज आफ पावर के कारण उत्पादन कम हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि कितने प्रतिशत पावर की कमी थी और कितने प्रतिशत उत्पादन कम हुआ ? इन दोनों मे कोई ताल मेल है या नही ? कई राज्यो में शार्टेज आफ पावर है, इंडस्ट्रीज को पावर नही दी जाती है लेकिन फिर भी वे पावर कंज्यूम करते है। एल्युमिनियम कम्पनी मे पावर का कितना प्रयोग किया जा रहा है, वास्तव में यह कितना प्रतिशत कम हुआ है और इसके लिहाज से उत्पादन कितना प्रतिशत कम हुआ है ?

SHRI BIJU PATNAIK : There is power shortage in U.P., Madhya Pradesh and Karnataka. He wants an arithmetical answer. The loss of production is directly proportionate to the lack of supply of power.

श्री भानु कुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय.....

MR. SPEAKER : He will require a separate notice for that; he cannot answer that. That is not a question directly arising out of this.

श्री भानु कुमार शास्त्री : क्या यह नहीं है कि यदि पावर में 20 प्रतिशत की कमी है तो उत्पादन में 80 प्रतिशत की कमी है ?

SHRI BIJU PATNAIK : As I have already said—I am sure, the hon. Member understands it—the loss of production is directly proportionate to the lack of supply of power.

Meeting of W.H.O. to fight serious Diseases

*894. SHRI YASHWANT BOROLE : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether a body of W.H.O. held its meetings recently in the Capital to consider ways to fight serious diseases; and

(b) if so, the practical steps evolved after discussion to meet the challange in this part of the world ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां। विश्व स्वास्थ्य संगठन को आयुर्विज्ञान अनुसंधान संबंधी क्षेत्रीय सलाहकार समिति का चौथा अधिवेशन 3 से 6 अप्रैल, 1978 के बीच नई दिल्ली मे सम्पन्न हुआ था :

(ख) अधिवेशन की विस्तृत रिपोर्ट भारत सरकार को अभी तक प्राप्त नही हुई है।

SHRI YASHWANT BOROLE : May I know from the Minister what are the important diseases that have figured in the discussion of these Regional Advisory Committees of the World Health Organisation, so far as India is concerned ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : जिन विषयो पर विचार किया गया व इस प्रकार हैं :

जिगर के चिरकालिक रोग जिनमें जिगर का कैंसर भी शामिल है।

डेगू रक्तस्रावी ज्वर, कुष्ठ रोग, मलेरिया, बच्चों में प्रवाहिका रोग। स्वास्थ्य सेवा अनुसन्धान, स्वास्थ्य सुविधायें सुलभ कराने की वैकल्पिक पद्धतियां।

समिति ने निम्नलिखित मामलों पर भी विस्तार से चर्चा की :

परम्परागत औषधियां।

ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्यकर वातावरण के सुधार के लिए समुचित टेक्नालाजी के विकास में अनुसंधान।

चिकित्सीय प्रयोग का नीतिशास्त्र जिसमें मानव विषय शामिल हैं।

ऊष्णकटिबंधी रोगों में अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम।

समन्वित, व्यापक क्षेत्रीय अनुसंधान कार्यक्रम का विकास।

SHRI YASHWANT BOROLE : He has not mentioned the diseases I want to know the serious diseases.

MR SPEAKER : There are serious diseases. What is your second supplementary ?

SHRI YASHWANT BOROLE : What is the extent of financial help, expertise as well as medicine that will flow on the basis of this discussion ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : विस्तार से तो उसका जो कार्यक्रम है वह हमारे पास पहुंचा नहीं है। इन्होंने लिस्ट मांगी थी, हमारे पास थी और मेंने दे दी है। पूरी सूचना जब आएगी तभी विचार कर के में बता सकूंगा।

श्री हुकम देव नारायण यादव : दुनिया में सबसे ज्यादा अंधे, टी बी के बीमार, कोढ़ी आदि भारत में हैं। इस तरह के रोगों का प्रसार भी अधिक हो रहा है। इधर बड़े लोगों में मधुमेह भी बढ़ रहा है। यह रोग भी उनको लग रहा है। इन सब रोगों की रोकथाम के लिए और खास कर अंधेपन और कोढ़ीपन के लिए जिनसे गांवों के गरीब ही सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्या सुझाव हैं और उनके साथ-साथ भारत सरकार इन रोगों को रोकने के लिए अपने देश में व्यापक स्तर पर कोई कार्रवाई करना चाहती है और कोई योजना इनके पास है या नहीं है ?

MR. SPEAKER : It does not arise.

श्री बी० पी० मण्डल : हमारे देश में मलेरिया और कालाजार एपेंडमिक रूप में फैला हुआ है। इसके सम्बन्ध में डब्लू० एच० ओ० से बात हुई है और क्या कोई आश्वासन उनसे मिला है ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : डब्लू० एच० ओ० से बात का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि आयुर्विज्ञान अनुसन्धान का यह क्षेत्रीय विश्व सम्मेलन हुआ था और उसमें किन-किन विषयों पर विचार किया गया और सिफारिशें हुईं। जो एजेंडा था वह मैंने रख दिया है। बाकी चीजों के बारे में उनकी पूरी रिपोर्ट हमारे पास आ जाए तभी मैं विचार करके बता सकता हूं।

Chinese delegation vist to Netaji Museum.

*895. SHRI SAMAR GUHA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is fact that the Chinese delegation which recently had visited India had gone to see Netaji Museum at Calcutta, Netaji Bhavan;

(b) whether they have shown keen interest in seeing the pictures and the personal effects of Netaji there;

(c) if so, the facts thereabout; and

(d) the facts about the observations made by them in paying respect to Netaji Subhash Chandra Bose ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU): (a) Yes, Sir. Some members of the delegation of the Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries, which visited India in March, 1978 visited the Netaji Museum, Netaji Bhavan, Calcutta, on March 22, 1978.

(b) to (d). According to the reports available with Government the members of the Chinese delegation were shown round the Museum by the officials of the Bhavan. The members of the Chinese delegation visiting the Museum thanked the Bureau for the reception accorded to them. Government are not aware of any observation having been made by the Chinese delegation regarding Netaji Subhash Chandra Bose.

SHRI SAMAR GUHA: The hon. Minister has missed the report that appeared in almost all the Calcutta papers where the Chinese paid tribute to Netaji by calling him a great leader of the Indian liberation; it come out in all papers in Calcutta. But that is not the question. The question is not so simple. I want to draw your attention to the fact that it is reported that, for some time, after reaching Russia, Netaji was free. It was also reported by the Communist Party leader, Mr. Gallacher, that Netaji visited Ireland in 1946 o meet Mr. De Balera. That was also reported by Mr. Gallacher in British Parliament. Again, the publisher of Netaji's book 'The Indian Struggle', Mr. Pulin Seal, made a public statement in London that Netaji was found in Mangolia as a Buddhist monk. There are several pictures that have appeared, group photos along with Chinese. There are three pictures here, and about these pictures, my hon. friend, Mr. Kamath......

MR. SPEAKER: Let us be relevant to the question.

SHRI SAMAR GUHA: This is very relevant, Sir. When these questions were raised by Mr. Kamath and when these photos were shown, Pandit Jawaharlal Nehru himself admitted on the floor of the House—this is on record—that these photos bore a resemblance to the picture of Netaji Subhash Chandra Bose. I would like to know from the hon. Minister whether, in view of our improved relations with the Government of China, Government will have these photos verified. It seems that some time in 1950 or 1951, Netaji visited China along with a Delegation which was called Mangolian Delegation. As I said, it has relation to the statement made by Mr. Pulin Seal. There are other pictures also. May I know whether the Government will make an enquiry from the Government of China whether these pictures bearing resemblance to Netaji can be properly identified and whether they have any information about him.

SHRI SAMARENDRA KUNDU: As you will appreciate, Sir, Samar Babu has raised a very important question. On this point he always raises very important questions, and he has given valuable information to this House. But, I think, he will bear with me, if I say that, so far as this question is concerned, it is, whether any reference, any observation, was made about Netaji by the visiting Chinese Delegation to the Museum......

SHRI SAMAR GUHA: Do not be technical.

MR. SPEAKER: His question is whether you will take up the matter with the Government of China......

SHRI SAMARENDRA KUNDU: If he writes to us......

MR. SPEAKER: Say that you will consider.

SHRI SAMARENDRA KUNDU: Yes; we will consider.

SHRI SAMAR GUHA: My second question is this. About four months before, Shri Sarat Chandra Bose made a public statement about verification of this. Four months before his death, Shri Sarat Chandra Bose, the elder brother of Netaji Subhash Chandra Bose, made a public statement where he had categorically stated that he had information that Government of India possessed information that, in 1949, Netaji visited China from Russia? Will the Government enquire about that also?

MR. SPEAKER: You will consider that also.

SHRI SAMARENDRA KUNDU: If he writes to us, we will consider.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

National machineries to protect human rights

*887. PROF. P. G. MAVALANKAR: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 5818 on the 6th April, 1978 and state:

(a) whether national machineries have been set up to protect human rights and fundamental freedoms of individuals in response to the unanimous decision of the Commission on Human Rights taken on the initiative of the Government of India; and

(b) if so, the broad details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU): (a) and (b) The Commission of Human Rights has only recently concluded its deliberations, during which time it unanimously adopted, at the initiative of the Govern-

ment of India, a decision urging Governments to establish national machineries to protect human rights and fundamental freedoms of individuals This decision has to be endorsed by the Economic and Social Council of the United Nations as well as by the forthcoming General Assembly of the United Nations It is only after this process is complete that the recommendations are formally made to Governments In the mean while Government is studying in consultation with the administrative Departments concerned the implementation of the recommendation

डिपथीरिया निवारक सीरम के मूल्य में वृद्धि

*888. डा० महावीपक सिंह शाक्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि डिपथीरिया निवारक सीरम के मूल्य मे अत्यधिक वृद्धि होने के कारण बहुत से बच्चे इलाज न हो सकने से मर जाते है और

(ख) यदि हां, तो जनसाधारण के लिए नि शुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) डिपथीरिया एन्टीन्टाक्सिन (बल्क) की कीमत 19-4-1974 की घोषणा के बाद संशोधित नही की गई है । डिपथीरिया एन्टीन्टाक्सिन से बनी दवाइयो की कीमतें भी साधारणतया 1970 से संशोधित नही की गई है भले ही केन्द्रीय अनुसधान संस्थान कसौली ने 1-2-1977 से छोटे एम्पूलो की कीमत आंशिक रूप से बढा दी है । इसलिए, डिपथीरिया-रोधी सीरम की कीमतो में अत्यधिक वृद्धि के कारण उपचार के अभाव में बहुत से बच्चो के मरने का प्रश्न नही उठता है ।

(ख) साधारण जनता के लिए डिपथीरिया का इलाज संक्रामक रोग अस्पतालो में नि शुल्क किया जाता है ।

भिलाई इस्पात संयंत्र के उत्पादों की बिक्री

*890 श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या इस्पात और खान मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि —

(क) भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा निर्मित ऐसी वस्तुओं का ब्यौरा क्या है जिनको व्यापारी समय-समय पर वहा से खरीदते है

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों में वस्तुओं की सप्लाई हेतु क्रयादेश प्राप्त हुए है परन्तु उनका वस्तुत अब तक सप्लाई नही किया गया है ,

(ग) क्या उन व्यापारियो ने इनमें से कुछ मामलो को मध्यस्थ निर्णय के लिए सौपा है और न्यायालयो मे दायर किया है जिनको राशि जमा करने के बाद भी उनके क्रयादेशो पर वस्तुओं की सप्लाई नही की गई है और

(घ) यदि हां तो इस समय ऐसे मामलो की संख्या क्या है और भिलाई इस्पात संयंत्र ने इन मामलों पर कितना धन व्यय किया है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) भिलाई इस्पात कारखाने द्वारा उत्पादित निम्नलिखित मदे व्यापारियो द्वारा सीधे कारखाने से खरीदी जाती है

1 औद्योगिक स्क्रैप , और

2 नट पल बीज और मिश्रित कोक ।

(ख) उपरोक्त मदो के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) और (घ) कोई भी मामला मध्यस्थ निर्णय के लिए नही भेजा गया है । मिश्रित कोक की सप्लाई से संबंधित एक मामला न्यायालय में अनिर्णित पड़ा है ।

कारखाने द्वारा इस मामले पर खर्च की गई कुल धन राशि के बारे में तभी मालूम होगा जब इस मामले का निपटान हो जायेगा।

बिहार में स्वचालित टेलीफोन लगाना

*891. श्री ईश्वर चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के उन जिलों का ब्यौरा क्या है जिनमें स्वचालित टेलीफोन अभी भी लगाये जाने है ,

(ख) क्या सरकार का विचार गया मे जो कि विश्व भर के बौद्धों का तीर्थ-स्थल है सीधे टेलीफोन घुमाने की प्रणाली लागू करने का है , और

(ग) यदि हां, तो ऐसी प्रणाली 1978-79 में जिन जिलो में लागू की जान है उनका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय :(क) अपेक्षित ब्यौरे सलग्न विवरण में दिए गए है ।

(ख) जी हा । फिर भी, टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त भूखड उपलब्ध न होने के कारण यह प्रस्ताव रुका हुआ है ।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार के किसी भी जिला मुख्यालय में आटोमेटिक एक्सचेज चालू करना सभव न होगा ।

विवरण

अनुबंध

बिहार के जिन जिला मुख्यालयों मे अभी आटोमेटिक एक्सचेज स्थापित किए जाने है, उनके ब्यौरे प्रदर्शित करने वाला विवरण पत्र

क्रम सं०	एक्सचेज का नाम	क्षमता	चालू कनेक्शन	प्रतीक्षा सूची
1	2	3	4	5
1.	औरंगाबाद	100	71	—
2.	बिहार शरीफ	360	329	—
3.	बेगूसराय	480	327	—
4.	बेंतिया	360	311	—
5.	भागलपुर	1440	1431	33
6.	दुमका	240	201	1
7.	गया	1680	1511	—
8.	गिरीडीह	480	430	3
9.	गोपलगंज	100	79	—
10.	हाजीपुर	200	172	—

1	2	3	4	5
11.	मधुबनी	200	125	—
12.	नवादा	100	94	—
13.	पूर्णिया	300	289	—
14.	सहरसा	300	294	—
15.	सीतामढ़ी	480	325	—
16.	सिवान	290	255	—

टिप्पणी :—इन एक्सचेंजों को आटोमेटिक बनाने का कार्यक्रम छठी योजना में रखा गया है । आशा है कि इनमे से चार एक्सचेंज अर्थात् बेतिया, सहरसा, सीतामढ़ी और सिवान वर्ष 1979–80 के दौरान चालू हो जाएंगे ।

Change in industrial and vocational training system to tackle unemployment problem.

*393. SHRI SURENDRA BIKRAM: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) what concrete steps Government have so far taken to make necessary changes in industrial and vocational training system to tackle effectively the problem of massive unemployment in a definite period;

(b) whether it is also proposed to change the employment information and placement system; and

(c) whether new employment exchanges would be set up in areas not covered so far and if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) 1. Institutional training in 53 trades is at present being imparted in 356 Industrial Training Institutes with a total seating capacity of 1,55,225. This training is intended to meet the basic skills required in industry.

2. Training is also imparted under the Apprenticeship Act, 1961 in 103 trades. There are 1,50,974 apprentices undergoing such training.

3. There are two tripartite bodies—the National Council for Training in Vocational Trades which reviews the schemes of training in Industrial Training Institutes and the Central Apprenticeship Council, the schemes of apprentice training. Changes in programmes and content of training are made in accordance with the recommendations of these Councils.

4. Some of the State Governments have started courses of short duration in a few selected Industrial Training Institutes with a view to promoting self-employmen and employment in specialised areas like Auto-Electrician, Scooter Repairer, Typewriter Mechanics, Sewing Machine Mechanics, Tractor and Motor Vehicle Mechanics etc. The I.T.I. passed candidates are given specialised training in these areas to improve their employability and self-confidence in setting up their own workshops.

5. Government are conscious of the need for further changes in industrial and vocational training and for that purpose they have appointed a high-powered Committee of Experts to recommend ways and means of improving the quality of training of I.T.I. trainees and the apprentices, with particular reference to the need for reorientation of both Apprenticeship Training and Industrial Training Programmes to subserve the needs of the rural areas of the country and for upgrading of skills among persons coming from such areas. The Committee would keep in view the special need for training of women and physically handicapped persons.

(b) The Government have recently set up a Committee on National Employment Service to advise and recommend suitable measures to improve its working, particularly with a view to (i) making it more responsive to the changed circumstances and needs, (ii) increasing placement of those registered with employment exchanges, (iii) recommeding special steps in the matter of placement services for the disadvantaged and handicapped sections and (iv) involving the Employment Service for dealing with the rural labour employment problem arising out of the changed planning strategies of the Government in giving primacy to the rural employment problem.

(c) The Employment Exchanges are directly under the administrative and financial control of the State Governments. It is for the respective State Governments to consider the question of opening of new employment exchanges in areas which are not covered so far.

Protest to Zambia

*897. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether India protested to Zambia against allegation made by the Zambian Prime Minister that Government was pursuing a policy of vindictiveness against the former Prime Minister; and

(b) if so, the reaction of the Zambian Government to that protest?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU): (a) and (b) Yes, Sir. It was pointed out through diplomatic channels that the letter sent by the Zambian Prime Minister to "London Times" on the subject was objectionable and amounted to lack of understanding of our constitutional system. Both the President and Prime Minister have expressed their regrets in this connection. The regrets of President Kaunda were conveyed to our Prime Minister by the Zambian High Commissioner.

Family Planning Programmes

*898. SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there was a considerable fall in the performance of the various family planning programmes during the last one year;

(b) if so, the facts thereof and reasons therefor;

(c) whether Government are taking any fresh steps to popularise these programmes; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) There was a fall in the performance of the Family Welfare Programme during the year 1977-78 except in the case of Oral Pills Programmes and Maternal and Child Health Programme as compared to the preceding year. The performance of the Family Welfare Programme during the year 1977-78 (April 1977—February, 1978) as compared to the corresponding period of the preceding year (April, 1976—February, 1977) is indicated in Statements I and II attached.

(b) Widespread complaints of compulsion and coercion in the implementation of the Family Welfare Programme particularly with regard to sterlisation in some States during the year 1976-77, have led to a serious set-back to the Family Welfare Programme.

(c) and (d). Educational and motivational efforts have been strengthened in order to make the small family norm popular among the people. Services and facilities for all methods of contraception, including male and female sterlisation, have been made extensively available. Particular attention has been given to the improvement and strengthening of maternal and child health services. A massive programme for training of village birth attendants (dais) has been undertaken and the newly launched community health worker scheme is also likely to help in spreading the awareness and acceptance of small family norm, particularly in the rural areas. Special orientation camps for village opinion leaders are also being held in various Primary Health Centres.

Statement—I

Performance of the Family Welfare Programme during the year 1977-78 (*April*, 1977—*February*, 1978) *is given below*

(Figures provisional)

Methods	Performance		Percentage increase (+) or decrease (—) in 1977-78 (April, 1977 to February, 1978) over the corresponding period of last year
	1977-78 (April '77 to Feb '78)	1976-77 Corresponding period	
1 Voluntary Sterlisations*	785,748	8,097,833	(—) 90·2
2 I.U.D. Insertions	262,175	532,312	(—) 50·7
3 Equivalent Conventional Contraceptive users	2,731,645	3,499,719	(—) 21·9
4 Equivalent Oral Pill Users	71,062	53,848	(—) 27·8
5 Medical Termination of Pregnancies	184,491	235,491	(—) 21·7

*The term voluntary applies specifically to performance since April, 1977

Statement—II

The performance under Maternal and Child Health Programme for the Period April, 1977—*February*, 1978 *was as under*

(Figures Provisional)

Immunisation	Achievements		Percentage Increase (+) or Decrease(—)
	1977-78 (April, 77 February 1978	1976-77 (Corresponding period)	
(a) (i) Tetanus immunication for expectant and nursing mothers	2,601,354	1,547,046	(+) 67·00
(ii) D.P.T Immunication for pre-school children	5,780,413	2,950,563	(+) 94·2
(iii) D.T. immunication for school children	4,875,341	1,745,063	(+) 175·9
(b) Prophylaxis against nutritional anaemia			
Total women	5,859,616	3,396,888	(+) 70·6
Children	5,267,959	2,384,600	(+) 119·1
(c) Prophylaxis against blindness due to Vitamin 'A' deficiency			
Total (1st & 2nd dose)	10,045,939	5,051,076	(+) 97·7

कर्नाटक में लघु इस्पात संयंत्र

*899. श्री राम सेवक हजारी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में लघु इस्पात संयंत्र बन्द होने वाले हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि ये संयंत्र चलते रहें और उनको कम दरों पर विद्युत उलिब्ध की जाती रहे ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) से (ग) । यह सच है कि कर्नाटक में विद्युत की दर में लगभग 100 प्रतिशत की अत्यधिक वृद्धि हो जाने तथा बिजली की अत्यधिक कमी होने के कारण लघु इस्पात संयंत्रों को बड़ी कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है । मैंने स्थिति की गंभीरता के बारे में कर्नाटक के मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है । उनके उत्तर की प्रतीक्षा है :

Fear of being laid off by Iron Ore workers.

*900. SHRI PRADYUMNA BAL: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that about one lakh workers engaged in the mining of iron ore are in the process of being laid off following about 20 per cent outback in the off take by foreign buyers as he said in Burnpur on the 27th February, 1978;

(b) the number of workers laid off so far;

(c) the particular reasons for slump in the world steel market; and

(d) the reaction of Government towards the whole situation ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) and (b) Due to cut back in imports of iron ore by Japan and other countries on account of extreme recession in the world steel industry, some lay-off of iron ore workers is apprehended. The precise number of workers who may have to be laid-off will depend, inter alia, upon the actual shipments to Japan and other countries.

(c) The recession in the world steel industry is a global phenomenon reportedly caused by a number of complex factors such as slowing down of economic and industrial growth rates, sluggish demand for steel, high rates of inflation due to abnormal rise in world oil prices reduced profit levels and lack of confidence about prospects of recovery etc.

(d) Government are taking all possible measures to minimise the extent of retrenchment on account of the recession in the world steel industry affecting our iron ore exports.

कारखानों में श्रमिकों का नियमित किया जाना

*901. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे;

(क) देश में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों में काम कर रहे श्रमिकों की पृथक पृथक संख्या का राज्य-वार, ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से कितने श्रमिक दैनिक मजूरी पर काम कर रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन्हें नियमित करने का है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) 1974 से 1977 तक की अवधि के लिए सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों के कारखानों में श्रमिक की, राज्य-वार, संख्या से सम्बन्धित अन्तिम आंकड़े दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । (ग्रंथालय में रखा गया । देखिये [एल टी 2207/78]

(ख) और (ग) अनुमानतः नैमित्तिक श्रमिकों के बारे में उल्लेख किया गया है जो सामान्यतः दैनिक मजदूरी पर नियोजित किए जाते है । सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों में उनकी संख्या के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नही है । जहां तक भारत सरकार के विभागीय उपक्रमों का सम्बन्ध है, माडल स्थायी आदेशों में निर्दिष्ट मार्ग-दर्शी सिद्धान्त, जो नियोजित मंत्रालयों को परिचालित किए गए थे, में किसी नैमित्तिक श्रमिक को नियमित किए जाने की व्यवस्था है, जिसने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 (ख) (2) (अ) की परिभाषा के अन्तर्गत छः महीने की लगातार सेवा पूरी कर ली हो । हालांकि सरकार की नीति सामान्यतः नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने को बढ़ावा देना है, तो भी प्रत्येक उद्योग या यूनिट मे वास्तविक स्थिति प्रत्येक मामले की विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करेगी ।

Number of doctors and engineers abroad

*902. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of doctors and engineers who have gone to Algeria, Arab and Gulf countries during the period from April, 1977 to March, 1978;

(b) the number of applications from doctors which are at present pending disposal;

(c) when th- pending applications are likely to be disposed off; and

(d) salaries and other facilities they are getting in these countries?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU): (a) During the period April, 1977 to March, 1978, 910 doctors and 288 engineers were selected for assignment abroad on government-to-government deputation in Algeria, other Arab and Gulf countries. The names of these doctors and engineers were sponsored by Department of Personnel & Administrative Reforms, Ministry of Home Affairs. It is not possible to furnish exact number of doctors and engineers who actually left during this period for these countries to take up their assignments.

(b) Th- total number of doctors (on 31-3-78) belonging to various disciplines registered on the panels maintained by the Department of Personnel & Administrative Reforms, was 11,006.

(c) It is not possible to indicate the time by which these pending applications are likely to be disposed off because names of these doctors are sponsored for assignments abroad in order of their date of registration on the panels, and, as and when demands suited to their experience and qualifications are received from the foreign Governments/Agencies.

(d) Pay scale and other emoluments offered to Indian experts working in these countries vary from country to country and even within the same country from organisation to organisaion Furthermore, these emoluments directly depend upon the qualification and experience of the experts concerned. However, in all the cases of bilateral recruitment it is ensured that the terms and conditions offered to the Indian experts are adequate and reasonable.

डाक-तार कर्मचारियों के लिए औषधालय

*903. श्री गंगाभक्त सिंह : क्या संचार मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ;

(क) क्या डाक तार विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये औषधालय की सुविधा की व्यवस्था की जाती है;

(ख) यदि हां, तो विभाग द्वारा देश के किन किन नगरों में उक्त सुविधा दी जा रही है; और

(ग) उत्तर प्रदेश के किन-किन नगरों में उक्त सुविधा उपलब्ध है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) जी हां, कुछ स्थानों में ।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में दो सूचियां सभा-पटल पर रखी जाती हैं। [ग्रन्थालय में रखी गई देखिये संख्या एल०टी० 2208/75]

Junior and Senior resident doctors in Safdarjung Hospital.

8320. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the junior and sernior resident doctors in the Safdarjung Hospital are exclusively taken from the students of Delhi University Medical College;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Kartar Singh Committee appointed by Government had recommended in 1974 that the selection to the first year and the second year junior residents should be made on merit by a duly constituted selection committee and that the junior residents should be taken on contract services;

(d) if so, what are the reasons for which the first year junior residents have been taken not on merit but from the Delhi University Medical College;

(e) the number of junior residents in Safdarjung Hospital who were taken from the Delhi University Medical College during the last 4 years, year-wise; and

(f) what steps Government are taking to stop such recruitment and to select candidates on merit as recommended by the Kartar Singh Committee?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) In so far as I year Junior Residents are concerned, preference is given first to the students of University College of Medical Sciences in the matter of appointment to I year junior residency at the Safdarjung Hospital which is attached to the College for clinical training of its interns. In case any vacancies are left out, the same are filled from amongst the eligible interns belonging to other institution. Admission to II & III year junior residency is made by the University of Delhi. Appointment to senior residency is made on all-India basis.

(b) The reasons for giving preference to the interns passing out their M.B.B.S. examinations from the University College of Medical Sciences in the matter of appointment to I year junior residency at the Safdarjung Hsopital is that it is the practice in other institutions that the students of the College are admitted in the same Hospital to which the College is attached. Since the Safdarjung Hospital is attached to the University College of Medical Sciences for the clinical training of students of the College, giving preference to such students in the matter of appaintment to I Year Junior Residency in the same Hospital is justified.

(c) Yes. Selection to the II year junior residency is, however, to be made by the University and not by the duly constituted selection committee as in the case of the I Year junior residents.

(d) Since the other medical institutions in Delhi give preference to their own interns in the matter of appointment to I year residency in the Hospitals attached to the respective institutions, it was felt that it could be prejudicial to the interests of the students belonging to the University College of Medical Sciences, if the facilities available with the Safdarjung Hospital for undergoing I year junior residency are not provided to the students of the University College of Medical Sciences.

(e) The number of students taken as I Year Residents at the Safdarjung Hsospital was 72 in 1977 and 96 upto the end of March 1978. The first batch of M.B.B.S. students from the Delhi University College of Medical Science was available only in 1977.

(f) In view of the reply given to part (d), it is not proposed to effect any change in the policy of recruitment to first year junior residency at the Safdarjung Hospital.

Relief to Cyclone victims in Kerala

8321. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the details of the medical assistance provided by the Government for the relief of the cyclone victims in Kerala, Tamil Nadu and Andhra Pradesh;

(b) whether the foreign countries have also extenced their cooperation to help the victims; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) The Central Government have provided the following medical assistance for the relief of cyclone

victims on crash priority basis in Kerala, Tamil Nadu and Andhra Pradesh States:—

Kerala:

(*i*) Free medicines worth Rs. 25,000 under Cholera Control Programme.

(*ii*) Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd., under Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizers have donated essential medicines worth Rs. 40,000 to the State.

(*iii*) Advance Plan Assistance worth Rs. 4·00 lakhs have been sanctioned by the Government of India against emergency health and medical care.

Tamil Nadu:

(*i*) Essential medicines, disinfectants, insecticides and medical equipment valuing Rs. 5,41,000 and vaccines valuing Rs. 51,875 have been supplied on payment basis.

(*ii*) Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd., have donated essential medicines worth Rs. 2,50,000 to the State.

(*iii*) Advance Plan Assistance worth Rs. 25·00 lakhs has been sanctioned by the Government of India against emergency health and medical care.

Andhra Pradesh:

(*i*) Essential medicine disinfectants, insecticides and medical equipment valuing Rs. 42,10,285·32 and vaccines valuing Rs. 88,375 have been supplied on payment basis.

(*ii*) Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd., have donated essential medicines worth Rs. 2,60,000 to the State.

(*iii*) Advance Plan Assistance worth Rs. 1 crore has been sanctioned by the Government of India against 'Emergency Health and Medical Care'.

(*iv*) A jet vaccination team from National Institute of Communicable Diseases, Delhi had been sent for the mass immunisation of the affected population.

Apart from the above the Ministry of Finance have also issued orders for the distribution of 792 gross of confiscated injection needles worth Rs. 87,840 to the State/Union Territory of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala & Lakshadweep in the proportion of 5:3:1:1.

(b) and (c) Yes. The Government of United Kingdom gifted essential medicines worth £18,000 which have subsequently been distributed to the Governments of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala and Lakshadweep in the proportion of 5:3:1:1 considering the severity of the disaster and population affected.

The World Health Organisation, on the basis of the request made by the Government of India, supplied 200 vials of Anti-Gas Gangrene Serum needed for Andhra Pradesh as sufficient quantity of the same was not readily available in the country.

British Red Cross have also supplied 500 vials of 10 ml. each of Anti-Gas Gangrene Serium worth £4,000 and these have been distributed to Andhra Pradesh and Tamil Nadu in the proportion of 350 : 150.

33 packages weighing 1041 Kg. containing medicines for cyclone relief have also been received through the Director General, Supply Wing, Indian High Commission, London.

Amendment to minimum wages Act

8322. SHRI K. PRADHANI: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have since processed the various proposals received for amending the Minimum Wages Act; and

(b) if so, the details thereto ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) and (b) Certain proposals for amendment of the Minimum Wages Act, 1948 relating to reduction in the time intervals for periodical wage revisions, speedier method of revision of wages but cutting short the procedure laid down in the Act, enhancement of the penalties for violation etc., are under consideration.

जावरा सिटी में टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार

8323. डा लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रतलाम जिले में जावरा सिटी में नये कनेक्शनों का आवंटन संभव नहीं है क्योंकि अतिरिक्त क्षमता नहीं है;

(ख) क्या प्रतीक्षा सूची में शामिल न किये गये बहुत से व्यक्ति टेलीफोन कनेक्शन लेने के इच्छुक है परन्तु उन्होंने अपनी मांग अपेक्षित राशि जमा करवा कर इसलिये दर्ज नहीं करवाई है क्योंकि कोई ऐसी निश्चित अवधि नहीं है जिसके बाद कनेक्शन मिल सके; और

(ग) क्या उपरोक्त एक्सचेंज का विस्तार आवश्यक है और यदि हां, तो इस बारे में की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) :(क) जी हां।

(ख) सरकार इस बारे में कोई टिप्पणी देने में असमर्थ है ।

(ग) टेलीफोन कनेक्शनों की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष में 100 लाइनें जोड़ दी जायेंगी और 200 लाइनों की क्षमता बढ़ा कर 300 लाइनें कर दी जायेंगी ।

Drug Manufacturers

8324. SHRI OM PRAKASH TYAGI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether at the time of giving a drug manufacturing licence to a concern is it necessary to ascertain that the concern has a Pharmacist for giving expert opinion:

(b) whether the Central Drug Control Organisation undertake periodical checks at the premises of the drug manufacturing concerns to see that the drugs are manufactured under the supervision of a qualified pharmacist; and

(c) if not the reasons thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Under the provisions of the Drugs and Cosmetics Rules, a manufacturer is required to employ c mpetent technical staff for supervising the manufac ure of drugs consisting of at least one person who is a whole time employee and who possesses qualifications prescribed under Rule 71 and 76 of the Drugs and Cosmetics Rules viz. a degree in pharmacy or a degree in science with chemistry as a principal subject or a degree in Chemical Engineering or Chemical Technology or medicine.

(b) Whenever the Central Drugs Inspectors inspect a manufacturing premises they check whether the manufacture is being conducted under the supervision of the competent technical person, who has been approved under rules 71 and 76 of drugs rules as the case may be.

(c) Guestion does not arise.

गुजरात के जनजाति और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का विकास

8325. श्री छीतुभाई गामित : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य के जनजाति और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ग) गुजरात में ग्रामीण और जनजाति क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के विकास के लिए वर्ष 1978-1979 में कितनी राशि निर्धारित की गई है तथा उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) चिकित्सा सुविधाओं के विकास हेतु गुजरात सरकार के प्रस्तावों पर तुरन्त कार्यवाही करने के लिए भारत सरकार द्वारा की जा रही ठोस कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) न्यूनतम आवश्यकता स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत इस राज्य के लिए 1978-79 में 105.14 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है :

(ग) न्यूनतम आवश्यकता स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करने के लिए 1978-79 के दौरान 105.14 लाख रुपये के आवंटन के लिए पहले ही सहमत हो चुकी है। आदिवासी उप-योजना के लिए 76.11 लाख रुपये की सीमा निर्धारित कर दी गई है गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों के लिए 13.00 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता के लिए भी सहमति दे दी गई है।

Drug Controller

8326. SHRI GOVINDA MUNDA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government had instructed the State Governments to appoint full time Drug Controllers in order to strengthen the Drug Control system;

(b) which are the States, who have not appointed full time Drug Controllers till date;

(c) the reasons and explanation in detail in respect of each State as to why they have not implemented the instructions; and

(d) when it will be possible for each of these States to appoint full time Drug Controllers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) The Central Council of Health in its meeting held in April, 1974 recommended *inter alia* the appointment of a full-time officer, technically conversant with the techniques of manufacture and testing of drugs etc. so as to ensure effective drug control measures. This resolution was forwarded to the State Governments for implementation. Again at the Fourth Joint Conference of the Central Council of Health and Central Family Welfare Council held at New Delhi in January, 1978, it was recommended that the States should re-organise the Drug Control machinery so that there is a whole time officer, technically conversant with the manufacture and testing of drugs, incharge of the Drugs Control Organisation. The Resolution passed by the Central Council of Health was forwarded to the States for necessary action.

(b) From the information available, it is known that Kanrnataka, Kerala, Orissa West Bengal and the Union Territory of Goa have appointed full time Drug Controllers. In the remaining States, officers of the Directorate of Health Services look after the enforcement of the Drugs and Cosmetics Act.

(c) and (d). Information in this regard is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Intervention by Ccentral Government to prevent closure of Industries in Maharashtra and Kanpur

8327 SHRI SUKHDEV PRASAD VERMA: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether Government have received representations from Maharashtra Rajya Kamgar Karmachari Parishad for Central Government intervention in the large number of industries that have either closed down, declared lockouts or instigated the workers to go on strike ;

(b) if so, the facts thereof;

(c) whether similar representations have been received from trade unions in Uttar Pradesh for various closed down and locked-out industries in Kanpur seeking Centre's intervention;

(d) if so, the facts thereof along with approximate number of workers remaining out of employment in Maharashtra and Kanpur; and

(e) the action being proposed to be taken thereon ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA) : (a) and (b) While no such representation has been received from the Parishad, the Ministry of Labour have received some representations from time to time from various parties seeking Centre's intervention regarding strikes, lock-outs and closure of units in the Bombay-Thana-Balapur regions of Maharashtra. The attention of the State Government has been drawn to the state of industrial relations in the area. There has been no information received from the Government of Maharashtra, so far.

(c) Yes sir; there have been some representations in recent months seeking Center, intervention regarding lock-outs and closure of mills in Kanpur

(d) and (e). As stated by the Minister of Industry in the Lok Sabha on April 14, 1978, the management of the entire group of Swadeshi Cotton Mills Co Ltd, Kanpur has been taken over under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951

2 The position regarding J. K. Manufactures Kanpur and J. K. Electronics, Kanpur, as reported by the Government of Uttar Pradesh is as follows :

J. K. Manufacturers, Kanpur (2,383 employees) had closed down from October 1, 1977 due to losses. Permission to close down the mills was refused by the specified State Authority under the Industrial Disputes Act, and the employer prosecuted by the State Industrial Relations. Machinery for illegal closure The employer in this case has obtained stay orders from the Allahabad High Court In the case of *J. K Electronics, Kanpur* (workers employed 145) which had closed down on 18th September, 1977 due to financial stringency and losses, the workers entered into an agreement with the employers in December 1977 and have not, it appears, opposed the closure

Medical Facilities in Emergency Wards

8328 SHRI MADHAVRAO SCINDIA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Police personnel are attached to each Hospital in Delhi to look after the cases specially of accidents for emergency treatment ;

(b) if so, whether it is also a fact that the Hospitals do not administer any medical assistance (even first-aid) even if condition of victim is very serious, in the absence of report of formalities of Police personnel;

(c) if so, whether it is also a fact that under these legal bindings/practices the victims die before any medical assistance is administered; and

(d) if so, what steps are being taken to rectify the legal procedure ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. Necessary medical aid is rendered without waiting for completion of police formalities.

(c) and (d). Question does not arise

Installation of Automatic Telephone Exchange at Kalwa

8329 SHRI R K MHALGI : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Government received a representation dated 20th February, 1978 from the Chairman of the Thane Manufacturers Association with respect to the proposed installation of automatic separate telephone exchange at Kalwa;

(b) what action have been taken by Government and whether, it was communicated to the Association concerned; and

(c) if no action has so far been taken, when the decision is likely to be reached ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) Yes Sir.

(b) The representation was carefully considered but could not be agreed to due to techno-economic reasons

(b) A reply has been sent to the Chairman, Thane Manufacturer Association on 20-4-1978

(c) Does not arise.

गुजरात को "मेलेथियन" की सप्लाई

8330. श्री धर्म सिंह भाई पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि गुजरात से मलेरिया के उन्मूलन के लिए डी० डी० टी० के बजाय "मेलेथियन" सप्लाई की जाये;

(ख) यदि हां, तो "मेलेथियन" सप्लाई करने की मांग कब और कितनी मात्रा में की गई है;

(ग) यह माग कितनी और कब पूरी की जायगी और उसे किस प्रकार पूरा करने का विचार है, और

(घ) क्या मलेरिया फैलाने वाले मच्छरो को मारने के लिये "मेलेथियन" डी० डी० टी० से अधिक प्रभावशाली है और दोनो कीटनाशी औषधियो के मूल्य क्या है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हा।

(ख) राज्य सरकार ने जून और नवम्बर 1977 के बीच लगभग 35,000 मी० टन मेलेथियन 23 प्रतिशत डब्ल्यू० डी० पी० सप्लाई करने का अनुरोध किया है।

(ग) चूकि बडे पैमाने पर मेलेथियन के अधाधुन्ध प्रयोग से कुछ खतरे उत्पन्न होते हैं, इसलिए यह विचार है कि इस समय इस कीटनाशी का प्रयोग धीमी गति से किया जाए। यह निर्णय किया गया है कि 1978-79 के छिडकाव कार्यों के लिए गुजरात को केवल 2276 मी० टन मेलेथियन 25 प्रतिशत डब्ल्यू० डी० पी० दिया जाए।

(घ) डी० डी० टी० उन क्षेत्रो में प्रभावकारी होती है जहा पर मलेरिया के वैक्टर पर इसका असर पडता है। जहां मलेरिया के वैक्टर पर डी० डी० टी० और बी० एच० सी० का असर नही पडता है, वहा मेलेथियन प्रभावी होता है।

डी० डी० टी० 75 प्रतिशत की लागत 11,200 रुपये प्रति मी० टन है, और मेलेथियन 25 प्रतिशत डब्ल्यू० डी० पी० की 10,000 रुपये प्रति मी० टन है। 10 लाख की आबादी को सुरक्षित रखने के लिए डी० डी० टी० 75 प्रतिशत से दो बार छिडकाव करने की आवश्यकता होती है। इस कीटनाशी की वार्षिक लागत केवल लगभग 11.20 लाख रुपये आएगी। इतनी ही आबादी को मेलेथियन 25 प्रतिशत डब्ल्यू० डी० पी० से सुरक्षित करने के लिए (तीन बार छिडकाव करने में) इस कीटनाशी की लागत केवल लगभग 90 लाख रुपये आएगी।

बिहार मे टेलीफोन कनेक्शन

8331. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) बिहार में चार हजार अथवा इससे अधिक जनसख्या वाले ऐसे गांवो की सख्या कितनी है जिनमें अभी तक तार तथा टेलीफोन सुविधाओं की व्यवस्था नही की गई है, और

(ख) इन गावो में उक्त सुविधा की व्यवस्था कब तक की जायेगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) (क) बिहार के उन गावो की सख्या, जहां की आबादी 4000 या इससे अधिक है और जहा तार और टेलीफोन की सुविधाए अभी तक नही दी गयी हैं क्रमश 901 और 991 है।

(ख) विभाग की मौजूदा नीति के अनुसार जिन स्थानो की आबादी सामान्य क्षेत्रो में 5000 या इससे अधिक और पहाडी तथा पिछडे इलाको में 2500 या इससे अधिक हो न्यूनतम राजस्व की किसी शर्त के बिना घाटा उठा कर भी टलीफोन और तार की सुविधायें दी जायेंगी। बिहार में ऐसे गांवो की सख्या, जहां तार और टेलीफोन की सुविधायें नहीं हैं, क्रमश 1826 और 1934 है। ऐसे प्रयत्न किये जा रहे हैं कि 1978—83 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान इनमें से अधिकाश स्थानो पर ये सुविधायें दे दी जायें। अन्य स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले जा सकते हैं बशर्ते कि वे प्रस्ताव वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य हों या इच्छुक पार्टियां उन पर होने वाले घाटे पूरा कर दें।

गूंगे बच्चों का उपचार

8332. श्री हरगोविन्द वर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार की संस्थाओं में उपचार के लिए कितने गूंगे बच्चों के नाम दर्ज किए गए;

(ख) क्या सरकार का विचार उन बच्चों के लिए उन संस्थाओं में ठहरने की व्यवस्था करने का है जिससे उनके लिए उचित उपचार की व्यवस्था की जा सके, और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क)से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

Occupation of Land of Poor Harijans By Bokaro Steel Ltd.

8333 SHRI A. K. ROY : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the land of the poor Harijans of Chas has been occupied by the Bokaro Steel Limited to make air strip at Bokaro, if so, the details thereof;

(b) whether those poor Harijans are not paid compensation nor job, not even any notice was given to them; and

(c) if so, reasons thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) to (c). The land for the airstrip was acquired by the Government of Bihar and handed over to Hindustan Steel Ltd who constructed the airstrip in 1962. The information asked for is not available and has been called for from the State Government. It will be laid on the Table of the House when received.

Air Parcels sent outside India

8334. SHRI NATHU SINGH : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) what is the total number of air parcels (foreign going) that went outside India in the last years' of the first and the third five years plans out of the total figures given in reply to Unstarrd Question No. 4920 dated 30th March, 1978;

(b) what is the total number of outgoing surface parcels that went outside India in the last years of the first and third five year plans respectively; and

(c) will the Minister lay on the table a copy (or details thereof) of the Parcel Post Agreement of Laussance, 1974 affecting report of commercial merchandise commercial samples and gift parcels to foreign countries ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) Total number of air parcels that went outside India in the last year of the first Five Year Plan (i.e. 1955-56) is not available separately. This total number of air parcels that went outside India in the first year of the third Five Year Plan (i.e . 1967-68) is 171,472.

(b) Total number of surface parcels that went outside India in the last year of the first Five Year Plan. (i. e. 1955-56) is not available separately. The total number of surface parcels that went outside India in the first year of the third Five Year Plan (i. e. 1967-68) is 308,578.

(c) The Parcel Post Agreement of the Universal Postal Union Lausanne Congress 1974 is an Agreement governing the exchange of postal parcels between contracting countries who are members of the UPU. This Agreement lays down conditions of exchange of parcels in postal terms only, for e.g. the categories of parcels such as ordinary parcel, insured parcel, 'Cash on Delivery' parcel, fragile parcel, service parcel, etc. Similarly, categorisation is made according to the method of despatch or delivery, for e.g. air parcel, express parcel, etc. This Parcel Agreement, therefore, does not affect the export of parcels to foreign countries in terms of commercial merchandise, commercial samples and gift parcels. The conditions regarding the export of such categories o parcels are laid down by the Chief Controller of Imports and Exports.

Regularisation of Casual Workers

8335. SHRI NARENDRA SINGH: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is not a fact that under existing rules, daily rated casual workers who work for a period of 480 days including break days in two years are absorbed in the regular establishment of a particular department;

(b) whether he is aware that the daily rated casual workers who are working in the Office of the Chief Administrative Office of the Ministry of Defence for more than 5 years and have exceeded the period of 480 days have not been absorbed in the regular establishment; and

(c) if so, his reaction thereof and steps proposed to be taken to absorb these workers?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA): (a) to (c). According to the information received for the Ministry of Defence, there are at present 10 casual workers employed in CAO's Office who have completed more than 5 years' service, but have not been absorbed in regular Group 'D' vacancies. They either to do not fulfil the conditions of eligibility of 240 days' service in each of the two preceding years or were over age at the time of appointment as casual labour. During the last one year or so, 12 casual workers who were working for more than 5 years in CAO's Office and who fulfilled conditions of eligibility have already been appointed against regular Group 'D' vacancies.

Demand for Zinc

8336. SHRI S. R. DAMANI: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) the present demand for zinc and the estimated demand by the end of the 6th Plan;

(b) the sources from which the present demand is met;

(c) the progress achieved upto 31st March, 1978 on the projects under construction for production of zinc; and

(d) the details of proposals if any, to set up new plants?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) The estimated demand for zinc during 1978-79 is approximately 1,02,000 tonnes which is likely to go up to around 1,22,000 tonnes by 1982-83.

(b) The present demand for zinc is partly met by indigenous production from Hindustan Zinc Limited (public sector) and Cominco Binani Zinc Ltd. (private sector) and balance from imports.

(c) Construction of both the projects of M/s. Hindustan Zinc Ltd, namely, expansion of the Zinc Smelter at Debari near Udiapur (Rajasthan) and new Zinc Smelter at Visakhapatnam (Andhra Pradesh) has been completed and production in the from of zinc ingots started.

(d) At present there is no proposal under the consideration of the Government, nor any in the private sector, to set up new Zinc Smelters.

Recognition to Employees Welfare Association, Delhi.

8337. SHRI C. N VISVANATHAN: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether any request for recognition of Labour Department Employees Welfare Association (Delhi Administration) is pending with the Labour Commissioner, Delhi Administration, Delhi,

(b) if so, since when and why recognition has not been granted so far; and

(c) by when the above-said Association is going to be recognised?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA): (a) Yes, Sir.

(b) Delhi Administration have reported that an application dated 27-6-77 was received in the Office of the Labour Commissioner, Delhi from the Labour Department Employees Welfare Association (Delhi Administration) and a reply thereto was sent on 27-9-77 stating that the general question of recognition of various service associations was under consideration of the Government of India. The general instructions in regard to the procedure for defacto recognition to the various service associations were communicated by the Delhi Administration on 27-10-77. As the association did not furnish complete information in terms of these instructions, recognition has not so far been granted.

(c) The question of recognition would be decided on receipt of complete information from the association.

Facilities for Renewal of T.V. Licence

8338. SHRI NATVERLAL B. PARMAR: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether the facilities have been created in some post offices in Delhi where T. V. owners can get their licenses renewed by paying requisite fee; and

(b) if so, the number of such post offices as the number of licences renewed during 1978 through these post offices with the names of the post offices and the number of such licenses issued by each?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) Facilities for issue of T.V. licences are available at all post offices in Delhi.

(b) Number of such post offices is 331. A list showing the names of such post offices and the number of T.V. licences issued by these post offices is laid on the Table of the House. [*Placed in Library See* No. LT-2209/78] 1,55,341 TV licences have been issued from 1st January to 31st March, 1978.

Coloured Diskets by Homoeopathic Manufactures

8339. DR. BHAGWANDAS RATHOR: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether coloured diskets prepared by the Homoeopathic manufacturers amount to medicines and their use may retard the Homoeopathic actions expected by the Scientific treatment;

(b) what action Government propose to take to ban the doubtful drugging through these coloured diskets, permitting the pure sugar cane white diskets instead to ensure proper action of the Homoeopathic treatment; and

(c) measures to be taken to penalise Homoeopathic manufacturers who manufacture against the 'Organon of Medicine' accessories and medicines resulting into health hazard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) The Homoeopathic system does not permit the addition of colours in Homoeopathic medicines. As such the use of coloured diskets cannot be called Homoeopathic medicines.

(b) and (c). The matter is being examined by the Drug Technical Advisory Board, under the Drugs & Cosmetics Rules, 1945.

पारपत्रों का जब्त किया जाना

8340. श्री हुकमदेव नारायण यादव: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनके विदेश जाने के लिये जनता सरकार को सत्ता मिलने के पश्चात पारपत्र जब्त किये गये तथा उनमें से उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनको विदेश जाने की अनुमति दी गई तथा उन्हें अनुमति देने के क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू): पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10(3) में दिए गए कारणों में से किसी भी कारण के आधार पर पासपोर्ट जब्त किए जा सकते है; इन कारणों में अन्य बातों के अतिरिक्त गलत तरीके से पासपोर्ट रखना, महत्वपूर्ण सूचना का छिपाया जाना, भारत की सुरक्षा पिछली दोषसिद्धि तथा सम्बद्ध व्यक्ति के खिलाफ दाण्डिक कार्यवाही अथवा गिरफ्तारी के वारंट या भारत से रवाना होने से मना करने के लिए न्यायालय के आदेश का होना भी शामिल है। पासपोर्ट जब्त करने के आदेश और विदेश जाने की अनुमति केन्द्र सरकार अथवा भारत या विदेश में पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारी ही दे सकते हैं। चूंकि इस बारे में बहुत से प्राधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करना होगा इसलिये सूचना एकत्र करके सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

News Item "Caroll's statement not true says CBI"

8341. SHRI C. K. CHANDRAPPAN:

CHOWDHRY BALBIR SINGH: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government's attention have been drawn to the news item appearing in the Indian Express dated the 14th

December, 1977 under the caption "Caroli's statement not true says CBI", and

(b) if so, what is Government's opinion on it ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) Yes.

(b) The report of the C.B.I. in this matter has been received and the final conclusion states that it appears that some attempt was in fact made on 4-3-1977 by someone to influence Dr. Caroli in the matter of hospitalisation of Shri Jagjivan Ram. However, there are far too many discrepancies in the version of Dr. R. K. Caroli and the allegations made by him have not been established beyond doubt. Hence no action is proposed to be taken against any person.

Availability of Rock Phosphate

8342. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether rock phosphate is available in our country ;

(b) if so, the places where they are available ; and

(c) the quantity required for Fertilizer factories to manufacture phosphates ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) Yes, Sir.

(b) Places where rock phosphate deposits occur are given in the Statement enclosed.

(c) The requirement of rock phosphate in the country during 1978-79 is estimated to be about 1.7 million tonnes.

Statement

Location of Rock Phosphate Diposit

State	District with localities
Rajasthan	*Udaipur*
	Maton
	Kanpur
	Karbaria-ka-Gurha
	Dhakan-Kotra
	Sisarma
	Neemuch Mata
	Badgaon
	Jhamarkotra
	Jaisalmer
	Birmania
Uttar Pradesh.	*Dehradun & Tehri Garhwal*
	Maldeota
	Durmala
	Masrana
	Paritibba-Chamasari
	Jhalikhal
Madhya Pradesh.	*Jhabua*
	Kelkua
	Khatamba
	Chattarpur
	Sagar

Request from Aluminium Utensil Manufacturers' Association

8343. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Aluminium Utensils Manufacturers' Association has requested the Finance Minister that the burden of price and subsidy should not fall on utensil consumers but should be rationalised in its sharing, and

(b) what action have Government taken or propose to take in the above matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) Yes, Sir.

(b) The Bureau of Industrial Costs and prices is engaged on a sutdy of the present cost sturcture in the aluminium industry. The pricing policy relating to aluminium will be reviewed on completion of the study.

Closure of large and Small Factories

8344. SHRI JYOTIRMOY BOSU : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) the number of closed large, medium and small factories to date state-wise;

(b) the number of workers out of employment becuase of closure state-wise.

(c) the factors responsible for these closures;

(d) the list of closed large factories and number of workers employed in these factories state-wise ; and

(e) the steps taken by the Central Government to get these factories re-opened?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA) : (a) to (e) The required information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Lok Sabha when received.

Confirmation/Promotion of Medical Officers

8345. Dr. RAMJI SINGH : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether there are about 484 General Duty Medical Officers without being confirmed or promoted since last 10 or 13 years in CGHS;

(b) is it under rules to hold Departmental Promotion Committee after five years of entry into the service; and

(c) whether Departmental Promotion Committee been postponed, if so, how many times and the reasons thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The Central Health Service was constituted with effect from 1-1-1965 and it was reorganised in September, 1966. After the reorganisation of the service, the first departmental promotion committee for promotion from GDO Gr. II to GDO Gr. I was held in March, 1971 and on the basis of the recommendation of the D.P.C. certain GDO Gr. II officers were promoted to GDO Gr. I in May, 1971 and later on in September, 1972. Thereafter no D.P.C. could be held due to the fact that in the meantime the recommendation of the Pay Commission relating to the C.H.S. were received. In accordance with the recommendation of the Third Pay Commission, the existing General Duty Officers were placed either in Senior Class I Scale (Rs. 1100—1600) or Junior Class I Scale (Rs. 700—1300) with effect from 1-1-1973. Even the GDO Gr. I Officers who had not put in five years service were allowed Senior Class I Scale of pay from 1-6-1973 or 1-10-1974. In accordance with the recommendation of the Pay Commission a person who has put in five years service in Junior Class I Scale of Pay was ligible for placement in Senior Class I scale subject to availability of posts in the Senior Class I of pay. As the persons who were appointed to Junior Class I Scale of pay from 1-1-73 were eligible to Class I appointment in Senior Class I Scale of pay from 1-1-1978 only. It was proposed to hold the meeting in the last week of December, 1977 for that purpose. However this could not be done due to the fact that the Character Rolls for the year 1977 in respect of all the eligible officers were not available. Normally the character rolls for the preceding year become available by the 31st March of the following year. A meeting of the D.P.C. has since been held in which cases of the officers whose up-to-date character rolls were available, have been considered. Some more meetings of the D.P.C. are proposed to be held as soon as the C. Rs. for 1977 of concerned officers become available. In the case of C.H.S. Officers the Ministry of Health & Family Welfare have to procure the C. Rs. of Officers working in a large number of participating units. All these units are being reminded to expedite the submission of C.Rs. of officers working under their control.

There is no provision under the rules that a meeting of the D.P.C. should be held after 5 years of entry into the Government service. As regards the confirmation of officers it is stated that all the available permanent vacancies in Supertime Gr. I, Specialist Gt. I, Supertime Gr. II and Specialist Gr. II have already been filled by the D.P.C. in this Ministry. As regards the question of confirmation of General Duty Officers Gr. I and Gr. II, the officers appointed in the initial constitution have already been confirmed. The postition with regard to availability of permanent vacancies at the maintenance stage in respect of all the participating organisations is being reviewed and more officers are expected to be confirmed as a result of the review.

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees

8346. SHRI R.N. RAKESH : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) total number of posts filled in each category of posts since, March, 1977 with

specific shares of S C. & S/.T. in such employment and also the number of posts de-reserved in each category and reasons thereof, and

(b) total number of departmental promotions/upgradation of posts in each category of posts and how many posts gone to scheduled castes and scheduled tribes ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of Lok Sabha

British curbs on immigration

8347 SHRI HARI VISHNU KAMATH : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to press reports to the effect that a British Parliamentary Committee has urged their Government to impose stringent curbs on immigration,

(b) whether the British Government has accepted the recommendations of the Committee, and

(c) if so, the details thereof and the likely repercussions thereof on future Indian immigrants to U K as well as those Indian nationals already resident in that country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU) (a) Yes sir A Select Committee of the British Parliamentary, consisting of 15 members from two main parties has submitted a Report on Race Relations and Immigration

(b) The British Government has not yet given its decision on the Report However, the British Home Secretary, Mr Merlyn Rees made a statement in the British House of Commons on 6/4/78 in which he rejected several of the main recommendations for stricter immigration controls put forward by the Select Committee.

(c) Does not arise

Declaration of Charitable Institutions as Industry

8348 SHRI D D DESAI : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether Government have studied the implication of the recent Supreme Court Judgement of what constitutes an 'industry' for purposes of the Industrial Disputes Act,

(b) whether Government are aware that even charitable institutions employing any person will come under this definition; and

(c) if so Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA) : (a) to (c) The entire matter is under examination in the overall context of the Industrial Relations Bills

पाकिस्तान को अमरीकी अस्त्रों की सप्लाई

8349. श्री उग्रसेन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अमरीका ने पाकिस्तान को 100-ए-7 लड़ाकू विमानों की सप्लाई करने का निर्णय सरकार ने किया है और यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ,

(ख) क्या उन्हें पता है कि अमरीका पाकिस्तान का 'न्यूक्लिअर प्रोसेसिंग प्लांट' देने को भी सहमत हो गया है, और

(ग) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) सरकार को ऐसे किसी निर्णय की जानकारी नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्दी में मैनुअल तथा फार्म

8350. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उनके मंत्रालय/विभाग में कुल कितने मैनुअल और फार्म उपयोग में लाये जा रहे हैं ,

(ख) उनमें से कितनों को हिन्दी में अनुदित किया गया है तथा कितनों को द्विभाषिक रूप से मुद्रित किया गया है ;

(ग) शेष को अनुदित न करने अथवा द्विभाषिक रूप में न छपवाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उन्हें कब तक द्विभाषिक रूप में तैयार किये जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) मुख्य मंत्रालय ने कोई भी मैनुअल नहीं निकाला है। तथापि, इसने 13 फार्म तैयार किए हैं।

(ख) से (घ) 13 फार्मों में से तीन फार्मों का हिन्दी में अनुवाद किया गया है और शेष दस फार्मों को दो या तीन महीनों के भीतर द्विभाषी रूप में छपवाने के लिए प्रयास किए जा रहे है ।

Appointment of Interpreters in the Ministry of External Affairs

8351. SHRI YADVENDRA DUTT : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether he is planning to have a full time post of Interpreters in the Ministry paid and maintained by the Government of India ;

(b) if so, a brief outline of the scheme ; and

(c) will Government consider to encourage military officers learning foreign languages and after becoming proficient, their service will be transferred to the post of Interpreters of the External Affairs Ministry?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU) : (a) and (b) The formation of an Interpreters Cadre in the Ministry of External Affairs has been sanctioned and the recruitment rules to the Cadre are being finalised in consultation with the Union Public Service Commission.

The proposed Cadre of Interpreters will consist of eleven Interpreters in the super-time scale Rs. 2000-125/2-2500), nineteen in the senior-scale (Rs. 1200-2000) and five in the junior scale (Rs. 700-1300).

(c) It is proposed to fill these posts by direct recruitment in consultation with the Union Public Service Commission.

Cost of A Starred Question

8352. SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) on an average how much amount of money is required to be spent over one Starred Question on which reply is given in Parliament (not those which lapse due to want of time) ; and

(b) break-up figures for the money needed for collecting the information and money spent during its answer along with supplementaries?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA) : (a) and (b) · There is no standard basis for arriving at the cost of a Parliament Question. It would mainly depend on the nature of the Question, the information to be collected etc. Manpower involved and the time spent in each case may therefore differ and depend on these factors. Moreover, no staff is solely employed for replying to Parliament Questions and staff in the Ministries and in some cases the State Governments or Public Organisations, Government Undertakings. etc. have also to work on collecting information for these questions. It is, therefore, extremely difficult to indicate the amount of money required to be spent in answering a Parliament Question.

टेलीफोन भंडार

8353. श्री आर० एल० कुरील : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यवार उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां टेलीफोन सम्बन्धी कल पुर्जों के भंडार हैं तथा उनमें कितनी मात्रा में कल-पुर्जे पड़े हुये हैं और गोदामों की संख्या कितनी है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : वांछित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं —

क्रम सं०	राज्य का नाम	स्थान का नाम जहां डिपो स्थित है	रखे गए भंडार का मूल्य (लाख रुपयों में) फरवरी, 78 में	डिपो जिन्हें माल सप्लाई करता है
1	2	3	4	5
1	आन्ध्र	सिकन्दराबाद	92	आन्ध्र सर्किल और हैदराबाद जिला
2	बिहार	पटना	85	बिहार सर्किल और पटना जिला
3	गुजरात	अहमदाबाद	100	गुजरात सर्किल, अहमदाबाद सूरत और बडौदा जिल,
4	कर्नाटक	बंगलूर	34	कर्नाटक सर्किल और बंगलूरा जिला
			51 (शाखा)	
5	केरल	एर्नाकुलम	109	एर्नाकुलम जिला और केरल सर्किल
6	मध्य प्रदेश	जबलपुर सी टी एस जबलपुर	207 (मुख्य) 081 (रिटेल)	मध्य प्रदेश सर्किल और इन्दौर जिला
7	महाराष्ट्र	बम्बई सी-टी-एस बम्बई	237 (मुख्य) 139 (रिटेल)	महाराष्ट्र सर्किल और पूना जिला
			148 (जिला)	बम्बई जिला
		नागपुर	88 (जिला)	नागपुर जिला
8	असम	गोहाटी	129	उत्तर पूर्व दूरसंचार सर्किल
9	दिल्ली	नई दिल्ली सी-टी-एस-दिल्ली	71 (मुख्य)	उत्तर पश्चिमी दूरसंचार सर्किल
			86 (रिटेल)	चंडीगढ़ और लुधियाना जिले
			337 (जिला)	दिल्ली दूर संचार जिला
10	उड़ीसा	कटक	53	उड़ीसा सर्किल
11	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	113	जम्मू और कश्मीर सर्किल

1	2	3	4	5
12	तमिलनाडु	मद्रास	88 (मुख्य)	तमिलनाडु सर्किल और
			83 (रिटेल)	कोयम्बटूर जिला
			141	मद्रास दूरसचार जिला
13	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	128	उत्तर प्रदेश सर्किल कानपुर, और लखनऊ जिला
14	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता सी-टी-एस कलकत्ता	711 (मुख्य)	पश्चिम बंगाल सर्किल
			019 (रिटेल)	
			335 (जिला)	कलकत्ता दूरसंचार जिला
		सिलीगुडी	036 (जिला)	पश्चिम बंगाल का उ[illegible] भाग
15	राजस्थान	जयपुर	163	राजस्थान सर्किल और जयपुर जिला
			3874 लाख रुपये	

उपर्युक्त डिपो निम्नलिखित का स्टाक रखते हैं :—

(i) लाइन और वायर और केबुल (ii) कैरियर उपस्कर (iii) पी-बी-एक्स बोर्ड (iv) टेलीप्रिंटर और सहायक उपकरण (V) टेट और टूल (Vi) उपर्युक्त उपस्करो के लिए काम मे आने वाले फालतू पुर्जे

भण्डार की मात्रा प्राप्तियों और समय समय पर की जाने वाली सप्लाई पर निर्भर करती है।

तथापि, यहा यह उल्लेख कर दिया जाता है कि सप्लाई के साधनों से सामग्री के उपलब्ध होने पर उन डिपो मे माग कर्त्ताओं की वार्षिक आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टाक रखा जाता है।

Brain Fever in Tamil Nadu

8354. SHRI M. ARUNACHALAM : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government is aware that the brain fever has spread in Tamil Nadu particularly in Tirunelveli District ;

(b) whether the Minister has received any information about deaths due to brain fever ; and

(c) if so, the measures taken by Government to eradicate the disease?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE : (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) Yes.

(b) 71 deaths are reported to have occurred in Tirunelveli District of Tamil Nadu.

by the Government in this regard :—

1. A Team of experts from Virus Research Centre Pune is carrying out the following investigations :

(i) Clinical Study.

(ii) Entomological Study.

(iii) Serological Survey among humans.

(iv) Serological Survey among animals and birds.

2. Another team from the Directorate of Public Health, Tamil Nadu has been deputed to assist the Virus Research Centre Team.

3. The Vector Control Research Centre Team from Pondicherry also completed collection of data and materials for the long term study of biological control of mosquitoes.

4. District Health Officer, Tirunelveli District, Medical Officer, Primary Health Centre of the concerned block; one Paediatrician from Medical College will also assist the Team.

'हिन्डाल्को' रेणुकूट (उत्तर प्रदेश) के बर्खास्त किये गये कर्मचारियों के बारे में मध्यस्थ निर्णय

8365. श्री भानु कुमार शास्त्री : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री 'हिन्डालको', रेणुकूट, उत्तर प्रदेश के बर्खास्त किये गये कर्मचारियों के बारे में मध्यस्थ निर्णय के बारे में 28 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5248 के उत्तर के सम्बन्धों में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यस्थ ने अपना निर्णय दे दिया है। और यदि हा, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) यदि नही, तो विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं और उसके द्वारा निर्णय कब तक दिये जाने की आशा है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख). राज्य सरकार से प्राप्त की गई सूचना के अनुसार मध्यस्थ ने अभी तक अपना निर्णय नही दिया है। बताया जाता है कि मध्यस्थ ने गवाहों की सुनवाई तथा जिरह के लिए 16-18 मार्च, 1978 की तारीखें निश्चित की थी। परन्तु श्रमिक पक्ष ने अगली तारीखें मांग लीं। गवाहों की सुनवाई/जिरह के लिए 16-18 मई, 1978 की नई तारीखें निश्चित की गई है।

Exetntion of CGHS service to Jaipur and Pune

8356. SHRI K. LAKKAPPA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) when was the scheme for extension of CGHS to the cities of Jaipur and Pune sanctioned by Government ;

(b) has the scheme been implemented in those cities and if so, from which dates ; and

(c) if not, the reasons for delay?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) 11th July, 1977.

(b) and (c). The requisite formalities for starting of the CGHS, viz, acquisition of suitable accommodation for the dispensaries, arrangements with the State Governments for hospitalisation/special investigations, procurement of medicines and other stores and recruitment of staff are nearing completion in Jaipur and Pune. As soon as these are completed, the Scheme will start functioning at these stations.

Malaria

8357 SHRI SHANKERSINGHJI VAGHELA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the total number of malaria cases during the year 1977 ;

(b) the total number of deaths due to malaria during 1977 ;

(c) the total amount spent on the Malaria Eradication Programme during 1977 and the total number of persons engaged on this programme and the expenditure incurred on them during 1977; and

(d) what other effective measures are proposed to be taken for the checking malaria, if not, completely eradicating it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) 45,65,517 (Provisional).

(b) 62, of which 16 only have so far been verified as due to Malaria.

(c) The total estimated expenditure on NMEP during 1977-78 incurred by the Government of India was Rs 58 crores. The total number of persons engaged on NMEP and the expenditure incurred on them during 1977-78 is not readily available. The total operational cost on the Programme, however, was about Rs. 21 crores.

(d) While eradication of the disease is not technically feasible, the Government have launched a Modified Plan of Operations from 1-4-1977 for containment of the disease.

Its main objectives are :—

1. to prevent deaths and reduce period of sickness;

2. to maintain industrial and agricultural production by undertaking preventive and anti-malarial measures in the affected areas; and

3. to consolidate the achievements attained, so far. A statement indicating the salient features of the Modified Plan of Operations is enclosed.

The sailent features of the Modified Plan of Operations are as follows :—

1. The existing NMEP Units have been reorganised to confirm to the geographical boundaries of the district. Previously the Chief Medical Officers of the districts were not involved in the programme, but with the re-organisation of the Units, they are primarily responsible for the programme in the district.

2. Increased quantity of various insecticides DDT, BHC, Malathion have been /are being supplied to the States. Alternative insecticides are also being provided to the Units/districts where the vector has become resistant to DDT/BHC.

3. Insecticidal spray operations have been undertaken in all rural areas which have incidence of 2 or more cases per thousand population.

4. Adequate quantity of anti-malaria drugs have been/are being supplied to the State/Union Territory Governments. About 1.13 lakhs Drug Distribution Centres/Fever Treatment Depots have been established to make the drug freely available. In areas where resistance to Chloroquine by parasites has been noticed, alternative antimalarials like quinine have been supplied.

5. Anti-larval operations under Urban Malaria Programme have been intensified. The Scheme has been extended to 38 more towns besides the 28 existing towns existing earlier during 1977.

6. Supervision of the field staff has been toned up.

7. Steps have been taken for undertaking both fundamental and operational research in the field of Malaria Eradication Programme . 14 Research schemes, i.e., 8 for operational field research and 6 for laboratory research on malaria has been associated by Government of India to ICMR.

8. For early examination of blood smears and quick treatment of positive cases, laboratory services have been decentralised to the BHC level.

9. With a view to control the spread of Plasrodium falciparum infection which accounts for death due to Cerebral malaria with the help of World Health Organisation, and intensive programme has been initiated in the States of North Eastern Region of the country.

10. The following steps for imparting health education regarding the disease and seeking public co-operation and participation for controlling have been taken;

(*i*) Panchayats and school teachers have been involved in the distribution of chloroquine tablets.

(*ii*) Drug Depots have been opened in inaccessible tribal areas. In some states this have been done in collaboration with the Tribal Welfare Departments.

(*iii*) A film 'The Threat' recently made has been released all over the country in fourteen regional languages.

(iv) Posters in regional languages "Fever May be Malaria" Take Chloroquine tablets", have been supplied to the States for display in Panchayats Ghars, Schools, Primary Health Centres and sub-centres.

(v) A pamphlet in regional languages 'Malaria-what to do' giving the signs, symptoms dose schedule of chloroquine, indication and Centre-indication has been supplied to the States for distribution to Panchayats, school teachers and other voluntary agencies.

(vi) It is also proposed to orient the presidents and the secretaries of the Panchayats on Malaria

(vii) Folder on the role of the Medical Practitioners has been supplied to the States for distribution to Medical practitioners. Similarly, a pamphlet "Why Marlaria again'? has been supplied, to the States for distribution to the Deputy Commissioners, Chief Medical Officers and Block Development Officers for apprising them about the existing problems of malaria and the action proposed to be taken

(viii) To disseminate the anti-malaria message, special postal stationery has been released by Posts and Telegraphs Department

मध्य प्रदेश में छतरपुर में खनिज सर्वेक्षण

8358. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सरकार मध्य प्रदेश में छतरपुर में किन स्थानों पर खनिज सर्वेक्षण कर रही है, और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) (क) भारतीय भूसर्वेक्षण संस्था द्वारा छतरपुर जिले में पुगावन, सलैया, सिलन और भ्रामटोली के आस पास आधार धातु के खनिजीकरण हेतु तथा छतरपुर और सागर जिलो में हीरापुर-मगदेबडा क्षेत्र में फास्फोराइट के लिए खोज कार्य किया जा रहा है ।

(ख) सलैया क्षेत्र में ड्रिलिंग के दौरान सलफाइड खनिजीकरण के पतले ओनो का पता है । अब तक के परिणाम महत्वपूर्ण नही है । हीरापुर-गरदेबडा क्षेत्र में फास्फेराइट हेतु किए गए खोज कार्यों से लगभग 14 लाख टन भंडार का पता चला है जिसमें 17 से 33 प्रतिशत तक फास्फोरस पेन्ट आक्साइड है ।

भारतीय चिकित्सा तथा होम्योपैथी अनुसंधान की केन्द्रीय परिषद द्वारा गर्भपात के बारे में अनुसंधान

8359. **श्री चतुर्भुज** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन भारतीय चिकित्सा तथा होम्योपथी अनुसधान की केन्द्रीय परिषद् गर्भपात के बारे मे कोई अनुसधान कर रही है, और यदि हा, तो उक्त परिषद् किस माध्यम से यह अनुसधान कर रही है और क्या यह अनुसधान आयुर्वेदिक ग्रन्थो मे वर्णित तथ्यो पर आधारित है ,

(ख) क्या परिषद् को इस कार्य मे अब तक काई सफलता प्राप्त हुई है और यदि हा, ता इस अनुसधान के लाभो को लोगों तक पहुचाने के लिए जनता सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए है , और

(ग) अब तक किए गए अनुसधान पर कितनी राशि खर्च हुई है और क्या एलोपैथी की तुलना मे यह खर्च तथा इससे प्राप्त सफलता कम है या अधिक है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसधान परिषद ने एक आदर्श और मान्य गर्भ निरोधक निकालने के लिए अनुसधान कार्य हाथ में

लिया है, न कि गर्भ समापन के किसी क्षेत्र का।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते :

Separation of Audit and Accounts in P&T Department

8360. SHRI SURAJ BHAN : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it is not a fact that in the P& T Directorate, three different empires, Engineering, Postal and Accounts are now functioning sometimes working at cross purposes but engaged in extending their respective empires by securing sanction for more posts in higher echelons, with the result such posts have been disproportionately multiplied in Accounts Wing which is the baby of the growing empires ; and

(b) will Government make an independent enquiry through the Administrative Reforms Commission or any other agency to study whether the separation of accounts from Audit in the Postal Branch has been in accordance with the desired objective and whether it has been achieved and at what cost?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir, Such an enquiry is not considered necessary.

Economic Co-operation with West Asian Countries

8361. SHRI C. K. JAFFER SHARIEF Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India and countries in West Asia are contemplating to launch an extensive programme of economic cooperation among themselves; and

(b) if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU) : (a) Yes, Sir.

(b) The age-old economic and trade links between India and the countries of West Asia have received a very significant impetus in recent years. These countries have drawn up massive economic development programme in the wake of the oil price boom, and given India's ability to supply goods and services at competitive rates, both in terms of price and quality, our exports have shown an impressive increase and reached the value of Rs. 703·88 crores in 1976-77 as compared to Rs. 177·98 in 1973-74.

Moreover, Indian engineering industrial construction and consultancy firms have found increased acceptance in these countries and they have been able to secure a number of contracts in various fields worth approximately Rs. 1500 crores. In recent years India has also been able to provide technical expertise as well as skilled and semi-skilled manpower to many of the countries in this region. To further consolidate and diversify these ties, the Ministers of Industry and Works and Housing, as well as the Minister of State for Commerce and Civil Supplies visited many of the countries in the region. In return Ministerial and official delegations from Sudan, Egypt, Iraq, Iran and YAR, Libya and Syria have paid visits to India. Fruitful meetings of the Indo-Iran and, Indo-Iraq Joint Commissions have also been held recently in September and November, 1977.

भाभर और अहमदाबाद के बीच टेलीफोन लाइन की खराबी को दूर किया जाना

8362. श्री मोतीभाई आर० चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भाभर और अहमदाबाद के बीच टेलीफोन लाइन की खराबी की ओर दिला दिए जाने के बाद भी उक्त टेलीफोन लाइन अक्सर खराब रहती है, परन्तु उक्त खराबी अब तक दूर नहीं की गई है ; और

(ख) क्या लोगों की सुविधा के लिए इस बारे में शीघ्र कार्यवाही की जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) जी नहीं । टेलीफोन लाइन का कार्यकरण सन्तोषजनक रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Prices of Metal

8363. SHRI KACHARULAL HEMRAJ JAIN: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether the price of metal has come down in the international market;

(b) if so, whether it is a fact that the Hindustan Zinc Limited, a Government undertaking, shall have to incur loss due to the fall of price of metals in the international market;

(c) if so, the steps taken to reduce the loss to the minimum ; and

(d) what efforts are made to ensure that lead and zinc is prepared by this undertaking at the international market rate ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) Yes, Sir. There was a downward trend in the international market price of zinc and lead during 1977-78.

(b) Consequent on the reduction in the selling price of zinc arising from the above, profitability of M/s. Hindustan Zinc Ltd. during 1977-78 has been reduced considerably.

(c) For minimising the impact on profitability, Hindustan Zinc Ltd. is actively pursuing areas of cost reduction in its operations.

(d) Despite constraints such as leaner ores, high power rates, high duties and interest rates etc. efforts are being made by the Hindustan Zinc Ltd. for bringing down their cost of production. These measures are indicated below:—

(i) Improvement in zinc recoveries by introduction of leach residue treatment.

(ii) Increasing recoveries of lead metal in the new lead plant by incorporating latest available technology.

(iii) Maximising plant utilisation.

(iv) Keeping a close watch on the consumption norms of costly chemicals and expensive stores.

(v) In-house research and development in technology for improving the process and productivity.

Criteria for Setting up of CGHS Unit

8364. SHRI GANANATH PRADHAN: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the criteria followed by Government to set up a C.G.H.S. Unit at a place;

(b) is there any proposal for any such unit in the capital of Orissa (Bhubaneswar): and

(c) if so, the probable date of its opening?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE: (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) Cities having a concentration of 7,500 families or more of Central Government employees are considered for being brought within the purview of the Central Government Health Scheme subject to adequate funds being provided for the purpose.

(b) No. Sir.

(c) Does not arise.

Cooperation of Soviet Surgeons for Curing Myopia

8365. SHRI S. S. SOMANI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that short sight of myopia which affects millions of men, women and children can be corrected with a simple surgery on the eye;

(b) whether it is also a fact that the USSR Surgeon have also extended their co-operation to India in this regard; and

(c) if so, the details regarding the help sought by Indian Government from USSR in this regard and how far it has benefited Indian people?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) The Moscow Scientific Research Laboratory of Experimental and Clinical Problems of Eye Surgery, USSR, has claimed to have developed a simple surgery to correct short sight or myopia. Such operations are, however, still in an experimental stage in India.

(b) and (c). Two teams of Soviet Eye Specialists visited India in April, 1977 and March, 1978 under the Indo-Soviet Programme of Cooperation in Science and Technology. The team performed operations including these to correct myopia at

the Sarojini Devi Eye Hospital, Hyderabad and also demonstrated techniques and gave lectures on ophthalmology at the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi and the Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh. An Indian team led by the Director of Ophthalmology, Sarojini Devi Eye Hospital, Hyderabad visited USSR in November/December 1977 and signed a protocol in which surgical correction of myopia has been included as one of the subjects of mutual interest in which scientific-technical collaboration could be carried out between the Sarojini Devi Eye Hospital, Hyderabad and the Moscow Scientific Research Laboratory of Experimental and Clinical Problems of Eye Surgery. Under this Indo-Soviet Programme of Cooperation in Science and Technology there is also scope for training Indian Ophthalmologists in techniques of eye surgery and for further visits to India by Soviet Specialists.

घोघा रोग

8366. श्री विनायक प्रसाद यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में सहरसा जिले में और विशेषकर बख्तियारपुर, सलरबूजा और अन्य प्रखण्डों मे सैकड़ों व्यक्ति एकाएक घोघा रोग (गर्दन मोटी हो जाना) से ग्रसित हो गए हैं और दिन प्रतिदिन यह बीमारी महामारी का रूप ले रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि लोगों ने स्थानीय बड़े डाक्टर को इसकी सूचना दी परन्तु राज्य सरकार डाक्टरी इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर हां में हो, तो क्या केन्द्रीय सरकार इसकी जांच के लिए डाक्टरों का एक दल भेजेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) . वांछित सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और ज्यों ही मिल जाएगी, सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Indians Working Abroad in U.N. Agencies.

8367. SHRI L. L. KAPOOR : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have any information of number of Indian citizens working abroad in different U.N. agencies and private and public organisation and with the foreign Government;

(b) what is the average salary per year of the post in the rank of Under Secretary and Asstt. Secretary General employed in the U.N. organisation and its subsidiaries and the other perquisites given to them;

(c) whether this income is subject to income-tax, if not, the reasons thereof; and

(d) whether Government have any proposal to tax the salary and perquisites of such Indian citizens employed in U.N. and its subsidiary agencies. If not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU) : (a) According to the latest published information, 816 Indians were working in the United Nations and its various agencies in 1975. We do not have information regarding the employment of Indian citizens by foreign private and public organisations and governments.

(b) The annual gross salary of the post of Under Secretary General employed in the U.N. $76,030/- and of an Assistant Secretary General employed in U.N. is $67,430/-.

(c) and (d). The facts are being collected.

Appointment of Computers/Investigators

8368. SHRI MOHAN SINGH TUR :
SHRI VASANT SATHE :

Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether according to the rules of recruitment and Promotion and the amendments thereto, seniority lists of Computers and Investigators in the Ministry of Labour and the Labour Bureau, Simla have been regularly issued quota-wise each year; and

(b) whether Clerks and staff of the D.G. E. & T. have been accommodated in the posts of Computers/Investigators in the

Ministry and the Labour Bureau, Simla to the detriment of the interests of Computers and Investigators already working in these organisations, whose only avenue of promotion is in their own line and if so, the steps contemplated, if any to rectify this imbalance?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA)

(a) *Computers* In respect of Computers of Labour Bureau, the seniority list has been issued as per quota maintained for the purpose In respect of Computers of the Ministry of Labour, the question of finalizing their seniority has been taken up

Investigators grade II In respect of Investigators Grade II in the Labour Bureau, the seniority list has not yet been finalised due to Writ Petition filed by certain Investigators Grade II in the Himachal Pradesh High Court In respect of Investigators Grade II of the Ministry of Labour, the seniority list was finalized some time back and is being updated

(b) U D Cs /Steno Grade III/L D Cs are eligible for appointment as Computers/Investigators Grade II under the Recruitment Rules Computers are also eligible for promotion as Investigators Grade II under those Rules In view of this, the service interests of Computers/ Investigators in the Ministry and in the Labour Bureau are not jeopardized

डाक-तार विभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधायें

8369. श्री दया राम शाक्य : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) ग्रामीण क्षेत्रो मे काम करने वाले डाक-तार विभाग के कर्मचारियो को चिकित्सा सुविधाए देने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं और उनके एव उनके बच्चो के उपचार पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति किस प्रकार की जाती है, और

(ख) उत्तर प्रदेश मे ग्रामीण क्षेत्रो मे काम करने वाले डाक-तार विभाग के कर्मचारियो को गत दो वर्षों मे चिकित्सा बिलो के रूप मे कितनी राशि की प्रतिपूर्ति की गई ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा) नियमावली, 1944 मे शहरी और देहाती दोनो स्थानो के कर्मचारियो की प्राधिकृत चिकित्सको द्वारा चिकित्सा और उपचार के लिए व्यवस्था है और कर्मचारियो द्वारा चिकित्सा पर किये गये खर्च की प्रतिपूर्ति उन नियमो मे निर्धारित सीमा तक की जाती है। देहाती इलाको मे, जहा कोई भी केन्द्रीय या राज्य सरकार का डाक्टर नही होता, प्राइवेट रजिस्टर्ड चिकित्सको को प्राधिकृत चिकित्सक के बतौर नियुक्त किया जाता है। नियमो मे ऐसी भी व्यवस्था है कि आपातकाल मे यथोचित दूरी के भीतर यदि सरकारी/मान्यता प्राप्त अस्पताल या चिकित्सक उपलब्ध नही हो तो प्राइवेट चिकित्सको या गैर मान्यता प्राप्त अस्पतालो मे इलाज कराने पर भी चिकित्सा व्यय की एक निर्धारित सीमा तक प्रतिपूर्ति कर दी जाए।

(ख) उत्तर प्रदेश सर्किल के देहाती इलाको मे डाक-तार कर्मचारियो पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु किए गए खर्च के सम्बन्ध मे अलग से आकडे नही रखे जाते। तथापि 1975-76 और 1976-77 के दो वर्षों मे उत्तर प्रदेश के देहाती और शहरी इलाको मे इस सम्बन्ध मे कुल क्रमश: 30 91 लाख और 23 22 लाख रुपये खर्च किये गए थे।

P. C. Os. in Gujarat.

8370 SHRI HITENDRA DESAI Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state

(a) how many villages in Gujarat have facilities for telephone public call offices,

(b) what is the target of Government for next five years for improving these facilities?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEV SAI) (a) 786 village in Gujarat are having telephone facilities as on 1-4-1978.

(b) in the next five years, it is proposed to extened telephone facilities to 500 more villages in Gujarat State.

Seventh Asian and Pacific Labour Ministers' Conference

8371. SHRI PRASANBHAI MEHTA: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether India also attended the Seventh Asian and Pacific Labour Ministers' Conference;

(b) if so, whether India put forward some proposals in the Conference;

(c) the decisions arrived at in the Conference; and

(d) what were the subjects discussed?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA):

(a) Yes, Sir.

(b) to (d) : The two topics discussed in the Conference were (i) Active Employment Policy and (ii) Regional Technical Cooperation. At the close of the Conference, a Communique was issued outlining *inter alia* the decisions taken on the two topics. Relevant extracs from the Communique are given in the enclosed Statement.

Statement

Extracts from the Communique of Seventh Conference of Asian and Pacific Labour Ministers.

8. A number of specific aims and recommendations were considered by the panel on Active Employment Policy. The Conference:

(i) Accepted the broad social and economic objectives of an Active Employment Policy, recognising, however, that the objectives and operation of such a policy will vary in emphasis according to the circumstances of individual countries.

(ii) Stressed the need for labour ministries to be actively involved in the planning of national economic and development policies.

(iii) Recognised the importance of the principle of tripartism as an essential element in the planning and implementation of an Active Employment Policy.

(iv) Called for urgent attention to be given to providing special training programmes for dropouts from national education systems.

(v) Recognised freer access to international markets for the products of the countries of the region as being vital to the successful implementation of active employment policies, particularly is smaler countries.

(vi) Recognised the migration of labour is an important element of employment policies.

(vii) Noted, with respect to the working environment, the experiences of member countries in the areas of safety health and welfare. The Conference recognised that better management/employee communication was conducive to greater job satisfaction, security of employment and increased productivity. Ministers welcomed the inclusion of these topics in the agenda of the ILO Regional Conference in 1980.

(viii) Agreed that the compilation and analysis of statistical information that is of direct relevance to policy formulation is vital to the success of an Active Employment Policy. In this context the value of household surveys was stressed.

9. The Conference noted that the follow-up to the World Employment Conference would be on the agenda of the International Labour Conference in 1979. Attention was drawn to the possibility of Labour Ministries promoting action in favour of employment and the satisfaction of basic needs in other international forums and in relation to the formulation of a new International Development Strategy.

10. The Panel considering Regional Technical Cooperation matters focussed on ILO Regional activities and the degree to which existing projects met the needs of member countries. It was generally felt that these projects should lay greater stress on the development of the rural sector, particularly the development of employment opportunities and appropriate technology, especially labour intensive technology and productivity. It was considered appropriate to initiate action to identify problems in non-formal and rural sectors and there was general agreement that the effectiveness of regional projects could be improved.

11. The Conference made five specific recommendations to improve Regional Technical Cooperation in the region. These were:

(i) That steps should be taken by the ILO to strengthen and consolidate existing regional projects.

(ii) That any future related projects should preferably the undertaken within the framework of existing projects.

(iii) That while supporting the TCDC concept it was agreed that more time was needed for examination of the ILO project proposal. Participating countries therefore agreed to submit their comments on the proposal within one month to the ILO Regional Office in Bangkok. It was recommended that appropriate actions should lbe taken after the comments have been processed.

(iv) That, taking into account the urgent needs of the Asian and Pacific region, a greater share of UNDP and ILO funds should be allocated to the region.

(v) That in future Conferences of the Asian and Pacific Labour Ministers there should be one variable Agenda Item on a subject to be determined,, and a second permanent Agenda Item comprising two parts, namely Regional Technical Cooperation and a follow-up of recommendations of previous Conferences.

Decentralisation of Billing and Commercial Functions of Delhi Telephone

8372. SHRI MOHINDER SINGH SAYIAN WALA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether billing and other commercial functions of the Delhi Telephones are to be decentralised,

(b) if so, the benefits sought to be given to the subscribers by this move; and

(c) in how many places this has been done and the results thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI):

(a) Yes Sir,

(b) Subscribers. who used to approach General Managers office for various commercial and billing problems, will, after decentralisation, have these problems attended to by Area Managers whose offices are located in the respective areas. This will be more convenient to subscribers and ensure quicker attention. Decentralisation of Administrative functions and powers is expected to increase the efficiency of the system.

(c) This has been adopted the Central area comprising of Idgah, Connaught Place, Rajpath and Secretariat exchanges with effect from 16-1-78 The results can be known only after trial for about a year.

Post Offices opened in Maharashtra During 1977-78

8373. SHRI VASANT SATHE : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of Post Offices targetted/opened during 1977-78 in Rural areas of Maharashtra, District-wise and how does it compare with the performance during 1976-77,

(b) the number of offices proposed to be opened in rural areas during 1978-79 District wise with order of investment, and

(c) the number and names of Post Offices proposed to be upgraded in Maharashtra during 1978-79?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) 246 Post Offices were opened in the rural areas of Maharashtra State during 1977-78 against 236 proposed. The comparative figure for 1976-77 are 95 and 126 respectively. Districtwise position is given in the Annexure.

(b) 485 Post Pacifies are proposed to be opened in the rural areas of Maharashtra during 1978-79 at an estimated establishment cost of Rs. 7·27 lakhs Districtwise breakdown is given in the annexure.

(c) 58 Post Offices are proposed to be upgraded during 1978-79 in Maharashtra State. It is not possible to identify the Post Offices for upgradation at this stage due to the reasons that the upgradation of Post Offices depends upon the fulfilment of the prescribed standards and availability of accommodation.

Statement

Sl. No.	Name of the District	Post Offices opened				Post offices proposed to be opened (1978-79)	Estimated Expenditure on establishment
		1976-77		1977-78			
		Targets	Achievements	Targets	Achievements	Targets	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ahmednagar	3	3	11	11	15	22500
2.	Akola	3	2	3	..	5	7500
3.	Amravati	10	9	15	8	10	15000
4.	Aurangabad	5	1	9	6	5	7500
5.	Bhandara	2	..	5	4	15	22500
6.	Bhir	2	2	6	4	10	15000
7.	Buldhana	2	..	3	1	5	7500
8.	Chandrapur	5	2	11	8	30	45000
9.	Dhule	5	4	8	6	40	60000
10.	Jalgaon	..	..	6	1	10	15000
11.	Kolaba	5	3	11	40	40	60000
12.	Kolhapur	5	6	21	15	45	67500
13.	Nagpur	3	3	8	6	20	30000
14.	Nanded	3	..	5	4	15	22500
15.	Nasik	5	6	13	2	30	45000
16.	Osmanabad	5	5	3	4	5	7500
17.	Parbhani	2	..	4	1	10	5000
18.	Pune	5	2	17	19	25	37500
19.	Ratnagiri	25	25	15	15	30	45000
20.	Sangli	4	3	8	8	5	7500
21.	Satara	5	2	27	39	25	37500
22.	Solapur	5	3	5	16	5	7500
23.	Thane	5	5	14	28	55	82500
24.	Wardha	5	4	4	..	15	22500
25.	Yeotmal	7	5	4	..	15	22500
26.	Bombay	..	..	..	..	..	..
	TOTAL	126	95	236	246	485	7,27,500,000

ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रशिक्षित डाक्टरों को प्रशिक्षण देना

8374. श्री ग्र सेन चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रशिक्षित डाक्टरों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रबन्ध करने का विचार है, जिससे वे ग्रामीण लोगों की बेहतर रूप से सेवा कर सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : जी नही, ऐसा कोई प्रस्ताव नही है ।

Telephone complaints in Delhi, Madras, Calcutta and Bombay

8375. SHRI KANWAR LAL GUPTA Will the Minister of Communications be pleased to state:

(a) the number of telephone complaints during January, February and March, 1978 in Delhi, Madras, Calcutta and Bombay received by Government from the consumers;

(b) the number of complaints category-wise;

(c) in how many cases complaints were not removed in one week, in the month and in three months separately;

(d) how many officers were suspended during this period in these four cities;

(e) how many telephones were disconnected in this period for non-payment of dues in these four cities; and

(f) what new steps have been taken in this period to improve the service?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) to (c). The information is being collected.

(d) Gazetted officers—nil

(e)

	Jan. '78	Feb '78	March '78
Bombay	3,202	4,150	5,100
Calcutta	11,110		6,393
Delhi	2,069	1,940	2,496
Madras	1,400	978	1 058

(f) The important steps taken are as follows:—

(i) Systematic check of the exchange equipment.

(ii) periodic check of the performance of exchanges by service quality observation tests:.

(iii) Reducing congestion in various exchanges by expanding the capacity of telephone system.

(iv) Upgradation of crossbar exchanges to improve their performance.

(v) Overhaul of subscribers' telephone instruments and fittings to bring them to proper working condition:

(vi) Gas pressurisation of primary and joint cables.

Facilities in Kingsway Camp T. B. Hospital, Delhi.

8376. SHRI SHIV SAMPATI RAM: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the woeful lack of facilities at Kingsway T. B. Hospital, Delhi; and

(b) the steps taken to improve the situation in the interest of the health of the people?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). The Govt. has been seized of the lack of facilities at the Rajan

Babu T. B. Hospital, Kingsway Camp. The hospital is under the administrative control of the Municipal Corporation of Delhi. The shortage of medical and para-medical staff has been noted and the Corporation would be requested to provide the adequate staff in this regard.

S. C. and S. T. Employees in the Lok Nayak Jai Prakash Hospital

8377. SHRI MAHI LAL. Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) total number of Nurses, Staff Nurses, Sisters, Matrons, Asstt. Nursing Superintendents, Nursing Superintendents separately in Lok Nayak Jai Prakash Hospital New Delhi and the number out of them belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in each category separately;

(b) whether quota reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is complete in all categories; and

(c) if not, the reasons therefor and special steps taken or being taken to fill the back log?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV

(a)

Category	Total No. of posts	Scheduled Caste	Scheduled Tribe
(i) Matron	1	..	..
(ii) Nursing Superintendent	1	..	..
(iii) Asstt. Nursing Superintendent	10	..	..
(iv) Nursing Sister	70	2	2
(v) Staff Nurse	427	3	..

(b) No, Sir.

(c) The reasons for shortfall in the quota reserved for Scheduled Castes/Scheduled Tribes is non-availability of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes with the requisite qualifications. While sending requisition to the Employment Exchange they are requested to sponsor S.C./ST candidates for these posts.

Delhi Administration has been advised to seek the assistance of the Commissioner, SC/ST, the organisations of SC/ST, and also resort to open advertisements to meet the deficiency of SC/ST candidates.

Trade with Gulf Countries

8378. SHRI K. MALLANNA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether trade between India and the Gulf countries is not progressing satisfactorily because of inadequate staff posted in the Indian Embassies in those countries; and

(b) if so, what remedial steps Government have taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU) : (a) Trade with Gulf countries has progressed steadily in recent years. Exports for the year 1976-77 amounted to almost Rs. 538 crores while imports rose to Rs. 968·17 crores. The increase in imports was mainly due to quadruplication of petroleum prices.

This underscores the need for a continued export drive which is in full force. The increase in exports, together with greater Indian participation in developmental programmes and projects, has led to a great increase in the work of our Missions warranting the posting of additional staff. This, however, in itself has not been a constraint in India's endeavours to expand our economic exchanges with this region. There has also been no general complaint of non-cooperation on the part of the staff of our Missions. Individual complaints, as and when received, are looked into.

(b) In view of the large potential which exists in consolidating our rapidly expanding trade and economic relations with these countries, action is being taken to transfer additional personnel to the region and subsequently increase the number of

India-based and local posts in our Missions in this important region. This will enable our Embassies to function more efficaciously in realizing the trade potential, and other possibilities for economic collaboration.

पर्वतीय क्षेत्रों से खनिजों के लिए सर्वेक्षण

8379. श्री भारत भूषण : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पर्वतीय क्षेत्रों में छिपी हुई खनिज सम्पदा की खोज के लिए सर्वेक्षण करने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) और (ख). देश के पर्वतीय क्षेत्रों में सर्वेक्षण करने के लिए कोई अलग योजना नहीं है। लेकिन भूगर्भ सर्वेक्षण एक लगातार चलने वाला कार्य है ; तथा केन्द्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रैमिंग बोर्ड द्वारा अनुमोदित भारतीय भू-सर्वेक्षण के वार्षिक खोज कार्यक्रम में देश के पर्वतीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण भी शामिल होता है। चालू क्षेत्रगत सत्र कार्यक्रम (अक्टूबर, 1977 से सितम्बर, 1978) में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा देश के पर्वतीय क्षेत्रों में, क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक मानचित्रण के अलावा, बाक्साइट, कोयला, चूना-पत्थर, डोलोमाइट, मैगनेटाइट, ग्रेफाइट, सिलीमैनाइट, निकिल, कोबाल्ट, वर्मीकुलाइट, टंगस्टन, आधार धातुओ जैसे खनिजो और खनिज-ईंधनो के लिए अनेक खोजें करने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Guide Lines for withdrawal of Prosecution cases of Provident Fund

8380. SHRI RAM PRAKASH TRIPATHI : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether any guid lines have been laid down for the withdrawal of prosecutions cases launched against defaulters of provident fund dues;

(b) if so, the details thereof · and

(c) whether many prosecution cases were withdrawn recently without bothering about these guide-lines ; and

(d) if so, the details of those cases and the reasons for not adhering to the guide-lines ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAM KRIPAL SINHA) : The Provident Fund Authorities have reported as under : (a) and (b). Yes. The general guide-lines laid down by the Central Provident Fund Commissioner for the withdrawal of prosecution cases launched against defaulters of provident fund dues are :—

(i) the accused should be the offender for the first time and has not been convicted earlier for a similar offence; there should be no other prosecution pending against him;

(ii) the accused should set right all the contraventions for which the complaint was filed,

(iii) his current performance including in the matter of payment of all the dues is uptodate;

(iv) the accused has paid into the Fund the amount of damages due on the amount which remained outstanding for the entire period of default and also reimbursed the legal and other expenses incurred by the Regional Provident Fund Commissioners Offices in connection with the prosecution;

(v) where the employer has not paid the outstanding dues, he is required to offer a Bank guarantee from a Scheduled Bank for the total amount of dues, the probable amount of damages leviable and the legal and other expenses involved. He should also undertake to pay the current dues and the amount of instalments promptly and also to pay the amount if any due in respect of any outgoing member in one lumpsum;

(vi) Where an employer is not able to offer a Bank guarantee but produces collatoral securities for double the amount of dues outstanding and for the damages and legal expenses, he is required to give an undertaking to abide by the conditions relating to promptness in payment of current dues and instalments etc. as specified in the preceding item.

(c) and (d). All cases where the prosecution cases were withdrawn were examined in detail to ensure that these cases by and large fell within the guidelines enumerated above.

Condition of Indian Workers in Iran and other Arab countries

8382. SHRI RAM DHARI SHASTRI: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the press reports appearing in the 'Statesman' dated the 5th April, 1978 that Indian workers going to Iran and other Arab countries have been starving and there is no body to see to their interests;

(b) whether some bogus agencies are engaged in sending Indian labour abroad by offering them allurements and are extorting money from them in the name of bringing them prosperity; and

(c) if so, the names of such companies and remedial action being taken by Government ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA) : (a) No case of starvation of Indian workers has come to the notice of the Government.

(b) and (c). As and when complaints about unauthorised recruitment are received, these are got investigated through appropriate authorities and suitable action taken in the light of the results of investigation.

मैसर्स ए० एच० ह्वीलर के रेलवे बुक स्टालों के एजेंटों द्वारा भूख हड़ताल

8383. श्री रामानन्द तिवारी : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स ए० एच० ह्वीलर के रेलवे बुक स्टालों के एजेंटों ने शोषण और दमन के विरुद्ध रोष व्यक्त करने के लिए और अपनी सात सूत्री मांगों के समर्थन में 12 जनवरी, 1978 से भूख हड़ताल की थी और उनके द्वारा आश्वासन दिये जाने पर 21 जनवरी, 1978 को हड़ताल समाप्त की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उनको क्या आश्वासन दिये गये थे और उन आश्वासनों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) और (ख). रेल मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, मैसर्स ए० एच० ह्वीलर एण्ड कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड, जो रेलवे बुक स्टालों के ठेकेदार हैं, अपने बुक स्टालों को उन द्वारा नियुक्त बुकस्टाल एजेंटों द्वारा प्रबन्ध चलाते है। चार भूतपूर्व बुक स्टाल एजेंटों ने, जिन की एजेंसियां 4 से 10 वर्ष पहले धन के अभिकथित गबन के कारण समाप्त की गई थी, 13 जनवरी से 21 जनवरी, 1978 तक इलाहाबाद में अपने मुख्य कार्यालय के सामने आन्दोलन किया। यह बताया जाता है कि वे सभी उच्च न्यायालयों/निचली अदालतों में कानूनी मामले हार चुके हैं या उनके विरुद्ध न्यायालयों में मामले पड़े हुए हैं। राज्य श्रम मंत्री के कहने पर सहायक श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश ने एजेंटों की शिकायतों की विस्तार से जांच की और अन्त में यह आन्दोलन जनवरी 21, 1978 को वापस ले लिया गया।

प्राइवेट दुकानों को बेची गई केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की दवायें

8384. श्री प्रधान सिंह ठाकुर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि जिन दवाओं पर 'केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य

योजना' लिखा है वे दिल्ली तथा उसके आस पास के नगर में प्राइवेट दुकानो को बेची जा रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जाच करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाली दवाओ के प्राइवेट दुकानो मे बेची जाने की सरकार को कोई सूचना प्राप्त नही हुई है ।

(ख) यह प्रश्न नही उठता ।

Cholera

8385. SHRI MANORANJAN BHAKTA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether a large number of cases of cholera have been reported from J.J. colonies in Delhi recently ; and

(b) if so, the facts and reasons and what steps are being taken by Government to provide necessary medical facilities and to check this epidemic ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) and (b). According to information furnished by Municipal Corporation, Delhi not a single case of cholera has been reported from J .J. colonies in Delhi. However, a number of gastro enteritis cases have occurred in these colonies.

The following preventive steps have been taken by the Municipal Corporation, Delhi against cholera and typhoid :—

(1) Mass inoculation.

(2) Constant testing of water to ensure supply of safe drinking water.

(3) The people have been advised to use boiled water and aviod the taking of exposed foodstuff.

Proposal for Central Coal Washeries Organisation

8386. SHRI D. AMAT : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration with Government to form a Central Coal Washeries Organisation to ensure adequate supply of coal to the steel plants; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Construction of Post Office Building at Jamnagar

8387. SHRI VINODBHAI B. SHETH: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it is true that the present old Post Office Building at Jamnagar is to reconstructed;

(b) if so, what alternative temporary accommodation has been arranged, if yes, whether possession taken, if not, reasons therefor; and

(c) when the reconstruction work is to commence and is likely to be completed ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) Yes, Sir.

(b) Out of four offcers of buildings for housing the Jamnagar P. O. temporarily, one building has been found suitable. Executive Engineer, P & T Civil, Ahmedabad has been aksed to assess its rent, after which final decision will be taken expeditiously.

(c) Work is likely to commence this year and is expected to be completed during 1980-81.

गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं

8388. श्री अमर सिंह वी० राठवा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट चिकित्सा सुविधाएं देने का

विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मोटा ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी ;

(ख) कार्यरत स्वास्थ्य केन्द्रो में इस समय उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओ का ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या आदिवासियो मे फैलते हुए मलेरिया और ज्वर को रोकने के लिए कुछ ठोस उपाय किए गए है और यदि हा, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ,

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) आदिवासी खण्डो मे 53 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 11 सहायक स्वास्थ्य यूनिटें, औषधालयों सहित दर्जा बढायें गये सात उप-केन्द्र, 3 गश्ती औषधालय, 2 रेफरल अस्पताल, 25 पलगो वाला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 4 ग्रामीण अस्पताल है । ये 27 लाख आबादी की आवश्यकताओ को पूरा करते है।

वास्तविक व्यय का विवरण इस प्रकार है :

	लाख रु०
1974–75	7 73
1975–76	0.81
1976–77	29.88
1977–78	59 95 लाख रु० की व्यवस्था की गई है।

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ब्लाक के लोगो को रोग-निरोध, स्वास्थ्य सुधार तथा उपचार की सुविधाएं प्रदान करते हैं।

(ग) गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में संशोधित कार्य-योजना के अन्तर्गत निम्न-लिखित कदम उठाये गये हैं :

(1) मलेरिया निगरानी कार्यकर्ता प्रत्येक पखवाडे मे बुखार के रोगियों का पता लगाने के लिए घर-घर जाता है, इन रोगियों के रक्तलेप लेता है और अपने सामने ही संभावित इलाज करता है।

(2) इसी प्रकार बुखार के सारे रोगियो की रक्त लेपे इकट्ठी की जा रही है और चिकित्सा संस्थाओ के माध्यम से उनका इलाज किया जा रहा है।

(3) रोग फैलने के मौसम मे बीमारी की खास परिस्थितियो मे घरों के अन्दर कीटनाशी दवाई का छिडकाव किया जाता है।

(4) छिडकाव की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए छिडकाव कार्य मे पंचायतो को लगाया जा रहा है।

(5) रोगियों का तुरन्त उपचार करने के लिए उन्हे 4-अमाइनोक्वीनोलिन तथा प्राइमाक्विन दी जाती है। जिन क्षेत्रो मे पी० फाल्सी-परम की बहुलता होती है उनमे इलाज के लिए क्लोरोक्विन और डाराप्रिम का इस्तेमाल किया जाता है।

(6) ग्राम पचायतों/अध्यापको को मलेरिया-रोधी कार्यों मे परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की योजना बना ली गई है। बुखार के रोगियो को मलेरिया दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों और स्कूलों के अध्यापकों की सहायता से औषध वितरण केन्द्र और बुखार के इलाज के डिपो खोल दिए गए हैं।

उज्जैन एक्सचेंज में ट्रंक काल टिकटों का उपलब्ध न होना

8389. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उज्जैन डिवीजन के विभिन्न टेलीफोन एक्सचेजो मे ट्रक काल टिकट (फार्म न० पी० एस० टी० 1068) उपलब्ध नही है ,

(ख) यदि हा, तो क्या इसके परिणाम-स्वरूप अनेक गलतिया हो जाने की सम्भावना है और टेलीफोन प्रयोक्ताओ को भार वहन करना पडता है, और

(ग) क्या फार्म काफी समय मे उपलब्ध नही है और यदि हा, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) जी नही ट्रक काल टिकट (पी० एच० टी० 1068) उपलब्ध है ।

(ख) प्रश्न ही नही उठता ।

(ग) इन फार्मों की सप्लाई दिसम्बर, 1977 के बाद कुछ समय के लिए कम रही थी । अब ये फार्म छपवा लिए गए है और सम्बन्धित एक्सचेजो को सप्लाई कर दिये गए हैं ।

टेलीफोन कनेक्शन के लिए जमा कराई गई राशि पर ब्याज का भुगतान

8290. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय लागू नियमो के अनुसार जो व्यक्ति नये टेलीफोन कनेक्शन लेना चाहते हैं उसके लिए 1200 रुपये की राशि जमा कराना अनिवार्य है ,

(ख) क्या उक्त राशि जमा कराने के बाद भी लम्बी अवधि तक टेलीफोन कनेक्शन नही दिये जाते हैं ,

(ग) यदि हा, तो राशि जमा कराने के बाद टेलीफोन कनेक्शन किस अवधि के बाद दिये जाने की आशा होती है, और

(घ) क्या विभाग इस राशि पर कोई ब्याज अदा नही करता है और यदि हा, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) नियमो के अनुसार नए आवेदकों को जिस टेलीफोन एक्सचेंज से टेलीफोन की जरूरत है, उसकी क्षमता के आधार पर ओ० वाई० टी० श्रेणी के मामले मे 5000 रु० 4000 रु० और 3000 रु० और गैर-ओ०वाई०टी० श्रेणी के लिए 1000 रु०, 800 रु० 600 रु० और 400 रु० की अग्रिम जमा राशि का भुगतान करना पडता है ।

(ख) टेलीफोनों की मजूरी प्रतीक्षा सूची मे आवेदकों की बारी के अनुसार दी जाती है । प्रत्येक मामले मे प्राथमिकता की तिथि अग्रिम जमा राशि की अदायगी की तारीख से निर्धारित की जाती है । अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध न होने के कारण कुछ एक्सचेंजों में लम्बी प्रतीक्षा सूचियां है । इसलिए आवेदकों को इन एक्सचेंजों मे अपनी बारी आने के लिए एक लम्बी अवधि तक प्रतीक्षा करनी पडती है ।

(ग) यह निश्चित रूप से नही बताया जा सकता है कि कोई टेलीफोन कनेक्शन कितनी अवधि के बाद दिया जा सकेगा, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि एक्सचेंज मे कितनी अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है, पहले से कितने मामले बकाया पड़े है साज-सामान उपलब्ध है या नही और तकनीकी दृष्टि से टेलीफोन कनेक्शन देना व्यवहार्य है या नही ।

(घ) अग्रिमों जमा की रकम पर जमा करने की तारीख से लेकर टेलीफोन मंजूर करने की तारीख तक उसी दर से ब्याज मिलता है, जिस दर से भारतीय स्टेट बैंक ऐसे बैंकों में एक वर्ष के लिए जमा की गई सावधि जमा की रकमों पर देता है।

Strict Visa conditions for Indians for Iran & Arab countries

8391. SHRI SUKHDEV PRASAD VERMA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government is aware that very recently Arab countries and Iran have imposed strict visa conditions on Indian visitors to these countries;

(b) if so, whether Government has taken up the issue of visa with concerned Governments of such Arab countries and Iran;

(c) if so, the outcome of such correspondences;

(d) whether imposition of such visa conditions has brought about a great set back to various Indians and Indian organisations in the matter of trade promotional activities; and

(e) if so, how Government is contemplating to sort out the issue ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU) : (a) to (e). The Government is aware of the strict visa regulations imposed by Arab countries and Iran to regulate the entry of Indian visitors to these countries, which have sometimes caused difficulties and delay in procuring of visas. All assistance is given to Indians who wish to visit these countries in the matter of trade promotion etc. There appears to be no marked adverse effect in export promotion and other activities as a result of the exiting visa regulations of these countries. From time to time, any specific or general problems regarding issuing of visas are taken up with the countries of the region or with their Missions in India.

Malpractices by private Employment Agencies

8392. SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Will the Minister of PARLIAMENTARY ARRAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) the details of the malpractices in respect of private Employment Agencies that have been brought to the notice of Government during the last two years;

(b) the action taken by Government against these agencies; and

(c) the steps that have been taken till now or proposed to be taken to check the malpractices effectively in this regard ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) to (c). It is presumed that reference is to Employment Agencies which undertake selection of personnel for employment in India. There was a complaint received in 1977 that a private employment agency had invited applications for a certain post and had asked for payment of Rs. 10/- for supply of each application form. In the absence of any criminal intent, it was not an offence to ask for payment for the supply of forms.

Transfer of Telephones

8393. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether telephone subscribers are permitted to transfer their telephones to their relatives;

(b) if so, what are the rules in this regard ;

(c) the number of applications received in Delhi during the last one year for transferring their telephone connections to their close relatives;

(d) the number of applications disposed of and the number of applications pending at present; and

(e) what are the reasons for keeping these applications pending and when these applications will be disposed of ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) Yes, Sir.

(b) During the life time of the hirer, the transfer of telephone may be permitted to near relatives, viz., father, mother, wife, husband, son daughter, brother and sister including step brother and step sister but not cousin. This is irrespective of the category under which the connection was originally obtained provided the period for which the connection has actually worked for the original hirer is not less

than one year and provided also that if the telephone was sanctioned under any priority or special category the original hirer shall not be given any new telephone connection under that particular category within five years of the date of transfer. The transfer is charge Rs. 50/- for each connection.

(c) 143 applications.

(d) 111 applications have been disposed of and 32 are pending at present.

(e) These cases are under process/correspondence with the subscribers for completion of necessary formalities.

हिन्दी सलाहकार समिति का गठन

8394. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय मे हिन्दी सलाहकार समिति का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हा, तो इसके सदस्यों के नाम क्या है और उनमे राजभाषा विभाग की सिफारिशों पर मनोनीत किये गये सदस्यों के नाम और सख्या क्या है ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख). हिन्दी सलाहकार समिति गठित करने का प्रश्न विचाराधीन है :

हिन्दी सलाहकार समिति

8395. **श्री नवाब सिंह चौहान** : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या मंत्रालय मे हिन्दी सलाहकार समिति का गठन कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या हैं और उनमे से उन व्यक्तियों के नाम और उनकी संख्या कितनी है, जिन्हें राजभाषा विभाग की सिफारिश पर नामांकित किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां ।

(ख) समिति का गठन विवरण मे दिया गया है। समिति के सदस्यों में से 5 नाम, जो क्रम सख्या 26 से 30 पर हैं, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने सुझाए थे ।

विवरण

हिन्दी सलाहाकार समिति का गठन

अध्यक्ष

1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

उपाध्यक्ष

2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री

सदस्य

3 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव

4 अपर सचिव (स्वास्थ्य)

5. अपर सचिव (परिवार कल्याण)

6 संयुक्त सचिव (वित्त सलाहकार)

7. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक

8. निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, दिल्ली

9 निदेशक, राष्ट्रीय संचार रोग संस्थान दिल्ली ।

10. निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली

11. चिकित्सा अधीक्षक, विलिंग्डन अस्पताल, नई दिल्ली

12. चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली

13. निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली

14. सचिव, राजभाषा विभाग और हिन्दी सलाहकार, भारत सरकार। सदस्य

15. राज्यभाषा विभाग का प्रतिनिधि सदस्य

संसद् सदस्य

16. डा० भगवान दास राठोर, सदस्य लोक सभा सदस्य

17. श्री गोविन्द मुडा, सदस्य, लोक सभा सदस्य

18. डा० लोकेश चन्द्र, सदस्य, राज्य सभा सदस्य

19. डा०एम०एम० सिद्धु सदस्य, राज्य सभा सदस्य

संस्थाओं आदि के प्रतिनिधि

20. डा० भागेश्वर, काशी विद्यापीठ, वाराणसी सदस्य

21. डा० मलिक मोहम्मद, प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, कालीकट विश्व-विद्यालय सदस्य

22. डा० रघुवश, प्रयाग विश्वविद्यालय, इलाहाबाद सदस्य

23. श्री राजेन्द्र अवस्थी, सपादक, कादम्बिनी, दिल्ली सदस्य

24 श्री नर सिंह पण्डित, हिन्दी विद्यापीठ, वैद्यनाथ, देवघर सदस्य

25. डा० कुमार विमल, पटना सदस्य

26. डा० आत्म प्रकाश, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली सदस्य

27. डा० आर० के० मिश्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान सस्थान, नई दिल्ली। सदस्य

28. श्री लल्लन प्रसाद व्यास, नई दिल्ली सदस्य

29. डा० विश्वनाथ अय्यर, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग कोचीन विश्व-विद्यालय, कोचीन सदस्य

30. रंजित शिव शर्मा, बाहारिस्तान, 9-ए, ब्रोमन पेटिट रोड, कम्बाला हिल, बम्बई। सदस्य

सदस्य-सचिव

31. संयुक्त सचिव (प्रशासन) सदस्य सचिव

लाठ गांव में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

8396. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल :** क्या संचार मंत्री जूनागढ, राजकोट तथा जामनगर जिलो में टेलीफोन एक्सचेंजो की स्थापना के बारे मे 9 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न सख्या 2249 के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गुजरात मे सौराष्ट्र क्षेत्र के राजकोट जिले मे उपलेटा तालुक के लाठ गाव के लगभग 18 व्यक्तियों मे से प्रत्येक ने टेलीफोन कनेक्शनो के लिए दिसम्बर, 1977 मे 800 रुपये जमा किए थे और क्या इस बारे मे एक आवेदन लाठ ग्राम पचायत ने मार्च, 1978 मे अहमदाबाद, राजकोट और धोलाजी आदि मे प्राधिकारियो को भेजा था ; और

(ख) यदि हा, तो लाठ गाव में टेली-फोन एक्सचेज की स्थापना और वहा के निवासियो के लिए टेलीफोन कनेक्शनो की व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय): (क) जी हां। 16 व्यक्तियो ने दिसम्बर, 1977 मे और दो व्यक्तियों ने जनवरी 1978 मे आठ-आठ सौ रुपये जमा कराए थे। लाठ ग्राम पंचायत का एक पत्र भी मार्च मे प्राप्त हुआ था।

(ख) आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान यह एक्सचेंज चालू हो जाएगा और कनेक्शन दे दिए जाएंगे।

गांव सिताना, जिला जूनागढ़ को टेलीफोन कनेक्शन

8397. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र मे जिला जूनागढ़ के सिताना गाव मे माणावदर तालुक पचायत के अध्यक्ष के निवास पर टेलीफोन कनेक्शन के लिए माणावदर तालुक पचायत कचहरी ने कितनी राशि जमा की है, और यह राशि कब और कहा जमा कराई गई है, और

(ख) वहा अभी तक टेलीफोन न देने के क्या कारण है और वह कब तक लगाया जायेगा, और

(ग) क्या 4 जनवरी, 1978 को माणावदर तालुक पचायत कचहरी ने अहमदाबाद तथा जूनागढ मे टेलीफोन विभाग का पत्र लिखा था, और यदि हा, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) कुल 3750 रु० की रकम नीचे लिखी तारीखों को बाटवा डाकघर मे जमा कराई गई थी :—

(1) 1000 रु० 1–7–76 को

(2) 750 रु० 6–7–77 को

(3) 2000 रु० 21–11–77 को

(ख) टेलीफोन कनेक्शन-एक्सचेज से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर मागा गया है और इसके लिए भारी मात्रा मे लाइन सम्बन्धी साज-सामान की जरूरत है। इनकी व्यवस्था की जा रही है और ऐसी संभावना है कि करीब दो महीने के समय मे टेलीफोन दे दिया जाएगा।

(ग) जी हा। माणावदर तालुका पचायत के अध्यक्ष ने अपने तारीख 3–1–78 के पत्र मे टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए प्रार्थना की थी और यह कहा था कि पचायत जनोपयोगी सेवा के लिए है और टेलीफोन की माग विकास कार्यों के निष्पादन मे सुगमता लाने के लिए है।

विलिंगडन और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रोगियों की रिकार्ड सम्बन्धी फाइलें

8398. **श्री हरगोविन्द वर्मा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार अस्पतालों (विलिंगडन अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान सस्थान) मे रोगियो के रिकार्डों वाली फाइलें आमतौर पर गुम रहती है,

(ख) यदि हा, तो विगत तीन वर्षों के दौरान कितनी फाइलें दोबारा तैयार की गई थी, और

(ग) क्या इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारियो के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी, और यदि हा, तो उसका स्वरूप क्या है, और यदि नही, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) विलिंगडन अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान सस्थान मे रोगियों के रिकार्ड आमतौर पर गुम नही होते है। छुट-पुट मामलों मे जब ये रिकार्ड गुम पाए जाते हैं, तो उचित कार्यवाही की जाती है।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

Retrenchment of workers of Bailadilla Iron Ore Mines.

8399. SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that retrenchment notices have been served to thousands of workers of Bailadilla Iron Ore Mines in Madhya Pradesh;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the workers of the said Iron Ore Mines are on a strike demanding the withdrawal of the retrenchment order; and

(d) if so, the details and Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) and (b). In view of the conclusion of their contract on 31-3-1978, M/s. Ashok Mining Company, one of the Contractors supplying manually mined iron ore in the Bailadilla area, had served notice of retrenchment to their workers. Out of 1375 workers with M/s. Ashok Mining Company on 31-3-1978, about 1327 workers had received their retrenchment benefits between 1st and 3rd April, 1978.

(c) Workers of Bailadila Iron Ore Mines are not now on strike.

(d) Does not arise.

मंत्रालय में भ्रष्ट अधिकारी

8400. **श्री हुक्म देव नारायण यादव :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के ऐसे अधिकारियों की, श्रेणीवार, कुल संख्या कितनी है जिन पर गत तीन वर्षों में भ्रष्टाचार और गोलमाल करने के आरोप लगाए गए हैं; और

(ख) कितने अधिकारियों को सजा दी गई और कितनों को दोषमुक्त किया गया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (1) अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :—

	1975	1976	1977
(क) उन अधिकारियों की संख्या जिनके विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं :—			
राजपत्रित	1	—	—
अराजपत्रित	—	5	—
(ख) 1. उन अधिकारियों की सख्या जिन्हें सजा दी गई है :—			
राजपत्रित	—	—	—
अराजपत्रित	—	*—	—
*तीन मामले अभी विचाराधीन हैं।			
2. उन अधिकारियों की सख्या जिन्हें दोष-मुक्त किया गया है :—			
राजपत्रित	1	—	—
अराजपत्रित	—	2	—

Sons of the Soil.

8401. SHRI A. K. ROY:
SHRI MADHAVRAO SCINDIA:

Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether the Ministry's attention has been drawn to the proposition "Sons of the Soil" call by Shri Raj Narain while presiding over a function of the Indian Telephone Institute Complex at Rai Bareilly; and

(b) if so, whether Ministry agrees with the definition of the "Sons of the Soil" put forward by Shri Raj Narain a Cabinet Minister for its application all over India and if not, why not ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) Government have seen certain newspaper reports in this regard.

(b) This is a matter in which the constitutional right of a citizen to work in any part of India has to be reconciled with the right of local persons to find adequate employment opportunities.

S.C./S.T. Employees in Steel and Mines.

8402. SHRI R. N. RAKESH: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) total number of posts filled in each category of posts with specific shares of S.C. & S.T. in such employment in his Ministry, its attached and subordinate offices including public undertakings if any, for the entire period of Janata regime and also the number of posts de-reserved in each category and reasons thereof; and

(b) total number of departmental promotions/upgradation of posts in each category of posts and how many posts have gone to S.C. & S.T. ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) and (b). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Grant of contracts Licence to S. C. and S. T.

8403. SHRI R. N. RAKESH: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) the total number of contracts/Licences granted by the Ministry, its attached and subordinate offices including the public sector undertakings if any, for the entire period of Janata Government regime and the share thereof, if any, to S, C. and S. T. in each category of such contracts/licences; and

(b) if not, why?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) and (b). Contracts are not awarded on consideration of caste but on the basis generally of the highest or the lowest bid depending upon the nature of the contract, whether for sale or purchase. It is also not the practice to maintain statistics about the award of contracts, by SC/ST.

Industrial licences are granted by the Ministry of Industry, Department of Industrial Development in accordance with the proced ure prescribed in the guidlines. It does not take into account the caste of the applicant, nor does it require maintenance of any record of caste of the licences.

R.M.S. Rest House, Calcutta

8404. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased so state :

(a) whether the RMS Rest House of Bihar at 156 M. G. Road, Calcutta is located in a building which is an old requisitioned premises and the period of requisition is valid upto 1980 ;

(b) whether there has been a demand from the staff and their service Union for shifting of the said RMS. Rest House from the present location to elsewhere ;

(c) whether there is a serious proposal to construct a multi-storeyed 'RMS BHAVAN' at the site of old Bara Bazar P. O. ; and

(d) whether the P. &. T. Department is paying Rs. 1500/- per month as rent both for office and RMS Rest House, at present and on shifting of the RMS Rest House alone it would have to pay at least Rs. 15,000/- P. M. ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTERY OF COMMUNICATION (SHRI NARHARI PRADESH SUKHDESN SAI). (a) and (b) : Yes, Sir.

(c) and (d) : The condition of the present Rest House is not satisfactory. The case for hiring alternative accommodation near Howrah Railway Station or for constructing a Departmental Rest House at the sit of the old Bazar Post office under examination.

The rent for the present building which accommodates the Rest House and the Sub Record Office is Rs. 1500/-per mensem. The P&T Department does not propose to hire accomodation for the Rest House at 15,000/- per mensem.

COMMUNICATION FROM U.S.A. RE. SUPPLY OF ENRICHED URANIUM FOR THE TARAPUR ATOMIC PLANT

8405. SHRI HARI VISHNU KAMATH : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIR be pleased to state:

(a) whether Governmnt have received any official communiction or intimation from the Government of U.S.A regrding the supply of enriched uranium for the Tarapur Atomic Power Plant:

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether and strings. visible, or otherwise are attached to the supply ;

(d) whether future supplies have also been assured; and

(e) if the asnwer be in the negative, what alternative arrangements are being made?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU). (a) to (e) : while Government have received no official communication from the Government of the U.S.A. recently regarding the supply of enriched uranium, for the Tarapur Atomic Power Station,attention is invited to the Prime Minister's statement made in the Lok Sabha on the 25th April, 1978, relating to this subject.

PRIME MINISTER'S VISIT TO U.S.A.

8406. Prof. P.G. MAVALANKAR : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Prime Minister is visiting the U. S. shortly on an official invitation;

(b) if so, broad details thereto;

(c) whether he is also, while in U.S.A. attending and addressing the UN General Assembly's Special Session on Disarmament; and

(d) if so, when ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTERY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU). (a) Yes, Sir.

(b) to (d): The Prime Minister is expected to reached New York on 8th June 1978 afternoon and address the Special Session on Disarmament of the U.N. General Assembly in the morning of 9th June. He will be in United Stated till 15th June. The details of the Prime Minister's programme during his visit to U.S.A. are still being worked out.

Central Council for Research in Indian Medicare and Homoeopathy

8407. SHRIMATI MRINAL GORE: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Central Council for Research in Indian Medicine and Homeopathy is being split up into four research Councils, if so the reasons therefor and the budget allocation for each Council and the areas/fields where duplication of expenditure is involved;

(b) whether Government have already set up a High Power Committee to review the working of Central Council for Research in Indian Medicine and Homotopathy and if so, whether the recommendations of the Committee were taken into account while deciding the splitting of the Council, if not, the reasons therefor;

(c) whether this has the approval of Government being a major policy decision;

(d) whether it is a fact that when the Members of the proposed Councils met, their signatures were obtained on the memorandum of Associaton even before discussing the Agenda; and

(e) how far the present employees will be affected with reference to service conditions like seniority, scale of pay, promotion and benefit of past service and what will be the effect on the sanctioned strength of the employees?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE) SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Taking into account the fact that research in the various traditional systems of medicine under a single Council has not achieved the desired results, it has been decided to reorganise the Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy into four Councils, indicated below :—

1. Central Council for Research in Ayurveda and Siddha.
2. Central Council for Research in Unani Medicine.
3. Central Council for Research in Homoeopathy.
4. Central Council for Research in Yoga and Naturopathy.

An amount of Rs. 187·14 lakhs has been allocated, during 1978-79 to the existing Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy but this amount will be distributed amongst the four new Councils after taking into account the requirements of each of the Councils, before these Councils start functioning. No duplication of expenditure is likely to be involved in any area/field.

(b) Yes. The Committee was constituted mainly to evaluate the research work done by the Institutes/Centres/Units under the Council to ascertain if the research work is commensurate with the funds provided, to point out the reasons for impediments in the implementation of research programmes, to suggest methods for streamlining, accelerating and consolidating the research programmes and to suggest effective management of the Council, economically. Since the object of the constitution of the Committee did not relate to the splitting up of the existing Council, the question of taking into account the recommendation of the Committee, while reorganising the C.C.R.I.M.H., does not arise. However, the recommendations of the Committee as and when available, will be useful for all the four new Councils, in organising their research programmes in an effective and purposeful manner.

(c) As the proposal for reorganising the existing Council relates to the reorganisation of an existing registered Society it is not necessary to obtain the Cabinet's approval.

(d) No. The Memorandum of Association was signed by the Members after detailed discussion on the proposal for splitting up of the Council as well as about the contents of the Memorandum of Association.

(e) Steps have been taken to ensure that the interests of the employees of the Council are safeguarded and all the existing employees are absorbed in the proposed Councils.

भारत आयरलैण्ड सहयोग

8408. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और आयरलैण्ड के बीच दोनों देशों मे और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर बहुत से क्षेत्रों मे सहयोग बढाने के लिए कोई निर्णय किया गया है,

(ख) आर्थिक क्षेत्रों मे किये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का पूरा ब्यौरा क्या है, और

(ग) निरस्त्रीकरण के बारे मे भारत और आयरलैण्ड के बीच हुई बातचीत पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जनवरी मे आयरलैण्ड के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान आयरलैण्ड के विदेश मंत्री के साथ हुए विचार-विमर्श मे बहुत से विषयो पर भारत और आयरलैण्ड के बीच विचारो की निकट समानता और भारत-आयरलैण्ड सहयोग को सुदृढ करने मे हम दोनों की पारस्परिक रुचि प्रकट हुई ।

(ख) आर्थिक क्षेत्र मे किन्ही ठोस प्रस्तावों पर विचार-विनिमय नही हुआ था ।

(ग) दोनों पक्षों के बीच बहुत से विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ जिसमें निरस्त्रीकरण भी शामिल है । इसे लाभप्रद माना गया है ।

C.G.H.S. Homoeopathic Dispensary, Gole Market, New Delhi

8409. SHRI D.G. GAWAI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the question of converting the CGHS Homoeopathic Dispensary located at Gole Market, New Delhi as functional dispensary was under consideration of Government;

(b) if so, the decision taken in the matter and when the proposal is likely to be implemented; and

(c) in case no decision has been finalised so far, the reasons for delay and when a decision is likely to be taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) to (c). The question of providing emergency services during the off hours in the day time in one of the Homoeopathic Dispensaries under the C.G.H.S. Delhi is under consideration. A decision in the matter is likely to be taken shortly.

Schemes for Medical Privileges for Blood Donors

8410. PROF. P. G. MAVALANKAR: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that some countries in the world are having schemes of medical privileges for regular blood donors;

(b) if so, broad details thereto;

(c) whether Government propose to initiate and implement such a scheme in India;

(d) if so, when and how; and

(e) if not, why not?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). The information is being collected through W.H.O. and will be laid on the Table of the Sabha.

(c) to (e). The Government will duly consider introduction of a suitable scheme in this regard in consultation with the State Governments on receipt of information at (a) and (b) above.

Administration of Separate Telephone Districts

8411. PROF. P.G. MAVALANKAR: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether certain cities like Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad, etc. are having separate Telephone Districts with separate administrations;

(b) if so, full facts thereof;

(c) whether the said Telephone Districts administration function independently of the State Circles of the particular areas;

(d) if so, the reasons therefor; and

(e) whether such separate units lead to greater cost and more elaborate administrations?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) Yes, Sir.

(b) At present, there are seven cities having separate telephone Districts with administrations under General Managers, viz., Delhi, Bombay, Calcutta, Madras, Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad.

(c) Yes, Sir.

(d) and (e). When a telephone system of a big city reaches the equipped capacity of 25,000 lines and above, a major telephone district is formed. The requirements and features of planning, control of operations, maintenance, revenue collection network engine ering, etc. are such that the administration of these large systems can be efficient and effective only if it is kept independent of State Telecom. Circle which has a heavy load of its own work.

Constitution of Telephone Advisory Committee

8412. PROF. P. G. MAVALANKAR: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether the Telephone Advisory Committee in various cities and/or regions have been constituted;

(b) if so, full details thereof, including names of personnel, their duration of terms etc.;

(c) whether Ahmedabad city has been served with such a Committee and if so, by which personnel and since when and for how long, and

(d) if not, why not ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) (a) Out of 50, 21 Telephone Advisory Committees have already been constituted and the rest are under consideration

(b) The information as asked for is given in the Statement laid on the Table of the House [*Placed in Library See* No LT-2210/78]

(c) Yes Sir Details of Ahmedabad T A C is given at Sl No 20 of the Statement laid on the Table of the House [*Placed in Library See* No LT-2210/78]

(d) Does not arise

आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली

8413. डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि सरजरी के मामले मे आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली से कम विकसित मानी जाती है, और

(ख) यदि हा, तो आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली मे सरजरी को बढावा देने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है और यदि कोई कार्यवाही नही की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) आयुर्वेद मे सरजरी को शल्य तंत्र कहा जाता है। शल्य तंत्र का विकास करने के अभिप्राय से भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद् द्वारा तैयार की गई तथा भारत सरकार द्वारा देश भर मे समान रूप से कार्य-रूप देने के लिए अनुमोदित की गई स्नातक पूर्व शिक्षा की पाठ्यचर्या और उसके पाठ्य-क्रम के प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद् ने स्नातकोत्तर अध्ययनो और शल्य तंत्र मे प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम स्तर और पाठ्यचर्या भी तैयार कर ली है।

इस समय, शल्य तंत्र का स्नातकोत्तर प्रशिक्षण भारतीय चिकित्सा के स्नातकोत्तर संस्थान, आयुर्विज्ञान संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी मे दिया जा रहा है जिसके उपरांत "आयुर्वेद चिकित्सा मे डाक्टोरेट" की उपाधी दी जाती है। इस संस्थान के शल्य तंत्र विभाग मे भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् की सहायता से आयुर्वेदीय सिद्धातो के अनुसार शल्य क्रिया सम्बन्धी अनेक समस्याओ मे अनुसंधान कार्य भी किया जा रहा है। भगन्दर के आपरेशन पर किए गए अनुसंधान कार्य के उत्साहवर्धक परिणाम निकले है।

आफिस इक्विपमेंट कम्पनी आफ इंडिया, बम्बई की ओर भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया राशि

8414. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों मे अर्थवार, आफिस इक्विपमेंट कम्पनी आफ इण्डिया, 10—सी तुलसी पाइप रोड, महालक्ष्मी, बम्बई-13 की ओर भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा मे श्रमिकों के अंशदान की कितनी राशि बकाया है तथा इसे वसूल करने के लिए

अब तक क्या कार्यवाही की गई है और यदि नही , तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सूचित किया है कि नियोजक ने जनवरी, 1978 को समाप्त होने वाली अशदान अवधि तक अशदान कार्डों को भेज कर अशदान की राशि अदा कर दी है। ये कार्ड 11 मार्च, 1978 तक जमा कराए जाने थे। तथापि, फैक्टरी के रिकार्डों के निरीक्षण के परिणामस्वरूप पता लगाई गई 78 /–रु की राशि का भुगतान नियोजक द्वारा किया जाना है और इस राशि की अदायगी के लिए नियोजक को पहले ही कहा गया है। भविष्य निधि प्राधिकारियो ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1975--76 से 1977–78 तक के सम्बन्ध मे प्रतिष्ठान की ओर भविष्य निधि की कोई देय राशि बकाया नही है।

शाहूहाल इंजीनियरिंग वर्क्स, बम्बई पर भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया राशि

8415. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों मे वर्षवार शाहूहाल इजीनियरिंग वर्क्स, 10–सी, तुलसी पाइप रोड, महालक्ष्मी, बम्बई–13, पर कर्मचारियो की भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा के अशदान की कितनी धनराशि बकाया थी और उसकी वसूली के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है और यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : कर्मचारी राज्य बीमा प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि शाहूहाल इंजीनियरिंग वर्क्स, बम्बई के नाम का कोई कारखाना /प्रतिष्ठान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन पजीकृत नहीं है। तथापि, सोहाल इजीनियरिंग वर्क्स, भानरूप नाम का एक कारखाना है जिसका 10–सी, तुलसी पाइप रोड, महालक्ष्मी, बम्बई–13 मे एक और यूनिट भी है। सोहाल इजीनियरिंग वर्क्स के ये दोनो यूनिट कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन आते हैं और उन्होने नवम्बर, 1976 को समाप्त होने वाली अशदान अवधि तक के अशदानो का भुगतान कर दिया है। तथापि, उन्होने जनवरी, 1977 को समाप्त होने वाली अवधि से आगामी अवधि के अशदानो का भुगतान नही किया है। जनवरी, 1977 से जुलाई, 1977 की अवधि के सम्बन्ध मे 27027 रुपये के अशदानो की राशि के दावे का नोटिस नियोजक को दिसम्बर, 1977 मे जारी किया गया था, जो मिले बिना वापस आ गया। उक्त राशि का आवश्यक वसूली प्रमाणपत्र भूमि राजस्व की बकाया राशि के रूप से वसूल करने के लिए जारी किया जा रहा है। शेष अवधि के सम्बन्ध मे मामले की जाच की जा रही है। नियोजक पर पहले वर्ष, 1976 मे अभियोजन चलाया गया था और एक और अभियोजन 9 मार्च, 1978 को दायर कर दिया गया है।

भविष्य निधि प्राधिकारियो ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1975–76 से 1977–78 के सम्बन्ध मे प्रतिष्ठान के और भविष्य निधि की कोई देय राशि बकाया नही है।

हैमिल्टन इंडस्ट्रीज, बम्बई पर भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया राशि

8416. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के वर्षवार

हैमिल्टन इंडस्ट्रीज, प्राइवेट लिमिटेड 10–सी तुलसी पाइप रोड, महालक्ष्मी, बम्बई-13 पर कर्मचारियों की भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा के अंशदान की कितनी धनराशि बकाया थी और उसकी वसूली के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सूचित किया है कि नियोजक ने जनवरी, 1978 को समाप्त होने वाली अंशदान अवधि तक अंशदान कार्डों को जमा करा कर अशंदान की राशि अदा कर दी है। ये कार्ड 1 मार्च, 1978 तक जमा कराये जाने थे । भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1975–76 से 1977–78 तक के सम्बन्ध में प्रतिष्ठान की ओर भविष्य निधि की कोई देय राशि बकाया नहीं है ।

लोहे के मूल्य

8417. **श्री ईश्वर चौधरी :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री जी० एम० बनतवाला :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1975 की तुलना में इस समय लोहे के मूल्य कितने न्यूनाधिक हैं ;

(ख) क्या मार्च, 1977 के बाद लोहे के मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो लोहे के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) कच्चे लोहे (फाउण्ड्री ग्रेड एच० एम० –4) का स्टाकयार्ड मूल्य 914/- रुपये प्रति मी० टन है जबकि मार्च, 1975 में इसका मूल्य 840/– रुपये प्रति मी० टन था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

India Indonesia Cultural Links

8418. SHRI SAMAR GUHA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is fact that the Bali Island of Indonesia provides a big link for cultural relations between India and Indonesia;

(b) if so, whether any office of our Mission in Indonesia has been set up in Bali Island;

(c) if so, the facts thereabout;

(d) whether diplomatic mission has undertaken activities there to directly and indirectly, encourage strengthening of cultural relations between India and Indonesia; and

(e) if so, the facts thereabout ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU): (a) Cultural contacts between Indonesia and India have existed for many years and Bali island, which is a part of Indoenesia, is a notable example of such traditional links with India.

(b) and (c). We do not have a separate consulate in Bali. Cultural contacts with Bali are the responsibility of the Indian Embassy in Djakarta.

(d) and (e). Visiting dignitaries have been invited to visit Bali, and a troup of Indian puppeteers performed in Bali last year. The Bali Santi Sena Foundation is being encouraged to translate books on or by Mahata Gandhi. The Hindu Parishad and the Institute of Hindu Dharma, which is recognised locally as a University, is being assisted by us with books, etc.

Kashmir

8419. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the Statement made by Shri Agha Shahi Foreign Affairs Adviser to the Government of Pakistan on 19-3-78 to the effect that "U.N. resolution on Kashmir as not obsolete", and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU): (a) Yes, Sir.

(b) Government feels that the question of Jammu and Kashmir should be discussed bilaterally, in accordance with the letter and spirit of the Simla Agreement.

Malfunctioning of Telephones of M.Ps

8420. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government have received complaints about the mal-functioning of the telephones installed at the residences of the Members of Parliament in Delhi; and

(b) if so, what steps Government have taken to bring about an improvement in the functioning of these telephones?

THE MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) Yes, Sir. Only 8 complaints were received.

(b) All the telephones working at the residences of the M.Ps. have been inspected, the outdoor and indoor plants checked thoroughly and defects found rectified. There is, however, some difficulty due to overloading of two exchanges from which M.Ps. are mainly served. A proposal for reducing overloading of these exchanges by transferring some areas to Jorbagh is under consideration.

Ferro-vanadium plant in Rairangpur of Mayurbhanj district of Orissa

8421. SHRI PRADYUMNA BAL: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the ferro-vanadium plant proposed to be established at Rairangpur of Mayurbhanj District of Orissa as a Central sector core project has not been entrusted to the Orissa State Government;

(b) the project cost estimated earlier and the project cost estimated to reach now;

(c) the particular reasons for the Central Government not establishing it as a Central sector core project;

(d) whether Mayurbhanj is the notified backward District;

(e) if so, whether the proposed plant qualifies for concessional finance including 15 per cent outright subsidy, and

(f) what other assistance proposed to be provided by the Centre to the State Government for the said plant?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) and (c). Following detailed examination of the proposal of the Government of Orissa to set-up a ferro-vanadium plant a decision was taken that its implementation may be undertaken by the State Government as an export oriented project linked to technical and financial assistance from abroad. Government are, however, examining the technical and financial viability of the project related to the possibility of securing long-term exports of the ferro-vanadium production, irrespective of whether the project is taken up in the State or in the Central sector.

(b) The project cost initially estimated at Rs. 16 crores is now estimated at Rs. 18·50 crores based on 1975 prices.

(d) and (e) The proposed location of the plant near Rairangpur in the notified backward district of Mayurbhaj in Orissa would qualify for concessional finance, including 15% subsidy limited to Rs. 15 lakhs.

(f) The question of providing other assistance by the Centre to the State Government for establishment of the said plant would arise only after an investment decision has been taken.

राजभाषा क्रियान्विति समिति के अधिकारियों की बैठकें

8422. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय/विभाग में राजभाषा क्रियान्विति समिति का गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1977 में उक्त समिति की किन-किन तारीखों को बैठकें हुईं और उनमें क्या-क्या निर्णय लिये गये ;

(ग) उनमें से कितने निर्णयों को पूरी तौर से क्रियान्वित किया गया; और

(घ) शेष निर्णयों की क्रियान्विति में विलम्ब के क्या कारण है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) इस समिति की बैठक 11 अगस्त, 1977 को हुई थी। जो निर्णय लिए गए, उनमें से अधिक महत्वपूर्ण निर्णय ये थे :—

(i) हिन्दी टाइपिंग में प्रशिक्षित किए जाने के लिए और अधिक कर्मचारियों को भेजना।

(ii) हिन्दी का प्रयोग कर सकने के लिए और अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।

(iii) प्रत्येक कार्यालय (सलग्न और अधीनस्थ) में हिन्दी सम्बन्धी काम करने के लिए कम से कम एक पद सृजित करना।

(iv) हिन्दी के प्रयोग में की गई प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए कार्यालयों का निरीक्षण करना; और

(v) हिन्दी में भेजे गए पत्रों का पूरा-पूरा रिकार्ड रखना।

(ग) और (घ). इस समिति द्वारा लिए गए 14 निर्णयों में से 10 निर्णयों को पूर्णत: कार्यान्वित कर दिया गया या आगामी कार्यवाही करने के लिए नोट कर लिया गया और चार निर्णय कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

मंत्रालय में उपयोग में लायी जा रही नियम पुस्तिकायें / फार्म

8423. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय/विभाग मे कुल कितनी नियम पुस्तिकायें तथा फार्म उपयोग में लाये जा रहे हैं ;

(ख) उनमे से कितनों का हिन्दी में अनुवाद किया जा चुका है और कितने द्विभाषी रूप मे प्रकाशित किये गये है,

(ग) उनमे से शेष का अनुवाद न करने तथा द्विभाषी रूप में प्रकाशित न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) उन्हे द्विभाषी रूप मे कब तक प्रकाशित किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) 44 नियम-पुस्तिकाएं (मैनुअल) और 1700 से कुछ ज्यादा फार्म।

(ख) 20 नियम-पुस्तिकाओं का अनुवाद हो चुका है, 5 द्विभाषिक रूप मे छप गई हैं और 4 छापी जा रही है। 10 हिन्दी मे अलग से छापी गई है और शेष एक का पुनरीक्षण हो रहा है। इसके अलावा 13 नियम-पुस्तिकाओं का अनुवाद हो रहा है।

मानक फार्मों में से, 600 फार्म जरूरी हैं । इन जरूरी फार्मों मे से 581 का अनुवाद हो चुका है, 575 दो भाषाओं मे छापे जा रहे है और शेष 6 का पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

बाहरी देशों के साथ सम्पक में प्रयोग आने वाले विश्व डाक संघ के 24 फार्म केवल फ़ासीसी और अंग्रेजी में छापे जाते हैं ।

शेष गैर-जरूरी फार्मों में से 246 का अनुवाद हो चुका है और 157 दो भाषाओं में छापे/साइक्लोस्टाइल किये जा चुके है और शेष को छापा / साइक्लोस्टाइल किया जा रहा है ।

(ग) और (घ). शेष नियम-पुस्तिकाओं और फार्मों को यथाशीघ्र द्विभाषिक करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

संयुक्त राज्य अमरीका में भारत के प्रचार का करार

8424. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के प्रचार के लिए किसी प्रचार एजेंसी अथवा किसी विशिष्ट व्यक्ति को ठेका दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी शर्तें क्या हैं और जिस फर्म और व्यक्ति को करार दिया गया है, उसका नाम क्या है और वह कब दिया गया था; और

(ग) 9 जनवरी, 1970 से 31 मार्च, 1977 की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा उक्त फर्म अथवा व्यक्ति को कितनी धनराशि दी गई ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) और (ख). वाशिंगटन स्थित हमारे राजदूतावास का आर्थिक कार्य खण्ड पब्लिक रिलेशन अताशे इण्टरनेशनल नामक एक गैर सरकारी एजेन्सी की सेवाओं का इस्तेमाल कर रहा है । भारत सरकार ने आर्थिक पक्ष से सम्बन्धित मामलों के प्रचार कार्य के लिए संयुक्त राज्य अमरीका मे इस फर्म को नियुक्त किया है, जिसके प्रिंसिपल श्री जानकी गंजू है । इसके साथ की गई संविदा को पहले तीन वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया जाता था, लेकिन इसे 1-3-78 से केवल एक वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है । संविदा की शर्तों के अनुसार पब्लिक रिलेशन अताशे इण्टरनेशनल को प्रतिवर्ष अधिक-से अधिक 60,000 डालर तक की राशि का भुगतान किया जा सकता है । इस एजेन्सी से 19-8-1965 से काम लिया जा रहा है ।

(ग) 1970-71 से 1976-77 तक के वित्तीय वर्षों में इस फर्म को भुगतान की गई राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	डालर
1970-71	53,586.58
1971-72	52,465.57
1972-73	56,258.74
1973-74	50,652.02
1974-75	56,963.47
1975-76	57,500.00
1976-77	59,983.91

Talks Re : Indian Labourers in Iran

8425. Dr. VASANT KUMAR PANDIT : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether a discussion was held between the Union Labour Minister and his Iranian counterpart Amir Ghasin Moin on or about 21st March, 1978 on the problem of recruitment of Indian labourers in Iran ;

(b) whether arguments have been advanced to recruit skilled and unskilled labour on Government level ; and

(c) how many jobs of skilled and unskilled workers would be available during the next two years in Iran ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) Yes, Sir.

(b) During the discussion, the Minister for Labour and Social Affairs of Iran had desired that Iran's requirements for skilled workers may be handled on *Government-to-Government* basis.

(c) No estimates are available of the long-term requirements. However, immediately there are about 30 employers from Iran who wish to recruit about 2,000 workers.

Difficulty to Exporters to get visa for Pakistan

8426. SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN :
SHRI MOHINDER SINGH SAYIANWALA :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) has it come to the knowledge of the Government of India that the exporters having trade links with Pakistan are experiencing great difficulty in securing visas to visit that country for promotion of their business or settling problems ; and

(b) in view of the allegation that the applications are either rejected or inordinately delayed, what steps the Government of India propose to help such traders in getting visas quickly and effectively ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU) : (a) and (b). On being approached, the Government provides assistance to bonafide subiness men for securing visas for Pakistan by issuing letters of introduction to the Pa,istan Embassy. As far as Government are aware, visas in such cases are granted by the Pakistan Embassy expeditiously.

Sterilisation during Emergency

8427. DR. VASANT KUMAR PANDIT : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government has given instructions to the Health Departments of various States to find out cases of wrongful compulsory sterilisations during the period of emergency where recanalisation can be done ;

(b) if so, the number of recanalisation operations done in each state on young persons who had not married or who has less than three children and such other cases ; and

(c) whether Government have some system or machinery to follow-up these cases of recanalisation about their success etc. ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) The Government of India have requested all the States/Union Territories to promptly provide the recanalisation facilities free of cost to all those persons (both male and female) who seek such facilities irrespective of the number of their living children. The state Govts./Union Territory Administrations have further been requested to give adequate publicity for the arrangements made for the recanalisation operation.

(b) The requisite information is being collected from all the States/Union Territories and would be laid on the table of the Sabha when received.

(c) Though technically it is possible to join the cut ends of the vas, normally such operations are successful only in 25-30% cases. Research studies are going on in India and in other countries to develop the procedures so that such operations may be successful in cent per cent cases.

Seizure of Bogus Passports

8428. CR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of EXTER-

NAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) is it a fact that special CID Branch of Police seized bogus passports in Kirkee (Pune), if so, how many;

(b) how many persons have been arrested in the above matter ; and

(c) is it a fact that some rackets are working and cheating various persons eager to go to Gulf countries for job ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU) : (a) The Police had seized in 6th February, 1978 and 8th February, 1978, 15 passports but it is reported that the passports themselves were not bogus. However, it is reported that visas for Kuwait on nine of these passports could have been forged ; the remaining six passports were without visas.

(b) One person has been arrested. Three others wanted in the case are absconding.

(c) Yes, Sir. *Cases of rackets* and cheating of persons eager to proceed to Gulf countries for employment have been reported and whenever such cases come to the notice of the Central Government, these are communicated to the concerned State authorities for appropriate action.

खेतड़ी में हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड में उत्पादन कम होना और उसके कारण

8430. **श्री भानु कुमार शास्त्री :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी से हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड में ताम्बे का उत्पादन कम हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) जी हां ।

(ख) खेतड़ी में 1977–78 के दौरान उत्पादन में कमी के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:—

1. खेतडी प्रद्रावक मे प्रौद्योगिकी विषयक समस्याएं ।
2. खेतडी कापर कपलैक्स में 25-2-78 से 17–4–78 तक कामगारों द्वारा हडताल ।
3. राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड द्वारा लागू भारी बिजली कटौटियां ।

हिन्दुस्तान कापर लि० ने खेतडी प्रद्रावक के परिचालन मे सुधार के लिए सितम्बर, 1977 मे जापान के मैसर्स कुरुकावा की सेवाएं प्राप्त की । इसके फलस्वरूप, प्रद्रावक के प्रचालन मे दिसम्बर, 1977 से स्पष्ट सुधार हुआ है ।

प्रबन्धकों और सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप, प्रबन्धकों और यूनियनों के बीच 17–4–78 को समझौते के ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर के बाद खेतडी मे हडताल समाप्त हो गई। इससे अब खेतड़ी में औद्योगिक शान्ति सुनिश्चित हो जानी चाहिए । बिजली सप्लाई मे सुधार के लिए भी प्रयास किए गए है । खेतड़ी में उत्पादन में कमी के कारणों को देखते हुए किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रश्न नही उठता ।

सालडी और शंकरपुरा की दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को टेलीफोन कनेक्शन

8431. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सालडी और शंकरपुरा ग्रामों की दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा लंघंजा टेलीफोन एक्सचेंज से टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने की मांग मत

दो वर्षों से अनिर्णीत पडी है और इस बारे में धनराशि भी जमा करा दी गई है ; और

(ख) क्या इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए कि यह माग किसी व्यक्ति के लिए नही है बल्कि एक सहकारी समिति की माग है जो सार्वजनिक संस्था है, टेलीफोन कनेक्शन शीघ्र ही दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) और (ख). सालडी और शकरपुरा गावो की दुग्ध उत्पादक सहकरी समितियां को टेलीफोन कनेक्शन क्रमश 26-12-77 और 29-11-77 को लंघनाज एक्सचेंज से दे दिए गए है ।

डेला और तापड़िया गावों की मिल्क प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव सोसाइटी को टेलीफोन कनेक्शन

8432 **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** . क्या **संचार** मत्री यह बताने की कृपा करेगे कि ·

(क) डेला और तापडिया गावो की मिल्क प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा मेहसाना टेलीफोन एक्सचेंज से टेलीफोन कनेक्शन के लिए की गई माग कब से विचाराधीन है, और

(ख) क्या गाव मे टेलीफोन सुविधा के अभाव के कारण उक्त सोसाइटी के सदस्य मेहसाना कोआपरेटिव डेयरी से समय पर पशुओं के इलाज की सुविधा प्राप्त करने से वंचित रहते है जिसके परिणामस्वरूप गरीबों के पशु कभी-कभी मर जाते है और क्या इस बात को ध्यान मे रखते हुए सोसायटी को टेलीफोन कनेक्शन शीघ्र दिया जायेगा क्योंकि उनकी माग गत दो वर्षों से विचाराधीन है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद, सुखदेव साय) : (क) और (ख). डेला की दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को टेलीफान कनेक्शन 29-3-78 को दे दिया गया है । तापडिया की दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति की टेलीफोन कनेक्शन की माग 3-8-1974 से अनिर्णीत पडी है । रेलवे अधिकारियो से रेल की लाइन पार करने की अनुमति न मिल पाने के कारण यह काम अभी रुका पडा है ।

गांगटे दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को टेलीफोन कनेक्शन

8433. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी :** क्या **संचार** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गागटे दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति द्वारा चानस्या एक्सचेज से टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए टेलीफोन अधिकारियो के पास कब धनराशि जमा कराई गई थी ,

(ख) उन्हे अब तक टेलीफोन कनेक्शन न देने के क्या कारण है , और

(ग) टेलीफोन कनेक्शन कब दिया जायेगा और क्या इस तथ्य का ध्यान में रखते हुए कि माग सहकारी क्षेत्र मे है, उक्त टेलीफोन का प्राथमिकता दी जायेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) टेलीफोन कनेक्शन की माग दर्ज कराने के लिए अग्रिम जमा राशि की अदायगी 28-1-1976 को की गई थी ।

(ख) और (ग). टेलीफान कनेक्शन रानुज के नजदीकी एक्सचेंज मे 5 किलोमीटर की दूरी पर मागा गया है । इसके लिए लाइन सबंधी साज-सामान की भारी मात्रा में जरूरत है जिसकी सप्लाई कम है । लम्बी दूरी के कनेक्शनों के लिए पहले की कुछ मागे भी बकाया पडी हैं । सभी बकाया

मागे साज-सामान उपलब्ध होने पर बारी के अनुसार पूरी कर दी जाएगी। नियमो के अन्तर्गत कोई प्राथमिकता नही दी जा सकती।

बगला देश से बड़ी सख्या मे शरणार्थियों का भारत आना

8434 **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **विदेश** मत्री यह बताने की कृपा करेगे कि

(क) क्या हाल में बगला देश से बडी सख्या में शरणार्थी भारत आये हैं

(ख) यदि हा तो तत्सबधी ब्यौरा क्या है और

(ग) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मत्रालय में राज्य मत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) :(क) से (ग). विभाजन के बाद से और यहा तक कि इससे पहले भी पूर्ववर्ती पाकिस्तानी और वर्तमान बगलादेशी कुछ राष्ट्रिक अपना देश छोड कर भारत आते रहे है और यह प्रक्रिया हाल के महीनो में भी जारी रही है। भारत सरकार के पास उपलब्ध आकडो के अनुसार बगलादेश के जिन राष्ट्रिको को वैध यात्रा प्रलेख के बिना भारत में प्रवेश करने का प्रयास करते हुए पकडा गया है उनकी सख्या लगभग वही हैं जो पिछली तिमाही के दौरान थी। भारत सरकार ने 1 दिसबर, 1977 को लोक सभा में इस विषय पर बहस के दौरान अपनी नीति स्पष्ट की थी और उसके बाद से स्थिति में कोई परिवर्तन नही हुआ है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा किराए पर ली गई इमारतें

8434 **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दिल्ली, मेरठ, कानपुर, कलकत्ता और बम्बई में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा अपने औषधालयो के लिए कितनी इमारते किराये पर ली गई और उनके लिए प्रति वर्ष कितना किराया अदा करना पडता है, और

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान अपने औषधालयो के लिये इमारतो का निर्माण करने के लिए उक्त शहरो में सरकार ने जमीन खरीदी है और निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की सभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) एक विवरण सलग्न है।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान तिलक नगर दिल्ली में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वास्थ्य योजना औषधालय के भवन का निर्माण करने के लिए भूमि खरीद ली गई है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से भवन के प्रारम्भिक अनुमानो की प्रतीक्षा की जा रही है।

तथापि केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वास्थ्य योजना औषधालयो के भवन-निर्माण के लिए निम्नलिखित क्षेत्रो में भूमि पहले ही खरीदी जा चुकी है। भवनो के निर्माण की स्थिति प्रत्येक के सामने दी गई है —

(क) **दिल्ली** :

(1) **हौज खास** निर्माण कार्य चल रहा है।

(2) **नारायणा** : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से कार्य आरम्भ करने के लिए कहा जा रहा है।

(3) **मालवा राए** मजूरी दे दी गई और नगर कला आयोग/दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करने के लिए भवन के नक्शे उन्हें भेज दिए गए हैं।

(4) हरिनगर :—केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से प्रारम्भिक अनुमानो की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) बम्बई

वर्ली :—भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और भवन के निर्माण के संबंध में प्रशासनिक मंजूरी जारी करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

मेरठ, कानपुर और कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयो के भवनो के निर्माण के लिए अभी तक कोई भूमि नही खरीदी गई है।

विवरण

क्रम संख्या	शहर	औषधालयों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा किराए पर लिए गए भवनों की संख्या	प्रत्येक वर्ष दिया गया किराया
1.	दिल्ली . .	21	1,49,452.80
2.	मेरठ .	4	23,220.00
3.	कानपुर	6	77,400.00
4.	कलकत्ता . .	6	57,528.00
5.	बम्बई . .	3	25,140 00

Assessment of Assets Left By Refugees in Bangladesh

8436. SHRI PRASANNBHAI MEHTA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Union Government was considering a proposal to make an up-to-date assessment of the total value of properties of Indian National in erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) with the help of claims filled by them with the Custodian of Enemy Property ,

(b) if so, to what extent the assessment has been made ; and

(c) what is the value of reassessment ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). About 56,000 Indian nationals have filed their claim with the Custodian of Enemy Property, Bombay, in respect of their properties left behind in erstwhile East Pakistan (now Bangladesh). The assessment of these claims, which apparently do not cover all the properties left behind by Indian nationols, is in progress and is likely to take about two years for completion.

गुजरात में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोला जाना

8437. श्री धर्मसिंह भाई पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 मे गुजरात मे लम्बी दूरी के काल के लिए कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गए है और वर्ष 1978-79 मे कितने खोले जाने का विचार है ,

(ख) जूनागढ जिले के वथली, माणावदर, कुतियाना, राणावाव, पोरबंदर, मागरोल तालुकों मे, राजकोट जिले के धोराजी, कडोरणा, जाम, उपलेठा तालुकों मे, जामनगर जिले के जाम, जोधपुर और मालपूर तालुकों, तालुकवार के किन गांवों मे वर्ष 1977-78 के दौरान सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गए है तथा प्रत्येक गांव मे कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गए हैं और उक्त तालुकों में किन गावों मे सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र अभी खोले जाने है ;

(ग) उक्त तीन जिलो के तालुको मे वर्ष 1978–79 के दौरान किन गावो मे सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले जाने का विचार है तथा ऐसे सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रो की कुल सख्या क्या है , और

(घ) उपरोक्त भाग (ख) मे उल्लिखित इन जिलो के किन-किन तालुको के किन-किन गावो मे सार्वजनिक टेलीफान केन्द्र का निर्माण काम पूर्ण हाकर चालू हो गया है और किन-किन गावा म निर्माण का काम अभी चल रहा है और यह कब तक पूण हो जाएगा ?

संचार मंत्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद, सुखदेव साय) : (क) वर्ष 1977–78 के दौरान गुजरात मे लंबी दूरी के 210 सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले गए है और 1978–79 के दौरान 130 सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का प्रस्ताव है ।

(ख) से (घ) वाछित सूचना विवरण मे दे दी गई है । इस अनुबध के अतिम खाने मे उल्लिखित दस गावो के अलावा अन्य सभी गावा मे सार्वजनिक टेलीफान घर उपलब्ध नही है । प्रश्न के भाग (ख) मे उल्लिखित जिलो म से किसी भी जिले म इस समय सार्वजनिक टेलीफोन घर खालने का काम नही हो रहा है

विवरण

जिले/तालुके का नाम	सार्वजनिक टेलीफान घर		
	1977–78 के दौरान खोले गय	1978–79 मे प्रस्तावित	आज की तारीख मे मौजद
1 वनथली	धाधूसार	कजा, थाना पीपली	धमधूसर
2 माणावदर	पाजोद	लिम्बुडा, सनोसरा (पाजोद नादिया, मोतियाना और कोयलाना) ·	
3 कुत्तियाना	महियारी	देवडा, खगेश्री	महियारी
4. राणावाव	—	मोकाड, वदवला-राना	रानाकडोर्ना
5 पोरबदर	नविबदर	शोधना, खटाना, मोधवाडा, बालचरला, ओडूंर, भाड, गरज, बुलेज, कडाछ, मदेर और बोखिना	नविबदर और बेगावदर
6 मंगरोल	जूठल	मेखडी	जूठल
राजकोट जिला			
7 धोरजी	—	—	पिपलिया
8 कंडोनजिम	—	—	—
9 उपलेटा	—	—	करचिया
जामनगर जिला			
10. जमजोधपुर	—	—	रंगपुर
11 लालपुर	—	—	—

Outcome of U.S.A. & U.S.S.R. Talks Re : Indian Ocean

8438. SHRI SUKHDEV PRASAD VERMA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item appearing under the caption "Dismantle Ocean basin says Aliev" in the "PATRIOT", New Delhi dated the 3rd April, 1978 ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ;

(c) whether Government has known the outcome of reported parleys between U.S.A. and U.S.S.R. in this regard; and

(d) if so, the details thereof, and also, the steps being contemplated for keeping Diego Garcia absolutely free from foreign domain ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d). The Government of India has been in touch with the Governments of the U.S.A. and the U.S.S.R. in regard to the talks taking place between them on questions concerning arms limitation measures in the Indian Ocean.

Our position on this question is well-known. We are committed to work for the establishment of Zone of Peace in the Indian Ocean and the elimination of foreign military presence and bases from the area and have reiterated this to the Great Powers. Our Policy is in line with U.N. resolutions on the subject. We are concerting our efforts with other like-minded States, which include the overwhelming majority of littoral and hinterland States of the Indian Ocean and the non-aligned movement.

Residential Telephones to Officials

8439. SHRI SUKHDEV PRASAD VERMA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the total number of residential telephones provided to various officials in Delhi attached to the Ministry including the number of personnel ranking in the Class IV Central Government employees ;

(b) whether some of the drivers of motor vehicles have also been provided residential telephones;

(c) if so, the total number of such drivers having residential telephone facility attached to his Ministry including the average cost and expenses thereof per year ; and

(d) Whether such facility has been provided to drivers belonging to other Ministries/Government of India officials and if not, the reasons for such provisions to such men working in his Ministry ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) 219-(including officers of the Posts and Telegraphs Directorate).

(b) and (c) Yes. The number of drivers having telephone facility is 9. These are "Service" connections.

(d) The information from all the Ministries etc. is not readily available.

Funds provided for telecommunications facilities in Vidharbha region of Maharashtra.

8440. SHRI VASANT SATHE : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the total funds approved for provision of various telecommunication facilities in Vidharbha Region of Maharashtra with details of important projects approved/under execution during 1977-78;

(b) the actual performance both in terms of physical and financial in general and project-wise for important projects;

(c) whether the work in regard to some projects including one at Akola has lagged behind the time schedule and the reasons therefor; and

(d) special steps taken/proposal to accelerate the programme of execution and the details of programme proposed/approved for 1978-79 with special emphasis to extension of the facilities to rural areas ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) and (b). (i) Funds approved during 1977-78 for provision of telecommu-

nication facilities in Vidharbha region of Maharashtra.

(1) Total provided	Rs. 91·83 lakhs.
(2) Actual spent	Rs. 60·30 lakhs (approx)..

(ii) Important projects and their progress

(1) Installation of 2000 lines trunk automatic Exchange at Nagpur.	Installation commenced in February, 1978
(2) Expansion of Itwari Exchange by 1200 lines	300 lines completed. 900 lines expected to be commissioned in 1978-79.
(3) Construction of automatic telephone exchange building at Akola	The tenders have been accepted and work order given. In the meantime, manual exchange expanded from 1200 to 1320 lines.
(4) Expansion of Yeotmal automatic exchange by 100 lines	Equipment supplies from I.T.I. commenced.
(5) Expansion of Malkapur manual exchange.	Expansion completed from 240 to 360 lines.
(6) Opening of small exchanges in rural areas.	10 new exchanges commissioned
(7) Opening long distance P.C.Os. in rural areas	9 New P.C.Os. opened.

(c) Yes, Sir.

(d) Building work at Akola has been awarded. Equipment has been allotted in 1979-80, manufacturing programme of I.T.I. It is hoped to commission the automatic exchange by 1982. Following other works are approved for 1978-79 :—

(i) 900 lines expansion for Itwari automatic exchange;

(ii) Increase in capacity of small exchanges by 2000 lines;

(iii) Opening of 7 small automatic exchanges in rural areas.

(iv) Opening of 23 long distance P.C.Os. in rural areas.

Propagation of Gandhiji's Teaching Abroad

8441. SHRI DURGA CHAND : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have collected the information from our Indian Missions abroad regarding honouring Gandhiji and his teachings in one from or the other in foreign countries; and

(b) if so, the names of places in such countries where Gandhiji has been honoured by erecting a statue and by propagating his teachings ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU) : (a) Many of our Indian missions abroad organise a suitable programme, either at their own initiative or through a local organisation/association, on the occasion of Gandhi Jayanti and Martyr's Day. The observance takes the form of lectures, symposia and film shows. Interested cultural organisations in some countries arrange special programmes in cooperation with our missions.

(b) A statement is laid on the Table of the House indicating the places where Gandhiji has been honoured or commemorated by erecting a suitable memorial, or statue, or in any other way as a mark of respect to him.

STATEMENT

A *School/Library/Street named after Gandhiji*

1	A School	Montevideo (Uruguay)
2	A School A library	Cordoba Rosario } (Argentina)
3	A memorial Hall	Singapore
4	A road	Nairobi (Kenya)
5	A School	Conakry (C)
6	A road	Tunis (Tunisia)
7	Gandhiji's birthday celebrated as peace day	New Jersey (U S A
8	A road	Rabat (Morocco)
9	A dispensary a school and a few roads	Livingstone (Zambia) [illegible]
10	An Avenue	Caracas (Venezuela)
11	A road	Mogadiscio (Somalia)
12	A library	Bangkok (Thailand)
13	Memorial institutions	Nanuoya Matale [illegible] puran Jaffna Killu [illegible] (Sri Lanka)
14	A primary school	(Rome (Italy)
15	A road	Khartoum (Sudan)
16	A road	Blantyre (Malawi)
17	An institute	Washington (U S A)
18	A memorial institute	Nicosia (Cyprus)
19	A memorial Hall	Rangoon (Burma)
20	A park	Santiago (Chile)
21	A square	Rio de Janrio(Brazil
22	A park	Lima (Peru)
23	A road	Mexico City (Mexico)
24	A School	Suva (Fiji)
25	An Institute (Mahatma Gandhi Institute)	Port Louis

B *Gandhiji's Statues and Busts*

1	Statue	Montevido (Uruguay)
2	Bust	in memorial Hall Singapore
3	Statue	Panama City
4	Statue	Vancouver (Canada)
5	bust	Caracas (Venezula)
6	Statue	Tavistock square London

7. Statue	Brussels (Belgium)
8. Statue	Luxemburg
9. Statue	.Guyana . . .
10. Statue	Santiago (Chile) .
11. Statue	Rio-De-Janrio
12. Statue	Lima City (Peru)
13. Statue	Mexico City (Mexico)
14 & 15. Statue	1. Port of Spain 2. Sanfernands (Trinidad)
16. Bust	Suva (Fiji).
17. Statue	Paramaribo (Surinam).

(C) *Organisations engaged in propagating Gandhiji's teachings in Foreign Countries*

1. Gandhi Peace League.

2. The Ganhi Adoration League Tokyo Kyoto (Japan)

Sending Goodwill missions to China and Pakistan

8442. SHRI DURGA CHAND : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to send goodwill mission to China and Pakistan in the near future;

(b) if so, the details thereof; and

(c) by when the missions would be sent to these countries ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU) : (a) to (c) No proposal to send goodwill missions to China and Pakistan is under present consideration, Exchanges of visits in various fields have taken place with these countries in the recent past and may furhter take place in the near future. Such visits, it is felt, would help in generating mutural goodwill between our countries.

Acquisition of land for Rourkela steel city

8443. SHRI DURGA CHAND : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a number of persons were evicted from their lands which were acquired for Rourkla Steel City;

(b) whether it is a fact that out of these persons a number of them belong to Adivasis ;

(c) if so, what is acreage of land acquired for the purpose and what is the number of persons affected by such acquisition; and

(d) the number of cases which are still pending for disposal and the reasons therefor and by when these cases would be disposed of ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) to (d). The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Transfers of officials in P&T.

8444. SHRI SURAJ BHAN : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether transfers and postings of officials in Lower Selection Grade in various Post Offices are made by the Director of Postal Services on Circle basis;

(b) whether such transfers and postings cause lot of hardships and even disruption of education of the school going chidren of the officials in the Circles comprising of different linguistic regions e.g. North Western Circle;

(c) whether Department has taken any steps to mitigate the hardships of these not highly paid employees; if so, their details;

(d) whether it is not feasible to confine such transfers to particular linguistic regions if not, why; and

(e) now that there are more than one Directors of Postal Circles in all the Postal Circles, it is not possible to assign them regional jurisdiction so that objective of transfers of officials in one linguistic area may be achieved apart from proper appraisal of the development needs of the area ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) (a) Yes Sir

(b) Transfers and postings are made by the Cicle authorities as per availability of vacancies in adjoining divisions There are instructions that transfers/postings in the middle of the academic session should be avoided a far as possible

(c) The requests for posting to the home division are always considered sympathetically where justified and transfers for home divisions are ordered as soon as vacancies become available

(d) The scope of service of such employees extends over the entire Circle Efforts are always made to accommodate such employees in neighbouring divisions to the extent of availablbihty of vacancies

(e) Regional jurisdiction is given to Directors of Postal Services But transfers of Lower Selection Grade officials through out the circle takes place as it is a circle cadre and not a divisional cadre

Norms for transit and delivery of various articles.

8445 SHRI SURAJ BHAN Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state

(a) whether the P&T Department has fixed any norms for transit of various types of articles and their delivery,

(b) if so, when they were fixed and what are the details,

(c) are these norms being adhered to or has any variation been made since then and what is the justification therefor, and

(d) what is the machinery to ensure that these norms are strictly observed to provide ample satisfaction to the people ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) (a) Yes, Sir

(b) In year 1967

Details of norms of delivery for various types of postal articles are thus —

(a) *First Class Mails*

(i) *Local mails*

Same day is posted before 8 A M otherwise 1 day

(ii) *Within the District*

Not more than 2 days

(iii) *Within the State*

Not more than 3 days

(iv) *Anywhere in the country*

Not more than 7 days

N B for registered articles one more day should be added

(b) *Packets and Parcels*	
(i) Local mails	1 day
(ii) Within the District	Not more than 3 days
(iii) Within the State	Not more than 7 days
(iv) Any where in the country	One day for every 308 K.M.s
(c) *Money Orders*	
(i) Local	2 days
(ii) Within the District	Not more than 3 days
(iii) Within the State	Not more than 7 days This may have to be increased upto 3 days where the M O is issued from or for payment in a rural area
(iv) Any-where in the country	Not more than 8 days

(c) Yes, Sir. These are being adhered to as far as possible except in cases of breaches, accidents and misconnections etc. In certain hilly places or far flung rural areas the trnsit time can be more in absence of mechanised transport. No variation has since been made because norms fixed are working satisfactorily.

(d) Test letters are regularly posted by all supervisory officers to check up adherence to these norms. A check right from collection of articles till delivery is carried out by supervisory staff to maintain the norms.

Norms for removing faults in telephones in Delhi

8446. SHRI SURAJ BHAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether any time limit has been fixed for the removal of faults in telephone connections and lines and if so, the norms prescribed for the purpose;

(b) whether these norms are being adhered to and if not, the percentage of cases in which the faults continue beyond the prescribed period;

(c) what steps have been taken, or proposed to be taken to ensure that prescribed norms are adhered to; and

(d) which exchange in Delhi and now circles heads the list of fault complaints and which heads the list where they are not removed within the prescribed time limit?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) Control limits for removing faults during monsoon period has been fixed at 3 hours and during non-monsoon period at 2·5 hours on an average.

(b) All exchanges in Delhi excepting Delhi Cantt., Tis Hazari & Hauz Khas exchanges are maintaining these average limits.

Percentage cases in which the faults continue beyond the prescribed period in these exchanges is given below:—

Tis Hazari . . .	26·2%
Delhi Cantt. . . .	18·6%
Hauz Khas . . .	8·4%

(c) Systematic inspection of 'subscribers' office fittings, instruments, DPs and the overhead loops are being made to reduce fault incidences and thereby adhering to the norm.

(d) Tis Hazari Exchange.

Strikes and Lockouts

8447. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) total number of strikes, lock-outs and closure in the last 4 months and in the corresponding period in last year and year before last;

(b) the number of violent incidents and gheraoes in the aforesaid period and in the corresponding period in last year and what was the loss of life and property in these two periods;

(c) how many persons were arrested in the last 4 months in violent activities and in making gheraoes separately;

(d) how many working hours were lost on account of strikes etc. in the 4 months; and

(e) what specific steps have been taken by Government in the said period to check such incidents?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) to (e). The required information is being collected from the State Govenments and will be laid on the Table of the Sabha when received.

आपात स्थिति के दौरान सेवा से हटाये गये कर्मचारियों का बहाल किया जाना

8448. श्री सुरेन्द्र झा सुमन : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या 'कारण बताओ' नोटिस के बिना अथवा किसी जांच के बिना सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को सेवा में बहाल करने के सरकार के निर्णय की सूचना सरकार द्वारा सभी संस्थानों को दी गई थी,

(ख) यदि हां, तो राउरकेला इस्पात संयंत्र को यह सूचना किस तारीख को दी गई थी,

(ग) श्रेणी I के कितने अधिकारियों और अन्य श्रेणियों के कितने कर्मचारियों को इन संस्थाओं में अनुदेश प्राप्त होने के बाद सेवा में बहाल किया गया है और कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को अभी तक सेवा मे बहाल नही किया गया है और कितने वे किस-किस श्रेणी के है ; और

(घ) सरकार का विचार शेष व्यक्तियों को कब तक सेवा मे बहाल करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) से (घ). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

Recorded Delivery Service

8449. SHRI SURAJ BHAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether the Recorded Delivery Service introduced in Post Offices after abolition of Express Delivery Service about three years back, is popular with the public;

(b) if so, the number of articles monthly handled in different Postal Circles in India;

(c) what steps have been taken by the Department to popularise the service and with what result, and

(d) what is the incidence of complaints on account of such articles and what is the percentage of satisfying replies to the complaints?

THE MINISTER OF STATE IN IN MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) Recorded Delivery Service introduced in Nov. 74 is picking up and has gained popularity.

(b) The number of articles handled in the various postal services monthly varies from about 4,000 to 1,64,000.

(c) Publicity through postal notices and also by insertion in the news papers periodically has been adopted to popularise the service. The results have been encouraging.

(d) The incident of complaints is less than 0.3 per cent and in most of the cases it is possible to give satisfying replies to the complaints.

CGHS Dispensary, Darya Ganj

8450. SHRI MAHI LAL: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the criteria adopted for making a doctor Medical Officer incharge of a CGHS Dispensary; and

(b) the average time a Doctor-in-charge is allowed to stay at a particular dispensary?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) The posting of a Medical Officer as incharge of a CGHS Dispensary is done on the basis of seniority-cum-merit.

(b) The average time of stay of a Medical Officer incharge in a dispenary generally varies between 3—5 years unless due to some administrative reasons or in public interest a relaxation is required to be made.

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, बिडे को टेलीफोन कनेक्शन

8451. **श्री मोती भाई आर चौधरी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिडे गाव की दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति ने गुजरात मे कडी टेलीफोन एक्सचेंज मे टेलीफोन के लिए मांग की है ; और

(ख) क्या इस समिति को टेलीफोन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पशु-पालन व्यवसाय के सिलसिले में उसे बार-बार टेलीफोन करना होता है और इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए उसे कब तक टेलीफोन दे दिया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) जी हां :

(ख) सभी आवेदकों को, जो अपनी मांग दर्ज कराते हैं और पेशगी रकम जमा कराते हैं, टेलीफोन कनेक्शनों की जरूरत

होती है । यह सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन की माग है, जो 6-5-1976 को दर्ज कराई गई थी और जिस स्थान पर यह टेलीफोन कनेक्शन मागा गया है, वह स्थान कडी टेलीफोन एक्सचेंज से लगभग 7 किलोमीटर दूर है । यह कनेक्शन देने मे बहुत ज्यादा साज-सामान की जरूरत है और साज-सामान की सप्लाई कम हो रही है । साज-सामान उपलब्ध हो जाने के बाद उनकी बारी आने पर टेलीफोन कनेक्शन दे दिया जाएगा । इस श्रेणी के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन प्रतीक्षा सूची के अनुसार बारी आने पर ही दिए जाते है तथा इसमे प्राथमिकता देने का कोई नियम नही है ।

Legal Adviser in E P F. Organisation

8452 SHRI RAM PRAKASH TRIPATHI Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state

(a) whether the Employees Provident Fund Organisation is having a legal adviser

(b) whether in many important court cases, the opinion of that legal adviser was not sought or were sought the same was ignored and

(c) the details of those cases and the reasons for not obtaining the advice of the legal adviser or ignoring it where such advice was obtained?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR RAM KIRPAL SINHA) (a) It has been reported by the Provident Fund Authorities that they have a part time Legal Adviser

(b) and (c) Since the cases are conducted generally by the Central Government Standing Counsels, the opinion of part time Legal Adviser is not sought in all cases There is no recent case where his opinion was sought and ignored However in the case of the Bihar Khadi Gram Udyog Sangh, Bihar, the Regional Provident Fund Commissioner there filed a petition for certificate of leave to appeal on the 29th September, 1977 being the last date for filing of such an application The Legal Adviser gave his opinion on the same date at New Delhi that he would not advise preferring an appeal.

Policy for Review of Damages

8453 SHRI RAM PRAKASH TRIPATHI Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No 4997 on the 30th March 1978 regarding damages imposed by R P F C reviewed by C P F C and to state,

(a) the details of the policy for review of damages by higher authority which were imposed by R P F C ,

(b) the name of the authority by whom this policy has been approved,

(c) whether in all the cases where damages have been reduced by the present Central Provident Fund Commissioner and which have come to the notice of the Central Government the reduction has been in accordance with that policy, and

(d) if not the reasons therefore and the action proposed to be taken for not complying with the so called policy?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR RAM KIRPAL SINHA) (a) and (b) A copy of the circular bearing No FP/E 128 (294) Dam/74 dated the 24th October, 1975 issued by the Central Provident Fund Commissioner to the Regional Provident Fund Commissioners is laid on the Table of the Sabha (*Placed in Library See* no LT—2711 78)

(c) and (d) The available information is being studied

Complaints Re Belated Coverages under E P F. and Miscellaneous Provisions Act, 1952

8454 SHRI RAM PRAKASH TRIPATHI
SHRI RAMESHWAR PATIDAR

Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state

(a) whether Government have received complaints about many belated coverages under the E P F and Miscellaneous Provisions Act, 1952 in the States of Karnataka and Maharashtra,

(b) if so, the details of those belated coverages and the persons responsible for that illegal action, and

(c) the action Government propose to take against theose officials who have sacrificed the interest of workers for their personal ends?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR RAM KIRPAL SINHA) (a) to (c) The Central Provident Fund Commissioner brought ko the notice of the Government in 1974 that he had received two letters from a member of the Central Board of Trustees complaining about belated coverages of establishments in Mysore (Karnataka) Region Copies of the letters are placed on the Table of the House After an examination of the same and as desired by the Government detailed instructions were issued by the Central Provident Fund Commissioner to the Regional Commissioners, a copy of which is placed on the Table of the Sabha [*Placed in Library See* No LT-2212/78]

Percentage of SC/ST for recruitment confirmation and promotion etc.

8455 SHRI R L KURIL Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state

(a) whether Government has prescribed certain percentage for the Recruitment Confirmation and Promotion of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees;

(b) whether this prescribed percentage has been followed in the P&T Civil Wing and by the Superintending Engineer, P&T Civil Circle, New Delhi,

(c) whether this percentage by the P&T Directorate, while promoting Junior Engineers Civil and Electrical against the posts of Assistant Engineers Civil and Electrical

(d) if so, the total number of posts and the staff recruited confirmed and promoted under the following categories (1) D'men Gr II (2) D men Level-II/III (Architectural Side, (3) A E (Civil)/Electrical and

(e) if not, the reasons therefore?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) (a) Yes

(b) Yes

(c) Yes

(d) (1) & (2) Information is being collected

(3) Necessary information is as under:

	Total No of posts	Staff recruited	Confirmed	Promoted	
				On regular basis	On Adhoc basis
Assistant Engineer (Civil)	330	45*	Nil	233	13
Asstt Engr (Elect)	83	7—	Nil	44	1

(e) Does not arise

*23 of them have been promoted as Executive Engineer (Civil

—4 of them promoted as Executive Engineer Electrical)

Expert Group on use of Antibiotics

8456 SHRI HARI VISHNU KAMATH: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No 641 on the 17th November, 1977 regarding expert group on use of Antibiotics and state

(a) whether the expert group has submitted its report;

(b) whether the said report will be laid on the Table, and

(c) if the group has not met so far whether Government propose to disband the group?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) (a) and (b) The recommendations of the expert group are enclosed and are under examination

(c) Does not arise

Statement

The expert group recommended as follows·

(i) In order to assess and maintain a surveillance of the drug resistent pattern of bacteria, State Governments be requested to inform all laboratories undertaking drug sensitivity tests (*i.e.* Bacteriology Labs) to maintain proper record of the results;

(ii) that information as above may be collected by the NICD, Delhi, for compilation and for dissemination.

(iii) that the practice of adding antibiotics to animal feeds as feed additives be viewed with concern and that such animals feeds be brought within the purview of the Drugs and Cosmetics Act;

(iv) that antibiotics should be judiciously used in the following manner:

(a) use of Chloramphenicol should be restricted to the treatment of enteric fevers and *H. influenzae* infections;

(b) the ue of streptomycin should not be so widely used for non-tuberculosis cases;

(c) careful watch should be kept for the finding of tetracyclin resistance in strains of V. cholarae, since tetracyclin is ofteen the preferred treatment for cholera;

(d) prophylactic use of antibiotics should be avoided;

(e) combination of antibiotics should not be used routinely;

(f) since the use of antibiotics in diarrhoeal diseses have little curative role, antibiotics should not be prescribed unless aboslutelly indicatd; and

(g) drugs such as trimethoprim and sulphamathoxozole marketted as "Septran", "Bactrin", Sulphaprim" etc., and gentamycin sulphate marketted as "Geramycin", "Ganticine" etc. should be restricted for "last line" therapy and not the "first line".

Supersession of D.G.H.S.

8457. SHRI K. LAKKAPPA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleaed to state:

(a) whether the officer appointed as DGHS has superseded three senior officers in the cadere of the Central Health Scheme and all those three Officers were holding posts higer and more important than what the selected officer was holding;

(b) whether one of the affected officers has not accepted the offer of appointment as Additional Director General and has proceeded on leave as a protest;

(c) whether this supesession has caused a lot of frustration and demoralisation in the cadre of Central Health Service;

(d) whether the officer selected for appointment as DGHS was not considered suitable at an earlier occasion for appointment as Medical Superintendent of Safdarjung Hospital; and

(e) if so, what special qualifications and experience the incumbant of the post of DGHS possessed on the basis of which he was selected for appointment and what is the procedure prescribed for filling up this post?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Dr. Balu Sankaran was appointed as D.G.H.S. on the recommendation of the Departmental Promotion Committee consisting of the following:—

Chairman, U.P.S.C.	Chiarman
Health Secretary	Member

and with the approval of the Appointments Committee of the Cabinet. He superseded the following three officers of Supertime Grade I of the Central Health Service.—

1. Dr. Lajpat Rai Pathak, Medical Superintendent, Willingdon Hospital and Nursing Home, New Delhi.
2. Dr. Nand Lal Pramanick, Medical Superintendent, Safdarjang Hospital, New Delhi.
3. Dr. R. Martanda Varma, Deputy Director General of Health Services (Rural Health Service).

All the officers including Dr. Sankaran were holding Supertime Grade I (level I) posts, whica are of the same grade and the same scale. All the above officers were therefore holding equally important posts.

(b) Dr. R. M. Verma, who was holding the post of Deputy Director General of Health Services (Rural Health Services)

was offered the post of Additional Director General of Health Services. He proceeded on leave for some personal reasons. He expressed his preference for the post of Director & Professor of Neurosurgery, National Institute of Mental Health & Neuro Sciences, Bangalore, to which he has been appointed on deputation basis.

(c) This selection has caused resentment amongst some C.H.S. Officers.

(d) Till the year 1972, there was no whole-time post of Medical Superintendent for Willingdon and Safdarjang Hospitals. One of the senior-most Supertime Grade I officers in the Hospital was called upon to shoulder the duties of Medical Superintendent. Dr. Sankaran was appointed to that post on 2-5-1971. Later on, when Dr. P. P. Goel, who was senior to Dr. Sankaran was transferred to to Safdarjang Hospital, New Delhi, he was appointed as Medical Superintendent of the Hospital.

(e) In accordance with the Central Health Service Rules, 1973 as amended from time to time, post of Director General of Health Services is to be filled in the following manner:—

"The post of Director-General of Health Services shall be filled on the recommendation of D.P.C. by promotion on the basis of mer it with due regard to seniority of

(i) officer holding the post of Additional D.G.H.S. or

(ii) Officer holding the post in Level I of Superintime Grade I in the scale of Rs. 2500—125/2—2750 who have rendered service for a period of not less than three years in that category."

Dr. B. Sankaran fulfilled all the conditions for being appointed to the post of D.G.H.S., New Delhi.

Telephone connection provided in Orissa during last two years

8459. SHRI D. AMAT : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state the number of Telephone Connections provided during the last two years in Orissa ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : The gross number of new telephone connections provided in Orissa during the last two years, i.e. 1976-77 and 1977-78 is 1660 and 1725 respectively.

Overseas Communication Building at Bombay

8461. SHRI L. L. KAPOOR : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to to refer to the reply given to Unstarred questions No. 4235 on the 23rd March, 1978, and state ;

(a) the estimated expenditure which would be needed for replacing 111 marble slabs and when this replacing work is likely to be completed and whether the Contractor would be asked to bear this expenditure ;

(b) besides marble slabs having got dislodging what are the other major defects which came into notice after the building was completed; the total amount spent in removing those defects and on whose account that expenditure was debited;

(c) whether the air conditioning machinery/plant equipment has not been functioning properly; and

(d) if so, the nature of defects value of repairs/replacements of such equipments ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) The estimated expenditure on replacement of 111 marble slabs would come to Rs 19,000 and would be borne by the Contractor. 27 slabs were replaced in 1972 and the remaining 84 are schduled to be replaced by the 31st December, 1979.

(b) No major defect has come to notice.

(c) The equipment is functioning properly.

(d) Does not arise.

Ethical Homoeopathy

8462. DR. BHAGWAN DASS RATHOR : Will the Minister of HELATH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Homeo-Central Council Act, 1973 was aimed at to give protection to everyway pure Homoeopathy, but the opposite activities are in practice;

(b) if so, what action Government propose to take to give protection to the Ethical Homoeopathy for the nation ; and

(c) what steps Government propose to take against those responsible for this ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) The Homoeopathic Central Council Act, 1973 was intended to prescribe the minimum standards of homoeopathic education and to maintain a central register of homoeopaths. It does not provide protection to any system of practice. If any case of unethical practice comes to the knowledge of the Council it will take necessary action. No. action can, however, be taken for deviation from homoeopathic principles laid down by Hahnemann

(b) and (c). Do not arise

Malaria menace in the Capital

8465. SHRI S. S. LAL :
SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK :
SHRI YADVENDRA DUTT:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that it has been detected by the Medical Personnel that there is a great fear of spread of malaria in the country and most particular-in the capital;

(b) if so, the steps being taken by Government to prevent the spread of malaria ; and

(c) whether Government are considering to appoint a high power committee of experts to find out the cause of spread of malaria in spite of the best efforts of NMEP ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : (a) No. On the other hand, there has been a decline in the number of malaria cases in the country as a whole as compared to those for 1976. However, the total number of malaria positive cases recorded in Delhi has increased.

(b) Government have launched a Modified Plan of Operations in the country from 1-4-77 to control the spread of malaria. A statement indicating the alient features of the Modified Plan is enclosed. Another statement indicating the remedial measures taken in the Capital is also enclosed.

(c) There are many reasons for resurgence of malaria which are well known. The Govt. had already appointed two High Powered Committees to suggest measures for control of the disease. It is therefore, not considered neccessary to appoint another higher power committee of experts therefor.

Statement

The salient features of the Modified Plan of Operations are as follows :—

1. The existing NMEP Units have been reorganised to confirm to the Geographical boundaries of the district Previously the Chief Medical Officers of the districts were not involved in the programme, but with the re-organisation of the Units, they are primarily responsible for the programme in the district.

2. Increased quantity of various insecticides DDT, BHC, Malathion have been/are being supplied to the States. Alternative insecticides are also being provided to the Units/district where the vector has become resistent to DDT/BHC.

3. Insecticidal spray operations have been undertaken in all rural areas which have incidence of 2 or more cases per thousand population.

4. Adequate quantity of anti-malaria drugs have been/are being supplied to the State/Union Territory Government. About 1·13 lakhs Drug Distribution Centres / Fever treatment Depots have been established to make the drug freely available. In areas where resistance to Chloroquine by parasites has been noticed, alternative anti-malarials like quinine have been supplied.

5. Anti-larval operations under Urban Malaria Programme have been intensified. The Scheme has been extended to 38 more towns besides the 28 existing towns existing earlier during 1977.

6. Supervision of the field staff has been toned up.

7. Steps have been taken for undertaking both fundamental and operational research in the field of malaria Eradication Programme. 14 research schemes i.e. 8 for operational field research and 6 for laboratory research on malaria has been associated by Govt. of India to I.C.M.R.

8. For early examination of blood smears and quick treatment of positive cases, laboratory services have been decentralised to the BHC level.

9. With a view to control the spread of Plasrodium falciparum infection whic h accounts for death due to Cerebral malaria with the help of World Health Organisa-

tion, an intensive programme has been initiated in the States of North Eastern Region of the country.

10. The following steps for imparting health education regarding the disease and seeking public co-operation and participation for controlling have been taken:-

(i) Panchayats and school teachers have been involved in the distribution of chloroquine tablets.

(ii) Drug Depots have been opened in inaccessible tribal areas. In some states this have been done in collaboraration, with the Tribal Welfare Departments.

(iii) A film 'The Threat' recently made has been released all over the country in fourteen regional languates.

(iv) Posters in regional languages "Fever may be Malaria Take Coloroquine tablets," have been supplied to the States for display in Panchayat Ghars, Schools, Primary Health Centres and sub-centres.

(v) A pamphlet in regional languages 'Malarai-what to do' giving the signs, symptoms, close schedule of choloroquine, indication and Centra-indication has been supplied to the States for distribution to Panchayats, school teachers and other voluntary agencies.

(vi) It is also proposed to orien the presidents and the secretaries of the Panchayats on malaria.

(vii) Folder on the role of the Medical Practitioners has been supplied to the States for distribution to medical practioners. Similarly, a pamphlet 'Why Malaria again' has been supplied, to the States for distribution to the Deputy Commissioners, Chief Medical Officers and Block Development Officers for apprising them about the existing problems of malaria and the action proposed to be taken.

(viii) To disseminate the anti-malaria message, special postal stationery has been released by Posts and Telegraphs Department.

Statement

The following remedial measures have been taken for the containment of malaria cases :—

1. The following agencies, which are responsible for carrying out anti-malaria measures have been requested to gear up the programme :

(a) Delhi Municipal Corporation;

(b) New Delhi Municipal Committee,

(c) Zoological Park,

(d) All India Radio

(e) President's Estate

(f) Indian Institute of Technology

(g) Northern Railway

(h) Defence Authorities

To bring about an effective co-ordination of these various agencies, a special Co-ordinating Officer has been appointed under the Government of India.

2. Government of India have provided adequate material and equipment and given financial assistance for meeting the operational cost to the concerned agencies.

The total assistance during 1977-78 was of the order of about Rs 32 lakhs and an amount of Rs 38 45 lakhs has been earmarked for this purpose during 1978-79.

3. The Municipal Corporation of Delhi have extended the anti-larval operations from 90 Sq. miles to 180 Sq miles. In addition to anti-larval work, spraying with BHC will be taken up in rural areas and riverine belt from Ist June, 1978.

4. 50 Malaria Clinics are functioning in Delhi and 50 more are being opened Over 500 Fever Treatment Depots are also being set up.

5. 40 teams for checking mosquito breeding in domestic situations have been put on the field.

6. The Director NMEP and the Commissioner, Delhi Municipal Corporation are holding periodical meetings to review the situation and coordinate activities of various organisations

Documents missing from Central Council Research in Indian Medicine and Homoeopathy

8464. SHRIMATI MRINAL GORE: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to State :

(a) whether certain important documents containing valuable original research data relating to medicinal plants availability in the country are Missing from the Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy and no action has been taken by the Council against the persons responsible for the loss,

(b) whether the loss was due to deliberate conspiracy on the part of certain senior officials in the council; and

(c) if so, the action taken to retrieve the official records and the present position ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) to (c) . A draft of the monograpgh entitled 'Medico-Botanical Flora of India, was compiled by the Central Council for Researh in Indian Medicine and Homoeopathy on the basis of various reports received by them from the Survey of Medicinal Plants Units and the same is missing. The matter is being enquired into by the Council and they have not yet come to any conclusion as to whether any official is responsible for the same.

MATTERS UNDERS RULE 377

12.05

(i) Reported Robbery in a Passanger Train on 21-4-1978.

श्री युवराज (कटिहार) : अध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुगलसराय से लखनऊ आने वाली यात्री गाड़ी 21—4—78 को प्रात: सवा चार बजे रूपामऊ स्टेशन के निकट लूट ली गई। सशस्त्र लुटेरे कम्पार्टमेंट न० 7536 के सभी यात्रियों के लगभग 25 हजार रुपये के जेवरात, नकदी, कीमती कपड़े, घड़ियां छीनकर फरार हो गये और इस डिब्बे के तीसरे डिब्बे में राजकीय रेलवे पुलिस के एक दर्जन हथियारबन्द जवान सुख की नींद सोते रहे। लूटे गये यात्रियों की चीख पुकार और असहाय महिलाओं का क्रदन भी उनकी नींद खोलने में सहायक नहीं हुआ। 722—वाई संख्या के डिब्बे में बैठे जी०आर०पी के बारह सिपाहियों तथा रेल कर्मचारियों ने भी यात्रियों की कोई सहायता नहीं की। जब ट्रेन रायबरेली रुकी तो स्टेशन के जी०आर०पी० कार्यालय में प्रथम सूचना को रिपोर्ट लिखायी गयी। ट्रेन की यात्रा निरापद नहीं देखकर जनता में आतंक फैलने लगा है।

(ii) Reported Cases of Food Poisoning in B.I.T. Mesra (Ranchi)

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, बिहार प्रांत के रांची क्षेत्र में बी०आई० टी० मिश्रा नामक एक इंजीनियरिंग संस्थान है, जहां बोर्ड की सूचना के अनुसार 200 व्यक्ति विषाक्त भोजन पाने के कारण बेहोश हो गये थे। इस संस्था में करीब-करीब एक वर्ष से हड़ताल चल रही है, जैसे ही यह संस्था खुली तो वहा के विद्यार्थियों में एक भोज हुआ जिसको खाने से 200 व्यक्ति विषाक्त भोजन के शिकार हो गये। मै सरकार से यह कहना चाहता हू कि इस शिक्षण संस्था में या तो किसी प्रकार की यह साजिश है अथवा वहां आपस मे कोई दलबंदी है जिसके कारण यह विषाक्त भोजन की घटना घटी है, जो कि बहुत ही चिन्ताजनक बात है। मैं शिक्षा विभाग से यह आग्रह करूंगा कि इस घटना की तुरंत जाच कराई जाये और संबंधित आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(iii) Reported Attacks by Hooligans on Foreigns Residents of Auroville Pondicherry

SHRI BIJOY SINGH NAHAR (Calcutta North-West) : A report from Auroville, Pondicherry, has disturbed many in the country.

On 17th April, 1978, some foreign residents of Auroville who have made India their home for the last ten years suffered at the hands of hooligans who launched barbaric attacks on these foreigners who are great admirers of this country's culture and philosophy and are following the path of Shri Aurobindo.

The scene of this barbarism was Bharat Nivas, a building under construction at Auroville with huge grants of the Central and State Governments given to Shri Aurobindo Society for the benefit oi Auroville. Bharat Nivas is a centre of Indian culture and its purpose is to foster the unity of India with other nations of the world.

In pursuance of this aim, residents of Auroville had organised a month-long cultural programme at the said Bharat Nivas to celebrate Pongal, the

the Tamil New Year commencing from 14th April 1978 in close collaboration with the local Tamil villagers. For the first three days the programme went off peacefully. But on the Fourth day, *i. e.* on the 17th April, 1978, at the instigation of a person Shri Navjat, an attack was made by a group of persons who were armed with sticks and steel rods. The attack was made at about 8 A.M. when one Mr. Frederick, a German National and a prominent member of Auroville for the last ten years was along, arranging for the programme in Bharat Nivas things. His personal belongings were forcibly removed and he was beaten up mercilessly. He sustained serious injuries and fell down unconscious. In the meantime, one Mr. Richard *alias* Narad, and one Mr. David rushed up to protect Mr. Frederick. They too were beaten up and were seriously injured. All of them have been removed to the hospital. It is apprehended that this outbreak of violence is the beginning of a pre-planned series, which needs immediate, intervention. Auroville has been sponsored by UNESCO by three unanimous resolutions of 1976, 1978 and 1970. About 300 foreigners have settled down permanently and they are completely self-reliant. They also work for rural development of about 12 to 15 neighbouring villages under a project of Integrated Rural and Educational Development Programme.

It seems after the passing away of the Mother, there have been a lot of mismanagements, and huge grants from the Central and State Governments totalling for Bharat Nivas alone a Rs. 74·05 Lakhs have been received and remained unspent and unaccounted for. The Government Audit of 1977 has shown not less than Rs. 22·64 lakhs as discrepancy, and the Audit has also charged them with fabrication and all that. The Audit has also pointed out that the authorities of Sri Aurobindo Society of which Shri Navjat is head now, have not submitted to the Government the evaluation and completion certificates of the amounts spent from the Government grants although years have a passed.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour) : This Navjat is a fraud and he is ruining the institution.

SHRI BIJOY SINGH NAHAR: They should now be directed to give proper accounts, failing which they should be charged . There are a lot of inner conflicts and it is necessary that the Central Government, since it involves central money as well as money of foreigners and the United Nations, should intervene in order to set things right and get rid of undesirable elements from this management.

I will suggest that team of Members of Parliament should visit this institution and give a factual report to the Government for their guidance and making proper arrangements for this institution.

(iv) PRESENT STATUS OF BANKING SERVICE COMMISSION

SHRI SAUGATA ROY (Barrackpore): Mr. Speaker, Sir, Under rule 377, I raise the following matter of urgent public importance with regard to the present status of the Banking Service Commission. The Banking Service Commission was set up by an Act of Parliament in February 1977. After the Janata Party came into power, in September, 1977, it came forward with an ordinance calling for the repeal of the Banking Service Commission. A Bill to replace the ordinance was introduced in the winter session of the Parliament. The Bill was opposed by our Party in the Lok Sabha and ultimately it was voted down in the Rajya Sabha, on 23rd December, 1977.

Under Article 123(2)(a), the ordinance will lapse six weeks after the expiry of the winter session of the Parliament and according to that, the ordinance has already lapsed. The Government has not come forward with any fresh Bill in the current session of the Parliament for repealing the Banking Services Commission Act.....

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkal): On the point of Order, Sir ....

MR. SPEAKER : What is the rule breached ?

AN HON. MEMBER : He is going beyond the written statement.

SHRI SAUGATA ROY : I did not get a copy of it.

MR. SPEAKER : I will give you a copy, you read it. You should have kept one copy for yourself.

SHRI SAUGATA ROY : So, legally, the Commission stands restored, but the Government continues to keep the Commission's office locked. The bank recruitment is stopped altogether. The Chairman and thirty employees have not been reinstated; as a result of all this, the banking recruitment has come to a standstill. This is a delibrate contempt of the Parliament and an attempt to bypass the Parliament by the Government. A Commission which has been restored according to law, is not being allowed to function.. ....

MR. SPEAKER : You cannot go on like this.

SHRI VAYALAR RAVI : On a point of order, Sir.

I would like to draw your attention to Rules 97, 98, 99 and onwards all relating to a Bill passed by this House.

MR. SPEAKER : I am not able to to follow your point of order. Is it against the statement or what ?

SHRI VAYALAR RAVI : The hon. Member has raised this point and I want to draw your attention to Rules 97 onwards ..

MR. SPEAKER: You must be objecting to something.

SHRI VAYALAR RAVI : This is to help you, Sir. This is a matter with which you are concerned and all of us are concerned. We passed this Bill. And we sent it to the Rajya Sabha and if I remember aright, Rajya Sabha has turned it down. Naturally , I do not know whether there has been a report to the House by an the hon. Secretary as he is bound to report to the House the decision of the Rajya Sabha. Then we can take into account what is the message that comes from that side. This is very clearly stated in all these rules 98, 99 and 100 all relating to the Bills passed by the other House with or without amendments. As you know, the other House has turned it down. Naturally we are expecting the decision of the Upper House and a report to the House so that we can take it up. But we are not given any opportunity to take that into account. We objected very strongly to government proceeding with the Bill. The Government is treating this House with contempt and they are proceeding in their own way and they have started recruiting. What they are doing , Mr. Saugata Roy has said. I would like to know what is your ruling on this matter.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): I am rising seeking a clarification. What has been said is something of a very serious nature. But, at the same time, I would like to have your observation as to what you are doing about setting up a parliamentary committee for scrutinishing the nationalised banks and financial institutions. We have a Public Undertakings committee but banks cannot be touched. We have a Public Accounts Committee.

There you can not touch the banks. We have an Estimates Committee. You can not touch the banks and financial institutions. It is very important that in this session we take a decision to set up a parliamentary committee on the lines of the committee on Public Undertakings to scrutinise nationa lised banks and other financial institutions which are not covered by these committees.

SHRI SAUGATA ROY : On a point of order, Sir. You were kind enough to permit me to speak on this subject under Rule 377 to raise a matter other than a point of order. But my main point was with regard to Rule 222 wherein I raised a question involving a breach of privilege against the Finance Minister, Shri H. M. Patel. You informed the House that you have written to Mr. Patel since he is a member of the House asking his opinion on my privilege motion. I would like to know from you by what date we will have an answer from the government because in the meantime banking recruitment has come to a standstill all over India. Corruption and malpractices in recruitment are continuing while the government is dilly-dallying.

I also want to know the legal status of the Banking Service Commission at the present moment, whether the government has a right to keep the office of the commission locked and whether it has a right to sack the Chairman of the Commission and the 30 employees belonging to it. These are all legal and constititional actions which demand urgent attention to be given to it.

MR. SPEAKER: We are on one point and you are going to another point. Rule 222 motions are separately dealt with. Now you are on 377. There is nothing more than that. There is one other person under Rule 377. At the appropriate time Rule 222 motions will be considered.

SHRI SAMAR GUHA (Contai): On a point of order. Last year in the course of the debate on the Finance Bill I raised this point on the floor of the House that a proper inquiry should be made regarding the functioning of the financial institutions, particularly, the nationalised banks.

MR. SPEAKER: Which is the rule that is broken ?

SHRI SAMAR GUHA: I am finishing. The hon. Minister made a commitment on the floor of the House and one year has since passed and we have not heard anything about it.

MR. SPEAKER: A point of order arises only when there is a breach of a rule. Everything is not a point of order.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): I want to make a submission....

MR. SPEAKER: If you want to make any submission, we have now published in the bulletin the procedure. You give me a notice of your submission and if I

consider it important and urgent, I will permit you......(*Interruptions*) My difficulty is......(*Interruptions*)

I am on my legs please. I have been seeking your co-operation to see that an orderly debate is there. I have allowed five 377 statements. I have even further said, if certain urgent things happen; you bring them to my notice. I will consider it. If I agree with you that it is urgent, I will allow you.

(*Interruptions*)

Why do you not allow me ? Everything that comes to my notice, I give my immediate attention. If I think it is urgent, I allow it, otherwise not.

I am seeking the co-operation, particularly of the senior members. It is not the new members who are giving encouragement to all this. It is you (senior members) who are coming in the way. You must co-operate with me. My anxiety is not for anything else. My anxiety is to have an orderly House. We can debate in a parliamentary way and discuss matters. If you have any important matter bring it to me, I shall discuss with you. I will try to satisfy you. If I am satisfied, I will give you opportunity.

SHRI VASANT SATHE (Akola): Please allow me. I want to co-operate with you.

I have for the last three days given you notice regarding medical college students. Calling Attention Notices also have been given. Yesterday when I pointed it out to you, I requested you to allow me at least to-day. You said 'I will consider to-morrow'. (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Mr. Sathe, so that maximum members may be given opportunity under 377, as a working rule I am not allowing more than one 377 statement to an individual member per week.

SHRI VASANT SATHE: It is not a question of individual.

MR. SPEAKER: Every individual thinks his point is very important.

SHRI VASANT SATHE: Importance should be considered.

MR. SPEAKER: Every individual thinks his point is very important. I am not saying that your point is not important. Everyone thinks his point of view is important. I am allowing 5 per day and if I allow one for a particular member, in a week 25 members get an opportunity.

SHRI VASANT SATHE: What about the subject ? How are....(*Interruptions*)

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो दिल्ली में बड़ी गभीर समस्या पैदा होने वाली है। दिल्ली के सभी हास्पिटल्स में हड़ताल हो जायेगी, सारे डाक्टर्स हड़ताल पर चले जायेंगे और यहां के मेडिकल हालात खराब हो जायेंगे। आप इसको चाहे काल अटेंशन के रूप में ले या नियम 377 में ले लें और मिनिस्टर साहब से कह दें कि इस मामले को वे देखकर जल्दी हल करें।

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I want to bring the matter to your notice which I consider to be of extremely urgent importance. Mr. Malhotra just now mentioned that medical college students and internees are on a hunger strike. If Delhi hospitals go on strike here will be utter chaos and mismanagement. We do not want to add to the problems. We have enough already and the Government must intervene effectively to put an end to this dispute. The demands are very legitimate.

The second thing is about Tobacco growers. This year there is a crash in price. (*Interruptions*) I only want to make one submission that tobacco has been sold at 25% of last year's price. The cigarette price should also come down.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN (Coimbatore): I would like to make a submission that we have given again and again notice of a Resolution to go into this question of banking institutions. It is an urgent matter. This may kindly be allowed.

(v) DEMAND FOR RUNNING EXPRESS TRAIN FROM DURG TO BANARAS

श्री मोहन भैय्या (दुर्ग) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

दुर्ग से बनारस एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांग को लेकर विगत 8-4-78 से देश की महान औद्योगिक नगरी भिलाई में आन्दोलन चल रहा है। रेल पटरी के किनारे लो

[श्री मोहन भय्या]

निरन्तर भूख हडताल पर बैठ रहे है । ट्रेनो का श्रावा गमन रोका जा रहा है । आन्दोलन उग्र रूप ले रहा है । यदि समय रहते ध्यान नही दिया गया तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है । मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ अचल से लाखो लोग उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थानो की यात्रा करने जाते है । छत्तीसगढ अचल मे विहार-उत्तर प्रदेश वासियो की यह पुरानी माग है । यह औद्योगिक श्रमिको की माग है जोकि भिलाई इस्पात सयत्र सीमेन्ट फैक्टरी "भाण्डर एव जामुल" लोहे एव कोयले की खानो आदि स्थानो में कार्यरत है । इस माग के समर्थन में यहा के करीब दस हजार हस्ताक्षर से भी ज्यादा भेजे जा चुके है । बीस ससद सदस्यो से हस्ताक्षर युक्त एक ज्ञापन भी इस सम्बन्ध में रेल मत्री को दिया गया है । दक्षिण पूर्व रेलवे के सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ क्षेत्र से औसतन 411 लोग प्रति दिन वाराणसी या इलाहाबाद की तरफ रेल मे यात्रा करते हैं । इसके अलावा कुछ लोग बस से यात्रा करते हैं । पश्चिमी एव उत्तर बिहार के रहने वालों को सीधी गाडी न होने के कारण टाटा-नगर होकर जाना पडता है । पश्चिमी एव पहाडी क्षेत्र के उत्तर प्रदेश वासी नागपुर होकर यात्रा करते हैं । दुर्ग वाराणसी ट्रेन चलने से यह सब लोग इसी गाडी से यात्रा करेंगे एव यह औसतन सख्या 411 से बढ़कर 1000 पहुच जायेगी । दक्षिण पूर्व रेलवे के अनुसार इस गाडी को चलाने से कोई आर्थिक घाटा नही है । रेलवे ने इस ट्रेन को चलाने की सहमति रेल मत्रालय को दी एव इसके समर्थन मे एक टाइम टेबल भी दिया था । इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा लिखे गए पत्र के उत्तर में रेल मत्री द्वारा बताया गया है कि लाइन क्षमता की कमी होने के कारण यह गाडी नही चलाई जा सकती । किन्तु हम यह बताना चाहते हैं कि इस माग के बाद गगा-कावेरी, वाराणसी कटनी के रेल मार्ग पर चलाई गई एव कलिंगा एक्सप्रेस बिलासपुर कटनी रेल मार्ग पर चलाई गई । उत्कल एक्सप्रेस पहले सप्ताह में दो दिन चलती थी, अभी सप्ताह में चार दिन चलाई जाती है । गगा कावेरी एक्सप्रेस दुर्ग वाराणसी ट्रेन की माग पर पहले वाराणसी कटनी बिलासपुर होकर जाने वाली थी किन्तु उसका रास्ता बदल कर वाराणसी कटनी इटारसी कर दिया गया । इस गाडी के चलने से छत्तीसगढ क्षेत्र का व्यापारिक-सामाजिक-शैक्षणिक-सास्कृतिक विकास होगा । इस पिछडे हुए इलाके का सीधा सम्बन्ध उत्तर प्रदेश के धार्मिक तीर्थ स्थानो से हो जायेगा ।

उपरोक्त सारे तथ्य रेल मत्री के निर्देशानुसार मैंने रेल मत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियो के समक्ष 16-4-1978 को रखे । उन्होने भी मांग को न्यायसगत माना है और ट्रेन चलाने की सभावना से इन्कार नही किया है । अत आन्दोलन मे प्रकट हो रही जनभावनाओ को देखते हुए भिलाई से वाराणसी तक एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की माग को रेल मत्री महोदय अपनी स्वीकृति प्रदान करे ।

9 मार्च, 1978 को मैंने रेल मत्री महोदय को लिखा था कि भिलाई इस्पात सयत्र में कार्यरत दक्षिण भारत के निवासियो के आवागमन सम्बन्धी कठिनाइयो के निराकरण हेतु त्रिवेन्द्रम तक सीधी रेलगाडी चलाई जाय ऐसे सुझाव भी दिये है

श्री सुरेन्द्र विक्रम (शाहजहापुर) · मत्री जी यहा पर बैठे हुए है, उन्हे इस का स्पष्टीकरण देना चाहिये ।

श्री मोहन भैय्या : इस सम्बन्ध में मुझे माननीय रेल मत्री जी का 22 अप्रैल, 1978 का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमे उन्होने कहा है कि पहली अक्तूबर, 1978 से लागू होने वाली अगली समय-सारणी में दुर्ग और वाराणसी के बीच सप्ताह मे दो बार चलने-वाली एक गाडी चलाने के लिये मैंने हिदायतें जारी कर दी है....

MR. SPEAKER: Please conclude. You are going out of the statement now.

12.28 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATION UNDER ESSENTIAL COMMODITIES ACT, 1955

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): Sir, I beg to lay on the Table a copy of Notification No. S.O. 257(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 10th April, 1978, under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955. [*Placed in Library. See No. LT—2188/78*].

NOTIFICATION UNDER COMPANIES ACT, 1956.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI NARSINGH YADAV): Sir, I beg to lay on the Table a copy of Notification No. G.S.R. 477 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 15th April, 1978, under sub-section (3) of section 637 of the Companies Act, 1956. [*Placed in library. See No. LT—2189/78*].

NOTIFICATION UNDER CUSTOMS ACT, 1962.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLAH): Sir, I beg to lay on the Table a copy of Notification No. 90—Customs (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 27th April, 1978 under section 159 of the Customs Act, 1962 together with an explanatory memorandum. [*Placed in library. See No. LT—2189A/78*].

12.28½ hrs.

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

SEVENTY-EIGHTH & EIGHTY-FIRST REPORTS

SHRI C. M. STEPHEN (Idukki): Sir, I beg to present the following Reports of the Public Accounts Committee:

(1) Seventy-eighth Report on Paragraph 49 of the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1975-76 Union Governmet (Civil Revenue Receipts, Voleme II Direct Taxes relating to Working of Salary Circles.

(2) Eighty-first Report on Paragraphs 9 and 11 of the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1975-76 Union Government (Defence Services) relating to Ministry of Defence.

12.29 hrs.

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

TENTH REPORT AND MINUTES

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Sir, I beg to present the following Report and Minutes of the Committee on Public Undertakings:—

(1) Tenth Report on Unusually High Expenditure by Public Undertakings for their Head Offices.

(2) Minutes of the sitting of the Committee relating to the above Report.

12.29 1/2 hrs.

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

TWENTY-FIRST AND TWENTY-THIRD REPORTS

SHRI SURAJ BHAN (Ambala): Sir, I beg to present the following Reports (English and Hindi versions) the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes:—

(1) Twenty-first Report on the Ministry of Railways (Railway Board)—Reservations for, and employment of, Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Northern Railway and award of petty contracts to Scheduled Casts and Scheduled Tribes in Northern Railway.

(2) Twenty-third Report on the Ministry of Finance, Department of Revenue (Indirect Taxes Division)—Reservations for, and employment of, Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Central Board of Excise and Customs and its field formmations.

12.30 hrs.

PETITION *RE*. GRIEVANCES OF EMPLOYEES OF COAL INDIA LTD.

SHRI DINEN BHATTACHARYA (Serampore) : Sir, I beg to present a petition signed by Shri Chitta Ray and others regarding grievances of employees of Calcutta offices of Coal India Ltd. and its subsidiary companies.

12.30 hrs.

STATEMENT *RE*. REPORTED AIR BROADCASTS ALLEGING TICKETLESS TRAVEL BY SOME CONGRESS (I) WORKERS

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI JAGBIR SINGH) : A news item was broadcast, by AIR in the morning of April 7, 1978 in English and Hindi bulletins that three Congress (I) Members, who were accompanying the Party President on way from New Delhi a Aligarh in the ACC Compartment of a train, were 'allegedly caught travelling without ticket They were fined Rs. 100/- each.

The news item was based on a Samachar report which was also carried by some of the newspapers. AIR report put it very cautiously and used the words "allegedly caught'. It was a categorical report by Samachar which even gave the amount of fine imposed.

When the report was denied by Shri Buta Singh, General Secretary of Congress (I), the denial was also broadcast on April 8, 1978, both in the English and Hindi bulletins by AIR.

It is incorrect that the original news item was broadcast for three days. It was broadcast only once in the respective bulletins. The denial by Shri Buta Singh was likewise carried in the concerned bulletins.

It is also incorrect that the news about the alleged tickletless travelling was broadcast even after the denial by the Railway Authorities on the Floor of the House.

12.33 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

SIXTEENTH REPORT

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): I beg to move:

"That this House do agree with the Sixteenth Report of the Business Advisory Committee presesented to the House on the 26th April, 1978."

MR. SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Sixteenth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 26th April, 1978."

The motion was adopted.

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): Sir, the Railway Minister is here. A Railway strike is going on in the South and we are suffering a lot.

12.35 hrs

APPROPRIATION (NO. 3) 1978

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : I beg to move*

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1978-79 be taken into consideration."

MR. SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1978-79 be taken into consideration."

As regards scope of the discussion, Rule 218(5) says:

"218(5). The Speaker may, in order to avoid repetition of debate, require members desiring to take part in discussion on an Appropriation Bill to give advance intimation of the specific points they intend to raise, and he may withhold permission for raising such of the points as in his opinion appear to be repetitions of the matters discussed on a demand for grant or as may not be of sufficient public importance."

---

*Moved with the recommendation of the President.

So, whatever points have been covered in the Demands, I have disallowed them. It is only in respect of the Demands which have not been covered, observations will be allowed.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Sir, Rule 218(4) says like this:

> "218(4). The debate on an Appropriation Bill shall be restricted to matters of public importance or administrative policy implied in the grants covered by the Bill whih have not already been raised while the relevant demands for grants were under consideration."

Sir, Railway was discussed but that particular point was not covered or highlighted. A Member has a right to say anything that has not been replied to by the Minister.

MR. SPEAKER: I am not in a position to get your point.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Sir, you can restrict me if I say something which is not of public importance. You can restrict me if it is not connected with the administrative policy implied in the grants. You can restrain me if I bring something which is not covered in the the Grants. You have now guillotined all those demands while the relevant demands for grants were under discussion. That means the grants which were being discussed, in that the point was not high. lighted on the Minister's reply did not cover that point or the House was not satisfied with the reply.

MR. SPEAKER: It is not like that. It has not been raised by any Member.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: If the Minister did not reply to the point....?

MR. SPEAKER: It is mentioned here.

> "—he may withhold permission for raising such of the points as in his opinion appear to be repetition of the matters discussed on a demand for grant or as may not be of sufficient public importance."

SHRI ANNASAHEB GOTKHINDE (Sangli): It was a specific matter regarding Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu zones while fixing the price of levy sugar. Nobody can say that it is not a matter of sufficient public importance. Neither the Minister of State nor the Cabinent Minister of Agriculture and Irrigation had even touched this point.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I have had the privilege of speaking on the Appropriation Bill for many years. This is the first time I am hearing such observations from you; I regret to say this.

SHRI VASANT SATHE (Akola): Two things will be important under subclauses 4 and 5. If it is a matter of public importance, although the demands for grants had been discussed, if it arise thereafter, it has to be raised now. Then there could be no bar under subcaluse (4) to stop that matter being discussed. Under (5), it is the time to be given; notice is normally to be given before 10 O'clock. What happens? You have allowed some time in your notice which was sent to us this morning. That envelope comes round about 9 or 8 'clock sometimes even later; some people get it earlier.

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDHAVATE): Le gets up late.

SHRI VASANT SATHE: If at that time the Member has some other business and he has to go out for a meeting, why should you debar him from giving notice before 11 O'clock to you? All that you want under the rules is notice in advance. Why do you want to prevent a Member? That is precisely what has happened to me today. I had to go out for a meeting.

MR. SPEAKER: Many people go out, for marriage or for some thing else.

SHRI VASANT SATHE. It is your disciplinary power and you should allow us to speak on demands which were not discussed at all, for instance, civil aviation and tourism.

MR. SPEAKR: No, I am sorry.

SHRI C. M. STEPHEN (Idukki): You have stated in the bulletin, 'before 10 O'clock. There is distinction between notice being given and advance intimation being given with respect to a debate. With regard to notice there is a standing rule that the notice must come before 10 O'clock; everybody knows that. Here is a question of debate coming up when advance intimation has got to be given and the 10 O'clock deadline will be very harsh. It is not contemplated also. Kindly go through the spirit of the rule. "The Speaker may, in order to avoid repetition

[Shri C.M. Stephn]

of the debate............"That is the most important part of it. Points will have to be spent out to you before he speaks; it should be before the debate, not before 10 O'clock. It happens that the notice in the bulletin escapes them or it reaches them late and they are not aware of it. Therefore I submit that with respect to notice by 10 O'clock. there must be relaxation. Any notice that comes to you before the debate begins must be taken note of and permission must be given because that is the spirit of the rule, it is to avoid repetition of debate. There is a difference between the rule with regard to notice and intimation with respect to the debate.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai) : May I seek a clarification from the Chair ? Where the rule refers to the repetition of a debate, it means that a point has been raised by an hon. Member and that point has been dealt with by the Minister concerned. If the point has not been dealt with by the Minister concerned, then there has been no debate. The same point may be raised by the hon. Member, because it happens to be a matter of public importance. Therefore, your ruling in this matter should be that if a point of sufficient public importance had been raised by an hon. Member, and had not been dealt with by the Minister concerned, then the hon Member who raised it or any other hon. Member would be quite in order to raise the same point and that would not be considered as repetition of the debate. This is extremely important because a Member may be very serious about a particular point and the country's mind may also be agitated on that point but the Government may conveniently pass over that point Therefore, it should be your ruling that that can of course, come within the scope of the discussion.

MR SPEAKER : When we come to the actual point, we will consider that.

SHRI VASANT SATHE : What is your ruling ? Kindly see Rule 332.

It reads :

> "Every notice required by these rules shall be given in writing addressed to the Secretary-General, and signed by the member giving notice, and shall be left at the Parliamentary Notice office which shall be kept open for this purpose between the hours to be notified from time to time on every day except Sunday,.."

This 10 O'clock business applies to the notice which is required by Rules : Sub-rule (5) of Rule 218 does not talk of notice at all. It talks only of the intimation to be given in advance before the debate starts Under the Rules, you cannot, even by circulation in your bulletin, tell us that it must be given before 10 O' clock, which is contrary to the Rules. I go to that extent Otherwise, you do not use your discretion How can you debar us from raising ? I want your ruling

SHRI C.M. STEPHEN : It is not a question of ruling and all that. It is a question of just accommodating. The Members have brought it to your notice that for certain reasons, they cannot give notice before 10 o'clock The point is whether those Members should also be allowed to participate if there is no repetition and if they have given advance intimation.

MR SPEAKER : The question arises when there is a written notice, whether it is before or after 10 O' clock Otherwise, it does not arise at all.

The first notice is that of Mr Jyotirmoy Bosu. Mr Basu has given as many as fourteen. He has avoided thirteen and given fourteen. The first one is, the Government's Industrial Policy with particular reference to the attitude towards the monopoly houses and multinationals This has already been debated and the Minister has replied to it.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : I will cover new grounds. It is a matter of sufficient public importance

MR SPEAKER : No. The matter has been raised, debated and replied to.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : The debate on an Appropriation Bill shall be restricted to matters of public importance.

MR SPEAKER : Undoubtedly.

The Rule further reads :

> "..implied in the grants covered by the Bill which have not already been raised while the relevant demands for grants were under consideration.

These demands were raised and considered.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : That way you will get no cooperation from us.

MR SPEAKER. I cannot purchase your cooperation on your terms.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : You allow me to speak. When I get into a forbidden area, you tell me. This House is totally averse to such observations calling from the Chiar. Economic Issues have got to be debated on the floor of the House.

MR SPEAKER : Economic issues are not the monopoly of a single Member it is the monopoly of the House.

This point has been raised, debated and replied to. I come to No. 2.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : Why are you labouring yourself unnecessarily ? You allow me to speak.

MR SPEAKER : I cannot allow. I have got the right to fix the time. Do not bother about that. The Rules provide for that. I come to the second one, viz, the activities in India of the following MNCs · ITC, Hindustan Lever, Pfizer, etc. This has also been raised, debated and replied to.

SHRI JYOTIRMOY BOSU No, Sir On which day ? In which debate? Let the library be brought here

MR SPEAKER: It is not for me to bring the library here.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: You tell me what I should not speak.

SHRI VAYALAR RAVI · You are going to give us limited time 5 or 10 minutes and nobody can cover everything under the sun in that short time. Allow us to speak and if there is something you can stop us.

MR. SPEAKER: I think it will be an easier procedure. Each member will have 5 minutes.

SHRI JYTIRMOY BOSU · I require 10 minutes.

MR SPEAKER : No There are a number of persons. Not more than 5 minutes.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : 10 minutes.

MR SPEAKER : I am presiding, not you ! After 5 minutes you should stop. The Finance Bill will have to be passed.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : Then I shall sit down.

MR SPEAKER : That is a very good gesture. Shri Prasada Rao.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : I will take 8 minutes.

MR SPEAKER : No, Mr Bosu Only 5 minutes. No bargaining.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : They have claimed that there is increase in food production But if you look at the Economic Survey of the current year, you will see that in coarse cereals including rice, other cereal, pulses, etc, the production has come down substantially. They talked about the most seriously affected countries. The Minister said that food production during 1974-76 was higher than in the previous triennium 1971-73. But if you read the United Nations report on this, page 18, it will show that what the minister had claimed is totaly baseless. There is so much famine in the sphere of edible oil. The report wich came in Business Standard dated 19th March is also a revealing thing, which belies what the minister has claimed. The Economics and Statistics Directorate of the Agriculture Ministry, and ICAR *do the costing of jute*, tobacco, sugarcane and other cash crops always in such a way that it is titled heavily towards the industrialists and the farmer is being exploited He is giving a pound of flesh on every commodity when he parts company with it. The matters relating to the most important scientific body in the country involving ICAR need immediate examination and probing A team of scientists of national importance must be deputed to do job evaluation of ICAR They must also tell us what steps they have taken on the Gajendragadkar Commission's report.

The permission for indiscriminate diversification to different businesses given to India Tobacco Co has enabled them to diversify into hotels fisheries and several low priority profitable areas. They are using dummy firms like Utkal Marine Co. and so many others Small fishermen are dying Small middlemen are dying. The whole thing is being swallowed by big business comapnies Cadbury & Co. which has earned enormous profit has been allowed to start and apple juice plant in Himachal Pradesh. Britania Buscuit Co are producing three times what they are permitted to produce under their licensed capacity. Then there is Union Carbide and so on. These are all economic offenders. They are manipulating invoices while exporting fish and so many other things. This year there has been plunder of the tobacco gorowers in Andhra Pradesh. The tobacco growers have lost not less than Rs 50 to 60 crores. I want to know whether the price

[Shri Jyotirmoy Bosu]

of cigarettes will be reduced to the extent of the tobacco growers' loss. Hindustan Levers Ltd. repatriated the maximum amount of profit. They have been caught with a tankerful of adulterated til oil in their Ghaziabad factory. I would like to know what has been done about it. The soap they are marketing has 25% less total fat content. Yet the Industry Minister is a silent spectator. The Commerce Minister and Civil Supplies Minister are silent spectators. It is very important that these things should be immediately looked into.

Sir, the Cadburys Ltd. have been charged by MRTP. Their profit for 1975 on Paid-up capital was 131·9 per cent. Their profit in 1977 on Paid up capital was 320 1 per cent. We are moving towards socialism. We realise this. May & Baker & Co. plundering the country have set up a dozen benami firms in order to hoodwink the MRTP. The Government's new drug policy in refusing to implement the majority Report of Hathi Commission on nationalisation is regrettable.

I would also like to know who are the owners or controlling hands behind the Coca Cola and Campa Cola. Is that the same interest and the same set of people ? I would like to know this immediately. Multinationals are being allowed to enter freely in low priority consumer goods areas, the highly profitable areas. The Hindustan Levers made a remittance of their profit to the extent of Rs 3,09,94,385. It is a record remittance Glaxo remitted Rs 86,44,134. The paid up capital of Colgate Polmolive is Rs 1 5 lakhs Their remittance is Rs 1,55,71,737. The remittance of Bata Shoes is Rs 14,02,500. The remittance of India Tobacco Company is Rs 2,04,17,637. Pfizer & Co with a paid up capital of only Rs 2 lakhs, in one year, in 1976, made a profit of Rs 2·36 crores and the total profit made so far with these Rs 2 lakhs is Rs 16·9 crores. I would like to have the explanations from the Ministers concerned on this issue. What the Finance Minister is doing with regard to Kapadias and Kohinoor Mills ? There is a fraud of Rs 26 crores. I would like to know the details as to what steps they have taken and whether they are going to prosecute them or not.

श्री केशवराव धोंडगे (नांदेड) : सदर साहब, अणु शक्ति के बारे में जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने घोषणा की है, मुझे बड़ा ताज्जुब मालूम होता है कि पूरी गलती पहले की गवर्नमेंट की है, हर पालिसी उनकी गलत है, ऐसा कहकर अणु क्षेत्र में जो प्रगति हम करना चाहते हैं, अणु विस्फोट कर के विकास करना चाहते हैं, उसको मना करना मेरे ख्याल में शरणागती है, बुजदिली का मामला है । इसलिये मै हुकूमत से कहना चाहता हू कि आप उसके दबाव के सामने झुक गये हैं, और कहना चाहते है कि साइंटिस्टो की और एक्सपर्ट लोगो की राय आप की जेब में है । हम यहां बैठने वाले क्या कोई नही हैं ? हम कहना चाहते हैं कि मुल्क की हिफाजत के लिहाज से, वक्त आ जाये तो आजादी को बरकरार रखने के लिये एटम बम रखना पड़ेगा । आपको इस हाउस को विश्वास में लेना पड़ेगा । मगर महज उस कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट किया था इसलिये वह करना नही है, यह ठीक नहीं अमेरिकन लाबी के सामने यह झुकना है, ऐसा में कहता हूं ।

दूसरी चीज यह है कि देश के बारे में हमको एटामिक एनर्जी में स्वावलबी बनना बहुत जरूरी है, मुल्क के लिहाज से बहुत जरूरी है, इसकी कोशिश करनी चाहिये ।

इसके अलावा ग्रामीण एरिया में टेलीफोन, पोस्टआफिस और टेलीग्राफ का इंतजाम बहुत कम है । मुझे परसों मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि एक एक जिले में 8 जगह पर है, 6 जगह पर है, इसके मायने यह हैं कि देहात के लोगो को हम सुविधाए देने को तैयार नही है । देहात के लोगों को आप इन्सान मानने के लिये तैयार हैं या नहीं यह मेरा हुकुमत से सवाल है ।

इसलिये मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि वह भी इन्सान हैं, उनको भी उतना ही हक है जितना शहर के लोगों को हक है । दवा को छोड़कर उनके लिये टेलीफोन का इतजाम नहीं हैं, पोस्टआफिस का इंतजाम नहीं हैं । आप उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन के बारे में मैं गुजारिश करूंगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पालिसी थी, उसमें तबदीली करना बहुत जरूरी है। बाहर के फार्नर्स के लिहाज से जो कुछ सुविधाए दी जाती हैं, उन्हें देहात के लोग, हिन्दुस्तान के लोग भी देखना चाहते है। वे लोग हिन्दुस्तान के पर्यटन केन्द्रो, तहजीब और तमद्दुन की जगहो को देखना चाहते है, लेकिन उन के लिए कोई सहूलियते नही हैं। यह सारी व्यवस्था इतनी महगी है कि गरीब आदमी उस का फायदा नही उठा सकता है। ऐसा मालूम होता है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट सिर्फ बडे बडे लोगों और फारेनर्ज के लिए है—अगर किसी को कोई टूरिस्ट प्लेस देखनी हो, तो वह फारेनर बन कर आये, गरीबो के लिए यह मना है। इस के माने ये हैं कि नो एडमीशन फार इंडियन्ज। यह बडे ताज्जुब की बात है। इस लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट में बुनियादी तब्दीली करनी चाहिए।

मैं गुजारिश करना चाहता हू कि नादेड के लिए भी हवाई जहाज की सर्विस शुरू की जाये। इस बारे में नेशनल इकानोमिक सरवे इंस्टीट्यूट ने 1974–75 में एक कामर्शल सरवे किया था। नादेड मराठवाड का एक प्रसिद्ध नगर है और पर्यटन केन्द्र है। वहा गुरु द्वारा है। बम्बई से हैदराबाद तक रोज दो वक्त की सर्विस है। अगर नादेड को भी इस सर्विस से जोड दिया जाये, तो उचित होगा। मैं समझता हू कि नादेड के लिए एयर सर्विस शुरू करना बहुत जरूरी है।

कंधार मे भी एक एयरस्ट्रिप बनाने की माग की जा रही है। वहा के शिवाजी कालेज ने कहा है कि हम लोग इस में मदद देने और श्रमदान करने के लिए तैयार है। लेकिन इस के लिए न तो स्टेट गवर्नमेंट तैयार है और न केन्द्रीय सरकार तैयार है। कंधार के नजदीक बहादुरपुरा शातिघाट के पास पर्यटक केन्द्र स्थापित करने के बारे मे मुझे महाराष्ट्र एसेम्बली में आश्वासन दिया गया था। लेकिन मैंने सुना है कि सरकार नये पर्यटक केन्द्र बनाने के लिए तैयार नही है। ऐसा मालूम होता है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट में भी फैमिली प्लानिंग आ गया है। मैं निवेदन करना चाहता हू कि हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रो मे सही सस्कृति मौजूद है। सरकार को उसे देखने के लिए लागो को मदद करनी चाहिए और बहादुरपुरा शातिघाट के पास पर्यटक केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था करनी चाहिये।

जहा तक हवाई जहाजों में व्यवस्था का सवाल है, मैं एयरबस मे बम्बई से दिल्ली आया, ता मैंने देखा कि वहा पर मच्छर थे वगैर टिकट के, जो देशी और विदेशी लोगो का खून चूसते थे। इन बातो से हमारे मुल्क की बदनामी होती है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हवाई जहाज का एक्सीडेंट भी नही होने देना चाहिये।

अगर सरकार लोगो को न्याय देने की व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण करना चाहती है, तो उसे मराठवाडा के लिए औरगाबाद मे हाई कोर्ट बैच स्थापित करनी चाहिए।

जो गरीब लाग कोर्ट में आते हैं, वहा उन के लिए बैठने की जगह नही है, कोई वेटिंग रूम नही है और इस लिए उन्हें धूप और बारिश में बैठना पडता है, जबकि बडे बडे लोग बार एसोसियेशन के रूम में बैठते हैं। लिहाजा हर कोर्ट में आम लोगों के बैठने के लिए वेटिंग रूम की व्यवस्था करनी चाहिए। इस के अलावा देहाती लोगो के लिए भी मोबाइल कोर्टस की भी जरूरत है।

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN (Coimbatore) : I wish to confine myself to just two points in the limited time that is there. There is a very serious case to which I would like to draw the attention of the Minister, but before doing

[Shrimati Parvathi Krishnan]

that, I have to make an appeal to him And that is this : he should immediately apply for a divorce. You will be surprised at this suggestion He must divorce himself from the rules All the time he is quoting the rules, or misquoting the rules, and he refuses to liberate himself from the rules

There was a case involving the Jeypore Sugar Co It was a case of serious defalcation of funds I should say because they have violated the Essential Commodities Act and they have black-marketed in sugar and avoided excise duty And they have been penalized for a more Rs 6 lakhs although they have gained Rs 30 lakhs in the black market Already this has been brought to the notice of the Minister And what does he reply ? Under Rule 173 Q of the Central Excise Rules, a penalty upto 2 times the value of the excisable goods can be imposed However they say that what is most relevant is not the value of the goods but the amount of excise duty evaded, or sought to be evaded in a particular case In this case the duty evaded was (*interruptions*) This levy sugar was sold in the black market and not given to the allottees At that time the price of levy sugar was Rs 150/ per quintal whereas the price of the open market sugar was Rs 360/-per quintal And these people have committed an anti social act by selling levy sugar in the black market and not giving it to the allottees And you penalized them only Rs 6 lakhs when they have made more than Rs 30 lakhs of black money I would like to draw the attention of the Minister to a judgement by Chief Justice Chagla and Justice Gajendragadkar in Bombay, when a person was sentenced by the Magistrate to 6 months imprisonment and a fine of Rs 2 lakhs, when he sold a small piece of cloth without issuing a voucher and made a profit of Rs 1 75 When it came on appeal, what did Chief Justice Chagla and Justice Gajendragadkar say ? They said that the imposition of a fine of Rs 2 lakhs was not excessive, and that such an economic offender must be dealt with severely so that he would not be able to enjoy his ill-gotten wealth after he came back from the jail I understand that this case was decided in the Bombay High Court as far back as 1948 He is old enough to remember that Therefore I would request he should go into these cases and see that the black market money that is being earned by these people is mopped up by this department, instead of introducing excise duty on many new items

13 00 hrs.

Secondly, I come to the old age pensioners He is no longer an old-age pensioner, but he should have sympathy for those who are retired, many of whom were working under him, or may have been his colleagues What do they ask for ? They have only said that there should be a Pension Commission to go into the pension rules and revise them so that they are brought up to date, the wide disparities between one pensioner and another are removed and they are given extra dearness allowance I think he should agree to those demands

Lastly the Finance Minister is today standing in the way of the Minister of Energy who is sitting here because the CDS amounts have to be repaid to the workers of the Singareni Collieries and that is being held up by the Finance Minister Khammam has been declared a cyclone affected area and the workers have been asking for the money back They are not being given that So they are on strike and coal is not being produced The thermal power station has come to a standstill in Madras and this will happen in Andhra and other places Let him wake up and sanction that amount

SHRI A K ROY (Dhanbad) Sir I say in all humility that the Energy Minister is being sandwiched because of all sorts of reasons He is making a power plan In Bihar even though the installed capacity is 750 mw you will be surprised to know that we are getting only 250 mw So, all our industries are getting closed When we ask the reason for that the hon Energy Minister is blaming the hon Industries Minister and the hon Industries Minister is blaming BHEL and BHEL is blaming somebody else All of them want to shift the blame on somebody else The result is that the entire Bihar is facing a crisis

The Energy Ministry is somehow or other apathetic to the demands of Bihar. Even in the next Five Year Plan, though they have made a Plan for 10,000 mw, the share allotted to Bihar is only 600 mw

The idea of setting up industries in the underdeveloped areas is for the development of the rural areas and surroundings But, in the case of coal industry it only results in clashes with the villagers In Dhanbad and Chottanagpur belt there is always clash and quarrel between the officials and the villagers You will be surprised to know that the land of the villagers is being teken away, no money is paid to them and no registration is made When the villagers want either job or compensation, that is also not being given to them Though that principle is being followed in the case of the steel industry and other

industris, it is not allowed so far as the coal industry is concerned. While an industry is meant to develop the villages, in this case it is being used for the exploitation of the villages and crushing the villagers.

Only a few days back, the President of India went to inaugurate the blast furnace of the Bokaro plant when he said that the steel industry must develop all the villages within a radius of 25 miles. But what is Bokaro Steel doing ? It is in fact withdrawing even those facilities which were earlier given to the displaced persons regarding training, education and employment.

Lastly, I come to the policy of importing coking coal. I do not know the present policy, because we are hearing that the import of coking coal has been dropped or postponed.

I would like to say that it is a suicidal policy to import coking coal. The Energy Minister is there, and the Steel Minister is there. No doubt, the Steel Minister looks more robust than the Energy Minister, but I would like the Energy Minister to oppose this firmly, and I assure him that the entire House will back him because in this country we have got coking coal reserves in Assam and other places with an ash content of only six to seven per cent. In the Dhanbad area it is 16 per cent but it can easily be reduced at a low cost to the percentage desired by the Steel Ministry. So, we must see that this this plan to import coking coal from outside at a cost of Rs. 700 per tonne, when we can produce similar quality coal at Rs. 150 per tonne in this country, does not go through.

SHRI ANNASAHEB GOTKHINDE (Sangli) : I am thankful to you for giving me this opportunity.

The decision of the Government to increase the levy price of sugar uniformly for all the regions was a shock to the industry. The industry expected that while fixing the levy price . sugar, Government would take into consideration the actual cost of production, but by increasing the prices uniformly for all the zones, Government is perpetuating the injustice done to the sugarcane cultivator so far. Government has been increasing the prices of levy sugar in the zones where the sugar production and the industry are in a bad shape, but I want to know why this being done at the cost of the zones where the industry is efficiently managed. The prices now fixed by the Government are both arbitrary and irrational. The recommendations of the Marathe Committee and the Bureau of Industrial Costs and Prices in the matter have been ignored by Government. This has led to resentment among the sugarcane growers in the Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Pondicherry zones. I therefore want to know from Government whether steps are being taken to rectify the injustice and the discriminatory treatment meted out to the Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Pondicherry zones.

SHRI P. ANKINEEDU PRASADA RAO (Bapatla) : I thank you for giving me an opportunity.

I want to bring to the notice of the Agriculture Minister the crashing down of paddy prices in Andhra Pradesh, so far as the first and second crops are concerned. The first crop was sold at Rs. 60 a quintal instead of Rs. 77. Even for the second crop, there are no buyers today, and for second crop, we are unable to get even Rs. 70 per quintal. Government or the FCI never purchase paddy, they speak only in terms of rice. But the paddy is bought by the millers at low prices, and they sell the rice at a profit, depriving the agriculturists of the prices which they should get for their paddy. Instead of procuring rice from the millers, I request the Agriculture Minister to take up the policy of procuring paddy from the agriculturists. About 200 co-operative mills were set up with the help of the Central Government. They are lying idle. These co-operative mills may be activised and paddy may be purchased from the agriculturists paying them at least the price fixed by Government, though we have got objections to the price fixed by the APC. The paddy can be given to the co-operative rice mills and then the FCI can take the rice from them instead of purchasing rice from the private millers and traders. This will help the agriculturists.

As far as the price of paddy is concerned, the other day the Minister of State, Shri Bhanu Pratap Singh, said that there was an increase of Rs. 3 and Rs. 2·50 in this year respectively, but if you compare the prices of 1967-68 and 1977-78, you will find that paddy was procured at Rs. 45 and wheat at Rs. 55. In 1967-68, the paddy is at Rs. 77/- and wheat is at Rs. 110/- in 1977-78. There is hundred per cent rise in wheat price and only 75 per cent rise in paddy price during these ten years.

The agriculturists of Andhra Pradesh are not able to sell their paddy even at the price fixed by the Agricultural Prices Commission. So, I request the Government to help the cyclone-hit agriculturists of Andhra Pradesh. The paddy of the

[Shri P. Ankineedu Prasada Rao]

first crop is lying unsold. The second crop is coming, but there is no buyer. They are left at the mercy of millers. If FCI comes to their help and lift their stock at the declared prices, that will be of great help to them. So I request the Minister to do something in the matter.

SHRI VASANT SATHE (Akola): I will take up only two points particularly relating to Civil Aviation and Tourism Ministry.

One thing in the Civil Aviation is that there are places and towns which have airports and landing facilities, but they are not yet linked. It is all right that big planes, airbus and Boeings may not be required for those areas but if you have an arrangement either with the Indian Airlines itself or with State or private companies if you like, to operate only those smaller routes and they need not interfere with your regular air lines operations, that will feed more areas and serve more areas.

About tourism, I think Government should give a fresh look to their policy. Today, you go to any of the top hotels, the Government hotels, you will find a total desolate look in the catering houses. They are empty in the evenings. Nobody goes there. I am not a person who is in favour of addiction to liquor, but in life throughout a man's life—even our saints advocate—the best thing is temperance and self-restriction and not abdication. I do not understand why we are doing this. Have you ever heard a rich man dying of illicit liquor? They do not. I think, it is harming tourism. It is going to curtail the earnings of foreign exchange. Do not try to be pontifical. Do not try to give sermons that we do not want to earn money if it is immoral. Let us be realistic about it. The Ministry of Tourism will realise this. Go to any place in the world like Japan, Switzerland, Germany any country. Are we going to say that all those people are immoral only because they do not have prohibition in those countries? Sir, I want the Government to give a serious look to this.

I do not want to mention names. But how many Ministers who are present here, do not take liquor? I am sure, except one or two, everybody takes. There is nothing wrong. They are not immoral people.

I would request the Government in the interest of tourism, at least for your hotels modify your arrangement. If you like, you can decide to do it for higher strata. Otherwise, your hotels are going to close down throwing lakhs of people out of employment.

Though we are a republic, yesterday, someone remarked that a 'republic' without a 'pub' becomes 'relic'. I hope, this country will not be like that.

SHRI VAYALAR RAVI: Sir, I will confine myself to two or three points relating to the Ministry of Communications.

The Communication Ministry is a vital link, a vital nerve, of the nation to move on. Unfortunately, many of the problems relating to communication and its employees are pending in the Ministry for long. There are more than 4·5 lakh postal employees out of which 2·5 lakh employees are called as extra-departmental employees. This was a new device invented by the British rulers to make Indians work like slaves with a Meagre remuneration. They are not regular Government servants. These 2·5 lakh employees are paid an amount of Rs. 85/- only. Recently, the hon. Minister said that the amount has been raised to Rs. 100/-. He has misled the people. They are not getting Rs. 100/-. Only a few of the employees may be getting it. But not all.

The D.A. has gone up 15 times. But these people have not been given all these instalments of D.A. Only when Mr. Bahuguna was the Minister of Communications, extra-departmental people got the D.A. No further D.A. has been given to these people. There are 12 instalments of D.A. which are due. I appeal to the hon. Minister to consider giving of D.A. to extra-departmental employees.

This system of having extra-departmental employees must be abolished completely. It was introduced when the population of undivided India was only 300 million. Now, the population of divided India, our own country, is 600 million. It is necessary that these 2·5 lakh employees who are serving the people of our country should be regularised as the employees of the P & T Department. Otherwise, they can be called always the slaves of modern India. It is a disgrace that for the last 30 years, this practice has been going on. Even during our regime, it was being continued. I would now request the hon. Minister to consider this matter.

They are introducing 1 lakh new post boxes. Who will take the delivery? They will need people. These extra-departmental employees work for more than 6 hours a day. They are working very hard, specially in remote villages. This is a matter which should be looked into. I appeal to the hon. Minister to look into it.

Coming to the Telephones Department, the employees of the Telephone Department are doing good work. The telephone system has been extended. But there is no sufficient staff. Recently, a circular has gone to reduce the staff by 10 per cent. These employees get abuses from the public as well as the officers. This is the condition of these poor employees of the Telephone Department. There is no proper staff; there is not even relief staff. Therefore, I say that this reduction of 10 percent in staff is very unfortunate. The Government should not introduce this thing. It will affect the working of the telephone exchanges.

Lastly, I would like to say about the supply of uniforms to post-masters, telegraphmen and other telegraph employees, etc Please give them clothes and they will stitch it. I have seen with my own eyes what sort of uniforms are being supplied to these people—small men get big uniforms and big men get small uniforms. There is corruption and malpractices going on. They are stitching more than 2 lakh uniforms. I know, it is a heavy expenditure involving Rs. 80 lakhs. I appeal to the hon. Minister to please give proper clohes to these employees and allow them to stitch. Let them supervise the whole thing. Otherwise, they will have to boycott these uniforms.

I would appeal to the hon. Minister to consider giving more facilities to P&T employees in the matter of housing. They are not getting proper housing faciliies, more so even in remote areas. As regards the RMS, there are a lot of problems. There is no accommodation provided at the railway stations, no accommodation at the halts.

I hope, the hon. Minister will consider all these points raised by me.

SHRI SAUGATA ROY (Barrackpore): Sir, I will confine my remarks mainly to the Energy Ministry.

West Bengal is plagued by a power famine. Small factories are closing down and in large factories, there are large-scale lay-offs. The local State Government has failed to tackle the power problem. They have failed to introduce power rationing. There is not only a shortfall in power generation but in its installed capacity also. The West Bengal Government has applied to the Central Government for a gas turbine which will immediately alleviate the power famine in West Bengal. Their application is pending with the Energy Ministry. I want the hon. Minister to immediately clear the application of the West Bengal Government for a gas turbine.

Then, the Energy Ministry has a plan for the coal carbonisation plant at Dankuni in West Bengal. I want that it should be carried forward and that should be allowed without any delay.

With regard to the Farakka Super-thermal power station, the work should be started immediately without any delay.

As regalds the rehabilitation of Dandakaranaya refugees, the condition of these refugees in Sundarbans is beyond human description. So, some special efforts should be made very soon by the Ministry of Rehabilitation so that these people can be at least temporarily settled in camps till they go back to Dandakaranaya.

With regard to communications, I want to say that the Minister has announced a programme for telephone exchanges and automatic telephone exchanges. In my constituency, there are only two telephone exchanges only 18 miles from Calcutta—one at Barrackpore and the other at Bhatpara—and both of them are not automatic and they are not supposed to be made automatic within 1985. I want the Minister to take up the work of at least making them automatic immediately at these two places because they are connected with the most industrialised areas in the whole of India.

Lastly, with regard to atomic energy, I want to say that this Government is going too slow on our nuclear programme. Already the Government has given up the programme for peaceful explosion and implosion for scientific and research purposes. Dr. R. Ramanna who was one of the main thinkers about Pokhran explosion had been removed from his post unceremoniously in the Atomic Energy Commission and now he has been shifted to a new post of Scientific Advisor to the Ministry of Defence. Under no conditions, this atomic energy programme should be given up and this should be strengthened.

With regard to Air India, there is some discontent among the Air India staff about the removal of J.R.D.Tata. The staff really feels that the removal of J.R.D.Tata has really tarnished the image of Air India here and abroad. I know that it has been done against the wishes of the Minister by the intervention of the Prime Minister's Secretariat. I want the Ministry to do something about Mr. J. R. D. Tata. so that he is given a proper honour before he is unceremoniously removed.

SHRI K. T. KOSALRAM (Tiruchendur) : Mr. Speaker, I want to bring to your notice one important thing. The district Collector is there in the States.

[Shri K. T. Kosalram]

All the departments are working under his control. If there is any complaint against a particular department we represent to the district Collector. He goes through it and if there is anything wrong with the department concerned, then he pulls up that department and gets the things done.

As far as the Central Government is concerned, we have passed all the Demands for Grants and the Appropriation Bill is going to be passed. You are going to spend crores of rupees, as far as this huge country of ours is concerned. In the States, there are so many departments and the man who is at the top is the head of the department or the boss of the department or the emperor of the department. Every department is like that. But he does not bother about anything. Nobody is trying to effect coordination between these departments in the States. From Delhi to Kanyakumari, it is very difficult to control these officials. So, I would suggest that somebody must be there at the State headquarters to coordinate the work of various Central departments, agencies, who could without referring to Delhi, take decisions. This will be real decentralisation of decision making powers. to control these things. Some method should be adopted so that this problem could be solved ate the State level. I do not know how are you going to do it. We have to solve this problem in cooperation with these officials. (*Interruptions*) Regarding passport, I do not agree with my friend that the M. Ps should be given power. I had written to Shri Vajapeyeeji about the signing of application forms. I said ; even that power, we do not want. So, I request you to see that these departments must be controlled by somebody at the State level.

My friend Mr. Biju Patnaik has been talking about the production of aluminium and so on. He said that there was no control. But he has been importing 3 lakh tonnes of aluminium also. As far as small scale people are concerned, they are not getting their quota. But every day the Government is saying that whatever help the small scale people want, they are prepared to give. But everywhere the aluminium small industry people are crying like anything because they are not getting their quota. Nobody cares about these people. I want to know how are you going to solve this problem because you are importing 3 lakh tonnes of aluminium also. You must come forward with some system, the Government must come forward with some system so that the small scale people get their needss fulfilled.

Now I come to the Ministry of Finance, the Ministry of Shri H. M. Patel. The State Bank of of India wanted to employ 40,000 people. I do not know whether the Reserve Bank of India is coming in their way or the Government is coming in their way. As far as sanction is concerned, it has already been given. But as far as vacancies are concerned, these have not yet been filled up. I could not understand this.

The number of educated unemployed is going up every day. People are representing to the Members of Parliament. Now, State Bank alone wants 40,000 persons. Tamil Nadu alone wants 10,000 persons. Just I wanted to know who is standing in their way. The previous Government had issued a circular that all attenders and peons must be taken from the Harijan community alone. But not even a single Harijan has been taken in the State Bank. I can challenge this Government. We find that everywhere the Harijans are harasssed. They are denied even job opportunity. I request the Finance Minister to see that the 40,000 persons in the State Bank are recruited immediately.

MR. SPEAKER : Does any of the Ministers want to say anything ?...... Then I will call the Finance Minister.

Shri H. M. PATEL : The hon. Members have raised certain points. I shall certainly see that they are all examined and gone into.

Shrimati parvathi Krishnan said something about divorcing. It gave me a little shock. Thereafter, she proceeded to soften and said that it was only divorce from rules. I wish she had complied also with this business of complying with rules.

She said about Jeypore Sugar Mills. I think, the fine of Rs. 6 lakhs was imposed on them on the basis of rules. The Collector of Excise concerned cannot go beyond the rules...

Mr. SPEAKER : The question was, why did you not prosecute.

SHRI H. M. PATEL : That is not the business of the Collector of Excise. That is the concern of some one else and not of the Finance Ministry.

Then there was a question about old age pensioners. Certainly I would very much like to do much more for old age pensioners ...

MR. SPEAKER : Particularly if it could benefit us also.

SHRI H. M. Patel : But unfortunately the resources are limited. I must, therefore. harden my heart in spite of my great pesire to do something for them...

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN : (Coimbatore) : Appoint a Pension Commission.

SHRI H. M. PATEL : When you appoint a Commission, it will make its recommendations saying 'give this' and 'give that'. I have to find money.

Then there was the question of the workers in Singhareni Coalfields and about the return of money to them under the Compulsory Deposit Scheme. I heard about this only today. But the delay was not because of Government of India. The Singhareni Coalfields management had not forwarded those applictions to the Provident Fund Commissioner.

SHRIMATI PARAVATHI KRISHNAN : They have fowarded them and they are with you. (*Interruptions*) ...

SHRI H. M. PATEL : Why don't you be a little patient? Only just before I came to the House, I came to hear of that. I am taking steps to see that these things are immediately set right.

A great many other points were raised by hon. Members. I do not know whether they would like me to repoy to them individually now. To some points I could reply, but it seems to me that it will be much better if they are taken note of, and whatever action is to be taken regarding them will be taken by us.

MR. SPEAKER : Now, the question is..

SHRI VASANT SATHE : Some Minister are here. We made some points. In regard to the grants which have not been covered, if the Ministers who are here could reply, why should they not ?

MR. SPEAKER : I cannot speak for them. I asked them.

The question is :

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1978-79, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER : Now, we take up Clauses.

The question is :

"That Clauses 2 to 4 and the Schedule stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 4 and the Schedule were added to the Bill.

MR. SPEAKER : The question is :

"That Clause 1, the Enacting Formula and the Titlle stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI H.M. PATEL : Sir, I beg to move :

"That the Bill be passed."

MR. SPEAKER : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

13.30 hrs.

FINANCE BILL, 1978

MR. SPEAKER : We now take up the Finance Bill.

Three days have been allotted for all the stages of the bill. Therefore, approximately 12 hours would be available for its discussion. If the House agrees, we may have nine hours for general discussion, two hours for clause-by-clause consideration and one hour for third reading.

SEVERAL HON. MEMBERS : Yes.

MR. SPEAKER : So, this is adopted. Mr. Patel may move his Bill.

SHRI H.M. PATEL : Sir, I move :

"That the Bill to give effect to the financial proposal of the Central Government for the financial year 1978-79 be taken into consideration".

I would lkke to make a few remarks or observations. I have already explained the salient features of the main proposals contained in the Finance Bill in my Budget speech. The details of the specific provisions in the Bill have been given in the Explanatory Memoandum circulated to Hon'ble Members. I do not, therefore, consider it necessary to traverse the same ground again.

The Finance Bil! has been before the Hon. Members for nearly two months. During the debate on the Budget. and

[Shri H. M. Patel]

thereafter during discussions on the demands for grants of individual Ministries, various suggestions have been put forward by Hon. Members with regard to the proposals contained in the Bill. I have also received a number of representations from members of the public, chambers of commerce, and other trade and professional associations on the proposals contained in the Bill. I take this opportunty of expressing my gratitude to Hon. Members and to all others who have made constructive suggestions.

On a careful consideration of these suggestions, I have decided to modify some of my original proposals. With the indulgence of the House, I will briefly explain the principal chages that are proposed to be made in the provisions of the Finance Bill. I shall first deal with the proposed changes in the sphere of direct taxes.

The Bill provides for the disallowance, in the computation of taxable profits, of a specified percentage of expenditure incurred by tax-payers on advertisement, publicity and sales promotion. It has been represented that while large enter prises might be able to absorb the impact of this measure, the proposed disallowance will result in hardship in the case of medium and small enterprises. In order to avoid hardship to them, the Bill already provides that no disallowance will be made in cases where the aggregate expenditure on advertisement, publcity and sales promotion does not exceed Rs. 20,000 in a year. This has been criticised as being somewhat too low a sum. With a view to ensuring that genuine small enterprises are not adversely affected by this provision, I propose to raise the monetary limit of Rs. 20,000 to Rs. 40,000/-.

It has been represented that the proposed measure will seriously endanger the existence of small newspapers. In order to ensure that the proposed measure does not result in any fall in the advertisement revenues of such newspapers, I propose to provide that no disallowance will be made in respect of expenditure on advertisement in any newspaper with a circulation not exceeding 15,000. As there is little scope of any extravagance or wastefulness in statutory advertisements or advertisement for recruitment of staff, I propose to provide also that no disallowance will be made in respect of expenditure on advertsements which fall in these categories.

It has been pointed out that the expressions 'publicity' and 'sales promotion' are of wide amplitude and should be defined precisely. While an exhaustive definition of these terms is difficult, I propose to clarify that no disallowance will be made in respect of certain items of expenditure, including expenditure on sales conferences, press conferences and trade conventions; participation in trade fairs and exhibitions; establishment charges, including salaries of staff; catalogues and price lists. Power is also being taken to add to these items through rules framed by the Central Board of Direct Taxes.

Under the existing provision in the Income-tax Act, entertainment expenditure in excess of the specified limits is disallowed in computing the taxable profits. It is proposed to clarify that expenditure on entertainment in connection with publicity and sales promotion will continue to be disallowed under the existing provision which is more stringent than the provision proposed in the Finance Bill.

The Bill seeks to discontinue the grant of export markets development allowance in relation to expenditure incurred after 31st March, 1978. It has been urged that this tax concession has played a useful role in diversifying and stimulating India's exports. The process of diversification is, however, far from complete and continued efforts are required for larger exports of our products The share of the small-scale sector in these exports is of considerable importance. It has been represented that in view of the stiff competition in world markets, the export of Indian products is facing challenging problems, which necessitates continued marketing thrusts on the part of our exporters. I have given careful thought to these considerations and have decided to continue the scheme of export markets development allowance with some modifications.

The scheme of export markets development allowance will now be available only to Export Houses recognised by the Ministry of Commerce; small-scale exporters; and consultancy firms Currently, export markets allowance is granted at the rate of 150 per cent of the actual expenditure on development of export markets in the case of widely-held domestic companies, and at the rate of 133·3 per cent in the case of other taxpayers. I propose to reduce the quantum of deduction in the case of widely-held domestic companies from 150 per cent to 133·3 per cent It is also proposed to reduce the list of eligible items of expenditure qualifying for deduction under this provision by omitting two of the existing entries.

The Bill provides for a deduction in the computation of taxable income of 50 per cent of the amount invested in equity shares of new industrial companies. With

a view to providing a stimulus to house-building activity, I propose to extend this concession to investment in new equity shares of approved companies established for providing long-term finance for construction or purchase of residential houses in the country

The Bill seeks to provide that Indian citizens, who are rendering service outside India and who visit their home country during any financial year on leave or vacation, will not be regarded as resident in India in that year in cases where their stay in the country during that year does not exceed 89 days Under the provision in the Bill, this concession has been restricted to cases where the service of the Indian citizen outside is sponsored by the Central Government or the terms and conditions of such service has been approved by the Central Government or the prescribed authority. I propose to delete this restrictive condition so that this concession becomes available to all Indian citizens employed outside India, irrespective of whether the service of the individual is sponsored by the Government or the terms and conditions of such service have been so approved or not.

SHRI R. VENKATARAMAN (Madras South) : Thank you, that was my amendment also. That means, my amendment has been accepted.

SHRI H. M. PATEL : The Finance Bill seeks to provide that every person, irrespective of whether he has been assessed to income-tax or not, will have to pay advance tax on a voluntary basis. Under the provisions in the Bill, all taxpayers, including those who have not been previously assessed to income-tax would be required to make an estimate of the advance-tax payable by them before the date on which the first instalment of advance tax is due in their case. As it may be difficult for taxpayers who have newly set up a business or profession to make an accurate estimate of the advance tax payable by them early in the accounting year, I propose to provide that new taxpayers, that is, those who have not been previously assessed to income-tax, may continue to furnish, as hitherto, an estimate of advance tax before the date on which the last instalment of advance tax is due in their case.

The Finance Bill provides that fixed deposits with banks made after 28th February 1978, will not be regarded as an eligible mode of investment for the purposes of exemption of long-term capital gains. I had introduced this provision because banks were allowing substantial advances against the security of fixed deposits, with the result that tax payers who got exemption from capital gains by making such deposits obtained an unduly large benefit without commensurate sacrifice. On a careful consideration of the representations received against this proposal, I have decided to continue fixed deposits with banks as an eligible mode of investment subject to the fulfilment of certain conditions which are intended to ensure that no loan or advance is taken by taxpayers against the security of such desposits for a period of three years....

SHRI R. VENKATARAMAN : This is also a point I have raised. You have accepted all my points.

SHRI H. M. PATEL : Now that I have accepted all his points, I hope he will withdraw his amendments.

The various modifications proposed by me will result in a loss of Rs. 10·5 crores in a full year and Rs. 8·8 crores in 1978-79.

May I now turn to the proposals covering indirect taxes.

A number of hon. Members have spoken about the levy of excise duty of 2 paise per kilowatt hour on electricity generated in the country. I have also received representations from the State Governments, State Electricity Boards and industry. The imposition of a duty on the generation of electricity was with a view to mobilise resources needed for the Plan particularly in view of the large investments in the power sector. It has been brought to my notice that one of the problems faced is that power which is generated cannot be fully utilised and is not entirely available to the State Electricity Boards. This arises because of the use of power for auxiliary consumption as well as because of transmission losses. I must make it clear that since the tax on electricity is a tax on production and not on sales, the losses on account of transmission cannot be taken cognizance of from the strictly legal point of view. However, in view of the practical difficulties involved. I have already exempted the electricity which is used in auxiliary consumption. I propose to go further and give a uniform reduction of 10 per cent of the duty payable on the current generated after deducting the auxiliary consumption, thus restricting the levy to 90 per cent.

I had already proposed that a rebate of duty would be granted on electricity used for agricultural purposes. In order to simplify the administration of this rebate, I propose to make it available to current supplied by the Electricity Boards and others at their agricultural tariffs for agricultural purposes.

It has also been urged that there is a time-lag between the production of

[Shri H. M. Patel]

electricity and the receipt of money from the actual consumers thereof and that, therefore, collection of duty should be regulated suitably. Keeping the normal time-lag in view, instructions are being issued to allow a period of two months within which the producers could pay the duty.

Certain difficulties have also been expressed regarding the recovery of amounts resulting from this levy from the actual consumers of electricity in respect of production in the first one or two months beginning from 1st March. While there would be no case for any waiver of the levy itself, I am instructing the Department to allow payment in easy instalments, if need be, of the duty due in those months.

It has been urged that the duty on electricity falls heavily on certain industries. I recognise the need for considering the cases of industries such as aluminium in which electricity forms a large part of the actual cost of production of the goods and the desirability of affording some relief so as to maintain the availability of essential products at reasonable prices. This question will be gone into at the earliest in consultation with the concerned Ministries.

In the case of coal, on the analogy of the exemption granted to auxiliary consumption of electricity I propose to exempt from payment of duty 1% of the coal produced in the mines.

It has been represented that the procedure of availing of the pro forma credit of the duty paid on coking coal used in the manufacture of hard coke is presenting practical difficulties. Keeping this in view, I am exempting hard coke from the payment of duty. Thus, the actual levy will be limited to coking coal at Rs. 7 per tonne and other coals at Rs. 5 per tonne. There will be no real loss of revenue due to these changes.

Hon. Members will recall that I had proposed to reduce the basic excise duty on auto-rikshaws used as taxis from 12 1/2% *ad valorem* to 10% *ad valorem* subject to the condition that such auto-rikshaws are registered with the transport authorities as taxis for the paying of passengers on hire. It has been represented that most of the auto-rikshaws produced in the country are used as taxis and that the observance of the aforesaid condition is irksome in actual working. I, therefore, propose to remove this condition.

The modifications which I have proposed will result in a loss of Rs. 17·43 crores in a full year and Rs. 16·19 crores in 1978-79.

I hope that the House will now carry the Bill with the modifications now suggested.

MR. SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 1978-79 be taken into consideration."

SHRI VASANT SATHE (Akola): What about 5% *ad valorem*?

The first speaker will get 20 minutes.

Congress (I) will have 1 hour 5 minutes. Congress will have 1 hour, 1 minute.

I am sorry, it has been reduced. Shri Venkataraman.

SHRI R. VENKATARAMAN: Mr Speaker, the hon Finance Minister has followed a familiar pattern of loading the camel.

13·46 hrs.

[MR DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let me give you the idea of time.

We have allocated nine hours for the General Discussion, two hours for clause by clause and one hour for the Third Reading.

SHRI R. VENKATARAMAN: It is an old story of the person loading the camel to its utmost limit and then lifting a few packages and dropping it, thereby giving the impression that all the load has been taken away. Well, I am thankful to the Finance Minister for the concessions which he has given. I have still a few words to say in respect of this Finance Bill.

Before I proceed with the Bill in question, I would like to make one or two general observations. I would like the Finance Minister to revert to the old practice of giving in the Budget the Accounts for the year ended, then the Revised estimates and the Budget for the next year. Last year's Accounts—which have ended—have not been given at all with the result, we do not know, whether there has been any variation between the Revised estimates and the actuals. For instance, take 1976-77. We do not know what were the actuals in respect of 1976-77.

I have put a question to the hon. Finance Minister and he said—as late as December—that the Accounts are not yet ready and again as late as 17th March, 1978 he still said that the Accounts for the year ended were not ready. This is really depriving the Parliament of its control over expenditure. Unless we know what were Actuals in relation to the Revised expenditur we cannot ask the Government

to explain the variation as to how and why such variations took place. Parliamentary control does not merely rest in allotting monies for the future years. Parliamentary control rests in looking into the Accounts—the Actuals of the previous years and then asking the Government to explain why there has been such variation.

I put a question on this and the Finance Minister replied. Unfortuantely, it became an unstarred question in the ballot. The number of the question is 3364. The Finance Minister replied :

> "The variations in 1975-76 and 1976-77 are attributed to large revenue receipts and shortfalls in Plan expenditure."

Sir, if this had been presented in the Budget, considerable discussion would have taken place in the Parliament on this aspect, namely, the shortfall in the Plan expenditure and attention of the country as well as the House would have been directed towards that problem.

Sir, the Finance Minister replied to another question of mine No 446 which I would like to quote :

> Shri R Venkataraman : There is no statement of accounts for the year ended. No explanation is given for the variation between the revised estimates and actual accounts. Will the hon'ble Minister restore the old practice and present the accounts for the year ended also in the presentation of the Budget for the year 1978-79 ?
>
> FINANCE MINISTER : I can only say at this stage that I will do my best to revert to whatever is the correct practice.

I hope he will revert to the old practice at least in the next year's Budget and see that the accounts for the year ended are given. Without that it becomes difficult for Parliament to know what were the actuals in respect of the year and what variations took place and why such variations took place.

The second general observation I would like to make is that we seem to accept the growing expenditure as if it is of no concern. We seem to provide for the moneys without looking into the economy aspect of the Budget. I think the last enquiry into economy was made in the Inchcape Committee There has not been another examination of economy in Administration since then. I would like the Finance Minister to launch a serious drive for economy in administration and see the proliferation in the Administration that is taking place is held in check. A lot of money is unnecessarily spent, lavishly spent and unwisely spent because there has been an expanding secretariat, expanding services and so on. I know the answer of the Finance Minister. He will say that we have also expanding services. My point is whether the expanding is in commensurate with the expanding services. He may look into it and see that the economy which is so vital to our nation is practised in our Budget.

The Finance Minister has said that his Budget is a bold step. In fact, the only boldness I see in the Budget is the boldness in deficit. It is the biggest deficit that any Finance Minister has presented to the Parliament so far. Eversince the Keynesian doctrine of investment and growth became fashionable in economic thought. Finance Ministers have lost the inhibition against deficit budget and deficit financing and each Finance Minister is vying with one another in the larger and larger deficit budgets which they can produce From the complacency which I see in the Finance Minister's face, I think, he is going to improve upon it and in the years to come the deficit is going to be higher and higher. This is a matter of grave concern to the country. The magnitude of this deficit can be understood when you compare it with what the Plan document envisaged for the entire period of the Sixth Plan.

Sir, the Planning Commission in its chapter on financial resources contemplates—I do not want to read out the particular portion unnecessarily because the Finance Minister knows all these things by heart—that in a public sector plan of Rs. 69,380 crores, the resources gap would be Rs. 2226 crores. Now for the entire period of five years, the resource gap is expected by the Planning Commission to be of the order of Rs. 2226 crores. In the very first year of the budget, Rs. 1050 crores would be exhausted and 50% of the deficit gap expected in the plan of five years would be exhausted. It looks as if even before the ink on the plan has dried, the resources have gone awry.

SHRI NARENDRA P. NATHWANI (Junagadh) : You please see the Finance Minister's budget speech, that is, paragraph 109 of the budget speech.

SHRI R. VENKATARAMAN : Mr. Nathwani will have ample opportunity of rebutting my statement. How, the Finance Minister stated that the deficit would be reduced in two ways. One is by a significant draw down on the foreign exchange resources. The second is by sale of gold. I will now take the question of draw-down on foreign exchange resources. Our experience last year— he said last year that we would draw on the

[Shri R. Venkataraman]

oreign exchange of Rs. 800 crores—has proved absolutely without any foundation. In fact, we have not been able to utilise the foreign exchange of Rs. 800 crores which the Finance Minister was expected to utilise and that is added to the deficit of Rs. 957 corres. Now, the chances of utilising the foreign exchange resources in the future or in this year also appear to be bleak. Import of capital goods is not very bright because we have now achieved self-sufficiency in many fields and there are a vrev few items which we can import There is indigenous angle and there is also an angle of self-reliance. Therefore, I doubt very much whether we will be able to utilise it The result is that deficit will remain as it is and it will not be covered. There is another point which I would like to draw the attention of the Minister. The Planning Commission has taken credit for utilisation of Rs.1,180 crores of foreign exchange resources in the entire period of five years. Now, on an average, you can use only Rs. 200 crores for that purpose. Now, how much of the foreign exchange resource the Finance Minister is going to utilise this year or in the succeeding years is a matter on which the country would like to be enlightened.

Then I come to the next question, namely, the sale of gold. The information regarding the quantity of gold is not available, From various sources which I have culled, about Rs. 188 crores worth of gold is with the Reserve Bank of India as a currency reserve. The Finance Minister has stated in an answer to my question that 35162 Kg.—that works out to 3·5 tonnes—of gold is in stock which he has to repay in respect of the gold bond subcribed by the people. The other gold is said to be of the order of 70 tonnes, the value of which works out to about Rs. 500 crores. Now, if you are going to sell gold and utilise all the money of Rs. 500 crores in one year to meet the deficit of Rs. 1090 crores, you would have frittered the resourse which has been accumulated over 30 year deficit in one year.

14 00 hrs.

Mr. Patel will earn the resputation of being the prodigal son of India. It is certainly not advisable in the current context. The sale of gold is, in my opion, an ill conceived proposition. If you want to reduce smuggling in the country, then the sale of gold at market rates will not reduce smuggling; the difference between the international price and the local market price is 30 to 33 33 per cent; the current market price is higher to that extent than the international price and sumuggled gold will continue to flow into this country. On the other hand if you try to sell it at international price it is the most disastrous thing because you will be actually burning the house to roast a pig; that will be the position of sales at international price or at any price lower than the market price. Therefore, I consider that is not advisable at all to resort to this measure. After all what is the stock of gold that you have in this country? Only 70 tonnes. We do not have Fort Knox built up here from which you can draw infinite resources. Take the times of war. I want the Finance Minister to think very carefully on this matter. I am trying to be helpful and I am not trying to attack. In times of war SDRS will not help: no other assistance will come or will be of help to you. It is only gold that will detrmine ultimate international financial settlements. We have not eschewed war; we do not know when it would break. Why do you want to sell away such a small quantity of gold, 70 tonnes to reduce deficit or prevent smuggling which canot be done in my opinion. I am not very positive that this is a completely ill concieved scheme and I hope after the first sale which had been advertised for May, they will stop it completlety. This is a matter which is of great national importance and one has to be very careful about the sale of this.

The hon. Finance Minister stated that he would import gold for the purpose of exporting and earning foreign exchange by exporting jewellery. If you import gold you will have to follow the procedure, bonded procedure, etc. which you wanted to straighten and simplify. If you do not have this bonded procedure it will lead to so much of abuse and very soon the sale of gold will become discredited. Therefore, we need not resort to import of gold for the purpose of exporting jewellery. In fact import of gold using very valuable foreign exchange will be an archaic use of the resources of the country; it is totally unscientific.

The net result of this deficit and all that, is our public debt is going up by leaps and bounds. The Finance Minister quipped in this reply to the debate that it has gone up even earlier. Between 1973-74 and 75-76 public debt increased only by Rs. 5800 crores. But according to the Budget Explanatory Statement, in this one year, 1977-78 to 1978-79, it will go up by Rs. 4,117 crores, an incre ase of sixteen per cent in one year. The Finance Minister must give certainly serious consideration to the galloping debt position in the country.

Let me turn to the tax proposals. The Finance Minister says that the scheme of taxation is intended to develop the economy, encourage savings, etc. Now do we really achieve this objective is the question. In developing countries, it is well-

known that the scope for direct taxes is not very large. The Finance Minister said this in his speech at page 25 and the Planning Commission has also reiterated it in their document. But what do we do ? Instead of conserving whatever we have and trying to preserve the revenues from the direct taxes, the Finance Minister is giving up some of the revenues from the direct taxes. "In the direct taxes field." the Planning Commission said, "further efforts will have to be directed towards reducing the avoidance and evasion." They said : "the various concessions in the tax structure other than which stimulate middle income savings, labour intensive and other priority production need to be reviewed and if necessary, withdrawn," Instead of withdrawing, the Finance Minister has increased and enlarged the concessions.

I will tell you some instances. Last year the Finance Minister gave up a number of items of direct taxes. For instance, he exempted the closely held companies which are subject to additional income tax under certain conditions. Secondly, the capital gains tax was diluted and thirdly, the monetary ceiling limit in respect of donations for charitable purposes was raised from Rs. 2 to 5 lakhs All those benefits were given last year in the direct taxes.

And this year, what is he doing ? He restores to the Hindu Undivided Families. a concession which was withdrawn by the previous Government. What are these Hindu Undivided Families ? I Would like to read an extract from the wanchoo Committee Report and draw the attention of the hon. Finance Minister to that.

In respect of the Hindu Undivided Families, the Wanchoo Committee said :

> "Members of a Hindu undivided family are thus able to enjoy the economic benefits of both kinds of income and wealth without any additional tax liability. No wonder, the institution of the Hindu undivided family is widely used for tax avoidance."

Then they went on to make some enquiries.

> "To have some idea about the extent of tax avoidance by the Hindu undivided families and their members by splitting up their incomes in a number of hands, we arranged studies to be made in certain Commissioners' charges. For this purpose, five or six big families were selected in each charge. The studies revealed that tax avoided by the members of these families was quite substantial. The number of income-tax files in respect of each family was found to be more than the total number of members in the family and in one case, the income-tax and wealth-tax avoided for a particular assessment year was as high as 60 per cent and 30 per cent respectively." To this set of people viz., the Undivided Hindu Families, the previous Government withdrew the concessions and the Finance Minister has restored those concessions viz., deductions in respect of donations to certain funds and charitable institutions, deductions in respect of rent paid for residential accommodation in excess of 10% of taxable Income, tax holiday profits, etc

A number of concessions were withdrawn. The Finance Minister by one stroke restores all these concessions to the Hindu undivided families who, according to the Wanchoo Committee report, are indulging only in tax evasion. All of us know that the Hindu undivided family is only a myth and does not exist except for avoiding income-tax. Why should these people be given the concession? Therefore, we would strongly oppose this kind of concession being given in direct taxes

Coming to estate duty, the Finance Minister wants to forego revenue by raising the exemption limit for the levy of estate duty from Rs. 50,000 to Rs 1 lakh. I know the familiar argument that the value of the rupee has eroded, the purchasing power has gone down, etc. But are they the class of people who immediately need relief ? What would be the great harm done if the people leaving an estate of Rs. 50,000 and over are asked to pay 4% of their estate as estate duty ? I will tell you the context in which this is being given. Again, there is another point This is really a States' source of revenue, as the Finance Minister himself said. Already the States are running in deficit The total deficit for the year for all the States is nearly Rs. 800 crores. If you are going to deny them even this little money, you will be allowing them to have greater deficits. There may be a competition between the State Finance Ministers and the Union Finance Minister as to who will have the greatest deficit in the presentation of the budget. Why deprive the poor States of this income, especially when those people are in my opinion not in dire need of any relief ? The question is, are these people in need of such relief ? The question further is, is it equitable that you give this relief at this time of the year when deficit is over Rs. 1000 crores? Compare it with the persons on whom you are levying taxes The Jha Committee has given a table of the taxes borne by people in relation to their income. Persons having less than Rs. 15 monthly expenditure are paying 9% tax This is going to be increased by your further levy of 5% special duty on specified goods and 5% on not elsewhere specified goods. People who are spending between Rs. 75 and

[Shri R. Venkataraman]

Rs.100 are paying 10% of their expenditure as indirect taxes in this country. On the onehand you increase the tax on people spending less than Rs. 15 and on the other you want to reduce the estate duty for people with Rs. 50,000 worth estate ! You want to increase the tax on people drawing Rs. 75 to Rs. 100 by levying a 5% special duty on the goods they consume, while on the other hand you want to give exemption to the Hindu undivided families who have formed themselves into Hindu undivided families only for tax evasion Therefore, my submission is, so far as indirect taxes are concerned, it is going to hurt the national economy. It will lead to great deal of price spiral and accentuate the suffering of the common man. In the context of this, I want the Finance Minister to look into the concessions which he is going to give for people who are paying direct taxes.

MR. DEPUTY SPEAKER : It is about half-an-hour now- another two minutes to half-an-hour. Please conclude.

SHRI R. VENKATARAMAN : May I have 10 minutes more ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : You can take, but none of your other Party Members will get time.

SHRI R. VENKATARAMAN : I will skip over some of these things and then I will come to the Finance Bill as it is. Though I have been speaking a little harsh on some of the indirect taxes, I cannot say that the whole of the Finance Bill is unacceptable. On the other hand, it has a number of welcome points. Therefore, I will now divide the provisions of the Finance Bill into three categories, viz., those provisions which are welcome, provisions which need amendment, and provisions which are objectionable.

So far as the first part is concerned, the proposal to enhance from Rs. 1,200 to Rs. 2,400 the education in the annual value in respect of let-out residential units constructed after 31st March, 1978 is welcome. This may hopefully encourage building activity. Then, the proposal which enhances the initial depreciation from 20 per cent to 40 per cent in respect of employees' housing and welfare measures like canteens, hospitals etc. are also welcome. We hope it will help the employers to build a number of canteens, houses etc. and take up other welfare measures. I also welcome clause 14 which enables advance ruling being given in respect of amlgamations. My request in this regard is that this advance ruling should be extended to a very vital field in the income-tax law and that is in respect of foreign collaborations. People do not know what exactly is the tax liability and once the Foreign Investment Board (FIB) determines how much is the amount payable to the foreign collaborator, thereafter the income-tax department says the tax liability is so much the party has to come to the FIB and all that to get it enhance. If advance ruling can be given as it is now proposed in clause 14 in respect of foreign collaborations, it will help in the development of industries.

In clause 16 I welcome the provision which grants 100 per cent exemption in respect of long-term savings from Rs. 4,000 to Rs. 5,000. But I am not in favour of increasing the ceiling from Rs. 20,000 to Rs. 30,000 because, as I have said earlier a person who can save Rs. 30,000 must have an income of Rs 1,00,000 and a person having an income of Rs. 1,00,000 per annum is not in such a need of any relief and, therefore, this is one of the items in which unnecessary relief is given when severe tax levy is made on the poorper sections of the society. Clause 17 which provides for the tax concessions in respect of purchase of shares in the new ventres is also welcome But it should be extended to partnerships and to self-employment. I would like the Finance Minister to take note of it, why should this concession be confined only to limited liability companies ? A person might have become a partner and started a business. In this partnership also, 50 per cent deduction in respect of investment is new partnership and also in respect of self-employment in industry, in the small-scale industry, should be given. Clause 18 which gives tax exemption to the milk cooperatives, is welcome ; and I hope this will encourage a greater number of societies in our country.

As regards non-residents, I am grateful to the Finance Minister. He has accepted, *in toto*, the amendment which I have moved. I thought there was some mistake, when I moved my amendment, because there was no reason why a concession should be confined only to Government servants, though I know from my own experience, that whenever tax proposals are put forward. Government servants have a habit of excluding themselves from them.

In clause 9, you are seeking only to omit the proviso, where the Reserve Bank or the Government have fixed the compensation. The clause itself is really an improper one. In fact, what clause 52 (2) says is that even though there is no concealment, if an income-tax officer is of the opinion that the market value of the property disposed of is higher than the consideration shown, he can declare that market value to be the real value, and charge capital gains tax on it. This is

stated to be irrational. I will cite the decision of a court. You can have it looked into. I would suggest that 52(2) itself may be removed. The decision has been given in "Income-tax Reports", volume 100, at page 413. Therefore, 52(2) has become redundant, and the clause itself must be removed.

In respect of capital gains, I am very happy that the Finance Minister has accepted the amendment which I have suggested. I wish to point out that his own department i.e. the Department of Direct Taxes, issued a clarification in circular No. 229, saying that if the money deposited in fixed deposits in banks by those who take advantage of 54E is pledged, and money raised by overdraft or loans raised or accommodation obtained, then it will not forefeit the concessions given. I just want to read the position. It is stated here :

> "Cases where a specified asset in the form of fixed deposit with any bank referred to in clause (vi) of paragraph 17.1 is issued as a security for obtaining a loan or overdraft from the bank, will also not fall within the expression "converted (otherwise than by transfer) into money." This expression would cover cases where a deposit for a period of not less than three years with any such bank is encashed by the assessee before maturity."

This is a really welcome change, which he has made. I am also in favour of saying that the money deposited in the fixed deposit, must remain there for 3 years.

I now come to indirect taxes. We are against the levy on coal and electricity. The general excise of 5% is going to lead to price rise: and the hike of another 5% over specified goods will really retard industrial and commercial development in the country. I am not sure whether he has consulted legal opinion. The duty on electricity under the report of the committee which went into the working of the State electricity boards, really belonged to the States. How can the Centre levy such a duty on electricity ? Already, we have agreed it will go to the State Electricity Boards to fill the gap. Now he comes forward and says it will be a tax and it would go to the Centre. There is another point. If you levy a tax on the sale of electricity, it becomes sales tax and the Centre has no power to levy sales tax on electricity. So, you say it is on the generation. It is a subterfuge by which the Finance Ministry says that it is a tax on production, whereby you are depriving the State Electricity Boards, which are anaemic, of their dues.

So far as the advertisement tax is concerned, I am sure that somebody will challenge it later. Under article 269 of the Constitution, tax on the sale and purchase of newspaper and advertisements thereon are leviable by the Centre and divisible to the States. This is really a tax on advertisements. But, by a subterfuge, you say that it is not a tax on advertisements. You put a ceiling on advertisements and say that anything spent over the ceiling will not be treated as a deductible expenditure. Then it becomes an income on which income-tax is leviable. Honesty, in pith and substance, what is it ? It is a tax on advertisement, and as a tax on advertisement it is a source of revenue for the State. You are eroding that State revenue. Somebody may challenge it, but it is my duty to bring it to the notice of the Government.

The same practice has been followed even in the past. Before 1959 the income of companies was treated as income and tax thereon was divisible among the States. In 1959 you brought forward a subterfuge by which you said it is a corporation tax and, as such, it should entirely go to the Centre. People have protested against this throughout before the Finance Commission and every Finance Commission has pointed out that the corporation tax should be divisible among the States.

Therefore, I want to point out that the levy in respect of both electricity and advertisement will be challenged in the courts and you will not be able to sustain your stand.

On the whole, I am grateful to the Finance Minister for whatever little concessions he has given, but he may go a little forward in respect of indirect taxes, because indirect taxes are going to be more than Rs. 400 crores, which are going to weigh very heavily on the people.

श्री हरिकेश बहादुर : (गोरखपुर) मान्यवर, जो वित्त विधेयक सदन के सामने आया हुआ है, मै उस का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वित्त मंत्री जी ने जो कन्सेशन्स एनाउन्स किये हैं, उस के लिए हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। सरकार ने उन तमाम लोगों की समस्याओं को, जो बजट आने के बाद परेशानी अनुभव कर रहे थे, उनकी समस्याओं को सुलझाने में ठोस कदम आगे बढ़ाया है।

आज जो सब से बड़ी समस्या हमारे समाज में है—वह इस देश में आर्थिक

[श्री हरिकेश बहादुर]

सत्ता का कुछ व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रीय-करण है——सरकार को इस दिशा में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। क्योंकि पिछली सरकार के ज़माने में जिन बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों की पूंजी बहुत सीमित थी, वह उन के लम्बे शासनकाल में काफ़ी बड़ी है। जैसे उदाहरण के लिए बिड़ला की पूंजी जो आजादी के समय 100 करोड़ से कम थी, आज वह 1000 करोड़ से ज्यादा है। ऐसी स्थिति में, मान्यवर, यह स्पष्ट है कि पिछली सरकार ने पूंजीपतियों को गरीब जनता के शोषण के लिए खुली छूट दी थी और उन्होंने इस बात का कभी ख्याल नहीं किया कि आज जो आर्थिक सत्ता का केन्द्रीय-करण कुछ लोगों के हाथों में हो रहा है, उस का परिणाम आम लोगों के ऊपर क्या होगा। यही कारण था कि बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों ने देश की गरीब जनता का शोषण किया और अपने अर्थ-तन्त्र को मजबूत बनाया। हम यह उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार इस दिशा में विशेष रूप से ध्यान देगी और पूंजी की सीमा निर्धारित करेगी। क्योंकि हम इसे अत्यन्त आवश्यक समझते हैं। जिस व्यक्ति के पास सीमा से अधिक पूंजी होती है, वह समाज के शोषण के द्वारा आर्थिक सत्ता को केन्द्रित करने लगता है। निश्चित सीमा से अधिक पूंजी सरकारी नियंत्रण में होनी चाहिए। आय में भी भारी अन्तर का होना एक बहुत बड़ा अभिशाप है। मैं जहां पूंजी पर सीमा निर्धारित करने की बात करता हूं, वहां यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए कि आय की सीमा भी निर्धारित की जाए क्योंकि बड़े बड़े औद्योगिक घरानों में कार्य करने वाले बड़े बड़े ओहदों पर जो लोग हैं, वे इतना वेतन पाते हैं कि सम्भवत: वह राष्ट्रपति के वेतन से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, बिजनेस में जो लगे हुए लोग हैं, वे अपनी आय की जानकारी ठीक ढंग से नहीं देते हैं जिस के कारण इन्कम टैक्स भी सही तरीके से उन से वसूल नहीं हो पा रहा है। इन्कम टैक्स की चोरी करना, एक्साइज़ ड्यूटी की चोरी करना, इस तरह के तमाम इकोनोमिक आफेन्सेज़ पिछली सरकार के जमाने में बहुत अधिक हुए हैं लेकिन मैं वर्तमान सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उस ने इस दिशा में बहुत ठोस कदम उठाया है। अभी मोहन मेकिन्स के खिलाफ़ जो सरकार ने कार्यवाही की है, उस के लिए मैं वित्त मंत्री जी और अपने राज्य वित्त मंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। केवल मोहन मेकिन्स ही नहीं, ऐसे बहुत से औद्योगिक घराने हैं जिन्होंने टैक्सों की चोरी की है और उन के ऊपर कोई सही ढंग से कार्यवाही नहीं हो पा रही है। जो हमारे मौजूदा कानून हैं, वे कानून भी सफीशियेन्ट नहीं हैं और उन के रहते ये सब लोग बच जाते हैं। जो पकड़े भी जाते हैं तो अदालतों में मामले चलते रहते हैं, जमानत हो जाती है और इस तरह से ये लोग शोषण की प्रक्रिया में निरन्तर लगे हुए हैं और सरकार के जो कानून हैं, वे प्रभावशाली ढंग से इन लोगों पर लागू नहीं हो पाते। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस के लिए अलग से अदालतें बनाई जाएं और अगर आवश्यक हो, तो संविधान में भी संशोधन किया जाए जिस से इस प्रकार के एकोनोमिक आफेण्डर्स को कड़ी सजा देने की हम व्यवस्था कर सकें। अगर यह कार्य नहीं होगा, तो हम समझते हैं कि हमेशा ही ये बड़े बड़े पूंजीपति जनता का शोषण करते रहेंगे और सरकार को बदनाम करते रहेंगे और अपने पैसे के बल पर सरकार के ऊपर हमेशा दबाव भी डालते रहेंगे। मैं समझता हूं कि सरकार इस दिशा में ध्यान देगी और ऐसे कानून बनाए जाएंगे जिनमें इन बड़े बड़े पूंजीपतियों को जो देश के साथ धोखा करते हैं, ऐसे लोगों पर फाइन करने और जेल भेजने के नियम बना सकेंगे और इस उम्मीद के साथ साथ मैं यह विश्वास भी व्यक्त करना चाहता हूं कि सरकार इस

दिशा में किसी भी प्रकार के दबाव के अन्तर्गत नहीं आएगी और प्रभावशाली ढंग से इस दिशा में कार्य करेंगी ।

श्रमिकों का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं कि श्रमिकों को सब से अधिक परेशानी बड़े-बड़े उद्योगपतियों से होती है । सरकार ने तो अपने उद्योगों में श्रमिकों को कुछ राहत देने की कोशिश की है और सरकार यह भी कोशिश करती रही है कि उन श्रमिकों, जोकि पूंजीपतियों के उद्योगों में कार्य करते हैं, को भी कुछ राहत मिले लेकिन पूंजीपति बहुत चालाक होते हैं और वे एक विशेष ढंग से श्रमिकों का शोषण करते रहते हैं । इसलिए मेरा कहना यह है कि बड़े-बड़े उद्योग घरानों की पूंजी की सीमा निर्धारित करनी चाहिए । ये घराने अपनी पूंजी से देश की राजनीति एवं प्रशासन को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रभावित करते हैं । ये जनता का शोषण कर के अपनी पूंजी में वृद्धि करते हैं । पत्रकारिता पर भी इन का पूर्ण नियंत्रण है तथा पूंजी के द्वारा ये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं । श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए पूंजीपतियों पर, नियन्त्रण आवश्यक है । इस के अलावा निजी क्षेत्र के बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक है जिस से श्रमिकों का शोषण बन्द किया जा सके । इसलिए मैं समझता हूं कि निश्चित सीमा से जब पूंजी अधिक होती है, तो वही पूंजी शोषण का माध्यम बनती है, शोषण का हथियार बनती है और इस से पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं । श्रमिकों के शोषण को बन्द करने के लिए बड़े-बड़े पूंजीपतियों के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना मैं जरूरी समझता हूं । पूंजीपति श्रमिकों के सब से बड़े शत्रु हैं । इन पूंजीपतियों को भ्रष्ट नौकरशाही मदद करती है और उस की मदद से ग़रीब श्रमिकों के शोषण करने का काम आसान होता है ।

इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव यह देना चाहूंगा कि राष्ट्रीय वेज पालिसी, नेशनल वेज पालिसी सरकार को बनानी चाहिए और इसमें हमारा वित्त मंत्रालय काफ़ी कुछ पहल कर सकता है ।

मान्यवर, हमारी सरकार ने स्मगलिंग को रोकने की दिशा में बहुत प्रभावशाली कदम उठाये हैं जब कि पिछली सरकार ने केवल दिखावे के लिए ही काम किया था । 19 महीने के अत्याचारपूर्ण शासन को जस्टफाई करने के लिए कुछ स्मगलर्स को जेलों में डाला था । इसका सब से बड़ा कारण यह था कि स्मगलर्स की कुछ राजनीतिक तत्वों के साथ सांठगांठ थी । मान्यवर, इसकी जांच होनी चाहिए । मान्यवर मैं किसी पोलिटिकल पार्टी विशेष के बारे में नहीं कह रहा हूं बल्कि इस बात को कह रहा हूं कि तमाम स्मगलर्स के पोलिटिकल लिंक्स खोजे जाने चाहिएं । मैं किसी एक पोलिटिकल पार्टी को इस के लिए दोषी नहीं ठहराना चाहता हूं । मैं यह बात साफ़ कहना चाहता हूं कि जो भी स्मगलर्स के साथ सांठगांठ करता है उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए और इस बात की जांच होनी चाहिए ।

मान्यवर मैं सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने 150 लोगों को कोफीपोसा में अभी बन्द किया है । यह सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और सरकार इस के लिए बधाई की पात्र है । ऐसे लोगों को पकड़ा जाना चाहिए और जेलों में बन्द किया जाना चाहिए । इसके बाद उन पर मुकद्दमा भी चलाया जाना चाहिए । इसके लिए भी मेरा वही पुराना सुझाव है कि यदि आवश्यक हो तो संविधान में भी संशोधन कर इन स्मगलर्स पर कड़ा नियंत्रण स्थापित करना चाहिए ।

मान्यवर, मैं मंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार

[श्री हरिकेश बहादुर]

ने बहुत बड़ी मात्रा में हसीस पकड़ी है । उस हसीस को पकड़ कर, देश की अर्थ व्यवस्था को चोट पहुंचाने वाले कुछ तस्करों पर सरकार ने प्रहार किया है । इस तरह के कदम सरकार को हमेशा मजबूती और सफलता के साथ उठाते रहना चाहिए ताकि देश में तस्करी पूर्णतया बंद हो जाए ।

मान्यवर, सरकार ने स्वर्ण की बिक्री का कार्य शुरू किया है । अगर इस कार्य से प्राइस कंट्रोल हो सकती हैं, आवश्यक चीजों के दाम और साथ साथ सोने के दाम भी नीचे आ सकते हैं तो इस कार्य को अच्छा कहा जा सकता है । इस मायने मैं यह कार्य सराहनीय हो सकता है । लेकिन जब सोने का दाम गिरने लगे और यह एक सीमा तक नीचे आ जाए तो सरकार को सोने की बिक्री बंद कर देनी चाहिए क्योंकि इसको बेचने मैं सरकार का मूल्य उद्देश्य यह है कि इसके दाम को घटाया जाए और दूसरी चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण स्थापित किया जाए । मैं समझता हूं कि अगर सरकार के सोना बेचने से सोने का दाम गिरता है तो उस के बाद इसकी बिक्री बन्द हो जानी चाहिए और शेष सोने को सुरक्षित रखा जाना चाहिए ताकि फिर कभी इस कदम को उठा कर सरकार वस्तुओं के दामों को नियंत्रित कर सके ।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं कुछ और बातें कहना चाहता हूं जिनका हो सकता है इस फाइनेन्स बिल से सीधा सम्बन्ध न हो लेकिन फिर भी काफी कुछ सम्बन्ध मैं उनका इस फाइनेंस बिल से मानता हूं । आजकल हमारे देश में सब से बड़ी समस्या ग्रामीण विकास की है । इस ग्रामीण विकास में जितनी तेजी लानी चाहिए थी वह तेजी नहीं आ रही है । मान्यवर, साथ ही बेरोजगारी भी समाप्त नहीं हो रही है । मैं जानता हूं कि सरकार का इस सम्बन्ध मैं क्या इरादा है । सरकार को इसका उन्मूलन करने में पूरी आस्था और विश्वास है । सरकार चाहती है कि देश तरक्की करे, देश से बेरोजगारी दूर हो । मान्यवर, वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उससे देश की प्रगति में काफी मदद मिलेगी । मगर, मान्यवर, आज जनता को जितना संतोष चाहिए, उतना संतोष उसे नहीं मिल पा रहा है । गांवों के अन्दर आज भी हालत वैसी ही है । वहां पर सिंचाई के साधनों पीने के पानी, स्कूलों, अस्पतालों और छोटे-छोटे घरेलू उद्योगों की व्यवस्था सरकार को शीघ्र करनी चाहिए । अगर हमें विकास करना है तो इस में कोई सन्देह नहीं है कि बेरोजगारी को हमें दूर करना होगा । अगर इसको दूर नहीं कर सकेंगे तो देश मैं ऐसी स्थिति कायम नहीं रहेगी कि विकास कार्यों को तेज़ी के साथ हम चला सकें । बेरोजगारी ने ही आज देश के अन्दर सब से ज्यादा असन्तोष पैदा किया है और यही उसका सब से बड़ा कारण बनी हुई है । इसके लक्षण और इसकी प्रतिक्रियायें हमें समाज में हमेशा देखने को मिल रही हैं । ग्रामीण विकास, गृह उद्योगों के विकास, छोटे उद्योगों के विकास के साथ ही इस समस्या को समाप्त करने की दिशा में कारगर कदम उठाए जाने चाहिएं और हम को चाहिए कि हम अपने वित्तीय साधनों को इस तरफ डाइवर्ट करें, उनको इस तरह का मोड़ दें ताकि यह समस्या आसानी से और जल्दी से जल्दी हल हो ।

उत्तर प्रदेश , बिहार तथा कुछ अन्य राज्यों में चीनी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। वहां पर चीनी की मिलें हैं। किसानों को इस गन्ने की वजह से काफ़ी कुछ नुक्सान उठाना पड़ा है । तमाम लोगों का गन्ना खेतों मैं सूख गया है। कुछ लोगों ने अपना गन्ना जला तक दिया है। हो सकता है कि इस तरह की बात किसी और कारण से भी हुई हो लेकिन ज्यादा तर यही देखने में आया है कि चीनी मिल मालिकों के इरादे किसानों के खिलाफ़ हैं और साथ ही समाज विरोधी हैं। उसका भी यह एक परिणाम रहा है कि

लोगों को अपना गन्ना जला देना पड़ा है या उनका गन्ना खेतो में सूख गया है। अब से नहीं पिछले कई महीनों से बराबर मैं कहता आ रहा हूं कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। हो सकता है कि सरकार के सामने कुछ कठिनाइयां हों। लेकिन चीनी मिल मालिक किसी भी हालत में सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता है। वे किसानों का शोषण करते रहेंगे, किसानों को नुक्सान पहुंचाते रहेंगे। अपनी चीनी मिलों को बहुत ही खराब हालत में वे आज रखे हुए हैं क्योंकि उनको इस बात का सन्देह है कि ये मिलें सरकार द्वारा अपने हाथ में ले ली जाएंगी जिससे उनको बहुत बड़ा नुक्सान होगा। अगर हम उनके इन तमाम तरह के आडम्बरों के पीछे पड़े रहेंगे और डरते रहेंगे तो हम किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकेंगे। हमें इस काम को करना ही होगा भले ही इसके लिए सरकारी कोष से कुछ पैसा लगा कर हम को इन मिलों को फिर से नई हालत में लाना पड़े भले ही सरकार को इस काम के लिए कुछ ज्यादा पैसा खर्च करना पड़े। अगर किसान और देश का व्यापक हित हम चाहते हैं तो इन मिलों का राष्ट्रीयकरण करना बहुत ज़रूरी है और सरकार को इनको अपने हाथ में ले लेना चाहिए।

दो और समस्यायें हैं जिन के ऊपर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। हरिजनों की समस्याओं पर बराबर इस सदन में चर्चा होती रहती है। इसके लिए सरकार को दोषी ठहराया जाए इससे मैं ज्यादा सहमत नहीं हूं। खास कर विरोधी दल के लोगो ने जिस तरह से हमारी सरकार पर इस बात के लिए प्रहार किया है उससे भी मैं सहमत नहीं हूं। जनता पार्टी की सरकार ने हरिजन उत्थान की दिशा में जो कदम उठाए हैं उन से सदन अवगत है। अभी कर्नाटक के अन्दर क्या हुआ है इसको हमारे मित्र श्री मनोरजन भक्त अच्छी तरह से जानते हैं। इस सदन में इसको ले कर मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस भी दिया था लेकिन उसकी मुझे इजाजत नहीं दी गई। यह एक सामाजिक समस्या के रूप में हमारे सामने हैं। सभी राजनीतिक दल, सभी बुद्धिजीवी और तमाम ऐसे लोग जो आज सुविधा प्राप्त कर रहे हैं या अपने को उच्च वर्ग के समझते हैं यह उन सब की जिम्मेदारी है कि वे देखे कि किसी भी हरिजन, किसी भी आदिवासी, किसी भी ऐसे व्यक्ति के प्रति जो दलित है किसी भी प्रकार का अन्याय न हो। चाहे कोई भी सरकार हो, जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की हो सभी को प्रभावशाली ढंग से कार्य इस दिशा में करना चाहिए और अगर वे नहीं करती हैं तो मैं उनकी कड़े शब्दों में सदन के इस धरातल से निन्दा भी करना चाहता हूं। तरह-तरह के सुझाव भी इस समस्या के समाधान के लिए दिए जा सकते हैं। यह कहा गया है कि जिलाधिकारियों और जिले के जो पुलिस अधीक्षक होते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस होते हैं अगर इस प्रकार की वारदात होती है तो उनको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। मैं कहूंगा कि ग्राम सभा का जो पंच होता है, सरपंच होता है उनको भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए बल्कि हर ऐसे व्यक्ति को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए जोकि समाज के अन्दर रहता है और समाज के अन्दर शान्ति स्थापित करना चाहता है।

मान्यवर, इसके बारे में मेरा एक सुझाव है कि हरिजनों के उत्थान के लिए बड़ी बड़ी बाते यहां पर होती हैं, कुछ लोगों के लिए नौकरियों में जगह भी सुरक्षित हैं। लेकिन अगर आप हरिजन बस्तियों को देखे तो पायेंगे कि वहां पर इतनी गंदगी रहती है कि कोई भी इन्सान ठीक ढंग से नहीं रह सकता है। इसलिए तमाम गरीब लोग रोगों के शिकार हैं और उनका स्वास्थ्य खराब है। उन्हे ऐसा वातावरण नहीं मिल पाता है जिससे वे अपना शारीरिक

[श्री हरिकेश बहादुर]

और मानसिक विकास कर सके। इसलिए हरिजन बस्तियों के उत्थान के लिए बिजली पानी, सड़क निर्माण के लिए कुछ पैसा हमको डाइवर्ट करना चाहिए, और इस दिशा में सरकार को कदम उठना चाहिए।

अन्त में मैं गरीब बुनकरों की समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज यार्न का दाम बढ़ जाने की वजह से और साथ ही कुछ बड़े बुनकरों के हो द्वारा बनाय हुए माल का सरकारी संस्थानों और कारपोरेशन द्वारा खरीदे जाने के कारण गरीब बुनकरों की स्थिति खराब होती जा रही है। हमारे क्षेत्र में तमाम हथकरघे बन्द पड़े हुए हैं क्योंकि जो अलग अलग से लोग अपना कपड़ा बनाते हैं उनका कपड़ा सरकारी संस्थानों द्वारा नहीं खरीदा जाता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार राज्य सरकारों को इस तरह की हिदायत दे साथ ही केन्द्रीय सरकार इस दिशा में कदम उठाय कि जो गरीब बुनकर अलग कपड़ा बनाते हैं उनका कपड़ा सीधे खरीदने की व्यवस्था कोरपोरेशन्स के जरिए की जाये ताकि वे बेरोजगारी के शिकार न हों और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे तथा समाज में शांति और ठीक ढंग से रह सकें, सुख से जीवन बिता सकें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और सरकार को फिर से धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने बहुत से कन्सेशन्स दिये हैं जनता को और साथ ही देश को तरक्की की तरफ ले जाने का एक बजट पेश किया है, और जो वित्त विधेयक सरकार ने हमारे सामने रखा है वह विधेयक निश्चय ही इस देश के अर्थतंत्र को मजबूत करने में सफल होगा।

SHRI T A PAI (Udipi) Mr. Deputy Speaker, Sir, the Finance Minister was an angry man when he was replying to the debate last time. He would not like any criticism at all He expected the country to welcome the type of budget that he had presented and the type of taxation measures that he had suggested. Unfortunately, the whole country was unhappy perhaps except himself Nobody can be proud or happy of the type of budget that he had presented If only he was in the opposition, I think he would have criticised some of these measures and the way economy had been managed much more bitterly than perhaps one would have thought

As an Indian, I want this Government to succeed but as a Member of the opposition it is our duty to point out that this way the country cannot go ahead. After all last year, Rs 200 crores was not invested what was proposed to be invested and should not the House know why and under what scheme this money was not invested I would very much like in future the Finance Minister to give the break up of cost of any project year by year and take the approval of the Parliament so that we might know how much money was expected to be spent, why it had not been spent and what was coming in the way because the Finance Minister himself had pointed out last time, in the booklet about the cost of delay The Government's schemes which were not implemented in time would escalate the costs and caused damage to the economy so much that a job which we could do in two years, if we did it in three years it would be the same job, but the achievements would be far delayed

When it comes to a question of deficit also, feeling has been that every time the Finance Ministry- not only this time even in the past whenever certain deficits were promised they have always exceeded them Why should not the House know why is it that the deficits have gone up, what was the reason and under what heads so that we may have a chance to look into it? Why should we be presented with a blank deficit and be told that this is the deficit that we have arrived at? Well as a matter of fact the only defence that the Finance Minister had was that the Janata's deficit was different from the Congress's deficit Well, I do not know what he meant by it Deficit is deficit True, when the Congress Government presented the budget, it was Congress deficit and when the Janata Government presented the budget, it was Janata's deficit, but the effect of the economy on deficit is the same. Let us not fool ourselves by saying that we are presenting something which is more beautiful before the country.

SHRI NARENDRA P NATHWANI (Junagadh) : He would better refer to paragraph 34 of the Finance Minister's speech where

he has explained how out of Rs. 935 crores Rs. 414 crores were given to the States.

SHRI T.A. PAI : I would also like to point out that deficit is not only what has been promised by the Central Government this year. A large portion of the investment funds has been given to the State sector in this Budget. The State Governments knew, when their Budgets were drawn up, what were the amounts that were coming to them. In spite of that, the deficit by the State Governments this year are over Rs. 800 crores. It is the total deficit of the entire economy that we should be concerned with. You cannot have a Central deficit and a State deficit. They are not different for the economy.

Now, look at the Electricity Boards. The accumulated losses of the Electricity Boards come to Rs. 750 crores ; this year alone they have made a total loss of Rs.165 crores. If we go on managing the economy of this country in this way, that will be at the expense of the poorest man. I am only pleading for this nation becoming more efficient than what it is today.

It is not necessay to explain that we have failed. We cannot afford to fail. The others can. That is the reason why I am making this appeal to you.

Look at the way subsidies are being distributed. I have been strongly feeling that subsidy is one source of corruption in the entire economy Why don't you have a Subsidy Commission, and why don't you have a Subsidy Corporation, so that the Commission and Corporation may go into what type of activities. what areas of economic development for what classes of people, the subsidy must go. If subsidy has to be given, it has to go to the poorest people and not to the others who int he name of subsidy, are getting the benefit : in fact, they are the only people who derive the benefit . It is time that we tried to examine the cost-benefit effect of subsidies that we are extending.

I am suggesting, therefore, that, with regard to planned expenditure, there should be greater efforts. This year also omnibus sanctions have been given. The Finance Minister said that details of employment were being worked out. Are you not sure of the employment potential or problem in the past, the economists said that, if Rs. 1 crore were invested, automatically so many jobs would be created. But nobody has cared to find out whether the jobs are being created : even if you throw the resources into the Arabian Sea, nobody would know. Therefore, it is time that, in this country, we tried to decide how an investment of Rs. 1 crore now invested can create more jobs. Unfortunately, the Planning Commission consists only of economists. We do not have engineers who can say how this money can be invested to achieve our employment goal. We require experts who are in a position to give the alternatives—where employment can be created. Mere slogans that what is made in the cottage sector will create more employment or what is made in the small scale sector will create employment, will not do. These are only generalised statements. When during this year so much of money is being invested, it is better the House is informed, under each sector, how many jobs are sought to be created as a result of this investment. Then only the investment will be meaningful. Do not take it for granted as we did in the past. I am only drawing your attention to this. Mistakes may have been made in the country in the past at any time on account of our inexperience. This nation has the right to make a mistake once, but it cannot repeat it. It must learn lessons from the mistakes it has made—now they could be rectified. Do not take it for granted that we can go on extending our failures. It is time we get up and see what we have got to get over these problems.

My friend, Mr. Venkataraman, did not agree with gold imports. I would agree with gold imports for one thing When I went to the Middle East as Minister for Industries, I had received representations from many people that there was a big market for jewellery made in India. Therefore, if it could provide employment in this country, what is wrong in importing gold. making jewellery and exporting it ? I do not understand why all kinds of ideological conflicts are brought into this. Gold is a commodity. As a matter of fact, we had been following a wrong policy.

The Bharat Gold and the Kolar Gold Fields, for instance, whenever they mined gold they were required to sell it to the Reserve Bank at a price much below the present international price. In fact, it did not cover the cost of production. The result of it was that the Bharat Gold Fields has been continuously showing losses, because gold has been sold to the Reserve Bank at that price, and the activities of Bharat Gold Fields have been brought to a standstill. Soviet Russia does not mind the cost of mining : it goes on mining gold. Therefore, if on these false considerations, we do not explore and exploit the gold deposits—what—ever little deposits we have I think we would be doing a wrong thing.

There is a belief that gold is used only to hoard black money and it is used only by the rich people. Let us apply our

[SHRI T. A. PAI]

common sense. Millions of marriages take place every day. Even if only an ounce of gold is required for a Mangal Sutra—without which no marriage takes place in any community in India—what is the demand that is created ? If you are not going to meet the demand legally, it will have to be met by smuggling. This is an anti-smuggling measure and I do not know why the Finance Minister is on the defensive. Our difficulty is that we want, in this country, to be always playing the politics of rhetoric, without going into the sound reasons why a particular decision becomes necessary at a particular time. And gold is a commodity. If you can import any commodity and sell it in this country to create rupee resources, don't understand why we should not do it with gold.

My complaint is that you are saying that you will only sell the gold which is now with the Reserve Bank. Why should you have said it ? Because, the people know how much gold you have : and they are asking what you will do after that. People have been saying that you are doing somethting antinational, which the previous Government did not do I don't agree with that. What you should do is, if you want to import, in future you should announce the policy that in order to bring down the price of gold in this country, you will import as much gold as is necessary, without giving a time limit and without allowing for speculation to go on—because it is weakness that you are now projecting in your policy.

Take for instance the import policy. You say it is good for one year. People know that after one year it may be stopped. So they import as much as they can, store it, hoard it and make money. You are responsible for creating these conditions. Why don't you have a basic policy for five years at least ? Why should not the country know that for five years you know your own mind ? If you do not know your mind, how do you expect the country to know its mind—or your mind, for that matter ?

Now, I come to the question of indirect taxes. Well, the Jha Committee set on this, because, over a period of yours, our excise duties had become irrational. We imposed excise duty on certain commodities at particular times because there was shortage and there was a black-market price for them. Instead of somebody pocketing it, why should dot the Government pocket it through excise ? But now even when the black-market does not continue, you continue to have the tax and therefore it becomes impossible for people to even have those commodites made available.

You are now all for large-scale development of small scale industries. Now, when a small scale unit sells its product to a big plant, it is made to pay excise on that whereas one big plant making the product within itself will not have to pay excise on the product it makes. Then, who is interested in buying from small scale units where, at every stage, there is excise on excise? The cascading effect of this system makes the final product also very expensive. So we wanted the Jha Committee to rationalise this. But when they made their recommendation what did you do? You say that you have accepted it in principle but you have put an omnibus increase of 5% on everything. Now, do you require an expert Committee to put a 5% increase on everything? Why 5%? Why not 6% ? Why not 7% ? You don't require an expert Committee for that. What I regret is that we do not have any research as to the effect of any taxation measure on the nature of our economy from time to time. Because, fiscal measures also can build up the economy just as it can destroy the economy. So my appeal to you is not to quote some Committee. The Committee never asked you to have a 5% increase. And don't say that you have rationalised it. What have you rationalised ? You have thrown this report into the waste-paper basket and you have increased it by 5% because you are anxious to raise resources.

Then, what is the other tax that you have imposed? It is on the advertisements. Now, so many of these photographers and small people are engaged in this. One tax system can destroy the whole activity and throw them out of employment. While even now the companies can hold parties in the Five Star hotels and spend any amount of money. Put a stop to that. Why do you put a stop to the advertisements. I do not even agree that the small concessions which you have given are rational enough. There has been so much of opposition and so many problems have been pointed out. It is your duty to see not to stand on any prestige to scrap it altogether.

15.00 hrs.

Now, a word about taxation on electricity. As I told you the electricit boards are not functioning properly. They are not generating even 50 per cne of power. They make losses. You go not

providing funds to them and again you are now taxing them. I do not know whether it is not a question of transferring the resources from the States to the Centre. I would request you to call the Attorney General to the House to tell us before we consider this Bill whether it is legal for this government to impose this kind of a tax on electricity.

Regarding coal, well I know the working of Coal Ministry. We had a fuel policy decided. We said wherever coal can be used diesel shall not be used. Now, what do you see. Coal because it is not being transported by train now is transported as long as 1,500 miles to different parts of the country by trucks using diesel. Is there anything more foolish than this! Namely, using diesel to move coal so that coal can be used. Why not use diesel itself directly. Is there any economy which fits with these words but when it comes to implementation it does not care to see where we are going wrong. On coal you have imposed a duty. What will they do? CMA will have to pay the duty as soon as they mine. So, the CNA whose bills are not settled by Government department—over 85% of coal is used by Government departments will run into further difficulties because CMA will not have money to pay you advance excise duty and apart from this the fact these electricity bills and coal bills and increased cost of electric generation because of increased coal bills is going to eat into the economy and when you say that *it is* not likely to create any inflation does it mean as if inflation like King Canute can be ordered to be stopped.

You have been publishing wholesale prices. Sir, when I was myself in Administration I thought this price index was a thing which people are fooled with because there is no realism in it. From 30 centres you ask your officials to collect the prices. If the Government wants to create a situation where there is no price rise they will get the same type of report that you want. Will the Minister of State and the Finance Minister go to the vegetable markets or the various other markets where the housewives have to go and then find out the increase in prices. When the people tell the merchants that the newspapers or the Doordarshan say there is no increase in prices the merchants tell them to go to Doordarshan or the Papers to buy whatever they wanted to buy. If you want to purchase you have to pay this price. So, let us not feel ourselves. The economy must have one objective. To say that the prices will not go up is foolish. If the wages and other things go up the prices will go up but we should have a ceiling. We can have a plan to say that beyond this we will not allow the prices to go up. One can understand that. We have to look into as to why costs are also going up. Have you got a policy of five years at least to stabilise the prices of basic raw-materials, such as, fertilisers, insecticides—so far as agriculture is concerned—steel, copper, aluminium and other metals? What is the idea of trying to control the end-product without having a stable policy for the prices of raw-materials?

Sir, I come to your Department now. Some of my friends referred to some people being detained under COFEPOSA and they were very happy. In a way we introduced the *MISA* and we also gave a solemn undertaking to this House that we were not going to detain any politicians or anybody under this. But you know what happened. COFEPOSA is equally dangerous because we may all support it saying that it is meant against smugglers just as we said that every politician is guilty of some crime under MISA and the COFEPOSA for the same purpose. *It is possible to use this because* any law in this country, where there is no trial, shall go. If you believe in restoring freedom, I think this is as bad as MISA so far as the detention powers are concerned. Why is it that the politicians or the Government does not want to put these smugglers on trial? Are they afraid that smugglers might disclose their connections with the politics of this country whichever party it may be? Why not prove that they are guilty? Why should you detain them? It is only because you can make their mouth shut that you keep them behind bars without any trial. Please look into it. It will not do any credit for you to get 20,000 letters opened every day and have the telephones also tapped. This may be a privilege of your Ministry. But that privilege deserves to be there if the smugglers are to be tried properly and punished properly. Let them know it. Let there be a fair trial according to everyone.

Another thing is about the difficulties that the people have to encounter with the customs. It is not that the customs people are sedastic, but they are not able to interpret your confused laws. Some years ago, three years ago, during our regime, a ship that was going from Greece to Hong Kong got into difficulties near Mangalore and the ship had to unload some of the motor-cycles because it was overloaded. The Captain of the ship came to the shore and offered the motor-cycles to the educational institutions as a gift. The Customs had said "No, you cannot do it." Then the Captain said "I am prepared to give them as gift to the Government". The Customs people said that they would not accept

[Shri T A Pai]

them without the permission from Delhi Then the Captain got in touch with Delhi for which the answer was No So he said I do not know what kind of people you are", and threw all the motor cycles into the sea and went away Now, ever since the British days the archaic customs laws have been continuing and God knows when it will be changed It requires an expert to understand Why don't you simplify them ? I also understand that a non resident Indian after staying abroad returns to the country within two years is treated as a traveller as a tourist and is not entitled even to the goods worth of Rs 500 to bring in Even when when we go out and return to the country we are allowed to bring them in Is it fair ? Why don t you treat all the people equally ? I am sure the whole administration is based on one theory An Indian cannot be trusted by another Indian The British started this system Whatever your administrative reform is as long as you are not prepared to trust the people of this country and as long as you do not have the courage to punish those who are going wrong you are in the name of punishing the wrong ones punishing the right ones and allow the wrong ones to escape this country would not progress I think you will have to see that your rules regarding the Income tax and Customs are so drawn up that it encourages the people to be more honest and do not avoid it Therefore I think it requires a lot of reform to be carried out I would very much wish the Finance Minister looks into the project implementation in time because he himslelf knows the cost of delays and I would very much like that the taxation measures particularly the advertisement tax is done away with and so far as the electricity duty is concerned the Attorney General is asked to appear before the House and advise us

श्री महामाया प्रसाद सिंह (पटना) आपने मुझे बैठ कर बोलने की इजाजत दी है इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हू । इसका कारण मेरी बीमारी है । मैं अपना हाल आपको क्या बताऊ ।

दर्द अपने हाल से तुझे आगाह क्या करे

जो सास भी न ले सके वह आह क्या करे ।

आज अपने देश की यही हालत है । हमारी भी यही हालत है । हमारे प्रान्त बिहार मे आप जाए वहा के हालात को देखें तो आपकी आखो से आसू टपकने लगेंगे । यह वह बिहार है जो महात्मा बुद्ध का है, महावीर का है जो महात्मा गाधी की कर्म भूमि रहा है जो जय प्रकाश जी का बिहार है, राजेन्द्र बाबू का बिहार है । उस बिहार को आज ऐसी दुर्दशा हो रही है कि जिस को मैं बयान नही कर सकता हू । आज से एक साल पहले जब मैं यहा चुन कर आया था उस वक्त हम लोगो ने राजघाट पर जा कर शपथ ली थी कि हम गाधी जी के विचारो को अमली जामा पहनाएगे जय प्रकाश जी की सम्पूर्ण क्रान्ति को लहर का दौडने देंगे, ऐसा वातावरण देश म बनाएगे जिस मे जातीयता न रहे प्रान्तीयता न रहे फिरका परस्ती न रहे साम्प्रदायिकता न रहे आपस म मेलजाल रहे किसी तरह का विवाद न हो और देश का शासन ठीक तरह से चल सके । लोगो ने इलैक्शन के पहले जिस उत्साह जिस प्रेम के साथ हम को जिताया था वह इस तरह से है

मस्जिद तो बना दी शब भर मे ईमान के
हरारत वालो ने
मन अपना पुराना पापी है बरसो में
नमाजी बन न सका ।

एक साल गुजर गया है लेकिन हालत बिगडती चली जा रही है । बिहार आग में जल रहा है । बिहार मे झगडे हो रहे है, गृह कलह हो रहा है लोग मर रहे हैं, राहजनी, डाकेजनी स्त्रियो का शील हरण, कौन कौन सी वारदाते नही हो रही है, मैं कहना नही चाहता हू । मैं चाहता हू यह सरकार कड़ाई के साथ देखे, सुने, सोचे, समझे और जो लोग गलत काम करते हैं उन्हे दड दे । दड कैसा गोली चला कर, लाठी मार कर, अश्रुगैस चला कर ? नही । दड देने का मतलब यह है कि एक ऐसा वातावरण बनाए ताकि लोग आपस में प्रेम से रहें, सद्भावना से रहे, आपस मे मेल मिलाप से रहें और गाधी जी के रास्ते पर चल कर देश को समुन्नत बनाने की कोशिश करे प्रयत्न करे । लेकिन ऐसा नही हो रहा है । मिनिस्टरो के बयान निकलते हैं कि देश में अमन चैन है । लेकिन

मैं साफ तौर से कहना चाहता हू कि बात ऐसी नही है। मैने पहले ही कहा कि— बिहार जल रहा है और अगर बिहार जल गया तो क्या आप समझते हैं कि हिन्दुस्तान बचेगा ? इसलिए बिहार को बचाना हैं तो आपका यह कर्तव्य है कि अगर यह बिहार सरकार का कर्तव्य है तो हमारा भी उस काम मे सहयोग देना धर्म है। गाधी जी के रास्ते पर हम चलें। आपको मै यकीन दिलाना चाहता हू, मैं किसी के ऊपर कोई दोषारोपण करना नही चाहता हू, लेकिन जिस तरह से पुरानी सरकार को लोगो ने एक जुट हो कर उसके खराब कामो के लिए उसको सजा दी और वह सरकार टूट गई और यहा आपकी सरकार बनी, और लोग वही है, हम वही है, आप वही है और अगर कोई भी सरकार जनता की रक्षा नही करती है, जन मानस के कल्याण के लिए कोशिश नही करती है वह सरकार बराबर खतरे में रहती है। लेकिन मुझको उम्मीद है कि इस सदन के नेता, हमारे नेता, आपके नेता माननीय मोरारजी भाई देसाई गाधीवादी है और वे एक ऐसी फिजा तैयार करेंगे कि सारा भारतवर्ष उस फिजा में मशगूल हो जाय और लोगो में जिस तरह का असतोष आया है उसको वह हटा सकेंगे।

साथ ही साथ कहा जाता है कि कीमतें कम हो रही है। हम भी कहते है, और लोग भी कहते हैं कि कीमते कम हो रही हैं। लेकिन जो लोग बिहार से आते है या दूसरी जगहों से आते हैं वह खबर देते है, कहते है कि कीमते कागज पर कम हो गई है, मगर दर हकीकत कीमते कम नही हुई है। जैसे कोयले को ही ले लीजिए। बिहार मे कोयला सब से ज्यादा निकलता है। धनबाद मे, झरिया मे और हजारी बाग मे कोयला निकलता है, लेकिन आपको मालूम है कि वही सबसे ज्यादा महगा कोयला बिहार मे बिकता है और बिक रहा है। आज भी दिल्ली मे कोयला सस्ता है बनिस्बत बिहार के। कारण क्या हैं ? आप सोचें इस पर और अमल करे। हम तो गाधी जी के साथ मे रहने वालों मे से एक थे, काम करने का मौका मिला था और असहयोग मे भी रहे और आज भी इस बुढापे मे 70 वर्ष की उम्र मे हम गाधी के मार्ग से विचलित होने वाले नही है, भले ही इस काम के लिए अपनी मातृभूमि के पादपदमो को अपने रक्त से पखारना पड़े। गाधीवाद के लिए मैं मरूगा, करूगा, और लड़ूगा, लेकिन देश को रसातल मे जाने से रोकने मे समर्थ होऊगा।

मुझको एक कहानी याद आयी, बगावत म मुझे यह सरकार मिली, मगर माफ कीजिए मेरे लम्बे भाषण के लिए और मेरी बोली के लिए, मेरे मुह मे अभी साफ आवाज नही निकलती है, एक साल से मै फालिज मे बीमार हू, एक किस्सा है और वह यह कि जब श्री राम लका जीत कर आये अयोध्या मे राजगद्दी हुई तो उन्होंने अपने सेनापतियों को इनाम इकराम देना शुरू किया। उसी हालत में उन्होंने हनुमान को भी एक बडी बेशकीमती माला दी। माला को ले कर हनुमान ने माला के दाने तोडने शुरू किये। लोगो ने पूछा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो ? तो हनुमान ने कहा जिस दाने मे राम नही वह माला हमारे लिए पहनना उचित नही है। उसी तरह से जिस काम मे गाधी नही, जयप्रकाश जी की सम्पूर्ण क्रान्ति की लहर नही, जो सरकार गाधी जी के रास्ते पर नही चलती है उसके साथ मै क्या कहू ? सहयोग दूगा, लडूगा, इनके साथ मरूगा, लेकिन बराबर यह आवाज उठाता रहूगा कि गाधी जी के रास्ते पर चलो उसी मे आपका कल्याण है, देश का कल्याण है और सारे ससार की मानवता का कल्याण है। इन्सानियत इसी मे है और उसी मे हमारी हैवानियत दूर जायगी। इससे ज्यादा मैं कुछ नही कहना चाहता। माननीय वित्त मन्त्री जी श्री पटेल जी बैठे हुए है, उनसे मै कहूगा कि कीमतो को आप कम कराने के लिए प्रयत्न कीजिए। कीमते कम नही होगी तो लोगों मे बेहाली

[श्री महामाया प्रसाद सिंह]

आयेगी, लोगों में तरह तरह की बुरी भावनायें पैदा होंगी ।

एक किस्सा कह कर मैं चुप हो जाऊंगा । हमारे यहां एक दावत हो रही थी, उसमें एक सूरदास गये । हमारे यहां का कायदा यह है कि जब तक दावत में घी न परोसा जाये, तब तक लोग कौर नहीं उठाते, भोजन नहीं शुरू करते । सूरदास के पास बैठे हुए एक आदमी ने उनसे पूछा कि सूरदास तुम खाना क्यों नहीं शुरू करते हो ? सूरदास ने कहा कि घी नहीं आया है । उसने कहा कि घी कड़कड़ा रहा है । उसने कहा कि घटों से मैं कड़कड़ाहट सुन रहा हूं, लेकिन घी हमारी थाली में नहीं आया, हलक के नीचे नहीं गया । तो कीमतें तो आप कहते हैं कम हो गई, तमाम कहते हैं, लेकिन वाकई क्या कीमतें कम हुई हैं ? आप गांव-गांव जा कर, घर-घर जा कर दरयाफ्त करें, लोगों से पूछें, अकेले में, चुप-चोरी जा कर, भेष बदलकर पूछें कि लोगों का क्या हाल है ? लोग यही कहेंगे, जो मैं कह रहा हूं, और कीमतें कम नहीं होंगी । भूख ज्यादा बढ़ती गई, हम गांधी के रास्ते पर नहीं चले तो हमारी दुर्दशा होगी और हमारा भारतवर्ष फिर धूल में मिल जायेगा, मगर जो आशा की किरण दिखाई देती है, वह यह है कि ऐसे लोग इस सदन और मिनिस्ट्री में हैं जो सब का उपकार चाहते हैं ।

एक शब्द मैं और कह देना चाहता हूं । मैं निहायत अदब के साथ आपसे हरिजनों के बारे में अर्ज करूंगा कि इस सदन में फिगर कोट होता है कि इन्दिरा गांधी के वक्त में हरिजनों पर अत्याचार क्या कुछ कम हुआ है, इन्दिरा गांधी के वक्त में बहुत से हरिजन मारे गये, लेकिन क्या आज हरिजन नहीं मारे गये हैं । ठीक है, माननीय मोरारजी देसाई ने कहा था कि अगर इस देश में एक भी हरिजन पामाल किया गया, एक भी हरिजन के ऊपर किसी तरह की आफत आई, तो वह लज्जा की बात होगी, हास्यास्पद है, शर्मनाक है, खतरनाक है और उसे देश को लाभ के ब.ले बहुत विपत्ति का सामना करना पड़ेगा । इसलिए आपस की लड़ाई जातीयता, द्रोह और कीमतों को कम करने के लिए आप कोशिश करें ।

हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं, सारा बिहार पुनः आपका साथ देगा । जिस तरह से हमने उस वक्त सारे के सारे लोगों को जिताया, कोई 5 लाख से, कोई 4 लाख से और कोई 3 लाख से जीता, फिर से वह स्थिति आ सकती है, लेकिन जो फिजा आज है, अगर यही रही तो मैं इस हाउस को और सरकार को वार्न कर देना चाहता हूं, एक पुराना खादिम होने के नाते, कि वह हमारा यश अपयश में परिणत हो जायेगा और हम धूल में मिल जायेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं, कृतज्ञता अर्पित करता हूं और माफी चाहता हूं कि अपनी बोली की वजह से मैं खड़ा हो कर नहीं बोल सका, बैठकर बोल रहा हूं । फिर कभी वक्त आयेगा, आपकी सेवा में हाजिर हो कर यह खादिम अपनी तकरीर करेगा ।

श्री राम देनी राम (पलामू) : आदरणीय उपाध्यक्ष जी, हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर ने फाइनेन्स बिल को मूव किया है, मैं उसका तहेदिल से समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

हमारे वित्त मंत्री न केवल वित्त मंत्री हैं, बल्कि इनका वित्त के मामले में व्यावहारिक ज्ञान भी है और मैं समझता हूं कि यह भारत की नब्ज को पहचानेंगे । इसी आशा के साथ मैं अपनी कुछ बातें आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष जी, आज कम-से-कम 15 बरस से मैं देख रहा हूं लेकिन अभी तक मैंड

रिफार्म्स आगे नही पढ़ पा रहा है इसका का क्या कारण है ? पिछली सरकार ने जो किया, उसका तो उस ने फल पाया । लेकिन मौजदा सरकार की लैंड रिफाम्र्ज की क्या पालिसी है, यह स्पष्ट होना चाहिए । हम और आप गांधी जी की रहनुमाई मे बराबर यह नारा देते थे कि लैंड शुड गो टु दि टिलर क्या हम उससे विमुख हो रहे है ? अभी माननीय महामाया बाबू ने—उन्होंने गांधियन फ़िलासफ़ी के अनुसार देश की सेवा की है—अपने विचार रखे है और मंत्री महोदय उन के हृदय की भावना को समझ गये होंगे । लैंड रिफाम्र्ज न करने से केवल किसानों का ही नुकसान नही हो रहा है बल्कि गवर्नमेंट का भी बहुत बडा नुकसान हो रहा है । एक तरफ जमीन मालिक समझते है कि हमारी जमीन जाने वाली है और दूसरी तरफ भूमिहीन समझते है कि हमे भूमि मिलने वाली है ।

यही वजह है कि आज जमीन-मालिक एग्रीकल्चर का काम कामर्शल ढंग से नही कर रहे है और वे उस मे पूजी नही लगा रहे हैं । क्या इससे केवल जनता को नुक्सान हो रहा है ? इससे सरकार का भी बहुत बड़ा नुक्सान हो रहा है । इसलिए मै चाहता हूं कि सरकार एक निश्चित समय तय, फिक्स, करे, और उस के अन्दर ही लैंड रिफ़ाम्र्ज लैंडसीलिंग और कानसालिडेशन आफ होल्डिंग्ज कर दे । उसके बाद ही वह कृषि मे पूजी लगाये । अगर वह यह कार्यवाही किये बिना पूजी लगायेगी, तो, इस देश में पिछले तीस वर्ष की आजादी के दौरान जिस तरह ग़रीब और गरीब होते चले गये है और अमीर और अमीर होते चले गये है, उसकी फिर पुनरावृत्ति होगी । इसलिए मेरा सादर अनुरोध है कि सरकार सब से पहले लैंड रिफ़ाम्र्ज करे और तब किसानों की मदद करना शुरू करे । यह ठीक है कि जमीन पर पूजी लगाने की आवश्यकता है, लेकिन लैंड रिफ़ाम्र्ज किये बिना पूजी लगाना व्यर्थ हो जायेगा ।

हमारे जिले मे नार्थ कोयल, औरंगा, अमानत, तहले और मलये नदियों को एक इनटेग्रेटिड प्लान मान कर नार्थ कोयल डैम सैक्शन किया गया था, जिसे कुटकू डैम भी कहते है । यह तय किया गया था कि उस डैम को फिफ्थ फाइव यीयर प्लान के अन्त तक पूरा कर दिया जायेगा । उस के प्रिलिमिनरी वर्क के लिए कुछ पैसे मिले है, लेकिन अभी तक डैम की शुरुआत भी नही हुई है, उस की बुनियाद भी नही पडी है । मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस बहुत बडे डैम के लिए काफी एलाटमेंट दे । हमारा पलामू जिला सदियो मे रेन-शैडो एरिया मे पडा हुआ है और वह विश्व भर मे सब से अधिक सुखाड और अकाल का जिला रहा है । इसलिए मंत्री महोदय विशेष कृपा कर के इस योजना के लिए एलाटमेंट दे । अगर यह योजना पूरी हो जायेगी तो यह जिला अन्न के मामले मे निश्चित रूप से दूसरे जिलों का मोहताज नही रहेगा ।

पलामू जिला बिहार का सब से पिछडा हुआ इलाका है । वह छोटा नागपुर के पठारी इलाके मे पडता है, जिस में काफ़ी अधिक संख्या मे हरिजन और आदिवासी रहते है । मै अनुरोध करता हूं कि इस स्कीम को जल्दी से जल्दी पूरा कर दिया जाये ।

यह बजट 15,000 करोड रुपये का है, लेकिन इस मे वैलफेयर के लिए केवल 125 करोड रुपया रखा गया है, जो पूरे बजट के 1 परसेंट से भी कम है । यह क्या साबित करता है ? आखिर यह सरकार हिन्दुस्तान के सर्वहारा हरिजनो और आदिवासियो के साथ क्या व्यवहार करना चाहती है ? यह तो भिक्षा के बराबर है ।

उपाध्यक्ष जी, डा० अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की जब माग की थी, तो गांधी जी के जीवन की रक्षा के लिए उसे उन्होंने

[श्री राम देनी राम]

वापस लिया था। उस वक्त गाधी जी ने क्या कहा था, वह मैं आप को पढ कर सुनाता हू

"I will get Swaraj and your right will be writt n in golden letters in the Constitution that we are going to frame for this country"

और उस का परिणाम आजादी मिलने के बाद हमे यह मिला है। यह प्रेजेन्ट सरकार का कारनामा नही है। मैं थोडा सा पीछे की ओर ले जाना चाहता हू ताकि उस से आप सबक ले। 30 वर्षों की आजादी के बाद आप जानते हैं कि हरिजनो के क्लास 1 पोस्टो मे सिर्फ डेढ़ प्रतिशत लोग है और दूसरो मे 4 5 प्रतिशत और एग्रीकल्चर लेबर मे 1951 मे जब कि 27 5 मिलियन लोग थे 1961 मे 33 5 मिलियन और 1971 मे 47 5 मिलियन थे इस तरह से यह सख्या बढो है और मै चाहता हू कि इस से अब आगे नही बढना चाहिए। इस से कम होनी चाहिए। यही मेरा आप से अनुरोध है।

जहा तक एट्रासिटीज का मामला है, इस मे शक नही है कि अगर इस चीज को माइनस कर दिया जाए, हरिजन एट्रोसिटीज और लोगो पर जो अत्याचार होते है, उन को माइनस कर दिया जाए तो इस प्रजेन्ट गवनमेट ने पिछली गवनमेट के मुकाबले मे डेफिनीटली बहुत अच्छा काम किया है और यह बहुत अच्छी गवर्नमेंट है लेकिन यह एक ऐसी चीज हैं जैसे कि पूरा भोजन बना कर रखे और उस मे एक मक्खी पड जाए, तो उस भोजन को खा नही सकते। इसलिए इस से आप को सबक लेना चाहिए। मार्च, 1977 से नवम्बर, 1977 तक 215 मर्डर हुए, यह गवनमेट की रिपोट है और एक क्वश्चयन के माध्यम से मै फीगर्स दिये गये हैं। रेप्स के 166 केसेज हैं। इतना ही नही हम बिहार की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जूडिशियल मजिस्ट्रेट शेड्यल्ड कास्ट के लिए 96 रिजर्व किये गये थे लेकिन 69 ही हैं। शेड्यल्ड कास्ट के लिए 50 थे लेकिन केवल 27 बहाल हुए। यह हमारी पिछली सरकार की प्रोग्रेस है। इतना ही नही वैलफेयर के माध्यम से पर कैपिटा शेड्यल्ड कास्ट पर 69 पैसे खर्च हुए है पर इधर और शेड्यल्ड ट्राइब्स पर 2 19 रुपये खर्च हुए है। ये सारी चीजे क्या बताती हैं और इसी तरह से शिक्षा और बेराजगारी की हालत है, बधुआ मजदूर और लैंडलेस लेबर की हालत है।

15.38 hrs.

[SHRI M. SATYANARAYAN RAO *in the chair*]

तिलक जी ने कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह उन्होने नारा दिया था और आज यह स्वराज्य सचमुच मे किसको मिला है। जो सर्वहारा वर्ग है, उस का इस तरह की आजादी मिली है कि जिस के तहत वह पहले गुलाम था, आज भी उसी के तहत है। इसलिये मैं आप के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हू कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, उन को आप मुक्ति दिलाये। यह ऐसी आग है जिस आग की लपेट मे सारा देश जा सकता है और उस आग को बुझाना मुश्किल होगा। अगर किसी घर मे आग लग जाए, और आप यह कहे कि थोडा थोडा पानी लाओ, तो उस से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए मेरा आप से अनुरोध है कि आप इन सारी बातो को ध्यान मे रखे।

एक चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हरिजनो की लिस्ट है, शेड्यल्ड कास्ट्स के लोगो की लिस्ट है, उस के सम्बन्ध मे मैं विशेष तौर पर आप का ध्यान बिहार मे हजारी बाग जिले की ओर दिलाना चाहता हू। वहां भुइयां जाति के लोगो को अनसूचित जाति की लिस्ट मे नही दिखाया गया है जबकि उस की बगल से पलामू जिले मे उस को अनुसूचित जाति की लिस्ट में दिखाया गया है। हजारी बाग मे उस को बेकवर्ड क्लासेज के

दिखाया गया है । अगर हजारी बाग की भुइयां जाति की लड़की की शादी पलामू में होती है, तो वह वहां जा कर हरिजन हो जाती है और पलामू की लड़की की शादी हो कर हजारी बाग में आती है, तो बैकवर्ड बन जाती है यह कहां का न्याय है । मैं आप से अनुरोध करूंगा कि इस विसंगति को दूर किया जाए ।

काका कालेलकर कमीशन ने, मुंगेरीलाल कमीशन ने ये सारी बातें बतायी हैं । लेकिन पता नही अभी तक सरकार क्यों ध्यान नही दे रही है ? सरकार का ध्यान मैं एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं । गुरु नानक जयन्ती, महावीर जयन्ती, गांधी जयन्ती के अवसर पर जेल के कैदियों को जेल से रिहा किया जाता है । मै सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह आदिवासी और हरिजन कैदियों को इस अवसर पर जेल से क्यों नही रिलीज करती है ? अगर उन को छोड़ा जायेगा तो उन का भी सुधार होगा बहुत सारे लोग तो जुर्मों में गलत तरीके से फंसाये जाते है। मिसाल के तौर पर, सभापति महोदय मैं एक केस बताना चाहता हूं। 22 वर्ष का एक नौजवान जब कालेज से घर आया और आकर अपने घर पर देखा कि लोग उसकी बहिन की बेइज्जती करने पर उतारू है तो लड़के से बर्दाश्त नही हुआ और वह लड़का आपे से बाहर हो गया । उसमें उससे हत्या हो गयी । वह जेलों में सड़ता रहा, कोई उस की जमानत देने वाला नहीं मिला । जब मुंगेरीलाल कमीशन वहां गया तो उसने वैरीफाई कर के गवर्नमेंट को सब बात की जानकारी दी । उसके बाद ही वह छूट सका । इस तरह की एक नहीं अनेकों घटनायें हैं जिसमें नाजायज तरीके से हरिजन और आदिवासी लोग फंस जाते हैं । मेरे जिले पलामू के थाना पाटन, गांव सगुणा का एक रामलखन पासवान टीचर का काम करता था । वहां मर्डर हुआ और उस को बीस वर्ष की सजा हो गयी । उसका कोई मां-बाप या अन्य पैरवी करने वाला नहीं था । वह भी जेलों में सड़ रहा है । इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि रेमीशन वाले कैदियों में हरिजन और आदिवासी लोगों को भी रिलीज किया जाए ।

सभापति महोदय, मैं सरकार से कहता हूं कि सचमुच में बिहार आप का है, बिहार की तरफ से आप उदास न हों । पिछली सरकार ने बिहार को जो दिया, उसको सारा बिहार जानता है । यह भी बिहार जानता है कि पिछली सरकार के शासन में बिहार मे कितने जुर्म हुए और कितने लोगों को गोलियों से मारा गया । बिहार के गांव-गाव मैं जा कर देखा जा सकता है कि किस कदर लोगों का केवल मजदूरी के लिए कत्ल किया गया । ऐसी स्थिति मे बिहार आज आप पर आशा लगाये हुए बैठा है । सारे बिहार की आशा आप की तरफ लगी हुई है । मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि बिहार की स्थिति अच्छी नही है । आप बिहार की तरफ देखें और बिहार की उन्नति करें । बिहार आप का है । इन शब्दो के साथ मै अपना कथन समाप्त करता हूं ।

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani) : Mr. Chairman, Sir, a close scrutiny of the fiscal policy, as it emerges from the Finance Bill, as also the past achievement, reveals a very painful fact, namely, that the social goals and objectives have been neglected. When the Finance Minister made his proposals with respect to direct taxes last year, he took the credit for emphasising that his proposals were for the purpose of strengthening the redistributive role that direct taxes must be made to play. Then he claimed that he had tried to raise Rs. 92 crores through direct taxes. It is one thing to make a claim and another to show a performance with respect thereto. There is an unfortunate gap between the proposals and the performance which shows how the redistributive role of taxes has been ignored.

According to the data given to us in the Explanatory Memorandum of the Budget for 1978-79, the total of the revised estimates of collections from corporation tax, income-tax and wealth tax amounts to Rs. 3,250 crores. This is as much as Rs. 41.32 crores lower than the targets. So, with respect to the claim made last year, we find that the performance did

[Shri G.M. Banatwalla]

not come up to the target. It was merely a tall claim about the red is tributive role of taxation policy.

This compares very unfavourably with the past record. During 1976-77, the actual collection was higher by as much as Rs. 205·09 crores than the Budget estimates. So, during the last year as compared to the years previous to that, the performance with respect to the redistributive role of taxation policy has been not satisfactory and up to the target.

Take the measures for promoting investment. Nobody would quarrel with the need for increasing investment, but my specific charge is that the socio-economic goals of investment have been neglected. The Janata Party's Economic Policy Resolution issued in 1977 had said :

> "Fiscal concessions such as development rebates and investment allowances which are in operation today must be reviewed by the Government with a view to promoting labour-intensive industries and discourage wasteful use of capital."

Here we have the investment policy with a view to stimulate investment in equity shares of new industrial companies. The Bill has provided for the grant of tax concessions for that purpose. Unfortunately, however, no distinction has been made between high priority and low priority goods. There ought to have been a distinction between investment in the production of high priority goods as compared with investment in the production of low priority goods, but this socio-economic goal in giving investment allowances has been neglected by the Government. If past experience is any guide, it is the companies engaged in the production of non-essential or low priority goods which will benefit by these proposed tax incentives for investment. I must, therefore, draw the attention of the Government to the need for having a socio-economic goal in matters of policy for stimulating investment. There must be a distinction between high priority and low priority goods, and our investment policy should be such as to stimulate investment in the producion of high priority goods as compared with the production of low priority goods.

Further, Sir, we find another interesting feature as far as the other items are concerned. It must be recognised that Indian industries are faced with the twin problems of wasteful use of capital (which I have already pointed out) and declining labour intensity. In an economy where there is abundance of labour, even skilled labour, the fiscal policy should be such as to promote more employment of labour and discourage more employment of capital. In other words, the fiscal policy should be oriented towards securing labour intensity in our industry. Unfortunately, however, the withdrawal of tax on interest income of banks and lowering of interest rates are capital intensive in nature rather than labour intensive. When these interest rates are lowered, when the tax on the interest income of banks is withdrawn, what is the economic significance of the same ? We find that the cost of capital is reduced and when the cost of capital is reduced, we have a picture of industry where capital intensity is promoted. A claim, I understand, is being made that this withdrawal of tax on the interest income of banks will secure a reduction in prices. But it is quite well known that interest is too insignificant a factor in the prices. It is really not the prices which are sought to be reduced by this Government but it is the cost of capital that is sought to be reduced for the benefit of the large investors and the capitalists by this Government. I, therefore, say that this policy of the Government which reflects capital intensity as compared to labour intensity, is anti-labour in character.

Sir, not only is the fixed policy anti-labour in character but we find the commonman is very badly hit. This is quite obvious from the cruel increase in the excise duty. It is a well known fact that it is the indirect taxes which are inflationary in character. The increase in excise duty is bound to create inflationary conditions and will serve as cost increasing. This increase in excise duty must be reviewed in its proper perspective. What is the present stark reality with respect to the economic situation in India ? The point is that even at present 60 per cent of the central revenue from indirect taxes comes from those whose monthly expenditure is less than Rs. 100/-. When it is so, when such is the stark reality of the economic situation that we have, it is condemnable that the Government comes foward with such a cruel increase in the excise duties. This is especially so with respect to the increase in the excise duties on electricity and coal. Other speakers have already referred to it. I would, therefore, not repeat. I would only say that we are totally opposed to this excise duty on electricity and also on coal which is all inflationary in character and anti-*Janata*. It is unfortunate that the policy of the Janata Government is both anti-labour and also anti *Janata*, as I have been trying to place before the House.

The hike in excise duty is very shocking. At present, we have recession. In the face of recession, an increase in excise duty is nothing but a distortion, a serious contradiction, in the economic situation and the economic policy.

A provision has been made for disallowance of a part of the expenditure on advertisement, publicity and sales promotion. The hon Finance Minister has been kind enough to declare certain relief in this matter. I am, however, totally opposed to the entire proposal that has been made. It will hit hard an important sector of our economy, namely, publicity which is an essential ingredient in the Indian economy. However, I reserve my comments on this particular aspect of the whole matter because I have also an amendment to move and I will take it up at that stage.

When we consider all these aspects we are rather pained at the entire fiscal policy that emerges out of the Finance Bill. I have also to draw the attention of the hon. Finance Minister to an important sector of our economy which is rather neglected and feels the pinch of the present economic position, that is, an increase in the yarn prices which has hit hard and brought about a crisis both in the handloom and the powerloom industry. Their case needs to be considered sympathetically and, I hope, the Government will consider the miserable plight and the crisis faced by both the handloom and the powerloom Industry.

With these words, I conclude.

श्री चन्द्रपाल सिंह (अमरोहा) : अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। जो माननीय मंत्री जी ने फाइनेन्स बिल प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करने के लिए मैं बोलने खड़ा हुआ हूं।

थोड़ा-सा हम पहले की तरफ विचार कर लें। आज हमारी सरकार नेकनीयती से सारे देश की आर्थिक समस्याओं को हल करना चाहती है और देश की तरक्की करना चाहती है। सबसे बड़ी बात देखने की यह है कि जितना पैसा जहां लगने की बात है, वह सही रूप में लगे, उसके लिए सरकार का सुदृढ़ और सक्षम होना बहुत आवश्यक है, उसमें एकरूपता होनी बहुत आवश्यक है। इसकी हमें आज कमी महसूस हो रही है। उसके लिए दिन-रात पार्लियामेंट में भी और बाहर भी चर्चा रहती है। विरोधी दल के

लोग करें तो करें, लेकिन विशेष रूप से सरकारी पक्ष के लोग, जो अपने सदस्य हैं वह भी यही चर्चा करते हैं कि सरकार की यह कमी है। हरिजन समस्या बड़े जोर से उठाई हुई है।

अगर हम गहराई मे आयेंगे, तो हम देखेंगे कि यह कोई नई समस्या नहीं है। यह कई सौ बरस पुरानी समस्या है, जो एक साल मे हल नहीं हो सकती है। इस समस्या को समाचारपत्रों और माननीय सदस्यों ने जिस रूप मे प्रस्तुत किया है, वह बहुत अतिरंजित है। जिस तरह की समस्या को लोग प्रदर्शित कर रहे है, वह कही नहीं है। मैं समझता हूं कि जिस ढंग से इस समस्या का प्रदर्शन किया जा रहा है, वह एन्टी-नेशनल, राष्ट्र-विरोधी, है, और देश के लिये बहुत घातक है। इस का प्रभाव सरकार पर पडता है। आज सरकार, अधिकारियों और जनता मे जो उदासीनता है उस का सब से बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में इस तरह का प्रचार चल रहा है। सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे और जो तत्व इस मे लगे हुए है, वह उन के बारे मे सजग हो।

जनता पार्टी ने अपने इलैक्शन मैनिफेस्टो मे यह घोषणा की थी कि बजट का 40 फीसदी भाग ग्रामों के विकास के लिये रखा जायेगा। सरकार ने इस के लिये प्रयास किया है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि यह धनराशि ग्राम विकास योजनाओं के लिए सही ढंग से खर्च की जानी चाहिए। आज सब से जरूरी काम ग्राम विकास है। अगर हम ग्राम विकास करेंगे, तो देश आगे बढ़ेगा। ग्राम विकास मे सब से बड़ी आवश्यकता यातायात की है। इन्दिरा सरकार ने क्रैश प्रोग्राम के नाम पर हर एक पार्लियामेंट के मेम्बर के लिए, उसके पार्लियामेंट्री हल्के मे सड़क बनाने के लिये

[श्री चन्द्रपाल सिंह]

कोटा निर्धारित कर दिया था। उसी प्रकार सरकार को हर एक पार्लियामेंट के सदस्य के लिए यह निश्चित कर देना चाहिए कि अपने क्षेत्र से वह आठ या दस किलोमीटर सड़क बनवाये। इस से देश का उद्धार और प्रगति हो सकती है। यातायात के मामले में सारा देश पिछड़ा हुआ है। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते हैं, दवाई की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, अपनी खेती की सही पैदावार नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि दुनिया बहुत छोटी हो गई है। इसलिए सड़कों के निर्माण की तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

किसानों को उन की पैदावार की सही कीमत दिलाना बहुत आवश्यक है। अभी तक उस की बहुत उपेक्षा होती रही है। उस की ओर सरकार का ध्यान बहुत ईमानदारी के साथ जाना चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि क्या सरकार द्वारा घोषित नीतियों का कार्यान्वयन ठीक ढंग से हो रहा है। सरकार जो कुछ कहती है, उस पर अमल बहुत देर से होता है। जैसे, सरकार ने गुड़ के एक्सपोर्ट का ऐलान कर दिया लेकिन जिस समय यह काम होना चाहिए था वह उस समय नहीं हुआ, उसके बहुत बाद में हुआ। इस ढील का जनता पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए सरकार द्वारा अपनी नीतियों का सुदृढ़ कार्यान्वयन जरूरी है। इस बजट का पैसा जहां लगाना चाहिए, अगर हम उसको वहां सुदृढ़ता, ईमानदारी और सख्ती से लगायेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा।

आज हमारी शिक्षा में बड़ी असमानता है। बड़े बड़े लोगों के बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं और जिन स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, वहां बैठने के लिये टाट भी नहीं है। आज देश में जो खराब वातावरण बना हुआ है, उस में शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका है। आज हमारे समाज में जो भेदभाव बना हुआ है, उस को तोड़ने के लिये शिक्षा के अन्तर को समाप्त करना होगा। पैसे वाले बड़े लोगों के स्कूलों और बहुत गरीब लोगों के स्कूलों में, हमारी शिक्षा में, जो अन्तर हो गया है, सरकार को उसे दूर करने का प्रयास करना होगा।

जहां तक अफसर शाही का सम्बन्ध है, आज हमारे अफसरों में उदासीनता फैली हुई है। हमें उन का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। इमर्जेन्सी के बाद जब हम लोग जीत कर आये, तो हमें अफसरों पर जिस तरह सख्ती करनी चाहिए थी, वह हम नहीं कर पाये। लेकिन आज हमें यह समझना चाहिए कि सरकार की गतिविधियां और योजनाएं अफसरों का विश्वास किये बिना नहीं बढ़ सकती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम उन का विश्वास प्राप्त करें।

16.00 hrs.

दूसरी एक और बात जो मैं कहना चाहूंगा वह सीमाबन्दी की बात है। एक बड़ी बात यह होती रहती है कि "सीमाबन्दी, सीमाबन्दी" इस से जमीन पर जो काम करने वाले हैं, उन के मन में दिन रात यही शंका रहती है, कि जमीन जायगी या रहेगी। मेरा कहना यह है कि सरकार इस को अन्तिम रूप दे और पांच, सात साल के लिये ऐलान कर दे कि अब सीमाबन्दी नहीं होगी, तो उस बात का कुछ असर होगा, कुछ प्रभाव होगा। हम इस बात का स्वागत करते हैं, कि जिन के पास ज्यादा जमीन है, उस का सरकार ले ले। सरकार को इस का पता है और सरकार का उसे ले कर जो भी भूमिहीन हो, उन को दे दे या जिन का वह देना चाहती है, उन को दे दे।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि लोगों के दिमाग में यह बात है कि शहर

की तरफ भी सरकार देखे । शहरो में जिन के पास ज्यादा जायदाद है, ज्यादा जमीन है, जिन के पास बडे बडे मकान हैं, जिन के पास बडे बडे व्यवसाय हैं उन की सीमाबन्दी की तरफ भी आप का ध्यान जाना चाहिए । आप छोटी जमीन की बात करते है लेकिन जिन के पास बडी बडी जायदादें है, जहा से आप को यह मिल सकती है, उन की तरफ भी आप देखें । किसान तो दिन रात मेहनत करता है मेहनत का काम करता है और अपने हाथ से काम करता है, तब जा कर वह कमाई करता है और चाहता है कि उसे पैसा मिले उस की ज्यादा तरक्की हो । सभी चाहते है कि उन को ज्यादा पैसा मिले और उन की तरक्की हो । तो वह भी क्यो नही चाहेगा । इन सब बातो को देखते हुए आप को जमीन की सीमाबन्दी के बारे मे सोचना चाहिए ।

अगली बात मै यह कहना चाहूगा कि इमर्जेन्सी के बाद भी बहुत से ऐसे लोग पडे हुए है, जो कि पुलिस विभाग मे और दूसरे विभागो में भी है, जिन के ऊपर अत्याचार हुए है । उन को बहुत से दूसरे विभागो मे फेंक दिया गया है सी० आई० डी०, सी० बी० आई० और इस तरह के और विभाग हैं, जिन मे वे अच्छा काम कर सकते हैं । उनको वापस लेना चाहिये ताकि उन के साथ न्याय हो । जो अच्छे दिमाग के लाग है, उन को हमे मौका देना चाहिए जिस से सरकार अच्छा काम कर सके । लघु उद्योगो की जा बात सरकार ने कही है, उस के लिए भी सरकार को पूरे दिमाग से काम करना चाहिए । सरकार ने जो नेकनीयती मे काम करने की बात कही है, उस पर वह चलेगी तो देश आगे बढ़ेगा और मे आशा करता हू कि सरकार अपने इस इरादे मे सफल होगी क्योकि अगर जनता सरकार चली जाती है तो देश में अशान्ति की बात होगी और प्रजातन्त्र अधकार मे होगा । मैं इस विश्वास का ले कर चलता हू कि सरकार ठीक काम करेगी ।

इन शब्दो के साथ मैं समाप्त करता हू ।

श्री कुंवर महमूद अली खां : (हापुड) : सभापति महोदय, मैं आप का आभारी हू कि आप ने मुझे इस समय बोलने का मौका दिया । मै फाइनेन्स मिनिस्टर साहब के बिल का समर्थन करने के लिए खडा हुआ हू ।

मै ने बहुत सी तकरीरे सुनी यहा पर और मैं इस नतीजे पर पहुचा हू कि बीमारी कुछ है और उस की दवा कुछ और है । इस के लिए हमे थोडा भारतवर्ष की हिस्ट्री का देखना हैं । मुगल यहा पर आये, उस के बाद अंग्रेज आये, फिर उस के बाद कांग्रेस आई और अब कांग्रेस के बाद जनता पार्टी आई है । मुगलो के जमाने मे जो सिस्टम था, वह जागीरदारी का सिस्टम था जिस म देहातो को बिल्कुल निगलेक्ट किया गया था । तीस-हजारी, दस हजारी और हफ्त-हजारी, ऐसी जागीरदारिया थी और बाकी रियाया कहलाती थी, उस के साथ जानवरो जैसा बर्ताव किया जाता था । उस के बाद अंग्रेज आए और अंग्रेजो का भी करीब करीब वही निजाम था । उन का निजाम इम्पीरियेलिज्म था और एक पुलिस स्टेट थी । जिस तरह मे पुलिस स्टेट चलती है उसी तरह मे उन्होने चलाया और उस मे भी खास खास लोगो को राय बहादुर, खान बहादुर बनाया क्योंकि उस जमाने मे सनअतकारी नही थी । वह जागीरदारी सिस्टम का निजाम रहा है । उसके बाद तीस साल तक कांग्रेस का निजाम नाफिज रहा । अंग्रेज चले गये लेकिन उनका बनाया हुआ इन्तजामी ढाचा, मशीनरी, ब्योरोक्रेसी वही रही । यही नही, जो कानून सूबो मे बने थे, सेन्टर में बने थे, उन सब को भी ज्यो का त्यो अडाप्ट कर लिया गया । इस तरह से वही मशीनरी और अफसरशाही, वही खयालात चलते चले आ रहे है ।

जवाहरलाल जी ने समाजवाद का नारा लगाया, वेल्फेअर स्टेट का नारा लगाया कि समाजवाद हिन्दुस्तान मे होगा और हिन्दुस्तान एक वेल्फेअर स्टेट होगा । क्या

[श्री कुंवर महमूद अली खां]

यह वेलफेयर स्टेट है ? क्या यह समाजवाद है ? बिल्कुल नही है। क्योंकि एक आदमी जमीन पर सोता है और एक आदमी को नींद लाने के लिए इजेक्शन दिया जाता है तब जाकर वह महलो मे सो पाता है। इतना बडा फर्क है। क्या इसे वेल्फेयर स्टेट कहा जा सकता है ? नही। यह एक धोखा है। इस बारे में मुझे एक शेर याद आ गया--

आ बताऊ तुझको रमजे आये इनल मलूक
सल्तनत अवा मे गालिब की है एक जादूगरी।
देवे इस्तबदाद जम्हूरी कबा मे पाए काब
और तू समझा है आजादी की यह नीलम परी।
नस्ले कौमियत कलीखा सल्तनत तहजीबो रंग
खाजगी न खूब चुनचुन कर बनाये मुस्करान।
कटभरा नादा ख्याली देवताओ के लिए
मुक्र की लज्जत में तू लुटवा गया नक्दे हयात।

अग्रेज ने हिन्दू और मुसलमानो के नाम पर यहा पर लडाया, उसके बाद काग्रेस आयी। उसने दो टुकडे ही नही किये बल्कि और भी बुरी तरह से भारतवर्ष के निवासियो को लडाया, तकसीम किया। इससे हैरत होती है, ताज्जब होता है। तू शहर का आदमी है, तू देहात का आदमी है, तू छोटा किसान है, यह बडा किसान है, तू मारजिनल फार्मर है, यह लेण्डलेस लेबरर है, तू हरिजन है, यह मुसलमान है तू बेकवर्ड क्लास का है, यह यह है, वह वह है। भारतवर्ष के इसानों को कितने कावेखानो में बाट रखा है। सभापति महोदय, आज मैं इस सदन मे एलान करता हू कि भारतवर्ष मे सिर्फ दो कौम रहती हैं--अमीर और गरीब। इसके अलावा कोई कौम नही है। यह जो जात-पात का मामला है, यह शादी-ब्याह के लिए हो सकता है, नमाज पढनी हो या मदिर जाना हो तो हो सकता है, गिर्जे मे जाने के लिए हो सकता है लेकिन वैसे हम भारतवासी सब एक है और एक रहेंगे। हम भूखे रहेंगे तो सब भूखे रहेंगे, हम पेट भरेंगे तो सब पेट भरेंगे। हमें बराबर बहकाया जाता रहा है। यह देश मे समाजवाद है, यह हमारी वेल्फेयर स्टेट है। हमें उसी तरह से लडाया जाता रहा है जिस तरह से अग्रेज हमे लडाता था। काग्रेस ने भी हमे चन्द वोट हासिल करने के लिए, शासन करने के लिए, लीडरी हासिल करने के लिए हमे लडाया है और बेगुनाह इसानो का खून बहाया है। यह अच्छी बात नही है।

तमीजे बन्दो आका फमादे आदमियत है
हजर ए चीरा दस्ता सख्त है फितरत की
ताजीरे है।

अगर इसी तरह से लडाया जाएगा, कुछ लोगो का गुलाम बनाया जाएगा और दूसरो को बादशाह बनाया जाएगा तो काम चलने वाला नही है। हमे यह देखना होगा कि किस तरह से समाजवाद आ सकता है, किस तरह से वेल्फेयर स्टेट हमारा मुल्क बन सका है। हमे इस मामले से सख्ती से कदम उठाने होंगे। हमे भारतवर्ष के तमाम इसानों को एक फेमिली की तरह से ट्रीट करना होगा, एक खानदान के आदमी की तरह से उन्हें मानना होगा। चाहे वह शहर का आदमी है, देहात का है, चाहे हिन्दू है, मुसलमान है, किसी जाति या धर्म का हो, इसको हमे एक मानना होगा। समाजवाद लाने के लिए हमे इनकम पर, एक्सपेंडीचर पर सीलिंग लगानी होगी। हमे अरबन सीलिंग करनी होगी, गावो की जमीन का हिसाब लगा कर सीलिंग करनी होगी शहरो मे जमीन की सीलिंग और इनकम की सीलिंग करनी होगी। अजीब तमाशा है कि 80 फीसदी आदमियो को जो गावो मे रहते हैं उन्हें गरीब ही रखा जाए और शहरो मे जो थोडे से लोग रहते हैं उनकी आसाइस के लिए हम सारी चीजें करें। कितने अफसोस और शर्म की बात है, इस तरह से यह हिन्दुस्तान चलने वाला नही है। जो राज है वह आउट हो चुका है, चीजें सामने आ चुकी हैं। हरिजनो को लडाया जाता है

किसानों से । हम कहते हैं कि सब चीज बांट दो, जमीन भी बांट दो, दौलत भी बाट दो । लाइसैंस और परमिट भी बाट दो, प्रापर्टी और दौलत भी बाट दो । जो दौलत दिखाई नही देती है वह भी बाट दो । इसमे क्या दिक्कत है ? आज तो सारा जोर सीधे सादे तौर पर लैंड सीलिंग पर ही दिया जाता है । यह कहा जाता है कि गावो मे ब्लैक मनी है । वहा दौलत बहुत ज्यादा हो गई है । लेकिन मैं पूछना चाहता हू कि किसान को अगर कुछ ज्यादा पैसा मिल जाता है तो जो आप कहते है कि इससे इनफ्लेशन हो जाएगा, क्या वाकई मे ऐसा होगा ? यह जो दलील दी जाती है इसको तो मै कहूगा कि वाह क्या कहने ? किसान के पास पैसा आता है तो वह उसको शहर मे लाता है, उससे मशीन खरीदता है, ईंट सीमेंट खरीदता है । खेतो की पैदावार बढाने मे वह इसका इस्तेमाल करेगा । कहा यह पैसे को ले जाएगा । ब्लैक मनी उसके पास नही है । यह जो पैरेलल इकोनोमी की बात की जाती है, ब्लैक मनी की, यह सब पूजीपति लोगो के पास है, इडस्ट्री मे बिजनैस मे है । माल कही और है और लडाई किस बात पर हो रही है । यह तो वैसी ही बात है जैसे कुत्ता किसी हड्डी को चिचोडता है और उसके मुह मे से खून निकलता है और वह समझ बैठता है कि मजा आ रहा है । माल कही और है लेकिन कहा जाता है कि दौलत देहात मे है । देहात मे किसान भूखा मर रहा है । हर किसान कोआप्रेटिव सोसाइटी का या बैंक का कर्जदार है । देहातो मे आपने क्या सहूलियत दी है ? वहा सडकें नही है पीने का पानी नही है, बीमार पड जाए तो दवा का इन्तजाम नही है, अस्पताल नही है, कुछ भी नहीं है । मच्छर वहां बेहिसाब हैं । गावो में आराम से सोया तक नही जा सकता है वहां बिजली नही, अधेरा है । दिल्ली में कैसा मजा आता है यह रात को हम देखते हैं । खूब मजा आता है । असल मे धोखेबाजी में हमें नहीं रहना चाहिये बल्कि साफ-साफ बात होनी चाहिये, मिसलीडिंग बात नही होनी चाहिये । गरीब इसानो को आपस मे लडाना नही चाहिये ।

आजकल रिजर्वेशन का सवाल चल रहा है देश मे । हवा इसको ले कर बहुत गर्म है । अगर तमाम दौलत बट जाए तो मैं समझता हू कि रिजर्वेशन की जरूरत ही नही रह जाएगी । दौलत बट जाए सब को मिल जाए तो कोई शोर नही मचाएगा । सारा शोर इसलिए है कि कुछ आदमियों के पास माल है और कुछ के पास नही है । समाजवाद आप ले आए, वेलफेयर स्टेट बना दें कोई झगडा नही रह जाएगा ।

आज अस्सी परसेंट आबादी देहातों मे रहती है । मेरा सुझाव है कि अस्सी परसेंट बजट देहातो पर खर्च होना चाहिये । इसानो के लिए स्टेट है । जब अस्सी परसेंट इसान देहातो मे रहते हैं तो क्यो नही अस्सी परसेंट बजट उन पर खर्च होता है बजाय चालीस परसेंट के जो आप इस साल खर्च करने जा रहे है । मैं आपको इसके लिए धन्यवाद दिए बगैर नही रह सकता हू कि हिन्दुस्तान का यह पहला बजट है जिसमे चालीस परसेंट बजट जनता पार्टी देहातों पर खर्च करने जा रही है । यह एक हिस्ट्री है । इसके लिए मै आपका आभारी हू ।

आप किसानो को कहते है कि वे पैदावार बढाए । किसानो ने गन्ने की पैदावार बढाई । उसकी क्या हालत हुई ? वह गन्ना फूक रहा है । इसका आपको पहले से कोई इतजाम करना चाहिये था ताकि गन्ने उसको फूकना न पडता । 1932 मे उत्तर प्रदेश मे चीनी मिल बनी । 33 परसेंट गन्ना मिलो मे पिरता है, बाकी खडसारी या कोल्हू मे जाता है । मैं सजैशन दूगा कि खास तौर पर उत्तर प्रदेश मे और चीनी की मिलें होनी चाहिये ताकि ओवर प्रोडक्शन अगर हो भी जाए तो उसको कट्रोल किया जा सके । अगर आपके पास सरप्लस चीनी है और गन्ने को आपको

[श्री कुंवर महमूद अली खां]

खपाना है तो मै कहूगा कि इसका बिल्कुल आप डी कंट्रोल कर दें । कंट्रोल की कोई जरूरत नही है । मे किसान हू, देहात का रहने वाला हू । मैं जानता हू इसको । साल भर अगर तीन रुपये क्विटल कम दाम भी किसान को मिला तो उससे कज्यूमर का फायदा होगा । इसमे किसान का नुकसान है । बीच का जो आदमी है वह बिला वजह खा रहा है । यह खत्म होना चाहिय । कज्यूमर या प्राड्यूसर को फायदा हो । लेकिन आज हिन्दुस्तान की मुसीबत यह है कि सारा सिस्टम मिडलमैन पर आश्रित है । अगर मिडलमैन खत्म हा जाए बिचौलिया खत्म हो जाए ता कज्यूमर भी ठीक रहेगा और प्रोड्यूमर भी ठीक रहेगा ।

उस सिलसिले मे एक बात और अर्ज करनी है कि प्राडक्शन के लिये फर्टिलाइजर और ट्रैक्टर की जरूरत पडती है । 12 हौर्स पावर तक ऐक्साइज ड्यूटी नही है । लेकिन क्या इतनी कम हौर्स पावर के ट्रैक्टर से जुताई हो सकती है ? नही। तो मै इस दवा करूगा वित्त मत्री जी से कि ऐसा ट्रैक्टर जैसा एशिया की तरफ से आया था डी० टी० 14 जो किसानो ने बहुत पसन्द किया था उसी ढाचे का ट्रैक्टर यहा पर आप बनाये 14 15 होर्स पावर का जो ट्रैक्टर 10,000 रु० का आता था तो यहा की कडीशन्स के हिसाब से वह ट्रैक्टर डी० टी० 14 बहुत अच्छा है, और इस ट्रैक्टर पर काई ऐक्साइज ड्यूटी नही होनी चाहिये, ऐग्रीकल्चर इमप्लीमेंट्स पर कोई ऐक्साइज ड्यूटी नही होनी चाहिये, फर्टिलाइजर पर ड्यूटी नही होनी चाहिये । सिंचाई के लिये बिजली सस्ती मिले, डीजल भी सस्ता मिलना चाहिये

मैंने दिल्ली मे देखा है कि जो टैक्सी और स्कूटर ड्राइवर्स है पेट्रोल चूकि महगा हो रहा है इसलिये उनको कुछ परेशानी है । तो ऐसे लोगों के लिये, चूकि हमने राजघाट पर कसम खायी थी सोशलिज्म लायेंगे, उसको मद्देनजर रखते हुए टैक्सी और स्कूटर ड्राइवर्स को सब्सिडाइज्ड रेट पर एक मात्रा तक पेट्रोल देना चाहिये जिससे पब्लिक को भी आसानी मिले ।

चूकि फाइनेंस का मामला है काफी रुपया फाइनेंस का खर्च करना पडता है, हमारा उत्तर प्रदेश बहुत बडा है । उसमे जो प्लानिग है या ऐडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखते हुए वहा का मामला बडा होने की वजह से मेरे ख्याल से यह जरूरी है कि यू० पी० के चार हिस्से होने चाहिये और इस पर हमे जार देना चाहिये, क्योंकि बडा प्रदेश होने की वजह से उसकी प्रौबलम्स भी अलग-अलग किस्म की है । एक वैस्टर्न यू० पी०, एक सेन्ट्रल यू० पी० एक ईस्टर्न यू० पी० और चौथा हिस्सा हिल स्टेट का जिसकी प्रौबलम मैदानी इलाके से बिल्कुल अलग है । और दो बाते वहा फोरन कर देनी चाहिये—एक ता मेरठ मे इलाहाबाद हाई कार्ट की बैंच आनी चाहिय, और दूसरे यू० पी के पब्लिक सर्विस कमीशन के चार ऐग्जामिनेशन सेन्टर्स और इटरव्यू सेन्टर्स होने चाहिये । मै 6 साल तक पब्लिक सर्विस कमीशन से रहा हू इसलिये उस तजुर्बे के आधार पर बता रहा हू कि यह बहुत जरूरी है, लडको का बहुत दिक्कत होती है । इसलिये एक बनारस लखनऊ, एक गढवाल मे और एक मेरठ मे सेन्टर होना चाहिये । और यू० पी० का पार्टीशन होना चाहिये चार हिस्सो मे । मेरा तो कहना है कि स्टेट्स रीआर्गेनाइजेशन कमीशन दोबारा बनाया जाए और बडी-बडी स्टेट्स का लिहाज करते हुए फिर से रीआर्गेनाइजेशन होना चाहिये कोई छोटी स्टेट अगर मिलना चाहे बडी मे तो कोई हर्ज नही है । और जो पुरानी कन्जरवेटिव बाते है कि राम लक्ष्मण की जमीन तकसीम नही होनी चाहिये इसमे मै इत्तफाक नही करता । हमारा मुल्क है अपनी आसानी और प्लानिंग के लिये जो भी मुनासिब कदम हो वह हम

उठा सकते हैं। उसका पुनर्गठन कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया।

श्री डी० जी० गवई (बुलडाना) : मान्यवर, आपने मुझे फाइनेंस बिल पर बोलने का जो मौका दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं इस फाइनेंस बिल का समर्थन करते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जनता पार्टी जिस समय सदन में आ कर बैठी और सरकार में आयी उससे पहले हमने कुछ वायदे किये थे कि जनता सरकार न्यायोचित समाज का निर्माण करेगी, ग्रामीण जनता के लिये कुछ अच्छे प्रोग्राम देगी जिससे देहातों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे। ग्रामों में जो हमारे लोग रहते हैं, काश्तकार रहते हैं, जो खेतिहर मजदूर रहते हैं जो रात दिन काम करते हैं, किसान भी अपने खेत की मिट्टी से प्रेम करता है उस पर अपना पसीना बहाता है, उन लोगों के लिये जो देहातों में बसे हुए हैं उनके लिये आपका यह बजट कुछ करने जा रहा था। और फाइनेंस मिनिस्टर ने पहले ही सैशन के टाइम में कुछ ऐसा वक्तव्य दिया था कि हम इस बात की तरफ ध्यान देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जो किसान हमारे गांव में बसे हुए हैं, जो रात-दिन मेहनत करते हैं, जिनको श्रमशूर इन्सान बोलते हैं, उनके लिये कोई आकर्षण नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है।

आप बोलते हैं कि 40 परसेंट हमने ग्रामों के लिये रखा है, लेकिन उसका क्या उपयोग हो रहा है इस एक साल में, यह हम देख रहे हैं। बहुत से सदस्यों ने कहा है कि बहुत महंगाई हो गई है, लेकिन किस बात की महंगाई हो गई है? क्या किसान का अनाज महंगा बिक रहा है, गेहूं, चावल, ज्वार का भाव बढ़ा है या और भी किसान की जो बहुत-सी चीजें हैं, उनके भाव बढ़े हैं? भाव बढ़े हैं सीमेंट, लोहा, कोयला और कपड़े के, या जो सौन्दर्य प्रसाधन हैं, जैसे पाउडर है जिसको किसान कभी यूज नहीं करता। भाव बढ़े हैं उन चीजों के जिसकी जरूरत किसान को है, जिससे वह घर और कुआं बनाना चाहता है, लोहा खरीदना चाहता है। लेकिन जो किसान अपने खून की एक-एक बूंद जमीन पर न्यौछावर करता है और अपनी मेहनत से इस देश के 60 करोड़ लोगों के मुंह में दाना डालता है, मुंह हिलाता है, कोटि-कोटि चूल्हे जलाता है, उस किसान की हालत इस देश में क्या है? गौर से देखिये, यदि फटे कपड़े पहने दिल्ली में कोई एक आध किसान आये तो आप समझेंगे कि यह पागल है, पागल कुत्ते ने इसको काटा है। उसके कपड़े ऐसे होते हैं। उनके लिये जनता सरकार क्या करना चाहती है, यह महत्व का सवाल है?

बड़े-बड़े शहरों में कारखाने बनते हैं, सीमेंट, लोहे और कोयले की हमें जरूरत है लेकिन उसके साथ साथ खेती का उत्पादन बढ़ाने की भी ज्यादा जरूरत है। किसान खेती पर इन्वैस्टमेंट करता है, खर्चा करता है, आप देखें कि अगर किसान को एक एकड़ में गेहूं बोना है तो उसे तीन चीजें लगानी पड़ती हैं। पहला डोज फार्टिलाइजर, खाद का लगाता है, दूसरे बैग पर यूरिया लगाना पड़ता है। इस पर उसके 300 रुपये खर्च होते हैं। उसके बाद मेहनत होती है, अन्तर्गत मशक्कत होती है। उसके 4, 5 महीने मेहनत में चले जाते हैं लेकिन उसको क्या मिलता है, निसर्ग।

अभी महाराष्ट्र में गेहूं पर पीलिये का रोग लग गया। एक एकड़ में ज्यादा से ज्यादा 3 क्विंटल गेहूं पैदा हुआ है। उसका खर्चा भी पूरा नहीं हुआ।

गन्ने के बारे में कहा गया कि लोग गन्ने को जला रहे हैं, यह सच्ची बात है। शुगर कारखाने किसानों से गन्ना लेते हैं, लेकिन उसे पैसा नहीं देते। कोई फैक्टरी ऐसी है जो 99 परसेंट देती है, लेकिन बहुत सी फैक्टरी किसानों को जल्दी पैसा नहीं देतीं।

[श्री डी० पी० गवई]

मैं यह कहना चाहता हू कि आपका बजट, इस देश का जो फाइनेन्स है, यह रूरल एरिया की तरफ जाना चाहिये और गरीबों मे किसी आकर्षण का निर्माण होना चाहिए । जनता सरकार को एक साल हो गया है, जब हम सारे हिन्दुस्तान मे अपने क्षेत्रो मे जाते है तो लोग पूछते है कि जनता सरकार क्या करती है हमारे गरीब लोगो के लिए ? हम बोलते है कि सदन मे 150, 175 दिन जो काम हुआ है, उसमे मे 100 दिन तो खाली इन्दिरा जी की चर्चा चलती रही कि इन्दिरा गाधी ने यह किया, वह किया । सारा मामला उन पर चला जाता है । देश मे यह प्रतिक्रिया हो रही है कि जनता सरकार अच्छे रास्ते पर नही जा रही है । अगर इन्दिरा जी दोषी है, अपराधी हैं तो उनको सजा क्यो नही देते ? सजय गाधी ने अगर इतने अपराध किये हैं तो उसको सजा क्यो नही देते ? जनता सरकार मे कोई दम नही है । जनता सरकार कुछ नही कर सकती है, लोग ऐसा कहते है । तो हम कहते हैं कि हम इस बात मे नही जाना चाहते है, लेकिन हम आप के प्रश्नो को पार्लियामेंट मे रखते हैं और माग करते है कि गरीबों और किसानो के लिए कुछ काम होना चाहिए ।

मैं फिनास मिनिस्टर साहब से बिनती करूगा—वह बडे तजुर्बेकार और अनुभवी हैं —कि इस देश का नकशा बदलने के लिए सरकार को उन लोगो के लिए कोई प्रोग्राम बनाना चाहिए, जो अपनी मेहनत के बल पर कुछ काम करना चाहते है, जिन्हे प्रोत्साहन की आवश्यकता है । और वह प्रोग्राम केवल कागज पर नही होना चाहिए, ससद् के हाल मे नही होना चाहिए, बल्कि वह किसान के घर और खेती तक पहुचना चाहिए । उदाहरण के लिए किसानो को जो चीजे महगे दामो पर मिलती हैं, उन पर से एक्साइज ड्यूटी हटा देनी चाहिए ।

जनता सरकार और जनता सरकार के फ़िनास मिनिस्टर से मेरी बिनती है कि पिछले एक साल मे इस देश मे लोगों की यह प्रतिक्रिया हुई है कि जनता सरकार कुछ नही कर रही है, जनता सरकार ने कुछ नही किया है, जब कि इन्दिरा गाधी ने हमे झोपड़ी, बकरी और भैस दी । वास्तव मे इन्दिरा गाधी ने यह सब कुछ नही दिया था, लेकिन लोगों मे ऐसी भावना है कि जनता सरकार हमे क्या दे रही है, वह क्या करने जा रही है—कुछ नही । इस लिए आज लोगो को प्रोत्साहित और प्रेरित करने की आवश्यकता है ।

मैं साफ बता देना चाहता हू कि अभी जो इलेक्शन हुआ, उस मे विदर्भ मे एकानोमिकली बैकवर्ड, शिड्यूल्ड कास्ट्स, हरिजन और बुद्धिस्ट लोगों ने इन्दिरा गाधी के कैडीडेट को वोट दिया । विदर्भ से 66 मे मे 56 सदस्य काग्रेस (आई) और श्री घोटे के आ गये । इसका परिणाम हम लोगो का भुगतना पडता है । लोगों को हम कहते हैं कि जनता सरकार का बहुत दूरदर्शी प्रोग्राम है, वह एक बडा प्रोग्राम है, वह कोई डुगडुगी बजाने वाला प्रोग्राम नही है, कोई बच्चो का खेल नही है, थोडा धैर्य रखिए, हमारे लोग अच्छा काम करेगे । लेकिन लोग कहते हैं कि हमारे पेट मे आग लगी है, हम भूखा मर रहे है, फटे कपडे पहनते हैं, कितने साल तक हम ऐसे ही बैठे रहेगे । हम ने जनता को यह आश्वासन दिया था कि हम दस साल मे गरीबी को खत्म कर देंगे । लेकिन क्या दस साल तक हम सरकार मे रहेगे ? कैसे रहेगे ? अगर देश और जनता के लिए हमारा कोई अच्छा प्रोग्राम नही होगा, तो हम कैसे यहा रहेगे ?

अगर हम ने इस देश की ससदीय लोकशाही को, प्रजातत्र को, सुदृढ़ करना है, विकसित करना है, ससदीय लोकशाही के पौधे को बढाना है और उस की जडो को जमीन मे गहरा और मजबूत करना है, तो

हमें इस देश के ग़रीब लोगों के लिए कोई प्रोग्राम बनाना होगा। हम इस देश की पवित्र लोकशाही के लिए मर मिटना चाहते हैं। हर एक आदमी के दिल में यह भावना है कि हम अपने देश पर आंच नहीं आने देंगे ; अगर हम जियेंगे, तो अपने देश के लिए; मरेंगे, तो अपने देश के लिए; हम सर्वस्व समर्पित करेंगे अपने देश के लिए। यह शूरों और वीरों का देश है, यह महान् देश है, बहुत बड़ा देश है। इस लिए इस देश की सरकार का उद्देश्य भी उतना ही बड़ा होना चाहिए कि इस देश के प्रजातंत्र को हमेशा जिन्दा और ताजा रखने के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया जाये कि इस देश में जो निराश जीवन जीने वाले लोग हैं, जिन बेचारों को शाम की रोटी नसीब नहीं होती है, जो भूखे मरते है, उन के जीवन में कुछ सुधार हो सके।

फ़िनान्स बिल पर बोलते हुए बहुत से माननीय सदस्यों ने हरिजनों का मामला भी उठाया। यह मामला कितनी सदियों तक चलता रहेगा ? हम देखते है कि हर डीबेट में, हर विषय पर और हर वक्त हरिजनों का सवाल उठाया जाता है। हमे ये बातें बहुत बुरी लगती हैं, क्योंकि हम उस घर में पैदा हुए है। लेकिन हम भारतीय है, हम अपने को कोई अलग नही मानते है। हमारे बहुत से लोगों ने कहा कि अगर हरिजनों के ऊपर अन्याय और अत्याचार चलते रहेंगे तो हम इस देश के टुकड़े बनायेंगे। मैं इस मत का नही हो सकता हूं क्योंकि इस देश की अखण्डता हमें कायम रखनी है। लेकिन इस देश में जो जातीयता की दरारें पड़ी है उन को मिटाना जरूरी है।

दूसरी बात यह है कि हरिजन के नाम पर बहुत से लोग फैसिलिटीज लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जो भी एकोनामिकली बैकवर्ड लोग हों उन को फैसिलिटीज मिलनी चाहिएं। उस में जाति का कोई सवाल नहीं है। जिन की मासिक आय 5 सौ या 6 सौ रूपये से कम है उन सारे लोगों को शैक्षिक और सर्विस वगैरह की फैसिलिटीज मिलनी चाहिएं जिस से जाति पांति का झगड़ा ही मिट जायेगा।

इस देश के प्रजातंत्र को सुखी, समृद्ध और निरोग रखने के लिए आप को अच्छे से अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे। यह कहने से काम नही चलेगा कि पहली सरकार ने यह नहीं किया यह गलती पहली सरकार की है, यह इंदिरा गांधी की गलती है, यह कहने से आप का काम नही चलेगा। आप को अच्छे काम करने पड़ेंगे। आप ऐसे काम करें जिस में उन को महसूस करना पड़े और उन की गर्दन शर्म से झुक जाए कि उन्होंने कुछ नही किया और जनता सरकार ने इतना काम किया। आप ऐसा कुछ करें। खाली उन को दोष देने से काम नही चलेगा। यह मैंने सदन को बहुत बार बताने का प्रयास किया लेकिन चेयरमैन साहब ने मौका ही नही दिया। यह इंदिरा गांधी का सवाल कितने दिन तक आप चलायेंगे ? आज लोग बोलते है कि जनता पार्टी की सरकार मे कोई दम नही है। वह उन को पकड़ नहीं सकती है। इतने अपराध होते है, क्यों नही पकड़ते ? संजय गांधी पथराव करता है, वह इतना झुंड लाता है, यह करता है, वह करता है, जनता पार्टी सोयी पड़ी है, क्यों नही उन को पकड़ती है? इसमें एक कारण यह भी है कि ये जितने आइ ए एस आफिसर्स है हिन्दुस्तान में वे सारे पुराने ढांचे के हैं जिन्होंने एमर्जेंसी का दुरुपयोग किया है, जिन्होंने अपने साथी अफसरों और नीचे के 'कर्मचारियों' के साथ बुरा बर्ताव किया है, उन का रिवर्शन किया है, उनको डिसमिस किया है और उन को प्रीमैच्योर रिटायर किया है। तो इन लोगों का भी ढांचा बदलना इस सरकार का काम है, इस सरकार का कर्तव्य है। उन का दिमाग भी ठिकाने पर लाना पड़ेगा। जो आफिसर

[श्री डी० जी० गवई]

अभी भी इस देश के प्रजातंत्र को दुखी करने के लिए, यहा अराजकता फैलाने के लिए प्रयास करते है, जनता सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते है उन की तरफ भी जनता सरकार का जरूर ध्यान होना चाहिए आप देखें कि ये आफिसर्स किस तरह बदनाम करते है ? बहुत सी जगह फायरिंग हुई । यह फायरिंग कैसे हुई । कुछ न कुछ तो उस में लोगों का अपराध जरूर होता है क्योंकि माग होती है, जोश आता है, जोश आने के बाद पथराव होता है, पथराव के बाद फायरिंग होती है । लेकिन उस के पीछे कुछ ऐसे आफिसर भी होते है जो उन बातो की तरफ ज्यादा ध्यान नही देते । वह सोचते है होता है तो होने दो बदनाम होगी तो जनता सरकार बदनाम होगी । तो ऐसे आफिसर्स को जल्दी से जल्दी हटा देना चाहिए या उन का तबादला कर देना चाहिए ।

देश के लिए कुछ अच्छे काम यह जनता सरकार करे यह हम आशा करते है और जो हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर है उनके कार्यकाल मे हमारे देश की परिस्थिति कोई एक नया रूप धारण करे जो सारे लोगों मे आकर्षण पैदा कर गरीब लोगों म आकर्षण पैदा कर और जनता सरकार पाच साल मे इस देश का नक्शा बदल दे । खाली दूसरी पार्टी को दोष देने से काम नही चलेगा, इतना मे बोल देता हू । आप को प्रयत्नशील रहना है, और अपने कर्त्तव्य के प्रति सतर्क रहना है । मै आशा करता हू कि हमारे फाइनेंन्स मिनिस्टर हमेशा सतर्क रहेंगे । वैसे उन की उमर तो बहुत ज्यादा है लेकिन ताकत उन मे बहुत है, काम कर सकते है । तो वह सतर्क रहेंगे और इस देश की जो भूमि है उस को सुजलाम सुफलाम् बनायेंगे ।

SHRI DHIRENDRANATH BASU (Katwa) Sir, so far as the Finance Bill is concerned, first of all, I should like to point out that there is one proposed amendment to the Income-tax Act. It is explained in the memorandum several provisions in the Finance Bill, particularly "Deduction in respect of investment in equity shares of new industrial companies" This will help the rich business people, this will help the big business houses and this will not help the common people Although in the Budget about 41 per cent of the amount has been provided for agricultural sector, for the development in rural areas, unfortunately there is no programme for development There is no well thought out plan and programme for development in rural areas What I find in the Finance Bill is, there is a concrete proposal for amendment to the Income-tax Act which is meant for benefiting the big business people I object to such an amendment

Regarding taxation on advertisements and sales promotion, I want to tell the Finance Minister, through you, that the hon Finance Minister should review the position and think again whether such a tax should be levied at all In the case of small firms they must have to advertise in papers for promoting their sales and without advertisement they cannot sell out their goods So, if these taxes are levied, you will see that the increase in the prices of consumer items will be about 16 to 17 per cent There is a general increase in the excise duty from 2 per cent to 5 per cent and there is a basic excise duty of 5 per cent If, you calculate it you will find that the manufacturers will be compelled to increase their prices not only to the extent of levy, but the extent will be about 17 to 18 per cent which is to be payable by the consumers So, it will tell hardly on the common people and the Finance Minister, I am sure, will consider this

With regard to modification of the provision relating to exemption of long-term capital gains here on page 5 of your Explanatory Notes, you will also find this will help the rich people This will not help the common people What was mentioned in the Election Manifesto of the Janata Party before elections ? It was mentioned in the Manifesto that the rural sectors would be getting priority and the common people case would get the best consideration But unfortunately here we find there are concrete proposals for amendment so that big business people can get some concessions What do we want ? We want small manufacturers, cottage industries and small-scale industries to get the advantage What we want is that cottage industries and small-scale industries to be established through the villages in the country so that consumers may get their requirements at

reasonable prices. But here you will find that only the big business people and the established business people will get the benefit.

Mr. Chairman, Sir, you will be surprised to learn that only a sum of Rs. one lakh has been provided for super thermal power plant at Farakka. What can be done with this Rs. one lakh when it requires crores of rupees. ? It means nothing. It means the proposal has been thrown in the cold storage. I have gone through the records and I find that as a consolation a sum of Rs. one lakhs is provided for this purpose. The proposal for the super thermal power plant at Farakka has been sanctioned since long and the hon. Minister is aware of it. There were big promises—promises by the previous government and promises by the present government. But nothing has been done. For the development of ports a various places, a very small amount has been provided. And practically no amount has been provided for the development of the ports in Haldia and Calcutta, The Calcutta and Haldia ports are dying. You will remember the Farakka Waters Agreement with Bangladesh. We have appeased Bangladesh, giving away more than what they wanted, keeping for India for the eastern region of India, only 20,000 cusecs of water ; and our canals, like the Hooghly river, are dried up in the season. No steamer can go to Calcutta. Even launches cannot ply on the Hooghly river. This is the position. We do not know why our Government had gone so far as to appease Bangladesh by giving away all the waters to Bangladesh, although the Government of India had to spend Rs. 56 crores for that—whereas Bangladesh did not pay a single penny. However, I am not going to dwell on that question.

Now about excise duty. The excise duty on fertilizers should be abolished. There should be no excise duty for fertilizers, because we want to encourage the small farmers and agriculturists. 70% of our countrymen are villagers and small farmers. They should be given the benefit. Excise duty should not have been imposed on fertilizers. I would request the honourable Minister to look into the matter and see if this can be cut down.

The growth in rural sectors will be practically nil, although we find that 41 % of the total budgetary amount has been provided for expenditure on the Department of Agriculture. There are no positive programmes. There is no policy as to how the money will be spent and how the farmers will get the benefit.

I had the opportunity to visit the Agricultural Research Institute several times. I found that many equipments had been manufacured by our engineers. Our engineers have talent. I must praise our engineers who have talent. Equipments have been manufactred and they are lying there. Those equipments are not being sold. There is no sales promotion. That is why I say there is no policy. There should be the infrastructure before we make out a plan. The last year of the 5th five-year plan has been gone through, but the Government could not complete the Plan. We have got a Draft Plan. I have gone through some pages of it. We shall certainly discuss the Draft Plan but in the intervening period, how will the money be spent, how will farmers get benefits and how will cottage and small-scale industries be developed in the villages ? How will fertilizers be distributed in the villages There is a gro up of dealers who are monopolizing in the matter. Fertilizers should be distributed in each village, and small dealers should be appointed -not the big ones who are earning thousands of rupees.

I attended several meetings of the Federation of Bank Employees and I have come to know that thousands of applications from agriculturists for loans are pending with the banks for sanctioning of loans. The banks have not sanctioned those loans. I want to mention a few figures: Punjab National Bank—55,000 applications from West Bengal; United Bank of India 36,000 applications from agriculturists and small farmers; the Central Bank of India—21,000 applications the United commercial Bank—31,000. These applications are pending. But, at the same time they are expediting the payment of loans to big industries. Our hon. Minister is certainly aware of it. Many of the Managing Directors or Chairman were present and I enquired of them for the reasons. The reply was that there were mistakes in the applications. I would say that it is their duty to rectify the mistakes. As they are public servants, they have to give assistance to the public. It is their duty to see that the mistakes in the applications are corrected so that the agriculturists, small farmers and the small scale industries get their loans. As a matter of fact, if you go through their accounts, you will find that about 60 per cent of the loans have been given to the big industrial houses and, out of the balance 40 per cent, only 30 per cent are given to the small-scale industries, agriculturists and so on. A time should come under the present Government when more than 60 per cent of the loans are given to the farmers of the villages, to the agriculturists and small traders so that the common people can get the benefit out of it.

[Shri Dhirendra Nath Basu]

The other day I was very glad to listen to the speech of our friend, Shri George Fernandes, at the meeting to the Federation of Chambers of Commerce and Industry where he said that 17 houses are monopolising the business I would appeal to the Finance Minister to see that this monopoly is broken Let the farmers of the villages, the small traders get the benefit of the loans from the nationalised banks Let the Finance Minister prepare a scheme He is a senior retired ICS officer Let him formulate a scheme and then implement it so that the people are benefited In my constituency there are many small and cottage industries which are not getting loans. In many cases it is only after my personal intervention that the applications for loans have been sanctioned by banks This has to be changed

Finally, Sir, I thank you for giving me this opportunity

श्री भारत भूषण (नैनीताल) किसी भी देश का नियंत्रण करने के लिए उस देश की सरकार के पास जो सब से बडा हथियार उसके हाथ में होता है वह वित्त व्यवस्था का होता है। इसका प्रारम्भ बजट की सामान्य चर्चा से हो कर अब वित्त विधेयक पर आ कर समाप्त हो रहा है। इस बीच हुई चर्चा को सुनने के बाद मे वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खडा हुआ हू। मैं कुछ सुझाव भी इस अवसर पर देना चाहूंगा और आशा करता हू कि उनकी ओर वह ध्यान देंगे।

सरकार बदली इसकी बडी चर्चा रही है। अभी हमारे एक मित्र ने मुगल शासन से ले कर कैसे अंग्रेजी शासन आया। कैसे कांग्रेस सत्ता मे आई और फिर जनता सरकार सत्ता मे आई, सारा इतिहास बताया है। किन्तु परिवर्तन नजर नही आ रहा है। इसका क्या कारण है? ऐसा मालूम पडता है, मुगल शासन की बात तो नही कहता, लेकिन अंग्रेजो ने जो इस देश के ऊपर शासन किया उसने एक व्यवस्था दी, उस व्यवस्था का बराबर हस्तांतरण हुआ है, इस देश मे क्रान्ति नही हुई है। उस पानी में से बदबू आयी, उसकी व्यवस्था करने के लिए सिरे पर कुछ लोग बैठा दिये गये, बदल दिए गये, लेकिन वह पानी ज्यो का त्यो ही रहा, उसकी बदबू जाती नही है। यदि आपको परिवर्तन करना है तो किसी प्रकार से इस पानी को सुधारना होगा तब जा कर इसकी बदबू निकलेगी, यह पेय जल बनेगा। इस देश में आजादी के 30 साल बाद भी जनता और सरकार के बीच में खाई बनी हुई है जिससे कभी भी जनता नही समझ पायी, उसने कभी भी यह नही कहा कि जो उसे देना है अपनी सरकार का देना है यह सरकार अपनी है, ऐसा अनुभव वह नही करती है। हम नियम बनाते है, दिन रात कडे नियम बनाते चले जाते है, सरकारी पक्ष मे बैठे हुए लोग, जो सरकारी दफ्तरो में लोग बैठे हुए हैं उसी जनता के बीच में से आये है, लेकिन उनके दिमाग में एक बात है कि बाकी जनता बेईमान है, यह सरकार को और समाज को लूट कर व्यक्तिगत रूप से रईस बन जाते है, यह भ्रष्ट है। और जो जनता में लोग है वह समझते है कि उन्ही के भाई बन्धु जो सरकारी दफ्तरो मे कुर्सी पर जा बैठे है यह सब भ्रष्टाचारी है, रिश्वतखोर है, बेईमान है, हमारी मेहनत की कमाई मे से हिस्सा लेना चाहते है। ऐसी खाई बन गई है। और यह व्यवस्था चलते चलते पिछले दिनो सब ने स्वीकार किया जो कांग्रेस सरकार सत्ता में थी उसने भी स्वीकार किया कि देश के अन्दर काला धन है चाहे रिश्वत से कमाया हो, चाहे टैक्स चुरा कर कमाया हो, एक पैरलल समानान्तर इकोनामी खडी हो गई।

कहने को बडा घमण्ड किया गया देश की अर्थ व्यवस्था बडी सुदृढ़ हो गई है, हमारे पास विदेशी मुद्रा बहुत सारी आ गई है, सोने के भी भण्डार है, ऐसी सुदृढ अर्थ व्यवस्था में जनता सरकार को सरकार मिली। कांग्रेस का कहना तो यह था, साथ साथ वह अपनी बात को काटते थे कि देश के अन्दर काला

धन है, समानान्तर अर्थ व्यवस्था चलती है, इसके द्वारा अपनी ही बात को काटते थे। इसके माने अर्थ व्यवस्था बिल्कुल गडबड थी। देश के अन्दर की राजनीति, यह ठीक है कि आज की परिस्थितियो मे अर्थ और राजनीति अलग अलग नही की जा सकती है। कोई भी राज्य स्थिर है यदि उसकी अर्थनीति सही है। वह राज्य हट जायेगा यदि उसकी अर्थनीति गलत हो जायेगी। तो दोनो को अलग नही किया जा सकता है। किन्तु कुछ पूजीपति लोग देश की राजनीति का सचालन करने लगे, और वह भी काले धन से। ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी इस देश में जिसको अब बदला गया। इस बदली हुई परिस्थिति में पिछले वर्ष जब यह कहा गया कि हमें जो कुछ विरासत में मिला है मार्च में सत्ता में आये उसको हमें आगे चलाना है, अधिकाश बजट यह जनता का बजट नही है, ऐसी घोषणा वित्त मत्री जी ने की। अगल साल में बजट हमारा होगा। मै बधाई देना चाहता हू अगले साल के बजट में उन्होने भारत के देश को, इस देश की जनता को जो हमने वचन दिया था कि 40 प्रतिशत धन देहातो के विकास के लिए लगायेंगे उसकी व्यवस्था की गई है। किन्तु फिर प्रश्न आता है, मैने जैसा कहा कि पानी मे बदबू है, व्यवस्था वही है इसको शेक अप करने की जरूरत है, हिला देने की जरूरत है। जिन्होने छोटे से स्तर पर एक्वेरियम देखी होगी मछली पालन की घरो के अन्दर करते हैं उसमें पानी में बुलबुले उठाने पडते हैं नही तो मछली मर जाती है। यहा की अर्थव्यवस्था में विकास की जितनी योजनायें आप देंगे यदि उसको शेक अप नही करेंगे वित्त मत्री जी तो इसमें सब को समाप्त करना होगा।

मैं आपको स्मरण कराना चाहूंगा कि गत सितम्बर मास मे मैंने आपको एक पत्र लिखा था जिसमें हिन्दुस्तान के उद्योगों को चलाने के लिए सौफ्ट टर्म पर कर्जा देने वाली सस्था आई० टी० पी० आई० और फाइनेन्शियल कार्पोरेशन की व्यवस्था के बारे में लिखा था। उसके बारे में आपका पहला पत्र मिला कि आपका पत्र मिला, देखेंगे और उसके बाद एक पत्र मिला कि जाच कराई जा रही है। लेकिन 9 महीने हो गये वह जाच पूरी नही हुई।

एक शुगर फैक्टरी का निर्माण 8 कराड रुपये में होता है, वह भी उन्ही से लोन लेती है और एक का निर्माण 6 करोड में होता है, वह भी उनसे ही लोन लेती है और दोनो का काम करने वाली कम्पनी एक ही है। इस प्रकार की अर्थ व्यवस्था पर आप बैठे है। आपका दफ्तर जो कुछ कर रहा है, जो लैप्स हो रहे है, इन को आपको खोज निकालना होगा, जब तक यह नही करेंगे, काम चलने वाला नही है।

मैने पिछले बजट के समय भी कहा था कि मेरी आदत नही है कि किसी व्यक्ति का नाम ले कर बुराई करता रहू, क्योंकि वह भी इनडायरेक्ट व्यक्ति पूजा है, व्यक्तिपूजा को बढ़ावा देने वाली चीज है। मै जानता हूं कि आप कुछ दूरन्देशी की कार्यवाही कर रहे है। और उससे देश को लाभ होगा लेकिन राजनीति में देश की यह माग है कि कुछ इमिजिएट मिलना चाहिए। आप उनकी तरह झूट तो नही बोल सकते है कि देश की गरीबी एकदम हटा देंगे, लेकिन कुछ तो करना चाहिए, देश आपका 10 साल इन्तजार नही करेगा। बढ़ते हुए कदम सिद्ध होने चाहिए।

आपका दफ्तर किस प्रकार से विकास योजनाओ को ठप्प कर रहा है, यह मैं बताना चाहता हू। जमरानी में एक डैम बनाने की योजना बनी, 62 करोड रुपये उसके लिए रखे गये। यह मेरे क्षेत्र मे पडता है, 1974 में उसका शिलान्यास भी कर दिया गया। देखने की बात यह है कि 1974

[श्री भारत भूषण]

में शिलान्यास किया हुआ डैम 1978 तक पूरा नहीं हुआ, उसमें एक पत्थर भी नहीं लगाया गया। उसका कारण यह है कि हमारे इंजीनियर्स यह तय नहीं कर पाये कि बाहर से आई हुई एक तकनीक के आधार पर डैम बना कर उस पर कंकरीट के स्लैब लगाये जायें या भारतवर्ष का जो पुराना तरीका चला आ रहा है कि मिट्टी की तह लगाकर बांध बनायें, इसमें से एक भी तरीका 4 साल में तय नहीं कर पाये। मैं जानना चाहता हूं कि यह शिलान्यास किस चीज का कर दिया गया ?

इन परिस्थितियों में विकास योजनाएं अगर खटाई में पड़ी रहेंगी तो आपका काम चलने वाला नहीं है, हमारा समय पूरा हो जायेगा लेकिन यह काम चलाने वाले यहीं रहेंगे। इसके लिए इनको हिलाना होगा। मैं समझता हूं कि चाहे इसमें थोड़ा व्यय हो, चाहे इसमें थोड़ी बुराई मिले, लेकिन जो लोग बहुत दिनों से एक जगह पर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने वैस्टेड इण्टरेस्ट डैवलप कर लिये हैं, उन्हें वहां से हिलाना होगा, रिशफल करना होगा क्योंकि काम उन्हीं से लेना है।

दूसरे हमें नारेबाजी से निकलना होगा। उत्तर प्रदेश का सब से बड़ा उद्योग चीनी उद्योग है। इसके बारे में 1967 से नारा लगा कि इसका राष्ट्रीकरण किया जायेगा लेकिन 1978 तक न तो राष्ट्रीयकरण हुआ और न निजी उद्योग ने उसमें एक पैसा लगाया। नतीजा यह हुआ कि चीनी उद्योग बैठ गया। जितनी कैपेसिटी की शुगर फैक्टरी थी, वह दिन-रात बैठती चली गई। आपको निश्चित रूप से भारत की अर्थनीति की घोषणा करनी पड़ेगी। अगर राष्ट्रीयकरण करना है, तो किसी दिन सुबह को पता देना होगा जैसे 1 हजार का नोट समाप्त किया और सुबह ही पता लगा कि 1 हजार का नोट समाप्त हो गया। नेशनलाइजेशन अगर करना है तो नारा लगाते रहने से काम नहीं होगा, एक दिन सुबह इसकी घोषणा करनी होगी कि नेशनलाइजेशन हो गया, फैक्टरियां टेक-ओवर हो गई तभी काम होगा। नहीं तो कोई काम नहीं होगा। इस तरह रोज भय में रखने से कोई लाभ नहीं है। जिस तरह से एक मेमने को आप रोज खाना खिलाइयें और शाम को भेड़िये के सामने कर दीजिए तो उसका सब खाया-पिया निकल जायेगा उसी तरह से इस उद्योग में भी ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। इससे न श्रमिकों को, न किसान को और न उद्योग को कोई लाभ होने वाला है।

16.59 hrs.

[SHRI DHIRENDRANATH BASU *in the Chair*]

गत वर्ष माननीय मंत्री जी ने घोषणा की इनकम टैक्स की प्रथम जो सीमा है वह 10 हजार तक बढ़ाई है, परन्तु टैक्स पहली सीमा 8 हजार से ही लेना शुरू हो जायेगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने जब यह कदम उठाया था तो इस सदन में इस बात का मेजें थप-थपाकर आपका स्वागत किया गया था। सारे देश ने इसका स्वागत किया था और मुझे यह भी विश्वास है कि इसके कारण से आपको टैक्स में हानि नहीं हुई।

परन्तु इसके व्यावहारिक रूप में 10 हजार की सीमा है पर 10 हजार के बाद ही टैक्स लागू नहीं होता। इससे ब्लैक मनी पैदा होता है। अगर 10 हजार से ऊपर में एक हजार रुपया और कमा लूं तो मुझको 510 रुपये टैक्स देना पड़ता है, 490 रुपये हमारे घर में पड़ता है, यानी 51 परसेंट टैक्स देना पड़ता है सिर्फ 1 हजार रुपया ज्यादा कमा लेने से। इस प्रकार के जब आपके नियम होंगे तो मैं कोशिश करूंगा

कि 490 रुपये रखने के बजाये मैं 1 हजार कही पर छिपाऊ, इस तरह काटू कि उस समय मेरी 999 रुपये आमदनी दिखाई दे ताकि मेरे ऊपर यह टैक्स न लगे। इस प्रकार के नियम बनाने मे हम भ्रष्ट तरीको को प्रोत्साहन देंगे।

17 00 hrs

इस वित्त विधेयक मे एडवरटाइजमेंट्स पर टैक्स लगाया गया है। इस बार टैक्स लगाने के मामले मे कुछ चीजो पर ब्लैकंट, काला कबल, डाल दिया गया है—सब को एक ही लाठी मे हाका गया है। यह नही होना चाहिए। सिग्रेट के प्रचार की कोई आवश्यकता नही है—मुझे उस की आदत है, और लोगो को उस की आदत है—, उस पर चाहे कितना टैक्स लगाया जाये। बेशक सिग्रेट और शराब का प्रचार बन्द कर दिया जाये। लेकिन क्या टूरिज्म कार्पोरेशन देश-विदेश मे एडवरटाइजमेंट किये बिना हमारे टूरिस्ट स्पाट्स को हाई-लाइट कर सकेगी? क्या एडवरटाइजमेंट किये बगैर इडियन एयरलाइन्ज चल सकेगी, जब कि उसे दूसरी एयरलाइन्ज का मुकाबला करना है? इस स्थिति मे हर एडवरटाइजमेंट पर टैक्स लगाना उचित नही है। इस से एक हानि यह होगी कि जितने लोग प्रचार के साधनों मे लगे हुए है —उन मे कुछ पेंटर्स और फोटोग्राफर्ज है, कुछ आइडियाज देने वाले लोग हैं —, उन सब के व्यापार और आजीविका को बडा भारी आघात पहुचेगा। इसलिए इस प्रावधान मे परिवर्तन की आवश्यकता है।

सब तरफ से सेविंग्ज बढाने की बात कही जाती है। लेकिन अगर कोई सेविंग कर ले, रुपया इकट्ठा कर ले, तो एक दिन उसे परेशानी का सामना करना पड सकता है। कहा जाता है कि एक खास तरीके से—डाकखाने मे या बाइज के माध्यम से—सेविंग की जाये। आज सारे बैंक नैशनलाइज्ड हैं। अगर कोई किसी बैंक मे नियत समय के लिए रुपया रखता है, सेविंग करता है, व्यर्थ का खर्च नही करता है, तो उसे भी बेनिफिट मिलना चाहिए।

इस देश की इकानोमी को चेंज करने के लिए बहुत से तरीको मे पापुलेशन कट्रोल की बात भी कही जाती है। किसान को कहा जाता है कि उसे जमीन मिलेगी परिवार के आधार पर, लेकिन इनकम टैक्स लगाया जायेगा व्यक्ति पर—वह परिवार पर नही लगता है। इस प्रकार की दुराव की नीति के बजाये परिवार को एक बेसिक यूनिट मान लिया जाये—और परिवार की सीमा निर्धारित कर दी जाये— और यह तय कर दिया जाये कि राष्ट्र उस को यहा तक सबसिडी, अनुदान, सहित राशन आदि चीजें देने मे क्षम है, उससे आगे नही।

यहा पर सीलिंग की भी चर्चा की गई है। कोई कह सकता है कि इस का वित्त विधेयक से सम्बन्ध नही है, लेकिन इससे देश की अर्थ-नीति और सारी इकानोमी का सम्बन्ध है। सरकार ने देहात मे सीलिंग लगाई है। पहली बात तो यह है कि बिना फ्लोरिंग के सीलिंग लगाई गई है—जमीन है नही और छत बन जाती है। दूसरी बात यह है कि जितना ज्यादा जमीन का फ्रेगमेंटेशन होता जायेगा, यूनिट छोटा होता जायेगा उतनी ही कृषि की आय कम होती जायेगी। यदि सरकार चाहती है कि कृषि का उत्पादन बढे, तो अब समय आ गया है कि ऐसा नियम बनाने पर विचार किया जाय कि इस से आगे जमीन के टुकडे न हो, ताकि कृषि सही ढग से हो सके। सरकार सीलिंग को अपनी जगह रखे, लेकिन जमीन के और टुकडे नही होने चाहिए। 18 एकड की सीलिंग है, तीन बच्चे है, 6–6 एकड हो गई, अगली ही पीढी मे। तो तीन तीन और दो दो एकड के ऊपर कृषि नही चलेगी, आप के इम्प्लीमेंट्स नही

[श्री भारत भूषण]

चलेंगे । इसलिए आपको कुछ नियम ऐसा बनाना पड़ेगा कि कृषि इकट्ठा रहेगी, उस परिवार की यूनिट बन कर रहेगी और उस को इकट्ठा करना पड़ेगा ।

आपके पास इस समय फारेन एक्सजेंज कम नहीं है । अभी मैं परसों अखबार में पढ़ रहा था कि इस समय पिछले सारे रेकार्ड्स उस के टूट गये हैं. . . .

एक माननीय सदस्य : सीधा समझा दीजिए कि खेती खेती करने वालों को दीजिए ।

श्री भारत भूषण : खती खेती करने वालों के पास ही रहनी चाहिए, उस में कोई दो राय नहीं हो सकती ।

मैं यह कह रहा था कि आप के पास फारेन एक्सचेंज वढ़ रहा है । आप देखिये कि एक ओर खेती की सीमा छोटी और एक ओर बड़े ट्रैक्टर का निर्माण यह कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिये छोटे ट्रैक्टर्स का निर्माण कराइये और जब तक छोटा ट्रेक्टर नहीं बनता है, तब तक आप ट्रैक्टर बाहर से लाइये ।

दूसरी बात हम इस समय बजट पर बात कर रहे हैं । इस में आप देखे, छोटे ट्रैक्टर्स या बड़े ट्रैक्टर्स कोई भी हों, आप की एक्साइज ड्यूटी का तरीका क्या हो गया है कि उस में डायनेमो बाहर से बन कर आये, उस पर एक्साइज ड्यूटी लग गई, टायर बाहर से आया उस पर एक्साइज ड्यूटी लग गई । पम्प वगैरह बाहर से आया, उस सब पर एक्साइज ड्यिूटी बन गई । एक जगह ला कर सब को एसेम्बल कर दिया, उस पर एक्साइज ड्यूटी लग गई इस से किसान की कमर टूट जाती है । आज उस की कीमत कितनी बढ़ी है ? 1970 में आप आधार मानते हैं 100 और आज 180 कीमत हो गई हैं । 1970 में मैंने ट्रैक्टर खरीदा था । 19 हजार रुपये का इम्पोर्टेड ट्रैक्टर आया था इंटरनेशनल हारवेस्टर 35 हार्स पावर का । आज उस की कीमत 45 हजार से भी ज्यादा 48 हजार है । यह स्थिति है । आप किसान की चीजों की कीमत कितनी बढ़ायेंगे । 76 रुपये के भाव से किसान ने उस समय गेहूं दिया था, क्या आज उस को 150 रुपयें का भाव आप दे सकेंगे ? तो यह कहना कि हम किसान के दृष्टिकोण से सोच रहे हैं । किसान के लिए कर रहे हैं, यह कहां तक सही है क्या वास्तव में हम किसान के लिए कुछ कर रहे हैं ? किसान की जो उपज है उस का भाव निश्चित करने के लिये दूसरा पैमाना आता है, उस की उपज का रेट कुछ और और किसान को जो सामान लेना है उस का रेट कुछ और है । इस तरह यह जीवन कैसे चलेगा ? यह परिस्थिति बहुत खुशगवार नहीं हैं ।

वित्त मंत्री जी यद्यपि उस से टअप से आए हैं, वित्त व्यवस्था में रहे हैं लेकिन मैं फिर निवेदन करूंगा कि एक बार इस देश की वित्त व्यवस्था को झकझोरना होगा ।

जितनी चर्चा राजनीतिक भ्रष्टाचार की की जाती है उस के अन्दर हमारा कर्मचारी वर्ग शामिल है । उन को या तो लैंकेट माफी दीजिये वरना तो इस खतरे में कि कहीं हम उस में फंस जायें, वे आप को हमेशा मिसलीडिंग रिपोर्ट देते रहेंगे । मैं मिसाल के तौर पर बताना चाहूंगा । आप की ही गवर्नमैंट की अंडरटेकिंग हैं मार्डन बेकरी । उस के एम डी के खिलाफ सी बी आई एन्क्वायरी भी हुई । जवाब दे दिया गया कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें एक महीने बाद रिटायर होना है । एक्सटेंशन तो मना ही कर दिया गया और उन्हें वापस कर दिया गया । लेकिन उन के किए हुए का क्या हुआ ? उन के सताए हुए लोगों को वापस न लेने के लिए सारी मिनिस्ट्री लगी हुई हैं कि नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता क्योंकि अगर उन्हें वापस लिया गया तो उन के दुष्कृत्यों की पोल खुलेगी । आज एक साल

22 दिन के अन्दर उस को जवाब नहीं दे पाए हैं । सरकार कहती है कि सरकार को कुछ नही करना है, वह तो कारपोरेशन है, कम्पनी है, इस का मैनेजमेंट करेगा और मैनेजमेंट के पास जाता है तो वह कहते हैं कि यह तो सरकार को रिपोर्ट आयेगी। एक साल 22 दिन में तो बनी नहीं । उस की सर्विस बुक मांगी गई, उस के खिलाफ रिकार्ड मंगाया, इस तरह से उस को तंग किया गया। वह रिकार्ड लाया तो अब उस को नये सिरे से बनाया जा रहा है। इस को 'बुकिंग" नही कहेंगे तो क्या कहेंगे, जानबूझ कर इस तरह की शरारतें की गई ।

इसलिये मैं आप से कहना चाहता हूं कि जो लोग जहा बैठे है, उन को हिलाना होगा, उन को हटाना होगा, वरना काम नही चलेगा। माननीय मंत्री जी एक साल के अन्दर जो अनुभव हुआ है और अभी जी चार साल आप के बाकी हैं, ये लोग आप को पहले वालो से ज्यादा बदनाम कर देंगे, क्योंकि पहले वाले तो उन के साथ हिस्सा बंटाते थे, आप रिश्वत खाते नही है, हिस्सा बटाते नही है। इसलिये आप ज्यादा बदनाम हो जायेंगे ।

मैं चाहता हूं कि एक्साइज ड्यूटी मे आप ने जो 5 परसेंट ब्लाकेट रेट बढ़ा दिया है, उस पर फिर से विचार कीजिये। जो अनावश्यक खर्च है, जैसे सौन्दर्य प्रसाधन की वस्तुए है, उन पर आप ज्यादा टैक्स बढ़ायें, लेकिन जो उत्पादन बढाने वाली वस्तुए है, उन पर टैक्स को समाप्त करें । 10 हजार रुपये की आय पर जो इनकम टैक्स हटाने की बात कही गई है, उस को व्यावहारिक रूप मे पूरा करे । 10 हजार की इन्कम पर इन्कम टैक्स प्रारम्भ हो, ऐसी व्यवस्था करे । मैं एक बात और कहना चाहता हूं —क्या ऐसा सम्भव नही है कि हम इन्कम टैक्स बिल्कुल समाप्त कर दें, उस की जगह खर्च पर टैक्स लगायें । जो कमायें और उस कमाई को उत्पादन में, नये रोजगार में धन्धों को बढाने में लगाता चला जाय, उस पर टैक्स न लगे, लेकिन जो व्यक्ति उस आमदनी को अपने ऊपर खर्च करने में लगायें, अपने ऐश-आराम में लगायें, उस पर टैक्स लगे । अब तक की राजनीति यह रही है कि हिन्दुस्तान के 80 प्रतिशत किसानों की कमर को तोड़ कर रखो, उन की क्रय-शक्ति को घटा दो, ताकि उन के अन्दर खरीदने की शक्ति न रहे, वे खरीदने के लिये आगे न आ सकें, इस से चीजो के भाव नीचे रहेंगे । यह भावों को नीचे रखने का सही उपाय नही है । 80 प्रतिशत किसान यदि भूखा मरता रहेगा, तो इस से काम नही चलेगा, इस से क्लास-वार शुरू हो जायेगी ।

यहां पर हरिजनों की बात भी कही गई है, यद्यपि इस का सीधा सम्बन्ध नही है, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा—जैसा हमारे माननीय सदस्य कुंवर महमूद अली साहब ने कहा—यह सब हम को आपस मे लड़ाने के लिए है । इस का वास्तविक कारण अर्थ-नीति है । जो रईस है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी सम्प्रदाय का हो, गरीब को सताने में ज्यादा मजा आता है । भाई को भाई सताता है, मैंने सगे-भाइयों को देखा है, दूसरो की बात तो छोड़ दीजिए, जो अपने सगे भाई को सताने मे खुश होता है । इस लिए आज हमारी अर्थ नीति का आधार यह होना चाहिए कि जो नीचे के लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, उन को ज्यादा सुविधाए दें, हमें उन को शिक्षित करना है । यदि समाजवाद की तरफ कोई बड़ा कदम उठाना है तो वह यह है कि सब को समान शिक्षा मिले। उस समान शिक्षा के दौरान जब उन को भोजन, वस्त्र और शिक्षा समान रूप से मिलेगी, तो जब वे शिक्षित हो कर बाहर आयेंगे तो उनका शरीरिक विकास, मानसिक विकास बराबर होगा । रईस के लड़के और गरीब के लड़के मे भेद नही रहेगा । जिस तरह से कृष्ण और सुदामा ऋषि संदीपन के आश्रम में एक साथ पढ़े, कृष्ण राजा के बेटे थे और सुदामा गरीब ब्राह्मण का बेटा था, दोनो जंगल मे साथ लकड़ियां काटने जाते थे, दोनो को खाने के लिए एक-एक मुट्ठी

[श्री भारत भूषण]

भूजा मिलता था—जब इस तरह की शिक्षा देश में मिलेगी, तब इस देश मे समाजवाद आयेगा, इस के अलावा दूसरा कोई तरीका नही है।

आज तक इस देश मे—चाहे पिछली सरकार हो—जितने वित्त विधेयक पेश हुए, उनसे समाजवाद के नाम पर असमानता बढ़ी, बडा ज्यादा बडा हुआ, गरीब ज्यादा गरीब हुआ, पिछडा और हरिजन ज्यादा पिछडता चला गया। यह जो व्यवस्था पैदा की गई है—जनता पार्टी के वित्त मंत्री होने के नाते आप का दायित्व है कि इस व्यवस्था को आमूल-चूल परिवर्तन दे कर देश मे एक नया जागरण, एक नई चेतना, एक नई दिशा दे।

इन शब्दो के साथ मैं इस वित्त विधेयक का समर्थन करता हू।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : चैयरमेन साहब, जनता पार्टी यह समझती है कि इस मे पहले जितनी भी गवर्नमेंट आई है, उन्होने रूरल डेवलपमेंट को कोई अहमियत नही दी। आप कहते हैं कि हमने एग्रीकल्चर को सब से ज्यादा महत्व दिया है। ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए ज्यादा बजट प्रोवाइड करने, तो हमे कोई एतराज नही है लेकिन बोलेंगे तो यह लेकिन करेंगे दूसरी बात। मुझे तो यही अफ़सोस की बात मालूम होती है। आप ने एक साल मे क्या किया है। एक साल के अन्दर लोगो के लिए क्या किया है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए यह कर रहे हैं और यह कर रहे हैं यही कहते हैं और होम मिनिस्टर साहब भी बोलते है कि हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए ज्यादा करेंगे, लेकिन आप ने क्या किया है, यह मैं पूछना चाहता हू।

एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मे पानी की बहुत जरूरत है और इर्रीगेशन के बगैर उस मे ज्यादा तरक्की नही कर सकते लेकिन पानी के सिलसिले मे आप ने क्या किया है, यह मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हू। इस से पहले भी यह प्रोपोजल था कि शुमाली हिन्दुस्तान मे, उत्तरी हिन्दुस्तान से जो ज्यादा पानी है, उसके लिए गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र आदि के पानी को बर्बाद न होने दिया जाए। ऐसी जो बहुत सी नदिया है उन का पानी समुद्र मे जा रहा है और उस का पूरा इस्तेमाल आप नही कर पा रहे हैं। मैं समझता हू कि 40 फीसदी से ज्यादा आप वह पानी इस्तेमाल नही कर रहे है और 60 परसेण्ट पानी समुद्र मे जा रहा है। इससे पहले जो डा० के०एल० राव थे, उन का सुझाव यह था कि सरप्लस वाटर जितना शुमाली हिन्दुस्तान मे है, उस गंगा के पानी को अगर कावेरी से मिला दें तो वह समुद्र मे नही जाएगा और वेस्ट नही हो पाएगा और वह पानी भी इस्तेमाल हो जाएगा और दूसरी जगहो पर उस पानी को इस्तेमाल कर के लाखो एकड़ जमीन मे काश्त की जा सकती है। इस सिलसिले मे आप ने क्या किया है, यह मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हू। वे बहुत तजुर्बेकार है और अच्छे आदमी हैं, लेकिन इस दिशा मे आप ने क्या किया है। मेरा निवेदन यही है कि यह जो डा० के० एल० राव का सुझाव था कि गंगा को ले जा कर कावेरी मे मिलाया जाए, तो उस के लिए आप ने क्या सोचा है।... (व्यवधान)... ब्रह्मपुत्र को मिलाना तो मुश्किल हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र के लिए आप ईस्ट इण्डिया मे कर सकते है। यहा पर कई जोन्स हैं जैसे नदर्न, सदर्न, इस्टर्न और मिडिल। इन को आप मिलाने का काम करे, तो काश्त की समस्या का निदान हो सकता है।

एग्रीकल्चर के वास्ते इलेक्ट्रिसिटी की भी बहुत जरूरत होती है। आप ने सुपर थर्मल पावर स्टेशन के लिए अनाउन्स किया था लेकिन क्योंकि पावर मिनिस्ट्री की

डिमान्ड्स नहीं आई, इसलिए हम इस मामले पर बहस नहीं कर सके । रामागुण्डम में एक सुपर थर्मल पावर स्टेशन के बारे में अनाऊंस किया था कि एक साल में इस को कर देंगे । इस में अभी तक कुछ नहीं हुआ है और कोई काम नहीं हो रहा है । अगर यह हो जाता है, तो इस से वहां के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा । अगर पावर मिनिस्टर साहब से इस के बारे में कहते हैं, तो वे यह कहते हैं कि असली पावर, मनी की पावर तो पटेल साहब के हाथ में है । इसलिये आप से इस बारे में कह रहे हैं कि जितनी फाइनेन्स की जरूरत है, उस को आप प्रोवाइड कीजिए । इस से पूरे साऊथ को फ़ायदा होगा और मुझे उम्मीद है कि आप इस बारे में कुछ करेंगे ।

तीसरी चीज स्टील के बारे में है । हमारे विशाखापटनम में एक स्टील का प्लान्ट है विजाग स्टील प्लान्ट । आप को मालूम है कि इस के बारे मे बहुत बडा एजीटेशन हुआ था । पिछले 10 साल से यह मामला चला आ रहा है और वह डिमान्ड पूरी नहीं हो रही है । बीजू पटनायक जी से कहा, तो उन्होंने कहा, नहीं, नही, हम इस के बारे में सोच रहे हैं और हम कुछ करेंगे उस के मुतालिक मगर उन के हाथ मे कुछ नही है । वह भी आप के हाथ में है । अगर आप पैसा देंगे तो स्टील प्लान्ट आ जाएगा । वह हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है । इसलिए आप हमदर्दी रख कर वहां पर स्टील प्लांट लगाने की कोशिश करें । अगर आप ऐसा कर दें तो बहुत अच्छा होगा ।

सभापति महोदय, हमारा तेलंगाना बेकवर्ड रीजन है । इंडीपेंडेंस आने के बाद से वहां पर सिंगल रेलवे लाइन है । अगर किसी रीजन में रेलवे लाइन नही है, तो आपको तो मालूम है कि वह रीजन तरक्की नहीं कर सकता है । हमारी डिमाण्ड बहुत समय से रही है कि वहां पर रेलवे लाइन प्रोवाइड की जाए । वहां पर एक रेलवे लाइन है— रामागुण्डम से ले कर निजामाबाद तक । हम बहुत समय से रेलवे लाइन के लिए लड़ते रहे हैं । आपको तो सभापति महोदय, पता है कि हम इस इलाके में रेलवे लाइन के लिए कितना लड़ते रहे हैं । हमारे रेलवे मिनिस्टर साहब ने भी हम से कहा था कि हम आप से हमदर्दी रखते हैं लेकिन हमारे पास पैसा नही है । इसलिए मैं पटेल साहब से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे रीजन में रेलवे लाइन के लिए आप पैसा दीजिए । तभी यह काम हो सकता है ।

चेअरमैन साहब, आप कहते हैं कि आप गवर्नमेंट में आने के बाद से दस सालों में अनएम्प्लाएमेंट प्राब्लम सोल्व करेंगे । इस बारे मे मैंने एक सप्लीमेंटरी क्वेश्चन भी किया था कि आपकी गवर्नमेंट को एक साल हो गया है, इस साल के अन्दर आपने कितनी अनएम्प्लाएमेंट प्राब्लम सोल्व की है ? इसका जवाब हमें नही मिला । इस सिलसिले मे मेरी आपसे एक गुजारिश है कि जितने भी अनएम्प्लाएड हैं, जो सेल्फ एम्प्लाएड स्कीम चलाना चाहते है, उनको पैसा दें । उन लोगों को पैसे की जरूरत है । यह पैसा कौन दे सकता है ? यह पैसा आपके बैंक दे सकते हैं लेकिन आपके ये बैंक, जो नेशनेलाइज्ड बैंक हैं, वे सहायता नही देते हैं । आप हमेशा कहते है कि नेशनेलाइज्ड बैंक्स से हम अनएम्प्लाएड ग्रेजुएट्स को सेल्फ एम्प्लाएमेंट स्कीम चलाने के लिए पैसा दिलायेंगे । लेकिन मैं आप से कहना चाहता हूं कि मेरी स्टेट में ही नहीं, दूसरी किसी भी स्टेट में बैंक्स किसी को भी पैसा नही देते हैं । वे बहुत सताते हैं । आप लोग एम्प्लाएमेंट नहीं देते हैं जो खुद एम्प्लाएड होना चाहते हैं उन्हें बैंक्स पैसा नही देते हैं । जो लोग स्माल स्केल इंडस्ट्री वगैरह चलाना चाहते हैं, दूसरे काम करना चाहते हैं, उन्हें आपके बैंकों को सहायता देनी चाहिए । यह क्या बात है पटेल साहब ? बैंक तो आपके हाथ में हैं । डिजर्विंग

[श्री एम० सत्यनारायण राव]

क्वालिफाइड लोग दरख्वास्त भेजते हैं लेकिन उन्हें लोन नही मिलता है । आपको उन्हें लोन देना चाहिए। अगर आप उन्हें लोन देंगे तो आप का एम्प्लाएमेंट देने का काम भी पूरा होगा नही तो आपके वायदे वैसे ही रह जायेंगे और लोग हसते रहेंगे ।

एक बात मैं ला एण्ड आर्डर के बारे में कहना चाहता हू। आज जो देश में यह समस्या है इसका कारण क्या है ? यह ठीक है कि हरिजन, गिरिजन और आदिवासियो के मसले को होम मिनिस्ट्री देखती है और ला एण्ड आर्डर का प्राब्लम भी होम मिनिस्ट्री का है। लेकिन इसका हमे कारण भी देखना होगा। आप लोग उस कारण को दूर नही कर रहे हैं। जितने भी देश मे लेण्डलेस परसस हैं उनको लेण्ड चाहिए । आपके पास सरप्लस लेण्ड है, आप वह लेण्ड उन लोगो को क्यो नही दे रहे हैं जो काश्त करना चाहते हैं? आप एक साल के लेण्ड रिफार्म्स नही कर रहे हैं। आपको दिलचस्पी ले कर फौरन इस चीज को करना चाहिए । मैं आप से कहता हू कि इसको करना आपकी पार्टी के इन्ट्रेस्ट मे भी है और मुल्क के इन्ट्रेस्ट मे भी है। जब-तक आप लेण्ड रिफार्स नही करेंगे तब तक यह ला एण्ड आर्डर की प्राब्लम रहेगी। मैं आपको कहना चाहता हू कि अगर लेण्ड रिफार्म्स नही हुए तो वीकर सेक्शन के लोग खामोश नही रहेंगे । वे तैयार हो गये हैं और वे सिविल वार पर भी आ सकते हैं । साथ ही अगर आप एक आदमी को चार-पाच एकड लेन्ड नही देते है तो ये लेण्ड रिफार्म्स करने से भी कोई फायदा नही है । क्योंकि बिना इसके उसे कुछ मिलने वाला नही है । उसे लेण्ड पर बहुत कुछ खर्च करना पडता है । जमीन के साथ ही उसे इलेक्ट्रिसिटी भी मिलनी चाहिए । आजकल आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नही करते है। आज किसान इससे मर रहे हैं । अभी तमिलनाडु मे देखा कि किसानो ने बहुत बडा एजीटेशन किया। यह हमने पहली बार सुना कि किसान भी एजीटेशन कर रहे हैं । लेबर एजीटेशन तो होते थे लेकिन किसानो का एजीटेशन हमने पहली बार देखा। पुलिस फायरिंग में किसान मर गये । किसान भी अपने राइट्स के लिए लडने के लिए अब तैयार हो गये हैं । वहा बडी समस्या यह है कि बिजली चीप सप्लाई नही हो रही है। एक्साइज ड्यूटी बढा कर आपने और भी परेशानी पैदा कर दी है। यह जो सारी समस्या है इसको आप हल करे। इसके साथ साथ सीड और फर्टिलाइजर भी आपको सप्लाई करना पडेगा । जब तक ये सब चीजें नहीं होगी उस वक्त तक कुछ भी नही होगा । जमीन दे देने से ही कुछ फायदा नही होगा ।

आंध्र प्रदेश की दो तीन बडी प्राजैक्ट्स हैं एक नागार्जुन सागर है एक पोचमपार है, श्री श्रीसेलम है। इन को शुरू हुए बीस साल हो चुके हैं । पडित जवाहरलाल नेहरू ने इनका फाउडेशन स्टोन रखा था। अभी तक भी इनको पूरा नही किया जा सका है । साठ करोड का यह प्लान था। अब 120 करोड या पता नही दो सौ करोड का हो गया है। इतनी कास्ट बढ़ गई है। इरिगेशन पाटेंशियल आप क्रियेट नही करेंगे तो कोई फायदा नही होगा । पैदावार नही बढ सकेगी । ये प्राजैक्ट आधी बन कर तैयार हो गई है। इनको कम्प्लीट करने के लिये पैसा चाहिये। शायद राज्य सरकार ने आपको इसके बारे म लिखा भी है । इनके लिए जितने पैसे की जरूरत है उसको देने की आप कोशिश करे तो अच्छा होगा ।

मुझे जो आपने समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हू ।

SHRI K GOPAL (Karur) Mr Chairman, on behalf of our party, we submitted a list of speaker Unfortunately, you did not go by order, with the result one of the Members had to leave the House in disgust, because he was waiting for his turn I would therefore request you to kindly call the Members according to the list

MR. CHAIRMAN : I called the Members one by one. But none of them was here. This is for your information.

SHRI K. GOPAL : Mr. Khan was very much in the House. He was bypassed.

MR. CHAIRMAN : Now, Mr. Pabitra Mohan Pradhan.

SHRI PABITRA MOHAN PRADHAN (Deogarh) : Mr. Chairman, I rise to support the Bill. The purpose of the Finance Bill, when it is passed is to authorise the Government to collect the money to defray the charges within the coming year ending 30th March, 1979. It is a very good thing. Without money no administration can run. So, the final budget was passed, the Appropriation Bill was passed. The Finance Bill must be passed. So, each and every person should support it. Without supporting it and without passing this Bill, the Government can not get the authority to collect the money and run the administration. Sir, the House has authorised the Government to spend money for the coming year. The amount is extremely very big. It is Rs. 36533,70,33,000. It is a very big sum. If this sum is properly spent, immense good will accrue to the society and to the individual.

From my experience in society and in administration I can say that not only in the Central Government but also in the state governments, fifty per cent of the money is mis-spent, ill-spent, and extravagantly spent. The first and foremost duty of the government, I do notsay of the Finance Ministry, because what can the Finance Ministry do, it can only audit and no body is respecting the audit reports, so it is the duty of the Government as a whole to take care and be cautious and see that the entire money is spent properly. From my varied experience, I say that we are not sincere or serious about spending money. Neither we, nor the previous government, nor those who were in authority in the beginning on August 15, 1947 were serious; I say this out of my experience and I can prove it. I do not lay any charge or any blame on ex-governments or on this government. It is the disease with the society and with the political parties. Today, this party, the Janata Party is here and the Opposition Party is criticising; when they were on that side they were also being criticised. Whoever comes to the gaddi is put to difficulty because of the nature of the society. So, it is their duty, the duty of the parties to support the government but catch the government by the neck if the government failed in the discharge of their duties in controlling the administration. So, I say that the first and foremost duty of the government, I do not speak of the Finance Minister or the finance depa rtment but of the government as a whole, is to have better administration free from delay, lethargy, indiscipline, corruption, bribery and bureaucracy. I think the government will take note of it and they will try to execute it. At present, where ever you go, be it the state government or the central government, you cannot get a paper from offices without worship, beginning from the lowest man to the highest man, somebody, with money, somebody with prayer, somebody with flattery. That is the system of our society. So, I say that all the political parties should combine and compel the government to do this. The government may be of any party, of Janata or Congress (I) or Congress (O) or Congress this and that, whoever is there should not be allowed to occupy the gaddi if insincere and incompetent.... (*interruptions*). Let the country go to dogs; let there be no administration. Because of such administration, people are put to difficulties. The departments and governments are so much harassing the people; had there not been those departments the people would be developing more and more. Departments, authorities and officers do not do their duty. If some persons volunteer to do their duty, they bring charges against them and concoct cases against them and book them in such a way that people do not volunteer to do certain things. When people come to the Ministers, the Ministers say: "What to do ? You did certain things like this and as a result you have been put to difficulties. The law should go in its own way." But when I was the Minister, I never said like that. But I do take a share of blemishes of my Government because I was also with them, just as you people were with Indiraji and have to take a share of her blemishes. So, the Government should be serious and sincere in controlling the expenditure of all the Government Departments. I think the institutions which are most extravagant are the Corporations, eithe belonging to the Cent al Gove nment or the State Governments. I would like to put a question to the hon. Minister. Is any Corporation self-supporting ? The Corporations have not been able to repay the loans and they are not paying interest. They are also not giving any dividend to anybody. Then, why should there be these Corporations ?

SHRI H. M. PATEL: Which Corporation ?

SHRI PABITRA MOHAN PRADHAN : You take any Corporation. No Corporation is making any profit. If you dive deep into their accounts, you will find that they cheat us this way or that way. We have no time to go through the papers. The audit people also, because of their brotherhood, are not very strict. I charge each and every Corporation that has taken money from the Government

[Shri Pabitra Mohan pradhan]

and which has not been able to pay interest and restore the capital How much money has been taken from the banks and from the Governments by them ? Why an individual or a Corporation that has taken loan from the public fund should not repay it ? Should we, politicans come and argue for them that the loan should be cancelled ? Why should it be done like that ? If I get an opportunity, I will prove my charges against the Corporations. I am not going to say anything more about this.

So many persons speak about the removal of poverty and unemployment In my opinion, nobody on earth can remove poverty of any other person and only when a person tries himself to remove his poverty, poverty will be removed. If the Government says that it would remove poverty, it cannot do it in any way. I say this from my experience. I was in the Government for a long period and I tried my best to see that poverty is removed. A lot of money has been spent profusely and even then, that could not be achieved.

I will give you one example.

I was Minister for Tribal and Rural Welfare Department in Orissa. I had to give land to thousands of families. I brought them from the hill-tops, gave each 5 acres of land, a pair of bullocks, plough, fowl, hen etc. and also seeds. In one colony 20 families were put and each family was given all the things I just mentioned After one year, I visited the colony. 10 families had fled away to the hill-tops. After 2 years, out of the remaining 10 families, 3 families were self-sufficient, 2 were living from hand to mouth and the rest were on the verge of going back. I visited another colony and the situation was the same So, what I am saying is, it is the mind of the persons and not the money that government gives which can remove poverty When you give some money, some people think, "Something has come to me; let me spend it this way or that way." You may give money; I do not obstruct it. But from my experience, I can say that it is the mind which is responsible When India was vivisected, in one section the refugees who came, there became self-sufficient within 5 or 7 years and started earning independently while in another section, they could not be self-sufficient because of the mind. And, of course, politics also played a part. So, nobody on earth can remove the poverty of any person unless that person himself sincerely desires to remove his poverty if he gets certain help from the government or society.

Coming to unemployment, every year the number of educated people is increasing. How will you give employment to all of them ? You cannot do it. If the Janata Government says it can do it. I say they are in the wrong. The only way is, you should make such a provision that every body in the house, educated or uneducated, must get some source of employment. No government can give employment to each and every educated person unless the government controls admission into the colleges every year. In communist countries they say, "This year, for this purpose only so many persons have to be sent for higher education" and only that number will go; not a man more will go. So, when they pass out, a job is ready for them. Now whether a boy has got first class, second class or third class, everybody is getting admission in schools, colleges and universities and they get a degree, sometimes without writing anything also. I know it happens in Bihar University, Orissa University, etc. and almost everywhere in India. If you want to control educated unemployment, you must control admission together with the number of students who are passing out every year in every course. So, if you say that you will remove unemployment within ten years, I think you are giving a wrong assurance to the society. You may say that you are trying your level best to give more employment, but not completely to remove unemployment

Sir, I have taken much of your time. I now come to my amendment. My amendment is to clause 38 where the excise duty and the customs duty on salt was to be completely removed. It is a very good thing. For this Mahatma Gandhi launched an agitation. So, when Mr. Desai became the Prime Minister, I think it is natural that he should desire that it should be completely removed. It has been done. It is very good. But to that I have added that together with that, salt either manufactured in or imported into the country, should not be taxed at any point and should not be made subject to sales tax. I think the hon. Minister will take note of it and see whether the customs and exicse duty can be taken out of it, and I am sure he will do it.

In conclusion I would say that when we are giving you so much money—by passing this Bill we are authorising the Government to defray the charges which will come in the course of payment during the coming year ending 31st March, 1979—the society demands from you, the society demands from the Government that the Government must control the administration, control the finances, control the expenditure, eradicate bribery and extravagance. So, I demand that the Government should have a clean administration, free from nepotism, favouritism, corruption, bribery and bureaucracy.

Mr. Chairman, Sir, with these words, I resume my seat.

श्री राम नरेश कुशवाहा (सलेमपुर) : सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मुझे प्रसन्नता है कि हमारी पार्टी ने जो वादा किया है उस की ओर हमारी सरकार धीरे धीरे बढ़ रही है । लेकिन आशा के अनुरूप नहीं बढ़ रही है, यह मैं जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं क्योंकि हम ने सगुण रूप समाजवाद का लिया है कि समता और समृद्धि के आधार पर जो समाज बनेगा वही समाज हम बनाने की कोशिश करेंगे । यह समाजवाद का सगुण रूप है । मैं इसकी व्याख्या नहीं करना चाहता हूं लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि यही सब से बड़ी कसौटी है समाजवाद की कि सब कितना आगे बढ़े, आप समानता कितनी लाए, आप सम्पन्नता कितनी लाए, इस पर आप के बजट की सफलता और आपकी सफलता निर्भर करेगी ।

मैं आप से कहना चाहता हूं, आप ने राजनैतिक समानता तो दी है लेकिन कानून की समानता नही दी है । कहने के लिए कानून की समानता है लेकिन आप का पूरा कानून जो आइ पी सी का बना है वह किस लिए है ? वह शासन करने के लिए है, गरीबों को सताने के लिए है और सताने वालों की रक्षा करने के लिए है । 323 का क्या मतलब है? जिस गरीब को जब चाहो जहां चाहो भर पेट मारो, उस की हड्डी मत तोड़ो, वैसे चाहे मारते मारते मार डालो कोई मुकदमा नही चलेगा । इसीलिए जब गाव का कोई अत्याचारी किसी गरीब आदमी को मारता है तो कह कर मारता है कि देखना ऐसा मारना कि टूटे फूटे नही, भले ही मारते मारते मार डालना क्योंकि तब 304 चलेगा, 302 नही । दफा 379 का क्या मतलब है? 250 रुपये से कम की चोरी होगी, तो पुलिस जांच भी नही करेगी । आप किसी भी गाव मे चले जाइये, गरीबों के मुहल्लो मे, आम तौर पर 50 फीसदी घर उन गरीबो के होते हैं, जिनके घर चोरी हो जाय, तो 250 रु० का माल नही मिलेगा ।

हमारे खेतों में खड़ी हरी खेती को कोई काट दे, तो क्या हश्र होता है । पूरे गांव की हरी फसल को काट दें, तब भी 50 रुपये की घास नही काटी गई—ऐसा माना जायगा और तब मुकदमा भी नही चलेगा । घास का दाम भी थानेदार लगायेगा, एक आना बोझा, दो आना बोझा या 10 पैसा बोझा कह लीजिये । चाहे जितनी खड़ी फसल काट दी जाय, 50 रुपय की घास कट ही नहीं पायेगी, इस लिय मुकदमा नही चलेगा ।

हमारे पशुओं को मार डालने को पूरी छूट है । 1861 मे आप का आइ०पी०सी० बना था, जिस वक्त 1 रुपये मन गेहूं और चावल था । उस समय 50 रुपये का पशु मारने पर मुकदमा चलता था और 50 रुपये का पशु कौन था ?

एक माननीय सदस्य : हाथी था ।

श्री राम नरेश कुशवाहा : सिवाय हाथी के कोई पशु नही था । वह कानून हाथी की रक्षा के लिये बना था, बकरी को रक्षा के लिये नही बना था । मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप का कानून एक दम उल्टा है—गरीब को पीट-पाट कर मार डालने की पूरी छूट है, उस का घर लूटने की पूरी छूट है, उस के खेत को काटने की खुली छूट है, उसके पशुओं को मार डालने की खुली छूट है, तब फिर पुलिस किस लिये है ? हमारे खेत-खलिहान मे सारा धन पड़ा हुआ है, जो भी गरीब के पास होता है, वहां पुलिस पहरा नही देती है, न आप का कानून पहरा देता है । पुलिस वहां पहरा देती है जहां का धन तिजारी मे होता है, जहा रात-भर बिजली जलती है, वही पहरा देती है । गरीबों के लिये पुलिस केवल एक काम करने के लिये है—जब किसी गरीब का लड़का

[श्री रामनरेश कुशवाहा]

अखाडे मे लडने के लिये आने लगे, थोड़ा मजबूत हो जाय और गाव के किसी जबरदस्त आदमी को जवाब दे दे, तब वह थानेदार के पास जाकर कहता है कि इसको थोड़ा ठीक कर दो । श्रीमन, उस के लिये 107, 109, 110, 147, 148, 149, 151 और पता नही कौन-कौन सी धाराये हैं, जिन मे उठा कर उस को जेल मे बन्द कर दिया जाता है ।

श्री एच० एल० पटवारी : (मगलदाई) दफा 302 भी है ।

श्री राम नरेश कुशवाहा : ठीक है । गरीब का लडका चोर न भी हो, लेकिन उसे जबरदस्ती चोर बना दिया जाता है । यह पुलिस गरीबो के लिये नही है ।

आप रोना क्यो रोते हैं कि ला एण्ड आर्डर बिगड रहा है ? आप के कानून क्या कर रहे है ? कोई जबरदस्त आदमी किसी कमजोर आदमी को रास्ता-चलते रोज दो तमाचे मार दे—कोई मुकदमा नही चलेगा, क्योंकि कमजोर बोल नही सकता, लेकिन अगर 5 वर्ष तक मारते चले आए, तो फिर पाचवे वर्ष वह जरूर सोचेगा—दिन मे तो बदला नही ले सकता हू, मुकदमा चल नही सकता है, सरकार मदद नही कर सकती, नेता सुन नही सकता, तो फिर क्या करू । रात को ही कट्टा उठा कर जान से मार देगा । इसलिये मैं पूछता हू—ला एण्ड आर्डर के लिये क्यो रो रहे हैं ? आप का कानून इतना ढीला है कि किसी भी अत्याचारी को पकड नही सकता है । मैं आप को चुनौती देता हू—बतलाइये किस अत्याचारी को पकड़ा है ? किस गरीब की मदद की है—आप के कानून ने । यहा पर बहुत हल्ला मचा—मीसा मत लाइये, नजरबन्दी कानून मत लाइये—मैं आप से पूछता हू—गरीबों के लिये अब भी मीसा है, 109 मे बन्द कर दिया जाय, तो कौन उस की जमानत देता है, कहा से उस को पैसा मिलता है कि मुकदमा लड सके, सालहा-साल बन्द पडा रहता है । 110 मे डाल दीजिये, चाहे जिस कानून मे बन्द कर दीजिये, वह मुकदमा लड नही सकता और आप यदि कत्ल भी रोज करेंगे, तो पैसे के बल पर, वकील रख कर जाति-बिरादरी के नाम पर, हर प्रकार की सिफारिश लगाकर छूट जायेंगे । रोज कत्ल करते रहेंगे और जब कानून रक्षा नही करेंगे तो लोग अपनी रक्षा खुद करेंगे । जब अपनी रक्षा करेंगे तो अत्याचारी दबाएंगे और वे उस का मुकाबला करेंगे और रोज हिंसा होगी । लोगो को इस से घबराहट होती है कि हिंसा हो रही है, अत्याचार हो रहे है । मेरे मन मे तो यह बात आती है और मुझे लगता है कि गरीब जाग रहा है और अत्याचारी का मुकाबला करने जा रहा है और जब अत्याचारी का मुकाबला करेंगे तो जान से भी मारते है, लूटते-पाटते है और सब बाते करते है । आजादी लेने के लिए वह सब कर रहा है । जितनी कुर्बानी करनी चाहिए, आज गरीब उतनी कुर्बानी कर रहा है और मैं समझता हू कि जनता पार्टी के आने से एक नई भावना का उदय हुआ है । लेकिन मैं यह कहना चाहता हू कि आप को जो नौकरशाही है, वह आप की भावना, आप के कार्यक्रम और आप की नीति को लागू करने मे एकदम अक्षम है और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप खुद भी उसे कन्ट्रोल नही कर पा रहे हैं । एक कोल्ड वार चल रही है, एक शीत-युद्ध चल रहा है और जैसी हमारे भोजपुरी मे कहावत है, भीतरी की मार, दहिजरू जाने । इस तरह की स्थिति आज हो गई है । आप कहते हैं कि अफसर हमारी बात सुनते नही है और जो आप कहते हैं उस का उल्टा वे करते हैं और आप इस में फंसे हुए हैं, यह मेरा चार्ज है आप पर । हमारा यह चार्ज इसलिए आप के ऊपर है कि जब हम आप से कुछ कहते हैं तो आप कह देते हैं कि अच्छा, ठीक है, हम देखेंगे लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो यह बयान देते हैं कि एम० पी०

और एम०एल०ए० कुछ भी कहें, अफ़सर अपना काम निर्भय हो कर करें और निर्भय हो कर वे क्या करते हैं? निर्भय हो कर वे आप के कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं, जो आप के समर्थक हैं, उन को अच्छी तरह से पीट रहे हैं क्योंकि अफ़सरों की सांठ-गांठ है उन घूस खिलाने वालों से जो उन के दलाल रहे हैं जोकि 30 साल तक सत्ता में रहे हैं। वे मिल बैठ कर पैसा बांट लेते हैं लेकिन आप के जो कार्यकर्ता हैं, वे इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं और न आप ही ऐसा कर सकते हैं। न आप उन को पैसा खिलाने का काम कर सकते हैं और न आप उन को कमीशन दे सकते हैं, इसलिये वे मन में आप के साथ नहीं हैं और जो आप की नीतियां हैं, उन से उल्टा वे काम कर रहे हैं। मैं आप को कहना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों को बदलने में आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर आप संत बन कर कंठी माला ले कर जाप करते रहेंगे तो मैं आप से कहता हूं कि इस से कोई कल्याण होने वाला नहीं है।

एक बात और मैं आप से कहना चाहता हूं। रिजर्वेशन के बारे में वहां पर बात हुई है और कुछ इशारा उस तरफ़ लोगों ने किया था कि रिजर्वेशन हो या न हो और हो तो किस आधार पर हो। मैं आप को कहना चाहता हूं कि रिजर्वेशन तो मनु-स्मृति के काल से चला आ रहा है। हम इस में कोई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। हम मनु-स्मृति को मानते हैं। मनु-स्मृति को ही आप ले लीजिए। उस का जो काम है, उस पर वह छोड़ दीजिए। वैश्य का काम है खेती, नौकरी और व्यापार, राज-पाट आप ले लीजिए। वैश्य और शूद्र अपने आप निपट लेंगे कि किस को खेती करनी है, किस को नौकरी करनी है और किस को व्यापार करना है। आप का जो संविधान है, उस में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की बात कही गई है और उसी आधार पर कांग्रेस की सरकारों ने रिजर्वेशन किया है और आज अगर हम उस को करने जा रहे हैं, तो आप गालियां दे रहे हैं। उन लोगों का क्या मुंह है जिस से वे इस बारे में कहें। आन्ध्र में 26 परसेंट रिजर्वेशन किया गया है, कर्नाटक में 40 परसेंट किया गया है, केरल में 40 परसेंट है, महाराष्ट्र में 33 परसेन्ट है और उत्तर प्रदेश में भी इन का ही किया हुआ है। तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि अगर हमारे कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में इस को शुरू किया है, तो किस लिए हल्ला कर रहे हो। कितनी आप में ईमानदारी है? आप बड़े लोगों का एक संगठन बनाना चाहते हो। मैं तो श्री कर्पूरी ठाकुर को बधाई देना चाहता हूं और उन की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने जनता पार्टी के सब से विवादग्रस्त कार्यक्रम को लागू करने का बीड़ा उठाया है। सम्पूर्ण क्रान्ति का बहुत नारा लगाया जाता है। सम्पूर्ण क्रान्ति का मतलब यह तो नहीं है कि जो मार खाता था वह मार खाता रहे, जो पिछड़ा हुआ था वह पिछड़ा रहे। पिछड़ा हुआ अगर आगे आएगा, जो मार खाने वाला है, वह आगे आएगा, तो फिर जिस के पास है, वह उसे नहीं देना चाहेगा और उसे देने के लिए नाराज होगा।

18.00 hrs.

चेयरमेन साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत इम्पार्टेन्ट मसला है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि 50 प्रतिशत से अधिक सीटों का रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। जो लोग 80 प्रतिशत हैं उनके लिए 50 प्रतिशत स्थान ही क्यों? मैं आप से कहना चाहता हूं कि अगर आर्थिक तौर पर यह करना चाहते हैं तो करें। आज हिन्दुस्तान के अन्दर एक ही वर्ग के, एक ही वर्ण के लोगों के पास खेती भी है, नौकरी भी है, व्यापार भी है और वही वर्ग या वर्ण सब चीजों पर कुण्डली मार कर बैठा हुआ है। हम आर्थिक तौर पर रिजर्वेशन के लिए तैयार...

[श्री राम नरश कुशवाहा]

हैं । हर गरीब हमारा भाई है, हरिजन भी हमारा भाई है । लेकिन जो ये सब चीज़ों पर कब्जा जमाये बैठे हैं उनकी संख्या दो प्रतिशत है । आप दो प्रतिशत के लिए 50 प्रतिशत रिजर्वेशन और 98 प्रतिशत के लिए भी 50 प्रतिशत रिजर्वेशन दें, यह हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं । इसलिये आपको अगर आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन करना है तो लाभकर जोत के किसान जिनका मूल वतन पांच सौ रुपये है या जो इंकमटेक्स देने वाले व्यापारी हैं उनका आप जनसंख्या में प्रतिशत निकाल लीजिए और उसका हिसाब निकाल कर उन्हें जनसंख्या के हिसाब से पांच प्रतिशत स्थान ज्यादा दे दीजिए । जितने ये लोग इस देश की सम्पत्ति पर कब्जा जमाये हुए हैं उनकी जनसंख्या के मुताबिक उन्हें दे दीजिए, । आप एक पेशे की नीति अपना लें । एक आदमी एक रोज़गार, खेती, नौकरी और व्यापार । बिना इसके न आप देश में बेरोज़गारी मिटा सकते हैं, न गरीबी मिटा सकते हैं । ये जातिवाद के हिमायती और जातिवाद पर पनपने वाले लोग जो हैं इनका प्रतिशत आप निकाल लीजिए ।

MR. CHAIRMAN : He may continue tomorrow. The House stands adjourned till 11 a.m. tomorrow.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, April 28, 1978/Vaisakha 8, 1900 (Saka).

GIPMAND—I—762 LS 880

PLS. 40 XIV. 45.78
880

© 1978 BY LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (SIXTH EDITION) AND PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI.